"आय, उपभोग एवं बचत–दौसा जिले के सम्बन्ध में एक आनुभाविक अध्ययन"

शोध–प्रबन्ध

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

में

पीएच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत

अर्थशास्त्र

(सामाजिक विज्ञान संकाय)

शोधार्थी

नरेन्द्र कुमार मीना

शोध निर्देशिका

डॉ. (श्रीमती) अरूणा कौशिक

विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग,

राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.)

अर्थशास्त्र विभाग

सामाजिक विज्ञान संकाय

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (राज.)

2017

घोषणा–पत्र (शोधार्थी)

मैं, **नरेन्द्र कुमार मीना** घोषणा करता हूँ, कि मेरे द्वारा कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में पीएच.डी. उपाधि **अर्थशास्त्र** हेतु प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध जिसका शीर्षक **"आय, उपभोग एवं बचत–दौसा जिले के सम्बन्ध में एक आनुभाविक अध्ययन"** है, मेरा मौलिक कार्य है।

मेरी जानकारी एवं विश्वास में इसमें किसी भी प्रकार की पूर्व प्रकाशित सामग्री, अन्य किसी के द्वारा लिखित सामग्री या किसी भी विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा के संस्थान में प्रस्तुत डिग्री या डिप्लोमा की उपाधि की सामग्री को प्रयोग में नहीं लिया गया है, अपरिहार्य स्थिति में ली गई ऐसी हर सामग्री का यथा स्थान संदर्भ एवं आभार व्यक्त कर दिया गया है।

नरेन्द्र कुमार मीना

स्थान – कोटा **शोधार्थी**

दिनांक – 25.04.2017 **(नरेन्द्र कुमार मीना)**

Date : 25.04.2017

Certificate

It is to certify that,

(i) The thesis entitled "आय, उपभोग एवं बचत–दौसा जिले के सम्बन्ध में एक आनुभाविक अध्ययन" submitted by **Mr. Narendra Kumar Meena** is an original piece of research work carried out under my supervision.

(ii) Literary presentation is satisfactory and the thesis is in a form suitable for publication.

(iii) Work evidence the capacity of the candidate for critical examination and independent judgement.

(iv) Candidate has put in at least 280 days of attendance every year.

Supervisor:

Dr. (Smt.) Aruna Kaushik
Head, Department of Economics,
Govt. Arts Girls College, Kota

आभार

वह ईश्वर ही है, जो कण–कण में समाया है। कुछ करने की शक्ति हमें ईश्वर से ही मिलती है। इसलिए सबसे पहले परमपिता परमेश्वर के प्रति आभारी हूँ, जिसने मुझे शोध–प्रबन्ध कार्य को सम्पादित करने की शक्ति प्रदान की।

मैं अपनी शोध–निर्देशिका डॉ. (श्रीमती) अरूणा कौशिक, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा (राजस्थान) का हृदय से आभारी हूँ, जिनके मूल्यवान निर्देशन, उपयोगी सुझाव, तार्किक पद्धति एवं प्रेरणादायी प्रोत्साहन के कारण शोध–प्रबन्ध पूर्ण हो सका।

मैं डॉ. रीटा गुलाटी, प्राचार्य, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा, डॉ. मंजुला त्यागी, प्राचार्य, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा एवं सभी संकाय सदस्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान किया।

मैं हृदय से आभारी हूँ सहायक निदेशक, सांख्यिकी विभाग, दौसा एवं चैयरमैन नगरपालिका, दौसा जिन्होंने विषय से सम्बधित सूचनाऐं समय पर उपलब्ध करवाने में महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया। साथ ही पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय, दौसा, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा, राजकीय महाविद्यालय, कोटा, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अध्ययन हेतु शोध से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध कराने में अपेक्षित सहयोग दिया।

मैं श्री कल्याण सहाय शर्मा, व्याख्याता अर्थशास्त्र–विभाग, राजकीय महाविद्यालय, दौसा का भी सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने इस शोध प्रबन्ध के सम्पादन में अपना महत्त्वपूर्ण समय निकालकर मेरा मार्गदर्शन किया।

मैं प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध की पूर्णता एवं शिक्षाध्ययन में अपने पिताजी प्रोफेसर भगवान सहाय मीना, सेवानिवृत प्राचार्य, बी. बी. डी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिमनपुरा, जयपुर के प्रति श्रद्धावनत हूँ, जिन्होंने विषय–चयन से लेकर विषय–निर्वाह तक की समस्त कठिनाईयों को दूर करने में सहृदयता से सहयोग किया, मैं सदैव इनका ऋणी रहूँगा।

मैं अपनी माताजी का वन्दन करता हूँ जिनके स्नेह एवं आशीर्वाद से ही यह प्रयास संभव हो सका। इसके अतिरिक्त चयनित परिवारों के मुखियाओं का भी दिल से आभारी हूँ जिन्होंने शोध–प्रबन्ध से सम्बन्धित प्रश्नावली के अन्तर्गत पूछे गये प्रश्नों के उत्तर एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने में पूरी मदद की।

मैं अपनी प्रतिदिन की सहयोगी बड़ी बहिन डॉ. मंजु मीना एवं जीजाजी डॉ. भरत सिंह मीना का आभारी हूँ, जिन्होंने अपने अति व्यस्त समय के बावजूद उचित मार्गदर्शन के साथ–साथ कार्य–सम्पादन में भी सर्वाधिक योगदान किया।

मैं आभारी हूँ अपने जीजाजी डॉ. समय सिंह मीना, डॉ. महेश चन्द्र मीना, श्री रामावतार मीना, श्री भीमराज मीना का जिन्होंने अपने आशीर्वाद एवं प्रोत्साहन से मेरा उत्साहवर्धन किया तथा बहिनों डॉ. प्रेमलता मीना, डॉ. हेमलता मीना, श्रीमती सुशीला मीना, श्रीमती ममता मीना, जागृति मीना, प्रतिभा मीना का जिन्होंने कार्य–सम्पादन के साथ अत्यधिक स्नेह प्रदान किया।

मैं इस शोध के माध्यम से उन विद्वज्जनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके सुयोग्य हाथों से यह शोध–कार्य निरीक्षण हेतु प्रस्तुत होगा।

नरेन्द्र कुमार मीना

दिनांक : 25.04.2017

शोध–छात्र

(नरेन्द्र कुमार मीना)

प्राक्कथन

किसी भी देश का आर्थिक विकास पूँजी निर्माण पर निर्भर करता हैं। पूँजी निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से आय, उपभोग एवं बचत प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, चाहे हम पूँजी निर्माण को पूर्ति पक्ष की दृष्टि से देखे या मांग पक्ष की दृष्टि से। अतः किसी भी देश के जीवन स्तर को ऊँचा उठाने के लिए पूँजी निर्माण एक अनिवार्य साधन है। पूँजी निर्माण जिस पर आर्थिक विकास की दर निर्भर करती है, देश में कितना होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि देश के नागरिक आय का उपयोग किस प्रकार करते हैं। इस दृष्टि से देश अथवा स्थान विशेष में आय तथा इसका उपभोग व बचत के रूप में उपयोग की वास्तविक जानकारी के लिए आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है।

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में उपभोग व बचत तथा अन्य कारकों के बीच सम्बन्ध का अध्ययन उपभोग व्यवहार व उपभोग प्रवृत्ति को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की दृष्टि से और भी महत्त्वपूर्ण है, जिससे उचित नीति निर्माण में सहायता मिले।

जन्म से ही दौसा जिले से सम्बन्धित होने के कारण मेरी रूचि दौसा जिले के विभिन्न आय वर्ग वाले परिवारों की आय, उपभोग एवं बचत से सम्बन्धित प्रवृत्तियों के अध्ययन में थी। अतः शोध–प्रबन्ध अध्ययन के लिए दौसा जिले के परिवारों को चुना है।

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य दौसा जिले की पारिवारिक इकाईयों की आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर यह ज्ञात करना हैं कि ये प्रवृत्तियाँ किन कारकों से प्रभावित होती हैं तथा इनमें परिवर्तन किस दिशा में हैं। प्रस्तुत शोध में कुल 500 सर्वेक्षित परिवारों को चार पृथक–पृथक आय वर्गों में विभाजित कर उनकी आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों का पृथक–पृथक रूप से अध्ययन किया गया है। अध्ययन में यह पाया कि यहां के निवासियों का जीवन–स्तर अधिकांशतः निम्न तथा मध्यम स्थिति को दर्शाता है।

सामान्यतया यह माना जाता है कि समाज व देश के लिए बचत आर्थिक विकास का आधार है तथा यह आय एवं उपभोग के अन्तर पर निर्भर करती हैं। बचत की मात्रा कितनी होगी यह आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। निम्न आय वर्ग की आय कम होने के कारण यह वर्ग बचत कम कर पाता है जबकि उच्च आय वर्ग की आय अधिक होने के कारण बचत करने में सक्षम होता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न आय वर्ग की अधिकता के कारण क्या इससे बचत की अपेक्षा न रखी जावे अथवा केवल उन लोगों से ही अधिक बचत की अपेक्षा की जावे जो संख्या में बहुत कम हैं। साथ ही उच्च आय वर्ग अपनी आय को प्रतिष्ठा के वशीभूत होकर विलासिता की वस्तुओं तथा

अनुत्पादक मदों पर व्यय करता है। वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है कि उच्च आय वर्ग की उस आय को बचत के रूप में एकत्रित किया जावे जो आय व्यय के रूप में अनुत्पादक कार्यों में प्रयोग की जाती है। साथ ही निम्न आय वर्ग को भी छोटी–छोटी बचत के लिए प्रेरित किया जावे, क्योंकि बूंद–बूंद से ही सागर भरता है।

इस उद्देश्य से प्रस्तुत अध्ययन दौसा जिले के चयनित परिवारों के क्रॉस–सेक्शन आँकड़ों के आधार पर उपभोग व बचत व्यवहार की प्रवृत्तियों को समझने का एक प्रयास है। इस क्षेत्र के लिए यह प्रथम प्रयास हैं जिससे क्षेत्रीय विकास नीति के लिए अध्ययन के निहितार्थ प्रासंगिक हो सकते हैं।

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध "आय, उपभोग एवं बचत–दौसा जिले के सम्बन्ध में एक आनुभाविक अध्ययन", शीर्षक का अध्ययन छः अध्यायों के माध्यम से किया गया हैं। जो इस प्रकार है :

प्रथम अध्याय : शोध–प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में प्रस्तावना शीर्षक के अन्तर्गत शोध का परिचय (विकासशील देशों में आय का विरोधाभास, विकसित एवं विकासशील देशों में आय, उपभोग एवं बचत), साहित्य की समीक्षा, अध्ययन के प्रमुख बिन्दु, शोध–प्रबन्ध के उद्देश्य, शोध–परिकल्पनाएँ, अध्ययन–क्षेत्र (दौसा जिला) का परिचय, सर्वेक्षण का कार्य–क्षेत्र, अध्ययन–विधि, शोध–तकनीक, शोध की सीमाएँ आदि का विवेचन किया गया है।

द्वितीय अध्याय : शोध–प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय में आय, उपभोग एवं बचत के सैद्धान्तिक विवेचन शीर्षक के अन्तर्गत आय, उपभोग एवं बचतः प्रतिष्ठित दृष्टिकोण, प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचना, कीन्सियन दृष्टिकोण, अल्पकालीन उपभोग फलन, दीर्घकालीन उपभोग फलन, बचत फलन, उपभोग फलन की तकनीकी विशेषताएँ, आय, उपभोग एवं बचत में आनुभाविक तथ्य (निरपेक्ष आय परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना, स्थायी आय परिकल्पना, जीवन स्तर में उपभोग का नियम–एंजिल) का विवेचन किया गया है।

तृतीय अध्याय : शोध–प्रबन्ध के तृतीय अध्याय में विभिन्न आय–वर्गो की आय प्रवृत्तियाँ का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न आय–वर्गों की औसत मासिक आय एवं उनकी परस्पर तुलना, विभिन्न आय–वर्गों के मध्य आय विषमता, विभिन्न आय–वर्गों के वर्ष 2010 से 2014 तक आय सूचकांक, आयु–वर्ग एवं आय–स्तर का सम्बन्ध, कार्य के घन्टे एवं आय–स्तर का सम्बन्ध, आय के सहायक स्त्रोत, आय–स्तर एवं परिवार में आय–अर्जकों की संख्या, वर्तमान अर्जित आय एवं जीवन–स्तर के प्रति दृष्टिकोण, उच्च आय–वर्ग एवं आयकर की प्रवृत्ति का अध्ययन किया गया हैं।

चतुर्थ अध्याय : शोध–प्रबन्ध के चतुर्थ अध्याय में विभिन्न आय–वर्गों की उपभोग प्रवृत्तियाँ का तुलनात्मक अध्ययन एवं उपभोग निर्धारक कारक शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न आय–वर्गों का औसत मासिक उपभोग एवं उनकी परस्पर तुलना, उपभोग–विषमता, वर्ष 2010 से 2014 तक उपभोग–सूचकांक, उपभोग–व्यय का औसत मासिक प्रतिशत, विभिन्न मदों पर व्यय के औसत प्रतिशत की वर्ष 2010 व 2014 में तुलना, औसत व सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति, विभिन्न मदों पर व्यय की औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC), प्रतीपगमन समीकरण, आय दुगनी होने पर विभिन्न उपभोग मदों पर व्यय, वर्तमान उपभोग–स्तर से सन्तुष्टि एवं असन्तुष्टि के कारण, उपभोग पर प्रदर्शन प्रभाव एवं उपभोग निर्धारक कारकों (सामाजिक स्थिति, शिक्षा स्तर, आश्रित सदस्यों की संख्या, सम्पत्ति, रोजगार तथा प्रवर्जन) का विश्लेषण किया गया हैं।

पंचम अध्याय : शोध–प्रबन्ध के पंचम अध्याय में विभिन्न आय वर्गो की बचत प्रवृत्तियाँ का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक के अन्तर्गत विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की औसत मासिक बचत–विषमता एवं उनकी परस्पर तुलना, बचत विषमता की स्थिति, वर्ष 2010 से 2014 तक बचत सूचकांक, औसत व सीमान्त बचत प्रवृत्तियाँ, प्रतीपगमन समीकरण, बचत संस्थाएँ, बचत के उद्देश्य, बचत करने में कठिनाईयाँ, बचत वृद्धि के उपाय, बीमा और बचत एवं पारिवारिक ऋण भार का विश्लेषण किया गया हैं।

षष्ठम् अध्याय : शोध–प्रबन्ध के षष्ठम् अध्याय में आय, उपभोग एवं बचत अध्ययन के निष्कर्ष एवं नीतिगत निहितार्थ शीर्षक के अन्तर्गत आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन, सर्वेक्षित परिवारों की आय, उपभोग एवं बचत वृद्धि से सम्बधित विभिन्न समस्याऐं एवं इन समस्याओं को दूर करने के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं।

प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध में यह पाया गया कि दौसा जिले के अधिकांश परिवारों का जीवन–स्तर अब भी उम्मीदों से काफी नीचे है। दौसा जिले का एक बड़ा प्रतिशत भाग निम्न आय वर्ग के अर्न्तगत आता है। यह उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति एवं अधिक लागत वाले रोजगारों के कारण है। उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके आय, उपभोग एवं बचत स्तर में सुधार की आवश्यकता है। अतः पारिवारिक इकाईयों को उस स्तर तक प्रशिक्षित एवं जागरूक करने की आवश्यकता है, जहां वे आय, उपभोग एवं बचत सम्बन्धी निर्णय अपने विवेक से लेकर अपने परिवार को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज को लाभान्वित कर सके। अतः प्रस्तुत शोध का उद्देश्य तभी सार्थक हो सकेगा, जब इसका विस्तृत अध्ययन कर सामूहिक कदम उठाकर अनुकूल परिवर्तन लाये जावें।

अनुक्रमणिका

अध्याय – क्र.स.	अध्याय विश्लेषण	पृष्ट संख्या
अध्याय– 1	**प्रस्तावना**	**1-45**
	1.1 साहित्य की समीक्षा	5
	1.2 अध्ययन के प्रमुख बिन्दु	13
	1.3 शोध–प्रबन्ध के उद्देश्य	15
	1.4 शोध–परिकल्पनाएँ	15
	1.5 अध्ययन–क्षेत्र (दौसा जिला) का परिचय	16
	1.6 सर्वेक्षण का कार्य–क्षेत्र	29
	1.7 अध्ययन–विधि	29
	1.8 शोध तकनीक	35
	1.9 शोध की सीमाएँ	39
	1.10 संदर्भ सूची	40
अध्याय– 2	**आय, उपभोग एवं बचत : सैद्धान्तिक विवेचन**	**46-75**
	2.1 आय, उपभोग एवं बचत : प्रतिष्ठित दृष्टिकोण	50
	2.2 प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचना	53
	2.3 कीन्सियन दृष्टिकोण	54
	2.4 उपभोग फलन की तकनीकी विशेषताएँ	58
	2.5 आय, उपभोग एवं बचत में आनुभाविक तथ्य	62
	2.6 निष्कर्ष	73
	2.7 संदर्भ सूची	74
अध्याय– 3	**आय–प्रवृत्तियाँ : विभिन्न आय–वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन**	**76-90**
	3.1 विभिन्न आय–वर्गों की औसत मासिक आय एवं उनकी परस्पर तुलना	78
	3.2 विभिन्न आय–वर्गों के मध्य आय–विषमता	80
	3.3 विभिन्न आय–वर्गों के वर्ष 2010 से 2014 तक	82

	आय–सूचकांक	
	3.4 आयु–वर्ग एवं आय–स्तर का सम्बन्ध	83
	3.5 कार्य के घन्टे एवं आय–स्तर का सम्बन्ध	84
	3.6 आय के सहायक स्त्रोत	84
	3.7 आय–स्तर एवं परिवार में आय अर्जकों की संख्या	87
	3.8 वर्तमान अर्जित आय एवं जीवन–स्तर के प्रति दृष्टिकोण	87
	3.9 उच्च आय–वर्ग एवं आयकर की प्रवृत्ति	88
	3.10 निष्कर्ष	89
	3.11 संदर्भ सूची	90
अध्याय– 4	**उपभोग–प्रवृत्तियाँ : विभिन्न आय–वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन**	**91-129**
	4.1 विभिन्न आय–वर्गों का औसत मासिक उपभोग एवं उनकी परस्पर तुलना	92
	4.2 विभिन्न आय–वर्गों के मध्य उपभोग विषमता	94
	4.3 विभिन्न आय–वर्गों के वर्ष 2010 से 2014 तक उपभोग सूचकांक	97
	4.4 विभिन्न आय–वर्गों में औसत मासिक उपभोग व्यय का प्रतिशत	97
	4.5 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की विभिन्न मदों पर व्यय के औसत प्रतिशत की वर्ष 2010 व 2014 में तुलना	106
	4.6 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की औसत व सीमान्त उपभोग–प्रवृत्ति	107
	4.7 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की विभिन्न मदों पर व्यय की औसत उपभोग–प्रवृत्ति (APC)	108
	4.8 प्रतीपगमन समीकरण	109
	4.9 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की आय दुगनी होने पर विभिन्न उपभोग मदों पर व्यय	110
	4.10 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की वर्तमान	112

	उपभोग–स्तर से सन्तुष्टि	
	4.11 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की असन्तुष्टि के कारण	113
	4.12 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों का उपभोग पर प्रदर्शन प्रभाव	113
	4.13 उपभोग निर्धारक कारकों का विश्लेषण	114
	4.14 निष्कर्ष	126
	4.15 संदर्भ सूची	128
अध्याय– 5	**बचत–प्रवृत्तियाँ : विभिन्न आय–वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन**	**130-148**
	5.1 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की औसत मासिक बचत–विषमता एवं उनकी परस्पर तुलना	132
	5.2 विभिन्न आय–वर्गों के मध्य बचत–विषमता की स्थिति	134
	5.3 विभिन्न आय–वर्गों के वर्ष 2010 से 2014 तक बचत सूचकांक	137
	5.4 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की औसत व सीमान्त बचत–प्रवृत्तियाँ	137
	5.5 प्रतीपगमन समीकरण	138
	5.6 बचत संस्थाएँ	138
	5.7 बचत के उद्देश्य	139
	5.8 बचत करने में कठिनाईयाँ	141
	5.9 बचत वृद्धि के उपाय	142
	5.10 जीवन बीमा और बचत	142
	5.11 पारिवारिक ऋण भार	143
	5.12 निष्कर्ष	147
	5.13 संदर्भ सूची	148
अध्याय– 6	**आय, उपभोग एवं बचत अध्ययन के निष्कर्ष एवं नीतिगत निहितार्थ**	**149-158**
	6.1 आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन	150
	6.2 समस्याएँ	154

	6.3 अनुशंसाएँ	155
परिशिष्ट	**शोध–अध्ययन का अपेक्षित योगदान** **संदर्भ ग्रंथ** **प्रश्नावली** **शोध–पत्र**	**159** **160-165** **166-175** **176**

संकेताक्षर (Abbreviations)

a	स्वायत्त उपभोग
APC	औसत उपभोग–प्रवृत्ति
b	आय–रेखा का ढ़ाल = **MPC**
BEP	सम–कटाव बिन्दु
C	उपभोग
Cp	स्थायी उपभोग
Ct	अस्थायी उपभोग
$Coefficient\ of\ Variation$	विचरण–गुणांक
ECM	त्रुटि शुद्धिकरण सिद्धान्त
GDP	सकल घरेलू उत्पाद
LC	जीवन–चक्र
LRM	तार्किक प्रतीपगमन सिद्धान्त
MPC	सीमान्त उपभोग–प्रवृत्ति
MRM	बहुविकल्पिय प्रतीपगमन सिद्धान्त
PIH	स्थायी आय परिकल्पना
r	ब्याज
S	बचत
$\overline{X}$	औसत
Y	आय
y	आय
Yp	स्थायी आय
Yt	अस्थायी आय
σ	मानक–विचलन

अध्याय – 1

प्रस्तावना

प्रस्तावना

आर्थिक विकास जीवन स्तर में सुधार की एक निरन्तर एवं बहुआयामी परिवर्तनों की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास के संदर्भ में अवधारणात्मक सोच में निरन्तर परिवर्तन हुआ है। प्रारम्भिक चिंतन (1940 तक) में आर्थिक वृद्धि को महत्त्वपूर्ण मानते हुए राष्ट्रीय आय में वृद्धि को इसका पर्याय माना जाता रहा है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में निरन्तर प्रति व्यक्ति उत्पादन या आय में वृद्धि की प्रवृत्ति हो तो उसमें यह निहित है कि उस देश में उत्पादन क्षमता के विस्तार से बेहतर भौतिक जीवन की संभावनाएँ बनी हैं। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय पर ही प्रति व्यक्ति वास्तविक उपभोग निर्भर करता है। आर्थिक विकास की एक अन्य अवधारणा के अनुसार प्रति श्रम इकाई पर वास्तविक कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि निर्भर है। इस अवधारणा के आधार पर अर्थव्यवस्था की उत्पादकता से दीर्घकालीन प्रवृत्ति का निर्धारण होता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि या तो निर्दिष्ट उत्पादन साधनों के गुणात्मक निष्पादन क्षमता अथवा इनकी उत्पादकता में परिमाणात्मक वृद्धि के कारण होती है अथवा उत्पादक साधनों की मात्रा में वृद्धि के कारण होती है। पाश्चात्य् देशों में यह भी सम्भव है कि उत्पादक साधनों की मात्रा तथा इनकी उत्पादकता दोनों ही में एक साथ वृद्धि होने के फलस्वरूप आर्थिक विकास हुआ हो।

1940–50 के दशकों में औपनिवेशिक शासन से मुक्त अर्थव्यवस्थाओं में पिछड़ी स्थिति से उबरने के लिए आर्थिक वृद्धि के स्थान पर आर्थिक विकास की सोच प्रारम्भ हुई। निम्न आय, निम्न उपभोग, निम्न बचत एवं निम्न उत्पादकता जैसे गरीबी–चक्रों को तोड़ने के लिए प्रभावी व्यूहनीति बनाने पर बल दिया गया। इस परिप्रेक्ष्य में केवल प्रति व्यक्ति आय विकास का सही मापक नहीं रहा। संरचनात्मक परिवर्तन (आधुनिकीकरण की ओर) को विकास का मापक माना गया। अर्थशास्त्रियों में यह सोच बनी कि आय की असमानता, निर्धनता एवं निम्न स्वास्थ्य स्तर आदि में परिवर्तन कमी के रूप में हो, इस दृष्टि से आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में माना जाने लगा जिसमें आय में वृद्धि के साथ निर्धनता तथा बेरोजगारी में कमी हो।

प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जरूरतें होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए वह अपने राष्ट्र पर निर्भर रहता है। प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उन्हें विकास का उचित अवसर उपलब्ध कराए। यही आर्थिक विकास की परिवर्तित धारणा का मूल आधार है। अन्य शब्दों में, अर्थपूर्ण आर्थिक विकास के लिए देश की जनता के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होना आवश्यक है।

तीव्र विकास हेतु भिन्न–भिन्न आर्थिक प्रणालियों का अनुप्रयोग व समर्थन समय–समय पर हुआ है। इसी संदर्भ में पूँजीवाद, समाजवाद एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था का पारस्परिक विकल्प के रूप में उदय हुआ। परन्तु उक्त पद्धतियों में से कोई भी एक पद्धति अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। सामान्यतः सभी अर्थशास्त्री आर्थिक वृद्धि हेतु निम्न दो प्रकार के साधनों को महत्त्वपूर्ण मानते हैं : (अ) भौतिक साधन तथा (ब) अभौतिक या मानवीय साधन।

आर्थिक वृद्धि में प्रो. डेनिसन, साइमन कुजनेट्स, शुल्ज इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने अभौतिक साधनों के योगदान को अधिक महत्त्वपूर्ण माना है। इसके लिए उन्होंने अनुभव–जन्य तथ्यों से निष्कर्ष प्राप्त किये। इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्री जैसे नर्कसे, हिक्स, सिंगर इत्यादि भौतिक तथा अभौतिक साधनों के संयोग को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। मानवीय पूँजी को महत्त्वपूर्ण मानने वाले अर्थशास्त्री भी अप्रत्यक्ष रूप से भौतिक साधनों की उपलब्धता का महत्त्व स्वीकारते हैं।

वस्तुतः आर्थिक वृद्धि का आधार वे भौतिक साधन होते हैं जिनमें पूँजी निर्माण एवं तकनीकी का स्तर शामिल होता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने पूँजी निर्माण एवं आर्थिक वृद्धि में प्रत्यक्ष एवं उच्च स्तरीय सहसम्बन्ध माना है। वास्तविक एवं विस्तृत अर्थ में पूँजी निर्माण से अभिप्राय किसी समय में एक समाज में निष्क्रिय पूँजीगत साधनों की मात्रा में वृद्धि एवं सक्रिय साधनों की दक्षता में वृद्धि की प्रक्रिया से है, अर्थात् मनुष्यकृत उत्पादन क्षमता में प्रत्येक वृद्धि पूँजी निर्माण की द्योतक होती है। इस धारणा के अनुसार वे देश प्रगति की दौड़ में आगे निकल जाते हैं जिनमें पूँजी निर्माण की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, जैसे– अमेरिका, जापान, ब्रिटेन आदि। भारतीय संदर्भ में देखा जाये तो पूँजी की अपर्याप्तता इसके आर्थिक विकास में प्रमुख बाधक रही है। पूँजी निर्माण मनुष्य तब ही कर सकता है, जब वह अर्जित आय का एक अंश बचत करके पूँजीगत साधनों के निर्माण में लगाये। चूंकि बचत, उपभोग के त्याग पर निर्भर करती है अतः वह समाज जो वर्तमान में उपभोग का त्याग करके बचत को पूँजी निर्माण में लगाता है वह भविष्य में अधिक उच्च स्तरीय जीवन प्राप्त करने में सक्ष्म हो जाता है एवं वह देश जो आय को पूर्णतः वर्तमान उपभोग पर व्यय करके बचत कम करता है उसका भावी जीवन–स्तर निम्न रहता है। अतः आर्थिक वृद्धि के लिए वांछित पूँजी निर्माण हेतु बचतें महत्त्वपूर्ण हैं।

बचत किसी भी अर्थव्यवस्था में पूँजी की अभिवृद्धि का एकमात्र साधन है। बचत की मात्रा जो कि पूँजी निर्माण का आधार है, स्वयं आर्थिक विकास को सम्भव बनाती है, वह

बचत करने की क्षमता, इच्छा एवं सुविधा आय की मात्रा पर निर्भर करती है। चूंकि बचत, आय एवं उपभोग का अन्तर है, अतः बचत, उपभोग पर निर्भर करती है।

बचत एवं आय में प्रत्यक्ष धनात्मक सम्बन्ध है जबकि बचत एवं उपभोग में अप्रत्यक्ष एवं ऋणात्मक सम्बन्ध होता है। यद्यपि बचत के पूर्ति पक्ष को आय एवं उपभोग के अतिरिक्त अन्य अनेक चर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं जिनमें देश की आर्थिक स्थिरता की स्थिति, आय–वितरण, पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण, करारोपण एवं बचत से सम्बन्धित संस्थागत कारण आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध में महत्त्वपूर्ण आर्थिक चरों आय, उपभोग एवं बचत के अन्तर्सम्बन्ध का अध्ययन किया गया हैं।

कीन्स के समग्र मांग दृष्टिकोण के पश्चात्, पूँजी निर्माण के मांग पक्ष पर अधिक जोर दिया जाने लगा। चूंकि पूँजीगत साधनों की मांग समाज में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग पर निर्भर करती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग मुख्यतः आय, उपभोग एवं बचत प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। इनके अलावा अन्य चरों में विनियोग हेतु प्रेरणाओं, ब्याज–दर एवं बाजार के आकार को शामिल किया जा सकता है। वास्तव में विनियोग हेतु प्रेरणा व बाजार का आधार समाज में उपभोग व बचत प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है।

इस प्रकार पूँजी निर्माण संश्लिष्ट रूप से आय, उपभोग एवं बचत प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, चाहे हम पूँजी निर्माण को पूर्ति पक्ष की दृष्टि से देखें या मांग पक्ष की दृष्टि से। अन्ततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी भी देश के जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने हेतु पूँजी निर्माण एक अनिवार्य साधन है। पूँजी निर्माण किसी देश में कितना होगा, जिस पर आर्थिक विकास की दर निर्भर करती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि देश के नागरिक आय का उपभोग किस प्रकार करते हैं।

एक विरोधाभास जो स्वतः ही एक सामान्य नागरिक के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है कि दोनों ही प्रकार से बचत एवं उपभोग को बढ़ाकर पूँजी निर्माण कैसे किया जा सकता हैं? चूंकि बचत व उपभोग में विपरीत सम्बन्ध है। बचत के बढ़ने पर उपभोग कम होगा जिसके फलस्वरूप पूँजी निर्माण की मांग कम हो जायेगी क्योंकि समग्र मांग में कमी हो जायेगी। दूसरी ओर यदि समग्र मांग को बढ़ाने के लिए उपभोग बढ़ाया जाये तो बचत की मात्रा कम हो जायेगी जिससे पूँजी निर्माण का पूर्ति पक्ष प्रभावित हो जायेगा एवं आर्थिक विकास अवरूद्ध होगा। परन्तु वस्तु–स्थिति यह है कि उपभोग एवं बचत में विपरीत सम्बन्ध केवल उसी स्थिति में ही सत्य होंगे जबकि हम आय को स्थिर मान लें या हम यह मान लें कि उपभोग एवं बचत में परिवर्तन से आय में परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः न केवल उपभोग

और बचत आय पर ही निर्भर करते है बल्कि स्वयं आय–स्तर भी उपभोग एवं बचत में परिवर्तनों पर निर्भर करता है। उपभोग में वृद्धि से चूंकि समग्र मांग में वृद्धि होगी जिससे रोजगार एवं अन्ततः आय में भी वृद्धि होती है जिससे स्वयं बचत भी बढ़ जाती है। यही स्थिति बचत पक्ष की भी है। बचत बढ़ने पर पूँजी निर्माण होगा एवं अन्ततः आय में वृद्धि होगी।

आज का विश्व दो भागों में विभक्त है। एक ओर ऐसे विकसित देश हैं जो जीवन–स्तर की चरम सीमाओं को छू रहे हैं जबकि दूसरी ओर ऐसे विकासशील देश हैं जो औसत जीवन–स्तर को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हैं। संसार में अविकसित देश भी हैं जो निम्नतम स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। यदि आय की दृष्टि से इन देशों की तुलना करें तो विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय विकासशील देशों की अपेक्षा कई गुना अधिक है। उदाहरण के लिए अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में लगभग 70 गुना अधिक है। इसी प्रकार जापान, ब्रिटेन इत्यादि विकसित देशों की प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय विकासशील देशों की अपेक्षा काफी अधिक है।

बचत की दृष्टि से दोनों प्रकार के देशों में काफी भिन्नता प्रतीत होती है। जहाँ विकसित देशों में बचत की दर लगभग 35 व 40 प्रतिशत तक है वहां विकासशील देश बचत दर को मात्र 20 प्रतिशत तक ही ला पाये हैं। इसके साथ ही विकासशील देशों के नागरिक आर्थिक विकास के लिए बचत के महत्त्व को भी नहीं समझते हैं। विकासशील देशों में विभिन्न सामाजिक कुरीतियों, अन्धविश्वासों, उत्सवों एवं रीति–रिवाजों आदि पर आय का काफी बड़ा भाग व्यय कर दिया जाता हैं। जिनमें विवाह एवं मृत्युभोज तथा अन्य ऐसे कार्यों पर आय को व्यय किया जाता है जो मात्र प्रतिष्ठा प्राप्ति से प्रेरित होते हैं।

उपभोग प्रवृत्तियों की तुलनात्मक स्थिति का यदि अवलोकन करें तो विकासशील देशों में आय का लगभग 3/4 भाग खाद्य सामग्री पर व्यय कर दिया जाता है। जबकि मनोरंजन, शिक्षा एवं अन्य मदों पर व्यय काफी कम होता है। जबकि दूसरी ओर विकसित देशों में आय का काफी बडा भाग खाद्य सामग्री के अतिरिक्त अन्य मदों पर व्यय किया जाता है। जहाँ विकसित (विशेषतया पूँजीवादी) देशों में विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन एवं उपभोग अधिक किया जाता है वही विकासशील देशों में आय का काफी बड़ा भाग अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग पर व्यय किया जाता है।

सैद्धान्तिक दृष्टि से आय व उपभोग में अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का महत्त्वपूर्ण विषय रहा है। कीन्स (1936) द्वारा प्रस्तुत उपभोग फलन की धारणा के बाद

आनुभाविक अध्ययन के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण शोध कार्य हुए हैं। कुजनेट्स (1952), स्मिस्थिज (1955), ड्यूजनबरी (1949), फ्रीडमैन (1957), एण्डो व मोद्गिल्यानी (1963) आदि अर्थशास्त्रियों ने काल श्रेणी व क्रॉस–सेक्शन अध्ययनों के आधार पर समष्टिगत आय व समष्टिगत उपभोग के बीच अल्पकाल व दीर्धकाल में पाये जाने वाले सम्बन्धों को ज्ञात करने का प्रयास किया है।

नीति निर्माण की दृष्टि से भी आय व उपभोग का सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण अध्ययन का विषय है। इस दृष्टि से क्षेत्रीय आधार पर आय व उपभोग में सम्बन्ध को जानने, विश्लेषित करने तथा इसके नीतिगत निहितार्थों को समझने की दृष्टि से प्रस्तुत शोध अभिप्रेरित है।

प्रस्तुत शोध में दौसा जिले की पारिवारिक इकाइयों के आय, उपभोग एवं बचत प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि विगत वर्षों में आय स्तरों में जो परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, तद्नुसार उपभोग एवं बचत में किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ बनी हैं? तथा इनमें अन्तर्सम्बन्ध का स्वरूप किस प्रकार का है?

चूँकि व्यष्टि स्तर पर विभिन्न परिवारों की आय, उपभोग एवं बचत की स्थिति की जानकारी से अध्ययन क्षेत्र में आय व उपभोग संरचना से लोगों के जीवन स्तर की स्थिति उद्घाटित होती है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखकर प्रस्तुत शोध में चयनित परिवारों में आय, उपभोग एवं बचत प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि जीवन–स्तर की वास्तविक स्थिति को समीक्षित किया जा सके। साथ ही निर्धनता उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए क्रियान्वित वर्तमान कार्यक्रम की पृष्ठ–भूमि में अप्रत्यक्ष रूप से नीतियों की प्रभावशीलता को मूल्यांकित किया जा सके।

वस्तुतः प्रस्तुत शोध एक लघु प्रयास है जिसमें उपभोग एवं बचत प्रारूप को समझ के माध्यम से प्राप्त नीतिगत निहितार्थों से गरीबी एवं कुपोषण जैसी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावी नीति प्रस्तुत करने के लिए निष्कर्ष प्राप्त किये जा सके।

1.1 साहित्य की समीक्षा :

समग्र उपभोग समग्र मांग का महत्त्वपूर्ण घटक है, अतः सक्रियतावादी आर्थिक नीतियों में इसके महत्त्व के कारण आर्थिक विश्लेषण में समष्टिगत आय एवं उपभोग के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन शोध का प्रमुख विषय रहा है। व्यापार चक्रों को समझने तथा इन्हें नियंत्रित करने लिए अपनाई जाने वाली आर्थिक नीतियों की दृष्टि से उपभोग के व्यवहार

को समझने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में अनेक शोध कार्य हुए हैं। कीन्स की उपभोग विषयक धारणा को आनुभाविक आधार पर जांचने से प्रारम्भ हुए शोध कार्यों का अब तक निरन्तर विकास हुआ है, जिसके आधार पर मांग प्रबन्धन नीतियों में उपभोग व्यवहार विषयक मान्यतायें प्रयोग में ली जाती हैं।

कीन्स के पश्चात् कुजनेट्स, ड्यूजनबरी, स्मिथिज, टोबिन, एण्डो, ब्रुमबर्ग, मोदिग्लियानी एवं फ्रीडमैन आदि इस क्षेत्र के प्रमुख शोधकर्ता अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने आय के साथ उपभोग में परिवर्तन की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रवृत्तियों तथा उन्हें निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या की। प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य एवं क्षेत्र सीमा को ध्यान में रखते हुए आय, उपभोग एवं बचत सम्बन्धी प्रवृत्तियों पर हुए कुछ प्रमुख शोध कार्यों की संक्षेप में विवेचना प्रस्तुत है।

आर्थिक विकास के आधुनिकरण के विचारों की प्राप्ति के लिए कई अर्थशास्त्रियों ने अपने शोध कार्यों में उत्पादन वृद्धि, सामाजिक एवं आर्थिक समीकरण, आधुनिक ज्ञान, सुधार, संस्थाओं के व्यवहार और अवांछनीय स्थिति को समाज से दूर करने में नीतिगत उपायों की एक तर्क से समन्वित प्रणाली का विकास करने की व्याख्या की। आर्थिक विकास के लिए सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक एवं संस्थागत ढ़ांचे में परिवर्तन को भी शामिल किया गया है। आर्थिक विकास जीवन की गुणवत्ता को अधिक सक्षम करने की क्षमता को बढ़ाता है।

ICMR (2006) के अनुसार एक क्षेत्र की संवृद्धि में आर्थिक विकास का प्रभाव पड़ता हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले योगदान को बताता हैं। आर्थिक विकास, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले योगदान को सक्रिय करने में परस्पर निर्भरता को दर्शाता हैं। अतः पारम्परिक विकास सिद्धान्त यह बताता है कि आर्थिक विकास पूँजी संचय की ओर जाता है। यह संचय पीढ़िगत बोध और अधिशेष के उस पुननिर्वेश के साथ होता है जो अचल पूँजी के उपयोग तथा श्रम के साथ जो श्रम आधिक्य पारम्परिक क्षेत्र में स्थानान्तरण से होता है [1]।

पूँजी निर्माण रोजगार को उत्पन्न करता है जो उत्पादन को बढ़ावा देता है। यद्यपि इस विकास को निरन्तर रखा जा सकता है, यदि आधुनिक क्षेत्र के लिए भोजन की पर्याप्त आपूर्ति की गारन्टी हो। यह भोजन की खपत की वृद्धि का परिणाम है। इस तरह की प्रक्रिया, पारम्परिक क्षेत्र को आधुनिक क्षेत्र में स्थानान्तरित करने में और इस तरह कम

विकसित अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपनायी जाती है [2]।

उपभोग प्रवृत्ति उपभोग करने की इच्छा मात्र है लेकिन वास्तविक उपभोग आय में परिवर्तन (वृद्धि) का स्थान लेता है लेकिन इससे वास्तविक उपभोग में हुई वृद्धि वह प्रयोज्य आय नहीं है, जिससे देश का आर्थिक विकास होता है। इस प्रकार से प्राप्त पूँजी निर्माण और उपभोग आर्थिक विकास के लिए बाधक है। उपभोग फलन कुल आय और कुल उपभोग के मध्य सम्बन्ध दर्शाता है। उपभोक्ता का पैसा अर्थव्यवस्था को चलाने में और फुटकर वस्तुओं को खरीदने में काम आता है [3]। खुदरा व्यापार मानव उपभोग के द्वारा निर्मित होता है।

Wilhite (2008) के अनुसार उपभोग, वह धारणा है जो "अर्जित सम्पत्ति का विभिन्न वस्तुओं (सामान, उत्पाद, तकनीकि परिवर्तन से बढ़ती हुई उपभोग प्रवृत्ति) के उपयोग में व्यय को दर्शाती है" [4]।

Williams and Zimmerman (1935) ने अपने अध्ययन में उपभोग, बचत व आय सम्बन्धी क्रॉस सेक्शन डाटा संकलित किये, जिनका उपयोग उपभोग सम्बन्धी अध्ययनों में व्यापक रूप से हुआ [5]।

Keynes (1936) ने उपभोग का आधारभूत मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार वास्तविक आय बढ़ने पर उपभोग में वृद्धि होती है, लेकिन आय वृद्धि से कम। अतः आय बढ़ने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती है तथा बचत प्रवृत्ति बढ़ती है [6]।

Haberler (1955) ने कीन्स के निष्कर्ष, ''मौद्रिक अर्थव्यवस्था में बिना हस्तक्षेप (स्वतः) संतुलन नहीं हो सकता'' को इस आधार पर सही नहीं माना कि जब कीमत–स्तर घटता है तो वास्तविक सम्पत्ति (आय) बढ़ जाती है जिससे उपभोग बढ़ता है। यह प्रभाव स्वतः अर्थव्यवस्था को संतुलन की ओर प्रेरित करता है [7]। Pigou (1943) ने अपने लेख "The Classical Stationary State" में इसी निष्कर्ष को प्रतिपादित किया जो पीगू प्रभाव के नाम से जाना जाता है [8]।

Brady and Friedman (1947) ने अपने अध्ययन में बताया कि एक उपभोक्ता का उपभोग उसकी निरपेक्ष आय पर नहीं वरन् समाज में आय वितरण की स्थिति पर निर्भर करता है। उन्होंने बजट आँकड़ों द्वारा सापेक्ष आय परिकल्पना की पुष्टि की [9]।

Duesenberry (1949) ने अपने लेख में सापेक्षित आय परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि उपभोग चूंकि प्रदर्शन प्रभाव व आदत बन जाने से प्रभावित होता है, अतः उपभोग निरपेक्ष आय के बजाय व्यक्ति की आय वितरण की स्थिति तथा भूतकालीन उच्च आय से निर्धारित होता है। Duesenberry (1949) ने यू.एस. अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित 1921–41 के आँकड़ों के आधार पर आय व उपभोग में प्रतीपगमन विश्लेषण से उक्त निष्कर्ष सही पाया। उन्होंने अपने अध्ययन में यह प्रतिपादित किया कि समृद्धि के समय आय वृद्धि की तुलना में उपभोग कम दर से बढ़ता है तथा मुद्रास्फीति के समय आय घटने पर उपभोग लगभग स्थिर रहता है अर्थात् उपभोग में अनिवर्ती प्रभाव पाया जाता है [10]।

Modigliani (1949) ने अपने अध्ययन में यह दर्शाया कि उपभोग निरपेक्ष आय के साथ–साथ व्यक्ति की सम्पत्ति व भावी आय स्थिति से निर्धारित होता है [11]।

Modigliani and Brumberg (1954) और Ando and Modigliani (1963) द्वारा प्रतिपादित जीवन–चक्र परिकल्पना यह व्यक्त करती है कि अल्पकाल में सम्पत्ति स्थिर रहने से श्रम आय व उपभोग में गैर–आनुपातिक सम्बन्ध पाया जाता है परन्तु दीर्घकाल में सम्पत्ति परिवर्तनशील होने से उपभोग व आय में आनुपातिक सम्बन्ध पाया जाता है। इसमें यह निहित है कि दीर्घकाल में आय बढ़ने के साथ–साथ उपभोग व बचत दोनों आनुपातिक रूप में बढ़ते हैं [12, 13]।

Ackley and Suits (1950) ने बताया कि सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन से उपभोग व्यय प्रभावित होता है [14]।

Tobin (1951) ने अपने अध्ययन में बताया कि उपभोग निरपेक्ष आय से निर्धारित होता है [15]। दोनों के बीच कीन्स की निरपेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार गैर–आनुपातिक सम्बन्ध पाया जाता है। समय के साथ सम्पत्ति प्रभाव से दीर्घकालीन आँकड़े आय व उपभोग में आनुपातिक प्रवृत्ति व्यक्त करते हैं पर अल्पकालीन उपभोग निरपेक्ष आय से ही निर्धारित होता है [6]।

Klein (1950) ने अपने लेख में उपभोग व सम्पत्ति के बीच सम्बन्ध को क्रॉस–सेक्शन आँकड़ों से जांचने का प्रयास किया [16]।

Kuznets (1952) ने अपने अध्ययन में 1899 से अमेरिका में बचतों का अनुमान लगाया। यह अध्ययन दीर्घकाल में कीन्स की परिकल्पना को पुष्ट नहीं करता। Kuznets ने

यह पाया कि अल्पकाल में apc > mpc होती है परन्तु दीर्घकाल में apc = mpc रहती है। अर्थात् दीर्घकाल में आय व उपभोग में आनुपातिक सम्बन्ध पाया जाता है [17]।

Hamburger (1955) ने अपनी पीएच.डी. शोध तथा अपने लेख में यह बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के वर्षों तथा बाद की समयावधि के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि सम्पत्ति–आय का अनुपात व उपभोग–आय के अनुपात में उच्च सह–सम्बन्ध रहा है [18]।

Hall and Mishkin (1982) ने अपने अध्ययन में इस तर्क का समर्थन किया है कि आय वृद्धि से उपभोग व्यय पर धनात्मक प्रभाव होगा। उनके विचार में ऐसे परिवार जो आय के एक समान स्तर पर हों परन्तु जिनके पास परिसम्पत्ति (बैंक जमा, सरकारी बांड, इक्विटी और वास्तविक सम्पत्ति आदि) दूसरे परिवारों की तुलना में अधिक हों तो वे उपभोग पर अधिक खर्च करते हैं अर्थात् उपभोग सम्पत्ति से प्रभावित होता है [19]।

Evans (1969) ने अपने अध्ययन में स्थायी आय परिकल्पना को ठीक पाया और यह माना कि व्यक्ति की दीर्घकालीन आय से दीर्घकालीन उपभोग जुड़ा होता है [20]।

Vakil (1973) ने अपने अध्ययन में 1919–60 तक के वार्षिक आँकड़ों को लेकर स्थायी आय परिकल्पना (PIH) को जांचने का प्रयास किया और अध्ययन में यह पाया कि भारत में स्थायी आय परिकल्पना सही नहीं पाई गई [21]।

Hall (1978) ने Random Walk Model में यह दर्शाया कि आने वाले समय का उपभोग वर्तमान उपभोग और यादृच्छिक त्रुटि के योग के बराबर होता है।

$$C_{t+1} = C_{t+Et}$$

चूँकि, यादृच्छिक त्रुटि अनियमित और भविष्यवाणी की जाने के योग्य नहीं होती, अतः उपभोग में Random Walk लागू होता है [22]।

Campbell and Deaton (1989) और Campbell and Mankiw (1991) ने अपने लेख में जीवन–चक्र (LC) परिकल्पना व स्थायी आय परिकल्पना (PIH) को परम्परावादी उपभोग फलन के साथ एकीकृत करने का प्रयत्न किया [23, 24]।

Dhakal and Sharma (2006) ने अपने लेख में खुली अर्थव्यवस्था में विनिमय दर को निर्धारक चर के रूप में लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था में समग्र उपभोग फलन को

अनुमानित करने का प्रयास किया तथा दर्शाया कि मौद्रिक व वास्तविक विनिमय दर समग्र उपभोग का महत्त्वपूर्ण निर्धारक चर है [25]।

Gupta and Kapoor (2002) ने अपने लेख में उपभोग पर ब्याज की दर में परिवर्तन के प्रभाव को ज्ञात करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के उपभोग सम्बन्धी आँकड़ों तथा जमाओं पर ब्याज दर के बीच प्रतीपगमन विश्लेषण में यह पाया गया कि ब्याज दर में वृद्धि से उपभोग घटता है [26]।

Palley (2008) ने अपने शोध में कीन्स, ड्यूजनबरी, एवं फ्रीडमैन के योगदानों को सम्मिश्रित करते हुए उपभोग व्यवहार का सैद्धान्तिक मॉडल विकसित करने का प्रयास किया, जिसे "सापेक्षित स्थायी आय" सिद्धान्त कहा गया। इस सिद्धान्त में अल्पकाल व दीर्घकाल में आय व उपभोग के मध्य सम्बन्ध को स्पष्ट किया है [27]।

उपभोग मॉडल के लिए Error Correction Model (ECM) एक प्रभावशाली पद्धति है। यह पद्धति उपभोग के गत्यात्मक टाईम सिरिज मॉडल को प्रस्तुत करती है तथा आय व उपभोग के मध्य दीर्घकालीन साम्य सम्बन्ध को भी स्थापित करती है [28]। उपभोग को समझने के लिए शोध अध्ययनों में इस दृष्टिकोण को उपयोग में लिया गया है।

Mei (2012) ने अपने अध्ययन में 2008 के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में जीवन–चक्र परिकल्पना की वैधता को परीक्षित करने का प्रयास किया। उन्होंने यह पाया कि जीवन–चक्र परिकल्पना के बजाय सापेक्षित आय परिकल्पना उपभोग व्यवहार की समुचित व्याख्या करती है [29]।

आय वृद्धि से उपभोग व्यय भी सामान खरीदने और अच्छी सर्विस प्राप्त करने के लिए बढ़ जाता है [30]।

Ajmair and Akhtar (2012) ने अपने लेख में आय, आयु, लिंग, शिक्षा व परिवार की संरचना का उपभोग पर प्रभाव ज्ञात करने का प्रयास किया तथा अपने अध्ययन में आय व उपभोग, आय व शिक्षा में सार्थक धनात्मक सम्बन्ध पाया लेकिन आयु व उपभोग में ऋणात्मक सम्बन्ध पाया [31]।

विगत शोधों के आधार पर उपभोग व्यय को विविध कारक प्रभावित करते हैं उनमें से सामाजिक–जनसांख्यिकीय कारक जैसे– मुखिया की आयु, निवास, परिवार का प्रकार, शिक्षा का स्तर आदि हैं। इन कारकों में सम्पत्ति के (चुने गए) घटकों का अध्ययन किया गया है [31]:

1) आयु : विभिन्न आयु वर्ग वाले सदस्यों का अनुभव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकि पर्यावरण आदि में अलग–अलग होता है। विगत शोधों में यह दर्शाया

गया है कि घर पर बने खाद्य पदार्थों, सेवाओं को छोड़कर अन्य उपभोग मदों पर मुखिया की आयु का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है।

2) निवास क्षेत्र : निवास क्षेत्र (शहरी एवं ग्रामीण परिवेश) जीवन–स्तर से सम्बन्धित होता है। उदारणतया, शहरी क्षेत्रों का जीवन–स्तर ग्रामीण क्षेत्रों से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों से अलग होता है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले परिवार घर से बाहर बने भोजन, घर, वस्त्र, सेवा एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर उपभोग व्यय कम करते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति इन मदों पर अधिक उपभोग व्यय करते हैं।

3) शिक्षा का स्तर : शिक्षा का स्तर परिवार के जीवन–स्तर, सामाजिक, व्यवसायिक और पर्यावरणीय परिस्थिति से प्रभावित होता है। पुराने शोधों के अनुसार शिक्षा, वस्त्र, सेवा, यात्रा एवं मनोरंजन पर प्रभाव डालती है, विशेष रूप से घर पर बने भोजन और उपयोगी वस्तुओं (ईंधन, बिजली एवं पानी) पर ऋणात्मक प्रभाव डालती है।

आज के समय में व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करने, अच्छे स्वास्थ्य, भौतिक सुविधाएँ, सुरक्षा, व्यवसाय एवं नौकरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवर्जन करता है [32]। विगत शोधों में यह देखा गया है कि प्रवर्जित परिवारों का उपभोग व्यय अप्रवर्जित परिवारों की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक बढ़ जाता है, यह अन्तर मुख्यतया घर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के कारण आता है। बहुत से गरीब परिवार रोजगार के लिए अपने पुराने आवासीय स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं।

Goldsmith (1955) ने अपने अध्ययन में पाया कि बचत की एक प्रमुख विशेषता यह है कि दीर्घकाल में कुल बचत एवं कुल आय का अनुपात स्थिर रहता है [33]।

Salam and Kulsum (2002) ने अपने अध्ययन में भारत में बचत के उच्चावचन के कारकों को पहचानने का प्रयास किया। यह अध्ययन प्रकट करता है कि राष्ट्रीय बचतों में परिवार–क्षेत्र की बचत सबसे अधिक योगदान देती है [34]। भारत में वैश्वीकरण का साक्ष्य नहीं मिलता अर्थात् उदारीकरण के बाद भी बचत घटने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ी ।

किसी देश के बचत व्यवहार को पांच मुख्य दक्षिणी एशियाई देशों (भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं श्रीलंका) में आधुनिक काल–श्रेणी विधि के द्वारा अध्ययन करके बताया कि बचत को ब्याज की दर तथा आय प्रभावित करती है [35]। दक्षिणी एशियाई देशों की बचत दर निम्न से मध्यम के मध्य रहती है जो तुलनात्मक रूप से अन्य विकासशील देशों, विशेष रूप से चीन व दक्षिणी/पूर्वी एशियाई देशों से कम है। वहां बचत दर 30 से 40 के मध्य होती है।

Burney and Khan (1992) और Gedela (2012) ने विशाखापट्टनम जिले में आदिवासी और ग्रामीण परिवारों के बचत को निर्धारित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। इस अध्ययन में आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित घरों के बचत व्यवहार को निर्धारित करने वाले कारकों को जानने के लिए बहुविकल्पिय प्रतीपगमन सिद्धान्त और तार्किक प्रतीपगमन सिद्धान्त प्रयोग किया। बचत को परिवार के मुखिया की आयु, निर्भरता अनुपात, आय और चिकित्सा व्यय प्रभावित करते हैं। जिसमें परिवार की आय मुख्य रूप से बचत को प्रभावित करती है [36, 37]।

Carpenter and Jensen (2002) और Kulikov et al. (2007) ने आधुनिक अर्थमितीय तकनीकों से पहचाना कि कैसे परिवार के सदस्यों की विशेषताएँ या लक्षण पाकिस्तान व स्टोनियाँ में बचत व्यवहार को प्रभावित करते हैं [38, 39]। Carpenter and Jensen (2002) ने इस बात पर जोर दिया की किस प्रकार बचत पर औपचारिक (बैंक) तथा अनौपचारिक (बचत कमेंटी) संस्थाओं की भूमिका होती है और उन्होंने पाया की आय बढ़ जाने से लोग बचत अधिक करने की कोशिश करते हैं लेकिन बचत अनौपचारिक संस्थाओं की तुलना में औपचारिक संस्थाओं में करना पसंद करते हैं [38]।

Losayza et al. (2000) ने मुख्य रूप से बचत निर्धारित कारकों का अध्ययन किया [40] और Attanasio and Banks (2000) ने मुख्य रूप से बचत का राष्ट्रीय आय, निवेश और समृद्धि (विकास) के मध्य प्रगतिशील (Dynamic) सम्बन्ध बताया है [41]।

Deaton and Paxson (2000) ने आय में वृद्धि एवं बचत के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन किया। उन्होंने इस सम्बन्ध को व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से इण्डोनेशिया, ताईवान (चीन) और थाईलैण्ड़ परिवारों के आँकड़ों को एकत्रित करके स्पष्ट किया [42]।

Bandiera et al. (2000) और Samwick (2000) ने विश्लेषण करके यह बताया कि बचत का घरेलू वित्तीय उदारीकरण [43], पेंशन में सुधार [44], टैक्स के लिए प्रोत्साहित [45] और सार्वजनिक बचत पर प्रभाव पड़ता है [46]।

Ramesh (2006) ने अपने अध्ययन में विभिन्न देशों में विभिन्न आय–वर्गों में घरेलू बचत एवं आर्थिक वृद्धि के मध्य सम्बन्ध बताया [47]।

Cilasum (2009) ने अपने अध्ययन में बताया कि उपभोक्ता की बचत के प्रति रूचि उपभोग करने के निर्णय पर निर्भर करती है जो कि पूँजी संचय, निवेश करने की प्रक्रिया, विकास एवं संवृद्धि के लिए महत्त्वपूर्ण है [48]।

20 वर्षो में विभिन्न आय–वर्गों की बचत पर शोध कार्य में यह पाया गया की उच्च आय–वर्ग वाले परिवार आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे होते हैं [49]।

बचत को आय, शिक्षा का स्तर, आयु, लिंग, परिवार का आकार, दीर्घकालीन ब्याज की दर, वित्तीय संस्थाओ से घर की दूरी, ऋण की मात्रा प्रभावित करती है [50]।

Brumberg and Modigliani (1954) और Ando and Modigliani (1963) ने क्रॉस–सेक्शन आँकड़ों के आधार पर बताया कि जिन परिवारों का आय स्तर उच्च होता है वे अधिक मात्रा में बचत करते हैं [12, 51]।

आर्थिक विकास के लिए पूँजी निर्माण व पूँजी निर्माण के लिए बचत का सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण चर है। बचत व्यवहार को समझने के लिए बहुत से शोध कार्य हुए हैं। इन सभी अध्ययनों में बचत व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे आय, ब्याज की दर, मुद्रा–स्फीति की दर, आय वृद्धि की दर, उत्पादन वृद्धि दर, विदेशी एवं घरेलू बचत अनुपात, आयु, शिक्षा, रोजगार की स्थिति, व्यवसाय, सम्पत्ति की खरीद, आयात, निर्यात, विदेशी सहायता, बैंक ऋण, मजदूरों को प्रेषण, सम्पत्ति, वित्तीय संस्थानों का विकास, उपभोग का तरीका एवं अन्य आय अर्जित करने के साधनों का अध्ययन किया गया है [52]।

निष्कर्ष रूप में आय, उपभोग व बचत में सम्बन्ध अर्थशास्त्रियों के लिए शोध का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहा है और उपभोग व्यवहार तथा इसके निर्धारक कारकों को लेकर अभी भी मतैक्य नहीं है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में उपभोग व बचत तथा अन्य कारकों के बीच सम्बन्ध का अध्ययन उपभोग व्यवहार व उपभोग प्रवृत्ति को सही परिप्रेक्ष्य में समझने की दृष्टि से और भी महत्त्वपूर्ण है, जिससे उचित नीति निर्माण में सहायता मिले। इस उद्देश्य से प्रस्तुत अध्ययन दौसा जिले के चयनित परिवारों के क्रॉस–सेक्शन आँकड़ों के आधार पर उपभोग व बचत व्यवहार की प्रवृत्तियों को समझने का एक प्रयास है। इस क्षेत्र के लिए यह प्रथम प्रयास है जिससे क्षेत्रीय विकास व्यूहनीति के लिए अध्ययन के निहितार्थ प्रासंगिक हो सकते हैं।

1.2 अध्ययन के प्रमुख बिन्दु :

अध्ययन का उद्देश्य स्थानीय समाज की वर्तमान समस्याओं की पृष्ठभूमि में समस्याओं के वास्तविक स्वरूप को पहचानकर उससे सम्बन्धित उन कार्यक्रमों, तथ्यों एवं संभावनाओं को प्रस्तुत करना है जिससे समस्या का समाधान निकाला जा सके।

प्रायः यह देखा गया है कि समाज का निम्नतम वर्ग अपनी आय का लगभग शत–प्रतिशत भाग उपभोग्य पदार्थों पर ही व्यय करता है। इससे उनकी बचत लगभग शून्य के बराबर रहती है। यह वर्ग तर्क देता है कि समाज का मध्यम एवं उच्च वर्ग जिसकी आय अपेक्षाकृत अधिक है, अपनी आय विभिन्न विलासिता मूलक वस्तुओं पर व्यय कर देता है। दूसरी ओर समाज का उच्च वर्ग यह तर्क प्रस्तुत करता है कि उसे आय के अनुपात में मजबूरन अधिक व्यय इसलिए करना पड़ता है कि उसे विभिन्न प्रकार के व्यय सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप करने पड़ते है जो कि उनके लिए अनिवार्य ही होते हैं तथा निम्न आय वर्ग को इस प्रकार के व्यय नहीं करने पड़ते हैं तथा यह वर्ग भी बढ़ती महंगाई के कारण अपनी आय की बचत, क्षमता के अनुरूप नहीं कर पाता। मध्यम वर्ग का तर्क है कि सबसे अधिक पीड़ित वर्ग वही है, क्योंकि उसकी आय तो निम्न वर्ग के निकट ही होती हैं, अतः इस वर्ग में अच्छी शिक्षा के प्रसार, प्रदर्शन प्रभाव, उच्च वर्ग का अनुशरण आदि के कारण व्यय बहुत अधिक होते हैं जबकि आय कम रहती है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग द्वारा प्रस्तुत विरोधी विचारों के बारे में वास्तविकता का अध्ययन तथ्यों को एकत्रित करके ही किया जा सकता है।

किसी भी देश का आर्थिक विकास पूँजी निर्माण के स्तर पर निर्भर करता है एवं यह स्वयं सिद्ध प्रमाण है कि अल्पविकसित देशों में पूँजी निर्माण बचत पर निर्भर करता है। एक ओर समाज यह अपेक्षा करता है कि देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से हो एवं दूसरी ओर समाज बचत के प्रति उदासीन है। यह इस तथ्य से प्रकट होता है कि जहां अमेरिका, जापान में बचत 40.00 प्रतिशत है, वहां भारत में बचत की मात्रा 25.00 प्रतिशत तक ही पहुँच पायी है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय समाज में उपभोग का स्तर काफी अधिक है। इस तरह की विसंगति एक समस्या बन जाती है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो सर्वेक्षण की समस्या से सम्बन्धित हैं, निम्नवत उभर कर सामने आते हैं : 1) क्या भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों की आय वास्तव में कम ही है ?; 2) क्या भारतीय समाज अधिक उपभोग का आदि बन चुका है ?; 3) क्या बचत क्षमता के अनुरूप लोगों की आय नहीं है ?; 4) क्या भारतीय समाज में बचत करने की सुविधाओं का अभाव है ?; 5) क्या भारतीय समाज बचत के प्रति इच्छुक नहीं है ?; 6) क्या कीमत व आर्थिक विषमताओं में वृद्धि बचत पर विपरीत प्रभाव डालती हैं ?; 7) क्या कीमत व आय वृद्धि में बढ़ता अन्तर बचत पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है ?

इन्हीं समस्याओं से प्रेरित होकर अध्ययन का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत उपर्युक्त विभिन्न समस्याओं का गहराई से अध्ययन करके वास्तविक तथ्यों तक पहुँच कर तथा समस्याओं का विश्लेषण कर उनके आवश्यक समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य, विभिन्न (उच्च, मध्यम एवं निम्न) आय वर्गों से सम्बन्धित आय के स्तरों के अनुरूप व्यय एवं बचत की विभिन्न प्रवृत्तियों का अध्ययन करके यह ज्ञात करने की कोशिश है कि विगत वर्षों में आय स्तरों में जो परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हुई हैं, तदनुसार व्यय एवं बचत में किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ रही। विशेषरूप से उपभोग एवं बचत की प्रवृत्तियाँ तथा विभिन्न मुद्दों पर किये जाने वाला व्यय (प्रतिशत में) एवं बचत की मात्रा, क्षमता, सुविधा एवं इच्छा के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है।

1.3 शोध–प्रबन्ध के उद्देश्य :

1. क्रॉस–सेक्शन आँकड़ों के आधार पर विभिन्न वर्गों की आय–प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।
2. आय–उपभोग सम्बन्ध विषयक विभिन्न परिकल्पनाओं का आनुभाविक आधार पर परीक्षण करते हुए अध्ययन क्षेत्र में उपभोग प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना तथा आय, उपभोग व बचत के अन्तर्सम्बन्धों की व्याख्या करना।
3. विभिन्न वर्गों की बचत व बचत उपभोग की वर्तमान प्रवृत्तियों के विश्लेषण से वर्गों के बीच आय व सम्पत्ति की असमानता को मापना तथा भावी स्थिति को पहचानना।
4. आय के अतिरिक्त उपभोग एवं बचत प्रवृत्तियों को निर्धारित करने वाले कारकों को पहचानना।
5. क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में आर्थिक वृद्धि के निर्धारक कारकों के रूप में वर्तमान प्रवृत्तियों के निहितार्थों को समीक्षित करना।

1.4 शोध परिकल्पनाएँ :

1. प्रयोज्य आय एवं उपभोग में धनात्मक सरलरेखीय गैर आनुपातिक सम्बन्ध पाया जाता है।
2. अधिक औसत आय वाले परिवारों में कम औसत आय वाले परिवारों की तुलना में औसत उपभोग प्रवृत्ति कम पाई जाती है।

$$\left(\frac{c}{y}\right)\text{Low Income} > \left(\frac{c}{y}\right)\text{High Income}$$

3. आय बढ़ने के साथ औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती है, लेकिन $apc > mpc$ रहती है।

1.5 अध्ययन–क्षेत्र (दौसा जिला) का परिचय[1] :

ऐतिहासिक पृष्ठ–भूमि :

दौसा के नाम की उत्पत्ति ''धोंसा'' शब्द से हुई है। पहाड़ी पर लकड़ी के प्रहार से बाहरी आक्रमणकारी की नगरवासियों को सूचना दी जाती थी। यह लकड़ी का प्रहारक धोंसा कहलाता था। कालांतर में इस शब्द का अपभ्रंश रूप ''दौसा'' हुआ।

दौसा एक अतिप्राचीन भू–भाग है। ऐतिहासिक एवं पुरातत्त्वीय अन्वेषणों से विदित हुआ है कि यह स्थल पूर्व–ऐतिहासिक एवं उत्तर–मध्यकाल में भी अस्तित्व में था। दौसा नगर वैदिक काल में मत्स्य प्रदेश के अन्तर्गत था। बाद में कछवाह वंश की प्रमुख गद्दी के रूप में विद्यमान रहा। दौसा को ही ''ढूंढ़ार'' राज्य की प्रथम राजधानी बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।

प्राचीन नगर पहाड़ी व किले के आस–पास था किन्तु बढ़ती जनसंख्या और विकास की प्रचुर सम्भावनाएँ तथा जिला मुख्यालय बन जाने से नगर का विस्तार लालसोट, जयपुर, आगरा की ओर सड़क मार्गों के आस–पास हुआ है।

दौसा जिले की स्थापना 10 अप्रेल 1991 में हुई थी। उस समय दौसा जिले में चार तहसील दौसा, सिकराय, लालसोट एवं बांदीकुई थी। तत्पश्चात् सवाई माधोपुर जिले की तहसील महुआ को भी दौसा जिले में शामिल कर दिया गया।

भौगोलिक स्थिति : दौसा जिला राजस्थान के पूर्व में 25'.33'' से 27'.33'' तक उत्तरी अक्षांश व 27'.33'' से 76'.5 तक पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। यह जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर व टोंक जिलों से घिरा हुआ है। दौसा जिले में पांच तहसील (दौसा, लालसोट, बसवा, सिकराय व महुआ) हैं (रेखा चित्र 1.1)।

भौगोलिक क्षेत्रफल 3,40,467 हेक्टर (2,950 वर्ग किलोमीटर) है। जिले की उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ अरावली श्रेणी का हिस्सा हैं। बाण गंगा नदी और मोरेल नदी क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं, परन्तु इनका बहाव पर्याप्त वर्षा के अभाव में नहीं के बराबर है। दौसा जिले में काली, पीली व दोमट मिट्टियाँ पाई जाती हैं जो कि आमतौर पर सभी प्रकार की फसलों की उपज के लिए उपयुक्त हैं। जिले में मौसम प्रायः शुष्क रहता है व दक्षिण–पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। जिले का न्यूनतम व अधिकतम तापमान क्रमशः 5 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस रहता है। औसत वर्षा का स्तर 604.03 मिलीमीटर है।

[1](स्त्रोत : जिला सांख्किीय रूप रेखा 2011–12, दौसा, राजस्थान)

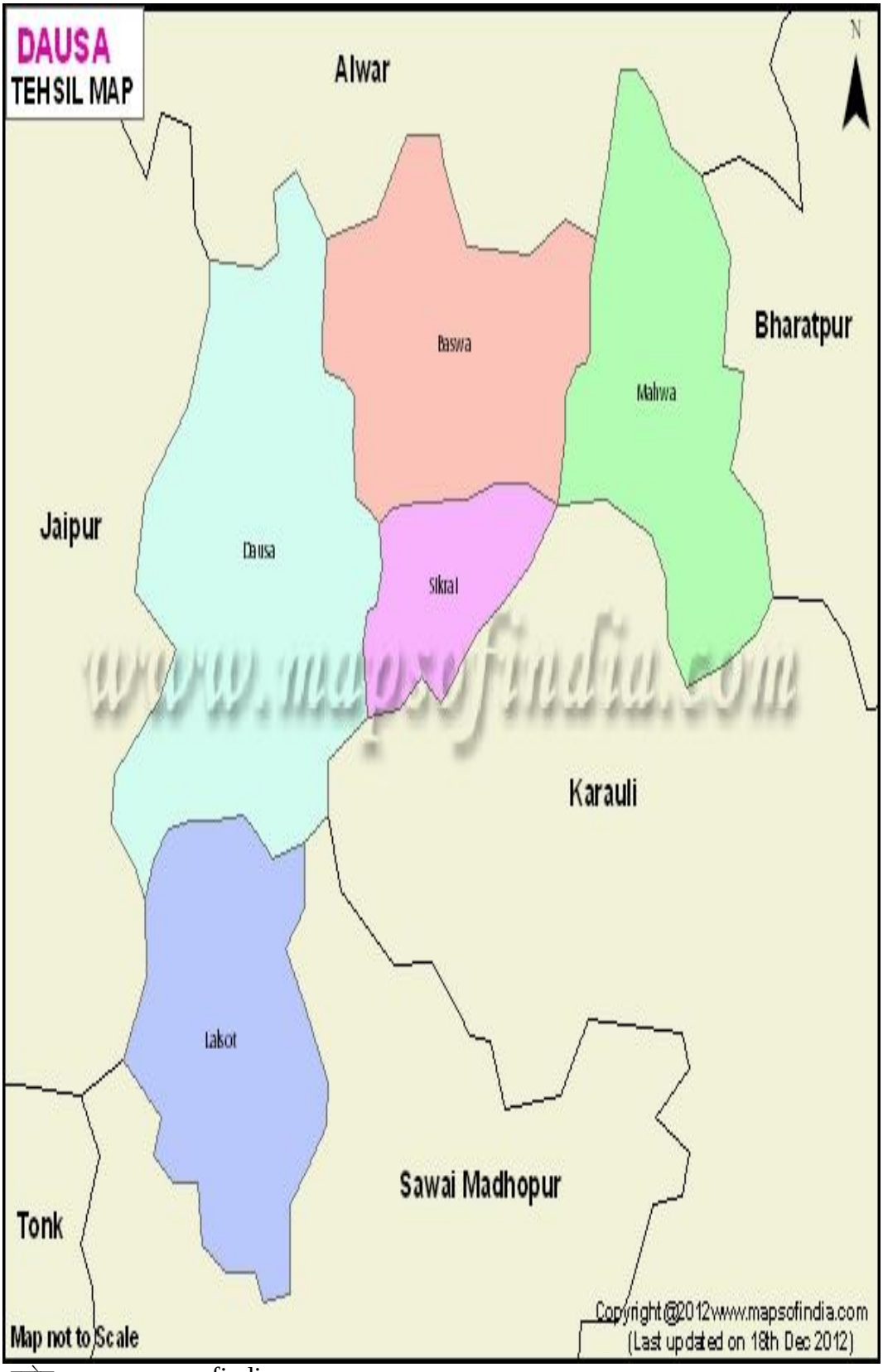

स्त्रोत : www.mapsofindia.com

रेखा चित्र 1.1 : दौसा जिले का मानचित्र

जनसंख्या : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दौसा जिले की जनसंख्या 16,37,226 है। जिसमें पुरुष 8,59,821 व महिला 7,77,405 हैं, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 2.39 प्रतिशत अनुपात है। दौसा जिले की 0–6 आयु वर्ग की जनसंख्या 2,56,802 है जो जिले की कुल जनसंख्या का 15.69 प्रतिशत है। दौसा जिले की औसत साक्षरता 69.17 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 84.54 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 52.33 प्रतिशत हैं, यह भारत की औसत साक्षरता 74.04 प्रतिशत से कम तथा राजस्थान की औसत साक्षरता 67.06 प्रतिशत से अधिक है। दौसा जिले का 2011 में लिंगानुपात 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 904 है, जो कि भारत व राजस्थान के औसत लिंगानुपात क्रमशः 940 व 926 से कम है।

दौसा जिले का शिशु लिंगानुपात 859 है। जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 में 406 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत व राजस्थान के औसत जनसंख्या घनत्व क्रमशः 382 व 201 से काफी अधिक है। सारणी 1.1 के अनुसार वर्ष 1981 से 2011 की जनगणनानुसार दौसा जिले की जनसंख्या वृद्धि निम्न प्रकार रही है।

सारणी 1.1 : वर्ष 1981 से 2011 की जनगणनानुसार दौसा जिले की जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि।

वर्ष	जनसंख्या				
	पुरुष	महिला	योग	दस वर्ष का अन्तर	प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (-)
1981	401199	358995	760194	-	-
1991	527747	466684	994431	234237	(+) 30.81
2001	693438	623625	1317063	322632	(+) 32.44
2011	859821	777405	1637226	320163	(-) 24.30

स्त्रोत : जनगणना प्रतिवेदन 2011, राजस्थान

सारणी 1.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना में जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत घटा है। परिवार नियोजन के माध्यम से "कम सन्तान सुखी इन्सान" के महत्त्व को बढ़ावा मिल रहा हैं। दौसा जिले में अधिकांश लोगों का प्रवर्जन उच्च शिक्षा, रोजगार, भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए ग्रामीण परिवेश से शहरी परिवेश में हो रहा हैं।

सारणी 1.2 से जानकारी मिलती है कि वर्ष 1991 की तुलना में वर्ष 2011 में शहरीकरण में वृद्धि हुई है।

सारणी 1.2 : वर्ष 1991 से 2011 की जनगणनानुसार दौसा जिले की जनसंख्या का वितरण।

जनगणना वर्ष		जनसंख्या		
		पुरुष	**स्त्री**	**योग**
1991	ग्रामीण	471678	417506	889184
	शहरी	56069	49178	105247
	योग	**527747**	**466684**	**994431**
2001	ग्रामीण	621591	559654	1181245
	शहरी	71847	63971	135818
	योग	**693438**	**623625**	**1317063**
2011	ग्रामीण	753670	680863	1434533
	शहरी	106151	96542	202693
	योग	**859821**	**777405**	**1637226**

स्त्रोत : जनगणना प्रतिवेदन 2011, राजस्थान

आय प्राप्ति के स्त्रोत : दौसा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जीविकोपार्जन के लिए मुख्यतया कृषि, मजदूरी एवं पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित उद्योग संचालित हैंः चर्म, लुहारी/सुथारी, चूना, गुड़–खांडसारी उद्योग, कुम्हारी, तेल, साबुन, अनाज, दाल, बांस–बैंत, हाथ–करधा, ताड़–गुड़, एल्यूमिनियम, टैक्सटाइल, लाख–चूड़ी, प्लास्टिक, इलेक्ट्रोनिक्स, माचिस, अगरबत्ती, फाईबर, पीतल एवं तांबे का सामान, मधुमक्खी उद्योग, जैविक खाध–उद्योग, ग्रामीण तेल–उद्योग, लकड़ी उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, मेसेनरी स्टोन, कंकर–बजरी, मार्बल ब्लॉक/खण्डा, पट्टी–कातला, ईंट भट्टे, चमड़ा उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, धातु आधारित उद्योग, मशीनरी एवं औजार बनाने से सम्बन्धित उद्योग, विद्युत मशीनरी एवं उपकरण आधारित उद्योग, रिपेयर एवं अन्य उद्योग सेवाएँ, व्यापार एवं वाणिज्य।

इसी तरह शहरों में तेल मील, भवन निर्माण, मजदूरी, पल्लेदारी, घड़ी रिपेयरिंग, ठेलों पर व्यवसाय, कपड़े की दुकानें, दालमिल, सिनेमाघर, ड्राइक्लीनर्स, फोटोस्टेट,

परचूनी/मिठाईयों की दुकानें, कम्प्यूटर, स्टेशनरी, बिजली के सामान, चमड़ा व्यवसाय, बूचड़खाने, खादी उद्योग, फ्लोरमिल, साबुन–फैक्ट्री, मोटर व्हीकल, दुग्ध व्यवसाय, सीनेटरी की दुकानें, सीमेन्ट की फर्म, आभूषण की दुकानें, जूते–मरम्मत का कार्य, क्रेशर मशीन, बोर काटने का कार्य, दर्जी का कार्य, दरी बुनाई, टी.वी. रिपेयरिंग, समरसेबल पम्प एवं रिपेयरिंग का कार्य, स्टोन–कटिंग, मिनरल ग्राइंड़िग, हैयर कटिंग, धोबी का कार्य, व्यवसाय केन्द्रों में सब्जी मण्ड़ी, कृषि उपज मण्ड़ी, जलाऊ लकड़ी मण्ड़ी आदि नित्य लगती हैं।

दौसा जिले में विद्युत मण्डल, तहसील, पंचायत समितियाँ, जलदाय विभाग, नगर निगम, नगरपालिकाएँ, पुलिस थाना, बैंक, न्यायालय, डाकघर, चिकित्सालय, कृषि विभाग, कलक्ट्री, आबकारी विभाग, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालय आदि सरकारी विभागों में लोग अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रामों, कस्बों, शहरों में रोजगार प्राप्ति के विकल्प हैं जिनमें व्यक्ति अपनी सेवाएँ देकर धनार्जन करते हैं।

उपभोग : दौसा जिले के ग्रामीण व्यक्ति अनाज, सब्जी, दूध, घी, दाल, तेल, मसाले, खाद्य पदार्थ, ईंधन, साबुन, माचिस, मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि स्थानीय विक्रेताओं से क्रय करते हैं। भवन निर्माण कार्य भी स्थानीय व्यक्तियों से कराते हैं। परिवार के लिए वस्त्र, सामाजिक उत्सवों के लिए आवश्यक सामान, वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु वस्त्र, जेवर, बर्तन, सजावटी सामान, टेन्ट आदि तथा भवन निर्माण के लिए सीमेंट, चूना, पत्थर, बजरी, ईंटें, लोहा आदि का क्रय अपने नजदीकी शहर से करते हैं।

शहरी व्यक्ति अनाज, सब्जी, दूध, घी, दाल, तेल, मसाले, खाद्य पदार्थ के साथ ही सीमेंट, चूना, पत्थर, बजरी, ईंटे, लोहा आदि शहरी विक्रेताओं से क्रय करते हैं। भवन निर्माण का कार्य सुविधानुसार ग्रामीण व शहरी लोगों से करवाते हैं। परन्तु परिवार के लिए वस्त्र, वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु वस्त्र, जेवर, बर्तन, सजावटी सामान आदि का क्रय जयपुर शहर से अधिक करते हैं। मनोरंजन के लिए पूनम टाकीज, सूर्य मन्दिर व गोल्ड टाकीज तीन सिनेमा हॉल हैं। विद्युत्, जल, डाकतार, टेलीफोन, सड़क तथा रेल यातायात की सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में हैं।

बचत : दौसा जिले के लोगों को अपनी छोटी–छोटी बचत जमा कराने की पर्याप्त सुविधाएँ हैं। वर्ष 2011–12 में 81 व्यवसायिक बैंक, 17 ग्रामीण बैंक, 12 सहकारी बैंक, 01 राजस्थान वित्त निगम हैं।

शहरी क्षेत्रों में, विभिन्न एजेन्ट जीवन बीमा आदि के माध्यम से बचत एकत्रित करते हैं। निजी क्षेत्र में साहूकार अधिक ब्याज की दर का प्रलोभन देते हैं, परन्तु लोग अपनी बचत बैंको में ही रखते हैं। सुरक्षा व अल्प बचत के कारण लोगों का बैंकों के प्रति ही झुकाव हैं। उक्त संस्थाओं के अलावा आदर्श क्रेडिट को–आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, सहारा इण्डिया, लाइफ इन्स्योर जैसी संस्थाओं में भी लोग अपनी बचतों को अच्छा ब्याज कमाने के लिए जमा कराते हैं।

जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपनी बचत को अधिक ब्याज दर पर अन्य लोगों को देते है या अपने पास जमा के रूप में रखते है अतः इन लोगों में जागरूकता के अभाव में उपर्युक्त संस्थाओं के प्रति रूझान नहीं है

आधारभूत संरचना :

विकास के आधारभूत ढ़ाँचे को प्रायः दो भागों में बांटा जाता है (1) आर्थिक व (2) सामाजिक। आर्थिक अथवा भौतिक आधार ढ़ाँचे में सिंचाई, शक्ति, परिवहन व संचार का प्रमुख स्थान होता है तथा सामाजिक आधार ढ़ाँचे में शिक्षा व स्वास्थ्य का प्रमुख स्थान होता है। दौसा जिले के आर्थिक आधार ढ़ाँचे की प्रगति व वर्तमान स्थिति का विवेचन निम्न रूप से है।

उर्जा एवं शक्ति : किसी भी क्षेत्र का विकास वहां की ऊर्जा के विकास पर निर्भर करता है। कृषि, उद्योग व परिवहन आदि को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के साधनों में व्यवसायिक ऊर्जा के अन्तर्गत कोयला, बिजली व पैट्रोल आते हैं तथा गैर–व्यवसायिक ऊर्जा के अन्तर्गत गोबर, ईंधन की लकड़ी तथा कृषिजन्य अवशिष्ट पदार्थ आते हैं।

दौसा जिले में व्यवसायिक ऊर्जा का विकास नहीं के बराबर हैं, क्योंकि यहां विद्युत् उत्पादन क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। इसका कारण वर्षा की कमी व ताप/थर्मल पावर जो कि कोयला, पैट्रोल, गैस व परमाणु–शक्ति से उत्पन्न की जाती है, आदि के अभाव के कारण उक्त क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है।

जिले में गैर–व्यवसायिक ऊर्जा के अर्न्तगत सौर ऊर्जा, ईंधन की लकड़ी व गोबर–गैस ऊर्जा का प्रयोग सीमित क्षेत्रों के साथ घरेलू कार्यों में किया जा रहा है, साथ ही इसके विकास पर ध्यान भी दिया जा रहा है। दौसा जिले में राजकीय विद्युत गृह नहीं है।

सारणी 1.3 से स्पष्ट हैं कि दौसा जिले में विद्युत का उपभोग काफी मात्रा में किया जाता है।

सारणी 1.3 : दौसा जिले में वर्ष 2011–12 में विभिन्न उपक्रमों में विद्युत का उपभोग।

1. विद्युतिकृत नगरों की संख्या	3
2. विद्युतिकृत ग्रामों की संख्या	1083
3. कुल ऊर्जा उपभोग	10177.24 यूनिट
(1) घरेलु उपभोग	1447.83 यूनिट
(2) सामान्य प्रकाश	32.41 यूनिट
(3) व्यवसायिक उपभोग	338.07 यूनिट
(4) औद्योगिक उपभोग	343.60 यूनिट
(5) सिंचाई	7035.35 यूनिट
(6) जल प्रदाय	270.04 यूनिट
(7) अन्य उपभोग	710.24 यूनिट
4. विद्युत् गृहों की संख्या	220kv2, 132kv4, 33kv96
5. विद्युतिकृत कुँए की संख्या	1750

स्त्रोत : दौसा जिला एक दृष्टि में 2011–12, राजस्थान

परिवहन सुविधाएँ : दौसा जिले में परिवहन में केवल रेल परिवहन व सड़क परिवहन का विकास हुआ है।

सड़क सुविधाएँ : वर्ष 2011 की आबादी के अनुसार 1082 कुल राजस्व ग्राम स्वीकृत हुए जो विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2012 तक आबाद ग्राम 1083 में से 225 ग्राम पंचायत मुख्यालयों सहित 775 ग्रामों को सड़क से जोड़ने के उपरान्त दौसा जिले की सड़क की लम्बाई 2,683.83 किमी. हो गई। आवागमन के साधनों की पहुँच गाँवों तक होने से आम आदमी की सुविधा को बढ़ावा मिला है।

रेल सुविधाएँ : दौसा जिले में रेल परिवहन का काफी विकास हो चुका है। जिले में दो रेलवे जंक्शन (दौसा, बाँदीकुई) व 14 छोटे स्टेशन हैं। रेल परिवहन के विकास से आवागमन में आम आदमी की सुविधा को बढ़ावा मिला है। रेल परिवहन से दौसा जंक्शन से दिल्ली, जयपुर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व गुजरात आदि राज्यों व

जिलों में आवागमन से आम आदमी को काफी सुविधा मिली है। दौसा जिले में से लगभग 44 पैसन्जर/सुपर फास्ट ट्रेन चलती हैं।

संचार सुविधाएँ : संचार के अन्तर्गत ड़ाक–सेवाएँ आती हैं। ड़ाक–सेवाओं का जिले के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान माना गया हैं। इससे ग्रामोंत्थान में भी सहायता मिली हैं। ड़ाक–सेवाओं का विस्तार ग्रामीण विकास, रोजगार–संवर्धन, अल्पबचत प्रोत्साहन व पिछड़े क्षेत्रों के उद्योग में मदद देने वाला माना गया है। जिले में एक प्रधान ड़ाकघर तथा तहसील स्तर व ग्रामीण स्तर पर भी ड़ाकघर सुविधाएँ उपलब्ध हैं। जिले में कुल 243 पोस्ट ऑफिस हैं, जो कि राजस्थान का 2.38 प्रतिशत हैं।

दूर–संचार सेवाएँ : टेलीफोन व टेलेक्स दूरसंचार के अन्तर्गत आते हैं। जिले में दूरसंचार के अन्तर्गत बी.एस.एन.एल. सरकारी क्षेत्र की कम्पनी हैं जिसका नेटवर्क जिले के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है, साथ ही निजी क्षेत्र की कम्पनियों का भी नेटवर्क जिले के सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है। जिले में बी.एस.एन.एल. का एक प्रधान कार्यालय हैं तथा तहसील स्तर पर भी इसके कार्यालयों की स्थापना की गई है। जिले में कुल 32 टेलीफोन केन्द्र हैं, जो कि राजस्थान का 1.79 प्रतिशत हैं, तथा तारघर दो हैं जो कि राजस्थान का 3.13 प्रतिशत हैं।

सामाजिक संरचना :

सामाजिक आधार ढ़ाँचे में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार–कल्याण, पेयजल, आवास व पर्यावरण आदि का समावेश होता है, लेकिन मुख्य रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य के विकास पर प्रकाश ड़ाला गया है।

शैक्षणिक सुविधाएँ : शिक्षा का मानवीय संसाधनों के विकास में प्रमुख स्थान है। शिक्षा एक साधन के साथ–साथ स्वयं में एक साध्य भी होती है, क्योंकि विकास का लक्ष्य लोगों को शिक्षित करना भी होता है। साक्षरता व शिक्षा के विकास से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसेः जन्म–दर गिरावट लाने में आसानी, शिशु–मृत्यु दर में कमी, बच्चों को दोपहर का भोजन देकर उनके पोषक तत्वों में सुधार की व्यवस्था, मानवीय दक्षता में वृद्धि से उत्पादन में बढ़ोत्तरी, जीवन स्तर में वृद्धि एवं सामाजिक परिवर्तन आदि से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में मदद मिलती है। यही कारण है कि सरकार ने शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम बनाये हैं।

राज्य सरकार शिक्षा एवं शिक्षा संसाधनों में सुधार के माध्यम से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रही है। इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं यथा– सर्वशिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सतत् शिक्षा कार्यक्रम और सम्पूर्ण साक्षर भारत आदि के माध्यम से सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।

दौसा जिले की वर्ष 2011 में साक्षरता 69.17 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता 84.54 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 52.33 प्रतिशत हैं, यह भारत की औसत साक्षरता 73.00 प्रतिशत से कम तथा राजस्थान की औसत साक्षरता 66.10 प्रतिशत से अधिक है (सारणी 1.4)। दौसा जिले के छात्र/छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। वर्ष 2001 में जिले की साक्षरता दर 61.84 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 69.17 प्रतिशत हो गयी है। अतः वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में साक्षरता का प्रतिशत 7.33 प्रतिशत बढ़ा है।

सारणी 1.4 : भारत, राजस्थान एवं दौसा जिले में वर्ष 2001 व 2011 में साक्षरता का प्रतिशत।

साक्षरता का प्रतिशत	कुल साक्षरता (प्रतिशत में)		पुरूष–साक्षरता (प्रतिशत में)		महिला–साक्षरता (प्रतिशत में)	
	वर्ष 2001	वर्ष 2011	वर्ष 2001	वर्ष 2011	वर्ष 2001	वर्ष 2011
भारत	64.80	73.00	75.30	80.90	53.70	64.60
राजस्थान	60.41	66.1	75.70	79.2	43.90	52.1
दौसा जिला	61.84	69.17	79.35	84.54	42.32	52.33

स्त्रोत : दौसा जिला एक दृष्टि में 2011–12, राजस्थान

प्रारम्भिक शिक्षा : प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में दौसा जिले ने गत दशक में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है। जिले में 1,054 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें छात्र व छात्रा विद्यालयों की संख्या क्रमशः 1,044 व 10 हैं। प्राथमिक विद्यालयों में विधार्थियों की संख्या वर्ष 2011–12 में 63,005 थी, जिसमें छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 29,685 व 33,320 है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राथमिकता दी गई है। जिले में 06–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को उपयोगी एवं समुचित शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रवर्तित योजना "सर्व शिक्षा अभियान" क्रियान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत विद्यालय प्रबंधन में जन भागीदारी से शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंग (जेण्डर) अन्तराल मिटाने से संबंधित गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया है। शत प्रतिशत नामांकन के ध्येय को प्राप्त करने एवं 06–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की उपस्थिति को विद्यालय में नियमित बनाये रखने के उद्देश्य से "चाइल्ड ट्रेकिंग सिस्टम" लागू किया गया है, तथा सघन पंजीकरण अभियान लागू कर विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा गया है।

साक्षर भारत मिशन : दौसा जिलें व सम्पूर्ण राजस्थान में भारत सरकार की एक केन्द्र प्रवर्तित योजना "साक्षर भारत" दिनांक 08 सितम्बर 2009 को घोषित की गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने की मानक आयु सीमा पार कर चुके तथा औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर खो चुके वयस्कों को शिक्षा के लिए विशेषकर महिलाओं को बढ़ावा देना एवं प्रौढ़ शिक्षा को सुदृढ़ करना है। साक्षर भारत योजना राज्य के 31 जिलों (कोटा एवं प्रतापगढ़ के अतिरिक्त) में लागू है। मनरेगा कार्य स्थलों पर निरक्षर कामगारों के लिए साक्षरता कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इससे दौसा जिले की साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है।

उच्च प्राथमिक शिक्षा : दौसा जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 2011–12 में 988 है, जिसमें छात्र व छात्रा विद्यालयों की संख्या क्रमशः 943 व 45 है तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कुल 1,68,108 है, जिसमें छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 89,293 व 78,815 है।

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा : दौसा जिले में वर्ष 2011–12 में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्रमशः 432 व 274 सरकारी क्षेत्र में है, जिसमें माध्यमिक स्तर पर छात्र व छात्रा विद्यालयों की संख्या क्रमशः 419 व 13 है, एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्र व छात्रा विद्यालयों की संख्या क्रमशः 255 व 19 है। माध्यमिक स्तर पर कुल विधार्थियों की संख्या 66,088 है, जिसमें छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 36,253 व 29,835 है। उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल विधार्थियों की संख्या 1,21,369 है, जिसमें छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 77,711 व 43,658 है।

शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के मध्य आवश्यक सेतु है। यह वह स्तर है जहां विधार्थी स्व–रोजगार/रोजगार हेतु तैयार होते हैं। इस उद्देश्य को

प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य/लक्ष्य वर्ष 2017 तक सकल नामांकन अनुपात को 61.44 प्रतिशत से बढ़ाकर 85.00 प्रतिशत करना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत गत दो वर्षों में 3,343 सिविल कार्य भी स्वीकृत किए हैं, जिसमें 73 सिविल कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है तथा 435 सिविल कार्य प्रगति पर हैं।

उच्च शिक्षा : दौसा जिले में उच्च शिक्षा के व्यापक और तेजी से विकास के परिणाम स्वरूप वर्ष 2011–12 में 46 महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में 7 राजकीय महाविद्यालय हैं, तथा 39 निजी महाविद्यालय हैं, जिसमें कुल विधार्थियों की संख्या 22,956 के लगभग है, जिसमें छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 15,210 व 7,746 है। राजकीय महाविद्यालय व निजी महाविद्यालय की भागीदारी के साथ "युवा विकास केन्द्र" स्थापित किये गये हैं।

तकनीकी शिक्षा : दौसा जिले में तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत पॉलोटेक्निक महाविद्यालय एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थित हैं।

1) पॉलोटेक्निक महाविद्यालय : दौसा जिले में तकनीकी शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु पॉलोटेक्निक महाविद्यालय संचालित किया गया है, जिसका पहला सत्र 2013–14 से शुरू हुआ है।

2) औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) : दौसा जिले में वर्तमान में एक आई.टी.आई. महाविद्यालय है, जिसमें विधार्थियों की संख्या 350 के लगभग है। निजी क्षेत्र में कई आई.टी. आई. महाविद्यालय भी है।

संस्कृत शिक्षा : संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन एवं सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। राज्य में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने एवं उसके विकास हेतु वर्ष 1958 में संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। वर्तमान में दौसा जिले में एक संस्कृत महाविद्यालय है तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 13 है।

राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु अनेक उपाय किये हैं, जिनमें कम्प्यूटर शिक्षा का विकास, राजीव गांधी डिजिटल विधार्थी योजना लागू की गई है, इसके साथ ही विद्यालयों में पुस्तकालय की सुविधा प्रदान की गई है और जो विधार्थी नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते उनके अध्ययन हेतु राज्य मुक्त विद्यालय की स्थापना की गई है।

चिकित्सा सुविधाएँ : "स्वस्थ इन्सान" विकास का साधन व साध्य दोनों होता है। स्वस्थ नागरिक ही देश का उत्पादन तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो ताकि वे बेहतर जिन्दगी जी सकें। देशवासियों का स्वास्थ्य प्रमुखतया उनके खान–पान, सुरक्षित पेयजल, आवास की सुविधाओं, पर्यावरण आदि तत्वों पर निर्भर करता है। इनका समुचित विकास होने से ही लोग निरोगी रहते हैं, क्योंकि उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियाँ ग्रसित नहीं कर पाती। स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवाएँ आती हैं, जो विशेषतया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिये लोगों को उपलब्ध कराई जाती हैं। उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं से शिशु–मृत्यु दर व सामान्य मृत्यु दर घटती हैं, जन्म–दर कम की जा सकती है, और जीवन की औसत आयु बढ़ती है।

दौसा जिले के विशेषकर कमजोर वर्ग व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार दौसा जिले के लोगों को संक्रामक व अन्य रोगों के नियंत्रण एवं उन्मूलन तथा उपचारात्मक व बचावात्मक सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। इसको मुख्य धारा में लाने हेतु विभिन्न प्रयास किये गये हैं। सारणी 1.5 में वर्ष 2012–13 में दौसा जिले में स्थित चिकित्सालयों की संख्या दर्शायी गई है।

सारणी 1.5 : वर्ष 2012–13 में दौसा जिले में चिकित्सालयों की संख्या।

चिकित्सालय	संख्या
जिला चिकित्सालय	01
एलोपैथिक चिकित्सालय	584
आयुर्वेदिक चिकित्सालय	100
यूनानी चिकित्सालय	03
होम्योपैथिक चिकित्सालय	03
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	29
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	09
उपस्वास्थ्य केन्द्र	237
मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र	02

स्त्रोत : दौसा जिला एक दृष्टि में 2011–12, राजस्थान

दौसा जिले में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएँ जैसे– मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोश, आयुर्वेदिक एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, धनवंतरि एम्बुलेस योजना, राजीव गांधी चल चिकित्सा इकाईयाँ, संस्थागत प्रसव एवं जननी सुरक्षा योजना, राजस्थान जननी सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस योजना, आशा सहयोगिनी योजना, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति योजना आदि। इनका का लाभ ग्रामीण परिवार व आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को प्राप्त हो रहा है।

अन्य सुविधाएँ :

प्रशासन : कलक्टर कार्यालय के निर्देशन में दौसा जिले का सामान्य प्रशासन नगरों में नगरपरिषद द्वारा संचालित होता है जो सफाई, सड़कों पर रोशनी, सड़क व नाली–निर्माण, भूमि क्रय–विक्रय तथा आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य व अन्य विकास का कार्य करती है। पंचायत समितियाँ आस–पास के ग्रामों में पंचायत राज संस्थाओं की गतिविधियों का संचालन करती हैं। तहसील/उप–तहसील भू–राजस्व एकत्रित करने का कार्य करती हैं। सार्वजनिक संस्थानों की दृष्टि से दौसा जिले की स्थिति दयनीय हैं।

दौसा जिले में 05 उप–खण्ड़, 05 तहसील, 05 उप–तहसील, 05 पंचायत समितियाँ, 01 नगरपरिषद, 02 नगरपालिका, 225 ग्राम पंचायतें, 1082 राजस्व ग्राम, 01 लोकसभा क्षेत्र हैं। शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ–साथ 15 पुलिस थाने, 15 पुलिस चौकी व 02 बन्दीग्रह मौजूद हैं।

धार्मिक : दौसा जिले में दर्शनीय स्थल आभानेरी, मेहन्दीपुर बालाजी, झाझीरामपुरा, भाँडारेज की बावड़ी, आलूदा का कुबानिया, गेटोलाव बांध के अलावा नीलकण्ठ महादेव का मन्दिर, सोमनाथ का मन्दिर, गुप्तेश्वरजी का मन्दिर, राम मन्दिर, दुर्गामन्दिर, खाटूश्यामजी का मन्दिर, गिरिराजधरण मन्दिर, मोड़ा का बालाजी, फलसा वाले बालाजी का मन्दिर, भोमियाजी का मन्दिर, हनुमानजी के मन्दिर, गुरूद्वारा, जैन मन्दिर, सुन्दरदास स्मारक, मीन भगवान के मन्दिर एवं विभिन्न मस्जिदों का दौसा में होना यहां के निवासियों की धार्मिक प्रवृत्तियों का द्योतक है। इनसे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है।

राजनीतिक स्थिति : दौसा जिला संसदीय क्षेत्र में शामिल है। दौसा विधानसभा सीट सामान्य जाति के लिए व लोकसभा सीट अनुसूचित जन–जाति के लिए सुरक्षित है।

1.6 सर्वेक्षण का कार्य–क्षेत्र :

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण के कार्य–क्षेत्र हेतु दौसा जिले के परिवारों को अध्ययन के लिए चुना। जन्म से ही दौसा जिले से सम्बन्धित होने के कारण मेरी रूचि दौसा जिले के विभिन्न आय वर्ग वाले परिवारों की आय, उपभोग एवं बचत से सम्बन्धित प्रवृत्तियों के अध्ययन में थी।

दौसा जिले के विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिए परिवारों का चयन मुख्यतया अध्ययन के उद्देश्य, समयावधि एवं वित्त पर निर्भर करता है। सर्वेक्षण के उद्देशानुसार विभिन्न आय वर्ग वाले परिवार के मुखियाओं को निदर्श इकाई का रूप दिया। अतः प्रस्तुत सर्वेक्षण में अपनी निदर्श इकाई में उन परिवारों को शामिल किया है, जो विगत 10 वर्षों से दौसा जिले में अपना जीवनयापन सरकारी नौकरी, निजी संस्था में सेवारत या निजी व्यवसाय कर रहे है। प्रस्तुत अध्ययन में समाज को आय की दृष्टि से चार भागों में विभक्त किया है जिनको निम्न प्रकार व्यक्त किया हैं [53] :

(1) उच्च आय वर्गः 10,00000 रू (80,000 रू मासिक से अधिक) प्रतिवर्ष से अधिक।

(2) मध्यम आय वर्गः 2,00000 रू – 10,00000 रू (16000 रू–80000 रू मासिक) प्रतिवर्ष।

(3) निम्न मध्यम आय वर्गः 90,000 रू – 2,00000 रू (7500 रू–16000 रू मासिक) प्रतिवर्ष।

(4) निम्न आय वर्गः 90,000 रू (7500रू मासिक से कम) प्रतिवर्ष से कम।

1.7 अध्ययन–विधि :

प्रस्तुत अध्ययन में मुख्यतः दो प्रकार के समंकों का प्रयोग किया गया हैं [26]।

(1) प्राथमिक समंक : जिनको सर्वेक्षणकर्त्ता ने स्वयं कार्यक्षेत्र में जाकर एकत्रित किया है।

(2) द्वितीयक समंक : जो सम्बन्धित विषय के अध्ययन से पूर्व ही किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा एकत्र किये जाते हैं, जिनका प्रयोजन या तो समंक संकलन होता है ताकि विभिन्न समस्याओं के विश्लेषण हेतु वे आवश्यकतानुसार कार्य में आ सके अथवा किसी समस्या के विश्लेषण हेतु एकत्र किये जाते हैं।

समंक आधार : प्रस्तुत अध्ययन में मुख्यतया दो प्रकार के समंकों का एकत्रीकरण सर्वेक्षक द्वारा किया गया है।

प्रथम : जिले में जनसंख्या से सम्बन्धित सदस्य संख्या जिला सांख्यिकी रूपरेखा 2011, नगरपालिका दौसा – प्रस्तावित ड्राफ्ट प्लान 2007–12, जिला एक दृष्टि में 2012, के आधार पर प्रतिदर्श चयन किया गया है।

द्वितीय : प्राथमिक समंक जो सर्वेक्षण के मूल आधार हैं, का संकलन सर्वेक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक चयनित निदर्श इकाई से सम्पर्क स्थापित करके किया गया हैं।

प्राथमिक समंक : प्रस्तावित शोध राजस्थान के दौसा जिले से सम्बन्धित है। दौसा जिले की पिछड़ी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखकर इस जिले का उद्देश्यानुसार अध्ययन हेतु चयन किया है। अध्ययन में चयनित ग्रामों के चयनित परिवारों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार द्वारा समंक एकत्रित किये गए हैं। इस तरह प्रस्तावित अध्ययन प्राथमिक समंकों पर आधारित हैं।

निदर्श संरचना : दौसा जिले में 5 पंचायत समितियाँ तथा 1,083 ग्राम पंचायत हैं।

द्वि–स्तरीय प्रतिचयन रीति का प्रयोग करते हुए प्रत्येक पंचायत समिति में से एक ग्राम पंचायत का चयन सरल यादृच्छित प्रतिचयन रीति से किया गया। द्वितीय स्तर पर चयनित ग्राम में से स्तरित प्रतिचयन रीति का प्रयोग करके परिवारों का चयन किया गया है। स्तरण का आधार सामाजिक–आर्थिक वर्ग हैं तथा आनुपातिक प्रतिदर्श चयन विधि काम में ली गई है।

वर्ष 2011 में जनगणना विभाग द्वारा संकलित एवं प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार दौसा जिले में कुल परिवारों की संख्या 2,92,294 है। सारणी 1.6 में दौसा जिले में निवास कर रहे विभिन्न आय–वर्गों वाले परिवारों का आय वर्गों के अनुसार पारिवारिक वितरण दौसा नगरपरिषद् द्वारा निम्न प्रकार दिया गया है।

स्तरित दैव निदर्शन विधि : निदर्श इकाईयों के चयन हेतु प्रस्तुत सर्वेक्षण में स्तरित दैव निदर्शन विधि की सहायता ली गयी है, जिसके अनुसार कुल समग्र परिवारों को विभिन्न स्तरों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि स्तर के अन्तर्गत निहित विभिन्न इकाईयों में जहां तक सम्भव हो सके समान हो तथा विभिन्न स्तरों की इकाईयों में पर्याप्त विषमता हो। स्तरों के निर्धारण के पश्चात् प्रत्येक स्तर में से आनुपातिक आवंटन की सहायता से निदर्श इकाईयों का चयन किया गया है।

सारणी 1.6 : दौसा जिले में विभिन्न आय–वर्गों वाले परिवारों का आय–वर्गों के अनुसार पारिवारिक वितरण।

जिला दौसा	कुल परिवार	उच्च आय वाले परिवार 80000 रू मासिक से अधिक	मध्यम आय वाले परिवार 16000 रू – 80000 रू मासिक	निम्न–मध्यम आय वाले परिवार 7500 रू – 16000 रू मासिक	निम्न आय वाले परिवार 7500 रू मासिक से कम
कुल परिवार	292294 N	32737 N1	54951 N2	87688 N3	116918 N4
प्रतिशत परिवार	100 n	11.2 n_1	18.8 n_2	30 n_3	40 n_4

प्रस्तुत अध्ययन में विभिन्न परिवारों की आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों में जहां एक ओर काफी समानता पाई गयी है, वहीं काफी विषमता भी दिखाई देती है। निम्न वर्ग के परिवारों की आय, उपभोग एवं बचत प्रवृत्तियाँ सम्बन्धित वर्ग की विभिन्न इकाईयों में काफी समानता पाई जाती है। जबकि यदि हम विभिन्न आय वर्गों की पारिवारिक इकाईयों की तुलना करें तो इकाईयों में परस्पर काफी विषमता दृष्टिगोचर होती है। आनुपातिक आवंटन की सहायता से विभिन्न आय–वर्गों मे से निम्न सूत्र की सहायता से निदर्शों का चुनाव किया गया है [54]।

$$ni = \frac{n\,Ni}{N}$$

N = समग्र परिवार (कुल परिवार)

Ni = i वें स्तर के आय वर्ग

ni = i वें स्तर के चयनित निदर्श

n = प्रतिनिधि परिवार

(1) उच्च आय वर्ग के लिए निदर्श का चयन :

$$n_1 = \frac{n \times N_1}{N}$$

$$= \frac{500 \times 32737}{292294}$$

$$= 56.00 \; = 56$$

(2) मध्यम आय वर्ग के लिए निदर्श का चयन :

$$n_2 = \frac{n \times N_2}{N}$$

$$= \frac{500 \times 54951}{292294}$$

$$= 93.99 \; = 94$$

(3) निम्न मध्यम आय वर्ग के लिए निदर्श का चयन :

$$n_3 = \frac{n \times N_3}{N}$$

$$= \frac{500 \times 87688}{292294}$$

$$= 149.99 \ = 150$$

(4) निम्न आय वर्ग के लिए चयनित निदर्श

$$n_4 = \frac{n \times N_4}{N}$$

$$= \frac{500 \times 116918}{292294}$$

$$= 200.00 \ = 200$$

स्तरित दैव प्रतिचयन विधि की प्रक्रिया :

$$N \text{ (समग्र)} = N_1 + N_2 + N_3 + N_4$$

$$292294 = 32737 + 54951 + 87688 + 116918$$

$$n \text{ (प्रतिदर्श)} = n_1 + n_2 + n_3 + n_4$$

$$500 = 56 + 94 + 150 + 200$$

सारणी 1.7 में दौसा जिले में विभिन्न आय वर्गों वाले चयनित परिवारों की संख्या दर्शायी गई है।

प्रश्नावली निर्माण एवं समंक संकलन का कार्य : पारिवारिक इकाईयों से सम्बन्धित प्राथमिक समंकों की उपलब्धता के पश्चात् स्तरित दैव निदर्शन विधि द्वारा निर्धारित एवं चयनित इकाईयों के सर्वेक्षण से सम्बन्धित समंकों के संकलन हेतु प्रश्नावली का निर्माण किया गया। जिसमें प्रत्येक परिवार के मुखिया से उद्देश्यानुसार तैयार प्रश्नावली प्रत्यक्ष साक्षात्कार से भरी गई हैं।

सारणी 1.7 : दौसा जिले में विभिन्न आय–वर्गो वाले चयनित परिवार।

जिला दौसा	उच्च आय वर्ग 10,00000 रू प्रतिवर्ष से अधिक (80000 रू मासिक से अधिक)	मध्यम आय वर्ग 2,00,000रू से 10,00000 रू प्रतिवर्ष (16000 रू–80000 रू मासिक)	निम्न–मध्यम आय वर्ग 90,000रू से 2,00,000रू प्रतिवर्ष (7500 रू–16000 रू मासिक)	निम्न आय वर्ग 90,000 रू प्रतिवर्ष से कम (7500 रू मासिक से कम)	कुल परिवार
आय वर्गानुसार परिवार	32737 N1	54951 N2	87688 N3	116918 N4	292294
चयनित परिवार	56	94	150	200	500
प्रतिशत	11.2	18.8	30	40	100

1.8 शोध तकनीक :

समंकों के वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण एवं निर्वचन में सांख्यिकीय व अर्थमितीय विधियों का प्रयोग किया है। औसत, मानक–विचलन, विचरण–गुणांक, सामूहिक–माध्य, उपभोग–सूचकांक, औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति, बचत सूचकांक, औसत बचत प्रवृत्ति, सीमान्त बचत प्रवृत्ति, प्रतीपगमन विश्लेषण एवं रेखाचित्र (आय, उपभोग एवं बचत) MS-EXCEL 2007 की सहायता से बनाये गये हैं

परिणामों के सभी सांख्यिकी जांच एवं मूल्यांकन, जो इस अनुभाग में उल्लेखित हैं, का अगले अध्यायों में प्रदर्शन एवं वर्णन किया गया है।

(1) औसत (आय, उपभोग एवं बचत) : किसी समंकमाला का औसत या समान्तर माध्य वह मूल्य है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है।

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

$\bar{X}$ = औसत या समान्तर माध्य

ΣX = मूल्यों के योग

N = पदों की संख्या

(2) मानक विचलन : किसी श्रेणी के समान्तर माध्य से निकाले गए उसके विभिन्न पद–मूल्यों के विचलनों के वर्गो के माध्य का वर्गमूल उस श्रेणी का मानक विचलन होता है।

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{\Sigma(X - \bar{X})^2}{N}\right)}$$

σ = मानक विचलन

X व $\bar{X}$ = व्यक्तिगत मूल्य व समान्तर माध्य

N = पदों की संख्या

(3) विचरण गुणांक : दो या दो से अधिक श्रेणियों में विचरण की तुलना करने के लिए विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। विचरण गुणांक वस्तुतः प्रमाप विचलन गुणांक का प्रतिशत रुप है अर्थात् प्रमाप विचलन को समान्तर माध्य से भाग देकर भजनफल में 100 की गुणा करने से प्राप्त प्रतिशत ही विचरण गुणांक होता है।

$$\boldsymbol{Coefficient\ of\ Variation = \frac{\sigma}{\bar{X}} \times 100}$$

σ = मानक विचलन

$\bar{X}$ = समान्तर माध्य

(4) सामूहिक माध्य : यदि एक समूह के दो या अधिक भागों के समान्तर माध्य तथा उनके पदों की संख्या ज्ञात है तो उनके आधार पर सामूहिक समान्तर माध्य ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात्

$$\boldsymbol{X_{1.2.3.....n} = \frac{\bar{X}_1\ N_1 + \bar{X}_2\ N_2 + \bar{X}_3\ N_3 + \ldots \bar{X}_n\ N_n}{N_1 + N_2 + N_3 + \ldots N_n}}$$

$\bar{X}$ = औसत या समान्तर माध्य

N = पदों की संख्या

(5) आय सूचकांक : आय सूचकांक को प्रचलित वर्ष के विभिन्न मदों में आय के जोड़ को आधार वर्ष के आय के जोड़ से भाग देकर 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है।

आय सूचकांक = सम्बन्धित वर्ग की चालू वर्ष में कुल आय/ सम्बन्धित वर्ग की आधार वर्ष में कुल आय X 100

(6) उपभोग सूचकांक : उपभोग सूचकांक को प्रचलित वर्ष के विभिन्न मदों में उपभोग व्यय के जोड़ को आधार वर्ष के उपभोग व्यय के जोड़ से भाग देकर 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है।

उपभोग सूचकांक = सम्बन्धित वर्ग की चालू वर्ष में कुल उपभोग/ सम्बन्धित वर्ग की आधार वर्ष में कुल उपभोग X 100

(7) औसत उपभोग प्रवृत्ति : औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) कुल आय एवं कुल उपभोग व्यय का अनुपात बताती है तथा यह कुल उपभोग व्यय (C) एवं कुल आय (Y) के अनुपात के रूप में मापी जाती है। अर्थात्

औसत उपभोग प्रवृत्ति = कुल उपभोग व्यय/ कुल आय

$$APC = \frac{c}{y}$$

(8) सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति : सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) कुल आय में परिवर्तन (ΔC) एवं कुल उपभोग व्यय में परिवर्तन (ΔY) का अनुपात दर्शाती है। यह कुल आय में परिवर्तन से उत्पन्न कुल उपभोग व्यय में परिवर्तन का सम्बन्ध बताती है। अर्थात्

सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति = उपभोग में परिवर्तन/आय में परिवर्तन

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

(9) बचत सूचकांक : बचत सूचकांक को प्रचलित वर्ष के विभिन्न मदों में बचत के जोड़ को आधार वर्ष के बचत के जोड़ से भाग देकर 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है।

बचत सूचकांक = सम्बन्धित वर्ग की चालू वर्ष में कुल बचत/ सम्बन्धित वर्ग की आधार वर्ष में कुल बचत X 100

(10) औसत बचत प्रवृत्ति : औसत बचत प्रवृत्ति (APS) कुल आय एवं कुल बचत का अनुपात बताती है तथा यह कुल बचत (S) एवं कुल आय (Y) के अनुपात के रूप में मापी जाती है। अर्थात्

औसत बचत प्रवृत्ति = कुल बचत / कुल आय

$$APS = \frac{S}{y}$$

(11) सीमान्त बचत प्रवृत्ति : सीमान्त बचत प्रवृत्ति (MPS) कुल आय में परिवर्तन (ΔS) एवं कुल बचत में परिवर्तन (ΔY) का अनुपात दर्शाती है। यह कुल आय में होने वाले परिवर्तन तथा इस परिवर्तन के फलस्वरूप कुल बचत में हुए परिवर्तन का अनुपात होती है। अर्थात्

सीमान्त बचत प्रवृत्ति = बचत में परिवर्तन/आय में परिवर्तन

$$MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

(12) प्रतीपगमन समीकरण : दो चर–मूल्यों X और Y के बीच रेखीय प्रतीपगमन का अध्ययन सरल रेखीय प्रतीपगमन कहलाता है। दोनों चरों में से उस चर को स्वतन्त्र माना जाता है, जो ज्ञात होता है एवं दूसरे चर के अनुमान का आधार होता है और वह चर आश्रित कहलाता है, जिसके मूल्य का अनुमान लगाना होता है। प्रतीपगमन की विधि का प्रयोग दो से अधिक चरों के पारस्परिक सम्बन्ध का विश्लेषण करने में भी किया जा सकता है।

(i) उपभोग प्रतीपगमन समीकरण :

$$\mathbf{c = a + by}$$

c = उपभोग

a = स्वायत्त उपभोग

b = MPC

y = आय

इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया है :

$$c - \bar{c} = bcy(y - \bar{y})$$

यहां $\frac{a}{c}$ = सम्बन्धित आय वर्ग का औसत मासिक उपभोग

$$bcy = MPC = \frac{\Delta c}{\Delta y}$$

$\bar{y}$ = सम्बन्धित आय वर्ग की औसत मासिक आय

(ii) बचत प्रतीपगमन समीकरण :

$$\mathbf{s = a + by}$$

S = बचत

a = स्वायत्त बचत

b = MPS

y = आय

इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया है :

$$(s-\bar{s})=bsy(y-\overline{y})$$

यहां $\frac{a}{s}=$ सम्बन्धित आय वर्ग का औसत मासिक बचत

$$bsy=MPS=\frac{\Delta s}{\Delta y}$$

$\overline{y}=$ सम्बन्धित आय वर्ग की औसत मासिक आय

(13) सार्थकता परीक्षण :

प्रतिचयन के अन्तर्गत प्राचल के अनुमान की परिशुद्धत्ता के लिए प्रमाप त्रुटि की गणना कर परिकल्पनाओं की जांच की गई है:

$$Z=\frac{t-E(t)}{\sqrt{V(t)}}\sim N(0,1)$$

$$Z=\frac{t-E(t)}{S.E.(t)}\sim N(0,1)$$

परिकलित अनुमानित मानों में अन्तर 1.96 S.E. से अधिक रहा हो वहां 5.00 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर परिकल्पना को अस्वीकार किया गया है।

आनुपातिक स्तरित प्रतिचयन रीति अपनाये जाने से माध्य के प्रसरण का अनुमान निम्न सूत्र के प्रयोग से किया गया हैं।

$$Var(\bar{Y}_{st})prop=\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{N}\right)\sum_{i=1}^{k}p_i S_i^2 \text{ यहां } \frac{N_i}{N^2}=p_i \text{ है}$$

1.9 शोध की सीमाएँ :

1) दौसा जिले के विभिन्न आय–वर्गों वाले परिवारों में आय, उपभोग एवं बचत से सम्बन्धित एकत्रित किये गये समंकों की विश्वसनीयता उत्तरदाताओं की स्मृति पर निर्भर करती है। यदि वे सर्वेक्षण के दौरान प्रश्नों के उत्तर देने में त्रुटि करते हैं तो एकत्रित किये गये समंकों के आधार पर परिणाम प्रभावित हो सकता है।

2) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग मौसमी कृषि पर निर्भर रहते हैं। अतः उनकी आय अस्थिर रहती है। जिस कारण उनसे आय एवं बचत की जानकारी एक निश्चित समयावधि के लिए नहीं मिल पाती है।

3) ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले परिवारों से आय, उपभोग एवं बचत से सम्बन्धित जानकारी सही नहीं मिल पाती, क्योंकि उनकी आय के स्त्रोत कृषि, गैर–कृषि व्यापार, मजदूरी, वेतन, किराया, ब्याज और विभिन्न व्यवसाय हैं, जिनका ये परिवार सही लेखा–जोखा नहीं रखते हैं।

4) ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार घर पर ही उत्पादित वस्तुएँ जैसे– अनाज, सब्जी एवं फल का इस्तेमाल करते हैं तथा इसके अलावा पशुपालन करते हैं जिससे उन्हें दूध, दही एवं घी प्राप्त होता है, जिसके कारण उन वस्तुओं का मूल्य उपभोग व्यय में शामिल नहीं करते हैं।

5) कुछ परिवार मादक पदार्थो पर उपभोग व्यय भी करते हैं लेकिन उस उपभोग व्यय की सही जानकारी नहीं देते हैं।

6) इसके अतिरिक्त कुछ परिवारों के सदस्य राज्य के बाहर काम करते हैं, जिसके कारण उन परिवारों में उस सदस्य से प्राप्त आय की सही जानकारी प्राप्त करने में मुश्किल होती है।

1.10 संदर्भ सूची (References) :

1. ICMR (ICFAI Center for Management Research), **(2006)**. Economics for Managers, ***Icfai Press***.
2. Chakrabarti, S. and Kundu, A. **(2009)**. Rural Non-Farm Economy: A Note on the Impact of Crop-Diversification and Land-Conversion in India. ***Economic and Political weekly***, XLIV (12): 69-75.
3. Chetan, B., Tuli, R. and Srivastava, N. **(2008)**. Retail Management. ***Oxford University Press Ninth Impression***.
4. Wilhite, H. **(2008)**. Consumption and the Transformation of Everyday Life: A View from South India. ***New York: Palgrave Macmillan***.
5. Williams, F. M. and Zimmerman, C. C. **(1935)**. Studies of Family Living in the United States and Other Countries. U. S. Department of Agriculture. ***Miscellaneous Publication 223, Washington, D.C.***, 95-113.
6. Keynes, J. M. **(1936)**. The General Theory of Employment, Interest and Money. ***Harcourt, Brace and Company and Printed in the U.S.A. by the Polygraphic Company of America, New York***, 96-97.

7. Haberler, W. **(1955)**. The Relation of Consumption to Wealth and the Wage Rate. ***Unpublished Ph.D. Thesis at the University of Chieqgo***, 1-17.
8. Pigou, A. C. **(1943)**. The Classical Stationary State. ***Economic Journal***, 53 (212): 343-351.
9. Brady, D. S. and Friedman, R. D. **(1947)**. Savings and the Income Distribution. ***X, New York: National Bureau of Economic Research***, 247-265.
10. Duesenberry, J. S. **(1949)**. Income, Saving and the Theory of Consumer Behaviour. ***Cambridge, Mass.: Harvard University Press***, 54-81.
11. Modigliani, F. **(1949)**. Fluctuations in the Saving – Income Ratio: A Problem in Economic Forecasting. ***New York: National Bureau of Economic Research***, 371-144.
12. Ando, A. and Modigliani, F. **(1963)**. The Life Cycle Hypothesis of Saving: Aggregated Implications and Tests. ***American Economic Review***, 53: 55-84.
13. Modigliani, F. and Brumberg, R. **(1954)**. Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross Section Data. ***In Post Keynesian Economics, New Brunswick: Rutgers University Press***, 383-436.
14. Ackley, G. and Suits, D. B. **(1950)**. Relative Price Changes and Aggregate Consumer Demand. ***American Economic Review***, XL (40): 785-804.
15. Tobin, J. **(1951)**. Relative Income, Absolute Income and Savings in Money, Trade and Economic Growth. ***John Henry Williams, New York: Macmillan Co.***, 135-156.
16. Klein, L. R. **(1950)**. Econoinic Fluctuations in the United States, 1921-1941. ***New York, Wiley***, 174.
17. Kuznets, S. **(1952)**. Proportion of Capital Formation to National Product. ***The American Economic Review***, 42 (2): 507-526.
18. Hamburger, W. **(1955)**. The Relation of Consumption to Wealth and the Wage Rate. ***Econometrica***, XXIII: 1-17.

19. Hall, R. E. and Mishkin, F. S. **(1982)**. The Sensitivity of Consumption to Transitory Income: Evidence from PSID Households. ***Econometrica***, 50 (2): 461-481.
20. Evans, M. K. **(1969)**. Macroeconomic Activity, Theory, Forecasting and Control. ***Harper & Row, New York***, 34.
21. Vakil, F. **(1973)**. The Propensity to Consume Permanent Income in India. ***University of California, Los Angeles***.
22. Hall, R. E. **(1978)**. Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theroy and Evidence. ***Journal of Political Economy***, 86 (6): 971-987.
23. Campbell, J. and Deaton, A. **(1989)**. Why is Consumption So Smooth? ***Review of Economic Studies***, 56: 357–373.
24. Campbell, J. Y. and Mankiw, N. G. **(1991)**. The Response of Consumption to Income: A Cross-Country Investigation. ***European Economic Review***, 35, 723-734.
25. Dhakal, D. and Sharma, S. C. **(2006)**. Causal Analysis between Exports and Economic Growth in Developing Countries. ***Applied Economics***, 38 (10): 1145-1157.
26. Gupta, S. C. and Kapoor, V. K. **(2002)**. Fundamentals of Mathematical Statistics. ***Sultan Chand & Sons Pvt. Ltd. New Delhi***.
27. Palley, I. T. **(2002)**. Economic Contradictions Coming Home to Roost? Does the U. S. Economy Face A Long-Term Aggregate Demand Generation Problem? ***Journal of Post Keynesian Economics***, 25 (1): 9-32.
28. Byrne, J. P. and Davis, P. E. **(2003)**. Disaggregate Wealth and Aggregate Consumption: An Investigation of Empirical Relationships for the G7. ***Oxford Bulletin of Economics and Statistics***, 65 (2): 197-220.
29. Mei, Y. **(2012)**. U.S. Consumption Function: An Empirical Test of the Life-Cycle Hypothesis. ***Senior Thesis, Trinity College Digital Repository, Trinity College Library, Hartford, CT***, 153.
30. Mellor, J. W. **(1976)**. The New Economics of Growth: A Strategy for India and the Developing World. ***Ithaca, New York: Cornell University Press***, 8-9.

31. Ajmair, M. and Akhtar, N. **(2012)**. Household Consumption in Pakistan (A Case Study of District Bhimber, AJK). ***European Journal of Scientific Research***, 75 (3): 448-457.
32. Rani, P. **(2014)**. Factors Influencing Consumer Behavior. ***International Journal Current Research Academia Review***, 2 (9): 52-61.
33. Goldsmith, R. W. **(1955)**. A Study of Saving in the United States. ***Princeton University Press, Princeton, New Jersey***, 1 & 2.
34. Salam, M. A. and Kulsum, U. **(2002)**. Savings Behaviour in India: An Empirical Study. ***Department of Economic's, AMU, Aligarh***, 78-80.
35. Agrawal, P., Sahoo, P. and Dash, R. **(2008)**. Savings Behaviour in South Asia. ***Working Paper Series No. E/289/2008***.
36. Burney, N. and Khan, A. H. **(1992)**. Socio-Economic Characteristics and Household Savings. An Analysis of Household Saving Behaviour in Pakistan. ***The Pakistan Development Review***, 31 (1): 31-48.
37. Gedela, S. P. **(2012)**. Determinants of Saving Behaviour in Rural and Tribal Households: An Empirical Analysis of Visakhapatnam District. ***International Journal of Research in Social Sciences***, 2 (8): 108-128.
38. Carpenter, S. B. and Jensen, R. T. **(2002)**. Household Participation in Formal and Informal Savings Mechanisms: Evidence from Pakistan. ***Review of Development Economics***, 6 (3): 314-328.
39. Kulikov, D., Paabut, A. and Staehr, K. **(2007)**. A Microeconometric Analysis of Household Saving in Estonia: Income, Wealth and Financial Exposure. ***Working Paper n° 8, Estonian National Bank***.
40. Losayza, N., Schmidt-Hebbel, K. and Servén, L. **(2000)**. What Drives Private Saving Across the World? ***The Review of Economics and Statistics***, 82 (2): 165-181.
41. Attanasio, O. and Banks, J. **(2001)**. The Assessment: Household Saving – Issues in Theory and Policy. ***Oxford Review of Economic Policy***, 17 (1).
42. Deaton, A. and Paxson, C. H. **(2000)**. Saving and Growth among Individuals and Households. ***Review of Economics and Statistics***, 82 (2): 212-225.

43. Bandiera, O., Gerard, C., Patrick, H. and Fabio, S. **(2000)**. Does Financial Reform Raise or Reduce Private Savings? ***Review of Economics and Statistics,*** 82 (2): 239-63.
44. Samwick, A. **(2000)**. Is Pension Reform Conducive to Higher Saving? ***Review of Economics and Statistics***, 82 (2): 264-72.
45. Berley, T. and Meghir, C. **(1998)**. Do Tax Incentives Rise Private Saving? ***World Bank, Washington, D.C. Processed***.
46. Lopez, H., Schmidt-Hebbel, K. and Luis, S. **(2000)**. How Effective is Fiscal Policy in Raising National Saving? ***Review of Economics and Statistics***, 82 (2): 226–38.
47. Ramesh, M. **(2006)**. Causal Relationship between Savings and Economic Growth in Countries with Different Income Levels. ***Economics Bulletin***, 5 (3): 1-12.
48. Cilasum, S. M. **(2009)**. Income, Consumption and Saving Behaviour of Turkish Households. ***A Thesis Submitted to the Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University***, 24 (296), 9-46.
49. Chowa, G. A., Masa, R. D. and Sherraden, M. **(2012)**. Wealth Effects of an Asset-Building Intervention among Rural Households in Sub-Saharan Africa. ***Journal of the Society for Social Work and Research***, 3: 329-345.
50. Lawrence, K. K., Benjamin, K. M., Desterio, E. O., Shem, A. O. and George, O. **(2009)**. Determinants of Household Saving: Case Study of Smallholder Farmers, Entrepreneurs and Teachers in Rural Areas of Kenya. ***Journal of Development and Agricultural Economics***, 1 (7): 137-143.
51. Brumberg, R. and Modigliani, F. **(1954)**. Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data. In Kenneth K. Kurihara (Eds.), Post-Keynesian Economics. ***New Brunswick, NJ: Rutgers University Press***, 388-436.
52. Abid, S. and Afridi, G. S. **(2010)**. Assessing the Household Saving Pattern of Urban and Rural Households in District Muzaffarabad. ***Pakistan Journal of Life Social Science***, 8 (2): 137-141.

53. Dutt, R. and Sundram, K. P. M. **(2006)**. Indian Economy. ***Chand & Company, New Delhi***, 365-366.

54. Singh, D. and Chaudhary, F. S. **(1995)**. Theory and Analysis of Sample Survey Designs. ***New Age International Publishers, New Delhi***, 55.

*****

अध्याय – 2

आय, उपभोग एवं बचत : सैद्धान्तिक विवेचन

आय, उपभोग एवं बचत : सैद्धान्तिक विवेचन

सामान्यतया समग्र उपभोग (समग्र बचत) तथा समग्र आय के बीच सम्बन्ध को उपभोग फलन कहा जाता है। यह फलन कीन्स की पुस्तक ''आय व रोजगार का सामान्य सिद्धान्त'' में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कीन्स के अनुसार समग्र उपभोग की मात्रा मुख्यतया समग्र आय की मात्रा पर निर्भर करती है। उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार वास्तविक आय जिस अनुपात में बढ़ती है, उपभोग उससे कम अनुपात में बढ़ता है अर्थात् वास्तविक आय के बढ़ने के साथ उपभोग की तुलना में बचत का अनुपात अधिक बढ़ता है [1]।

सैद्धान्तिक सोच ने अनुभवसिद्ध कार्य को प्रेरित किया है। गणितीय उपभोग फलन दो प्रकार के आँकड़ो से अनुमानित किये गये : (1) प्रथम विश्व युद्ध के बाद समय बद्ध श्रृंखला से प्राप्त आय, उपभोग, बचत, कीमत एवं समरूप चरों से सम्बन्धित आँकड़े [2]। (2) पिछली डेढ़ शताब्दी के दौरान व्यक्तियों एवं परिवारों के सर्वेक्षण नमूने से प्राप्त आय, उपभोग, एवं बचत के आँकड़े [3]। शुरूआत में उक्त स्त्रोतों से प्राप्त आँकड़े कीन्स की परिकल्पना की पुष्टि करते हुए प्रतीत होते हैं। तात्कालिक उपभोग आय के साथ उच्च रूप से सह–सम्बन्धित था। उपभोग की सीमान्त प्रवृति (MPC) इकाई से कम थी तथा उपभोग की सीमान्त प्रवृति (MPC) उपभोग की औसत प्रवृति (APC) से कम थी अर्थात् APC > MPC। अतः आय के बढ़ने से बचत आय का प्रतिशत भी बढ़ता था। लेकिन उसके बाद साक्ष्यों का एक गम्भीर विरोधाभास उत्पन्न हुआ। 1899 के बाद कुजनेट्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बचत का अनुमान लगाने पर पाया कि आय में भारी वृद्धि होने के बावजूद पिछली आधी सदी के दौरान बचत आय के प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुई। बचत आय का प्रतिशत पूरी समयावधि में समान था [4]।

ब्राडी व फ्रीडमैन ने सुझाव दिया कि एक उपभोक्ता इकाई का उपभोग उसकी निरपेक्ष आय पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि समाज में उपभोक्ता इकाईयों में आय के वितरण की स्थिति पर निर्भर करता है। उन्होंने सापेक्ष आय परिकल्पना के समर्थन में मुख्य रूप से आय–व्यय आँकड़ों से प्राप्त साक्ष्य प्रस्तुत किये [5]। ड्यूजनबरी ने इस समान परिकल्पना को एक सैद्धान्तिक ढ़ाँचे पर आधारित किया जो इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति उपभोग के सम्बन्ध में अपनी आय के साथ–साथ आस–पास रहने वाले पड़ौसियों के उपभोग व्यय से भी प्रभावित होता है। इन्होंने सापेक्ष आय परिकल्पना का समर्थन किया तथा सुझाव दिया कि सापेक्ष आय परिकल्पना का उपयोग आँकड़ों को समझने में किया जा

सकता है [6]। ड्यूजनबरी ने 1929–41 के बीच संयुक्त राज्य के लिये एक प्रतीपगमन का परिकलन करके समुचित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त किये। स्वयं मोदिग्लियानी ने भी मुख्य रूप से समग्र आँकड़ों के विश्लेषण के लिए समान सुझाव दिये तथा इसे विस्तृत सांख्यिकीय परीक्षण में प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि यह उत्तम परिणाम देता है [7]।

टॉबिन ने सापेक्ष आय परिकल्पना तथा पहले की निरपेक्ष आय परिकल्पना के सामंजस्य का परीक्षण अनुभव जन्य साक्ष्यों के सीमित ढ़ाँचे के आधार पर किया। यद्यपि उसने किसी भी परिकल्पना को पूर्णतया सन्तोषप्रद नहीं माना तथा यह निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश साक्ष्य निरपेक्ष आय परिकल्पना को अनुमोदित करते हैं [8]।

विलियम हैमबर्गर के द्वारा किये गये अनुभव जन्य अध्ययन में पाया कि धन का आय के साथ अनुपात व उपभोग का आय के साथ अनुपात में निकटतम सम्बन्ध होता है [9]। अन्य अध्ययनों, मुख्यतः जो "केलेन" द्वारा किये गये शोध कार्य में तरल सम्पत्ति की भूमिका को जांचने के लिए आय–व्यय आँकड़ों का प्रयोग किया गया है [10]।

पिछले कुछ दशकों में उपभोग फलन पर हुए कार्यों का संक्षिप्त वर्णन इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करने में सहायता प्रदान करते है। उपभोक्ता व्यवहार से प्राप्त विस्तृत अनुभव जन्य साक्ष्य जो सम्पत्ति से सम्बन्धित है, जिन्हें इस अवधि के दौरान प्रारम्भिक तथ्यों से जोड़ा गया है या विश्लेषणात्मक अध्ययनों की असाधारण संख्या व प्रकार जो इन साक्ष्यों से प्राप्त हुए है, पूर्णरूपेण से प्रकट नहीं करते है।

उक्त उपभोक्ता व्यवहार, उपभोग व्यय एवं आय के मध्य व्यक्त किये गये सम्बन्ध को समझाने के लिए एक और परिकल्पना प्रस्तुत करता है। प्रमाणित है कि नई परिकल्पना सम्भवतः अधिक लाभकारी प्रतीत होती है और कुछ मात्रा (कुछ मापदण्ड़ों में) में सापेक्ष आय परिकल्पना या सम्पत्ति आय परिकल्पना से अधिक व्यापक है। यह सम्पत्ति आय प्रभाव को पूर्णरूप से समाविष्ट करता है तथा बताता है कि सापेक्ष आय परिकल्पना को विशेष परिस्थितियों में क्यों मान्य किया जाना चाहिए। यह परिकल्पना वर्तमान में स्वीकृत उपभोक्ता व्यवहार सिद्धान्त से सीधे परिणाम निकालती है और प्रचलित अनुभव जन्य साक्ष्यों के अनुरूप ही प्रतीत होती है तथा निरीक्षण योग्य समस्या रखती है जो अतिरिक्त साक्ष्यों द्वारा खण्डित होने में सक्षम होती हैं। इसका आधारभूत तथ्य उपभोग व आय के मध्य सम्बन्ध को जोड़ना है तथा सैद्धान्तिक परिकल्पनाओं द्वारा प्रस्तावित आय जो आय के आँकड़ों द्वारा व्यक्त की जाती है जिनका उपभोग सापेक्ष आय स्तर में परिवर्तन के विश्लेषण के लिए किया गया हैं [11]। आय के आँकड़ों की व्याख्या करने का तरीका उपभोग आँकड़ों तक विस्तारित किया जा सकता है और इस प्रक्रिया में सापेक्ष आय स्तर में

परिवर्तन की समस्या को उपभोग व्यय के निर्धारकों की समस्या के साथ घनिष्ठता से सम्बन्धित किया जा सकता हैं। इस प्रकार यह परिकल्पना आय के वितरण से सम्बन्धित सांख्यिकीय प्रमाणों की व्यापक सीमा को उपभोक्ता व्यवहार की व्याख्या करने में सक्षम बनाती हैं [12]।

प्रस्तुत अध्याय में आय, उपभोग एवं बचत का अर्थ, प्रतिष्ठित दृष्टिकोण, प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचना, कीन्सियन दृष्टिकोण (उपभोग फलन, अल्पकालीन उपभोग फलन, दीर्घकालीन उपभोग फलन, बचत फलन), उपभोग फलन की तकनीकी विशेषताएँ तथा आय, उपभोग एवं बचत में आनुभाविक तथ्य (निरपेक्ष आय परिकल्पना, सापेक्ष आय परिकल्पना, स्थायी आय परिकल्पना एवं जीवन स्तर में उपभोग का नियम– एंजिल) का अध्ययन किया गया हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यानुसार आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों का विश्लेषण विभिन्न आय–वर्गों के अनुसार करना आवश्यक है। इन आर्थिक चरों में परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार रही है तथा विभिन्न वर्षों में इन प्रवृत्तियों में निरपेक्ष एवं सापेक्ष रूप से किस तरह के परिवर्तन आये है का समावेश आंशिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन तीन आर्थिक चरों से सम्बन्धित है : 1) आय, 2) उपभोग एवं 3) बचत।

हालांकि विनियोग नामक आर्थिक चर भी अप्रत्यक्ष रूप से तीनों आर्थिक चरों से परस्पर जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रस्तुत अध्ययन में विनियोग नामक आर्थिक चर का समावेश नहीं किया है। सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष तक पहुँचने से पूर्व यह जानकारी करना आवश्यक है कि आय, उपभोग एवं बचत तीनों आर्थिक चरों में परस्पर क्या सम्बन्ध हैं तथा वे स्वयं किस प्रकार प्रभावित होकर अन्य आर्थिक चरों को प्रभावित करते है का अध्ययन करने हेतु उपरोक्त आर्थिक चरों के सिद्धान्तों का अध्ययन करना होता है, जो हमारे एक विशेष क्षेत्र में उपरोक्त आर्थिक चरों में निहित प्रवृत्तियों के अध्ययन एवं उसको समझने के साथ तुलनात्मक व्याख्या करने हेतु आवश्यक है।

आय, उपभोग एवं बचत नामक आर्थिक चरों में पारस्परिक सम्बन्धों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु दो दृष्टिकोण प्रचलित है [1] : (1) प्रतिष्ठित दृष्टिकोण; (2) कीन्सियन दृष्टिकोण।

उक्त दोनों दृष्टिकोणों में निहित अन्तरों को स्पष्ट करने के लिए हमें आय, उपभोग एवं बचत की जानकारी करना आवश्यक है। इन तीनों चरों का व्यष्टिगत एवं समष्टिगत दृष्टिकोण यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

आय : व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर एक निश्चित समय अवधि में किसी व्यक्ति को प्राप्त मौद्रिक प्राप्तियाँ उस व्यक्ति की आय होती है। मौद्रिक प्राप्तियाँ निर्धारित समय अवधि में किसी उत्पादन या गैर–उत्पादक कार्यों में भाग लेने से प्राप्त होती है। वास्तविक जीवन में उत्पादन के साधनों से अर्जित आय वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्राप्त न होकर मौद्रिक आय के रूप में प्राप्त होती है। उत्पादन के साधनों से उनके कार्यों के अनुसार विभिन्न रूपों में आय प्राप्त होती है जैसे– श्रमिक को मजदूरी, भू–स्वामी को लगान, पूँजीपति को ब्याज, प्रबन्धक को वेतन व उद्यमी को उनकी सेवाओं के बदले लाभ।

$$\mathbf{Y = C + S}$$ (यहां Y= आय, C = उपभोग , S= बचत)

समष्टि–दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय किसी निश्चित अवधि में राष्ट्र के सभी उत्पत्ति के साधनों को मिलने वाली शुद्ध मौद्रिक प्राप्तियों का योग होती है, जो उन्हे किसी आर्थिक कार्य में भाग लेने पर प्राप्त होती है। अतः एक निश्चित समय अवधि में उत्पादन के साधनों को प्राप्त प्रतिफलों के योग को साधन लागत पर राष्ट्रीय आय कहते है।

उपभोग : व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर आय का वह भाग जो व्यक्ति वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने में व्यय करता है। इस प्रकार उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है, अर्थात् वस्तु में विद्यमान उपयोगिता के उपयोग को उपभोग कहते हैं।

$$\mathbf{C=Y - S}$$ (यहां C = उपभोग, Y = आय , S = बचत)

समष्टि दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय आय का वह भाग जो अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग्य वस्तुओं को क्रय करने के लिए व्यय किया जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं में टिकाऊ तथा गैर–टिकाऊ वस्तुएँ शामिल होती हैं जिनसे लोगों की आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष सन्तुष्टि होती है।

बचत : व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर आय का वह भाग जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय न करके भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यय किया जाता है जबकि समष्टि दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय आय में से राष्ट्रीय उपभोग पर किये गये व्यय को

घटाने पर राष्ट्रीय बचत प्राप्त होती हैं। इस प्रकार बचत एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त होने वाली आय में से उसी समय अवधि में होने वाले व्यय का अन्तर है।

$$\mathbf{S = Y - C}$$ (यहां Y = आय, C = उपभोग , S = बचत)

2.1 आय, उपभोग एवं बचत : प्रतिष्ठित दृष्टिकोण

प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अर्थशास्त्रियों में डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे.एस. मिल, जे.बी.से, एल्फ्रेड मार्शल तथा आर.एस.पीगू आते हैं। इन अर्थशास्त्रियों के सभी सिद्धान्त पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों को उचित प्रतिफल पर कार्य उपलब्ध रहता है। इनके अनुसार पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य स्थिति है। यदि इन अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी पाई जाती है तो केवल अल्पकाल के लिए ही होती है क्योंकि आर्थिक शक्तियों में इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिनसे बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। बेरोजगारी में मजदूरों की मांग उनकी पूर्ति से कम होने के कारण नकद मजदूरी कम हो जाती है। इससे श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है। श्रमिकों की मांग बढ़ने से पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जाती है। प्रतिष्ठित सिद्धान्त "से" के बाजार नियम तथा मजदूरी ब्याज की दर, स्थिर तकनीक तथा कीमतों की लोचशीलता की मान्यता पर आधारित है। "से" के बाजार नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। उत्पादक जितना भी उत्पादन करेंगे वह पूरा बिक जाता है। उत्पादक को यह आशंका रहती है कि उसका उत्पादन बिकेगा या नहीं। यदि किसी वस्तु की मांग कम होती है तो उसका उत्पादन कम कर दिया जायेगा जिससे बेरोजगारी फैलेगी। फलस्वरूप नकद मजदूरी की दर में कमी होने से श्रमिकों की मांग बढ़कर पूर्ति के बराबर हो जायेगी।

अतः बेरोजगारी समाप्त होने से पूर्ण रोजगार की स्थिति पुनः प्राप्त हो जायेगी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की मान्यता थी कि श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी ऐच्छिक, संघर्षात्मक, मौसमी जैसी बेरोजगारी पाई जा सकती है, परन्तु अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती और यदि पाई भी जाती है तो आर्थिक शक्तियों के स्वरूप में स्वतः ही इस प्रकार के परिवर्तन आ जाते है जिससे अनैच्छिक बेरोजगारी समाप्त हो जाती है।

इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का दृढ़ विश्वास था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार पाया जाता है क्योंकि बचत तथा विनियोग हमेशा बराबर होते हैं। उनके

अनुसार बचत आय के वृत्ताकार प्रवाह से हुआ निकास हैं। वस्तुतः आय व उपभोग खर्च के बीच अन्तर को बचत के रूप में परिभाषित किया हैं। इनके अनुसार आय के चक्राकार प्रवाह से हुई निकासी को किसी भी रूप में व्यय नहीं किया जाता हैं। अर्थव्यवस्था में न्यून उपभोग और बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं, जब तक अर्थव्यवस्थाओं में हुई निकासियों का किसी न किसी रूप में अन्तः क्षेपण होता रहेगा तब तक पूर्ण रोजगार तथा कीमत स्थिरता बनी रहेगी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने तकनीक परिवर्तनों को स्थिर मान लिया था। अतः इनके अनुसार आय में किसी प्रकार के परिवर्तन संभव नहीं होते अर्थात् आय को स्थिर मान लिया था।

$$\mathbf{Y = C + S}$$

आय की स्थिरता के पश्चात् उन्होनें बताया कि बचत में वृद्धि संभव है, यदि उपभोग के स्तर को कम किया जाये। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह बताया कि आर्थिक विकास करके जीवन–स्तर को तभी बढ़ाया जा सकता है जब बचत को बढ़ाया जाये। अब प्रश्न यह उठता है कि लोग उपभोग का त्याग करके बचत को कब बढ़ायेंगे। इस हेतु उन्होंने बचत को प्रभावित करने वाली ब्याज दर को बढ़ाने पर जोर दिया क्योंकि ब्याज दर व बचत में धनात्मक सम्बन्ध होता हैं। बचत में वृद्धि अथवा कमी प्रत्यक्ष रूप से ब्याज दर से सम्बन्धित है।

$$\mathbf{S = f\,(r)}$$

$$\frac{ds}{dr} > 0$$

तथा उपभोग एवं ब्याज दर में विपरीत सम्बन्ध को बताया है।

$$C = f(r)$$

$$\frac{dc}{dr} < 0$$

महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बचतों में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति फलन समग्र मांग फलन में पर्याप्त वृद्धि करने में असमर्थ रहेगा। परिणामस्वरूप वस्तुओं की माल सूची में वृद्धि हो जायेगी और उत्पादक श्रमिकों की छंटनी करने लगेंगे। परन्तु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार ऐसा नहीं होगा क्योंकि अर्थव्यवस्था में पुनः साम्य स्थापित करने में

केवल बचतकर्त्ताओं को प्राप्त ब्याज दर उनके दृष्टिकोण से ही महत्त्वपूर्ण नहीं है अपितु ब्याज की दरों में कमी विनियोगकर्त्ताओं के व्यवहार को भी प्रभावित करेगी। विनियोग पूँजीगत वस्तुओं के स्टॉक को प्रतिस्थापित करने के लिए किये जाने वाले व्यय का प्रवाह है। विनियोग व्यय भी उपभोग व्यय की तरह आय व रोजगार प्रवाह को जन्म देता है।

"से" का नियम वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में लागू होता है। प्रत्येक उत्पादक जब पूर्ति का निर्माण करता है तब वह ऐसा इसलिए करता है ताकि वह उसके बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करे अथवा मांग का निर्माण करे। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की प्रत्येक दशा किसी दूसरी वस्तु के लिए की जाने वाली मांग को प्रकट करती है। इसका कारण यह है कि कोई भी व्यक्ति वस्तुओं का उत्पादन या तो अपने निजी उपभोग के लिए करेगा अथवा उसके बदले में दूसरी वस्तुएँ खरीदने के लिए करेगा। इसका परिणाम यह होता है कि वस्तु विनियम अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की पूर्ति सदैव ही दूसरी वस्तुओं के लिए की जाने वाली मांग का प्रतीक होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक विक्रेता आवश्यक रूप से क्रेता भी होता है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री "से" के नियम को मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी लागू करते हैं। उनके अनुसार मुद्रा केवल विनियम के माध्यम का काम करती है। जब उत्पादक अपने उत्पादन को बेचकर मुद्रा के रूप में आय प्राप्त करेगा तो वह उस मुद्रा से दूसरी वस्तुएँ तथा सेवाएँ क्रय करने के लिए खर्च कर देगा। इस प्रकार मांग का निर्धारण होगा तथा वह कुल पूर्ति के बराबर हो जायेगी।

व्यवहारिक जीवन में लोग अपनी सम्पूर्ण मौद्रिक आय को वस्तुओं तथा सेवाओं पर व्यय नहीं करते हैं। वे इस आय का एक भाग बचा लेते हैं। आय का जितना भाग बचत के रूप में रखा जाता है उतनी ही मांग कम हो जाती है। अतः जब बचत होती है तो कुल मांग के कुल पूर्ति से कम होने की संभावना हो जाती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार बचत की स्थिति में भी "से" का नियम लागू होता है, इसका कारण यह है कि लोग बचत का विनियोग कर देते हैं। इस प्रकार उपभोग तथा निवेश की मांग का कुल योग कुल पूर्ति के बराबर हो जाता है। यदि किसी कारणवश बचत निवेश से अधिक होती है तो ब्याज की दर में इस प्रकार परिवर्तन होगा कि बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हो जाये। अतः मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम का कार्य करती है साथ ही ब्याज की दर पूर्णतः लोचशील होती हैं। इसलिए मौद्रिक व्यवस्था में भी "से" का नियम लागू होता है।

2.2 प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचना :

"से" का नियमानुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं कर लेती है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की आधारशिला रहा है, किन्तु मांग और पूर्ति में असमानता बनी रहती है। पूँजीवादी समाज का ढ़ाँचा ही ऐसा होता है जिससे समाज धनी और निर्धन दो भागों में बंटा रहता हैं। धनी समुदाय को राष्ट्रीय आय का अधिक भाग मिलता है परन्तु वह इसकी कम मात्रा का भाग खर्च करता है। कीन्स ने उपभोग का मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त प्रस्तुत करके कहा कि लोगों की आय में जितनी वृद्धि होती है उपभोग पर उतना खर्च नहीं करते हैं। आवश्यक नहीं है कि जितनी पूर्ति में वृद्धि हो उतनी मांग में भी वृद्धि हो। वास्तविक जीवन में नकद, मजदूरी दर में कटौती करना आसान नहीं है, क्योंकि श्रम संगठनों द्वारा मजदूरी कटौती का विरोध किया जाता है। कीन्स के अनुसार पीगू ने आय पक्ष की अवहेलना करके लागत पक्ष को ही महत्त्व दिया है [13]। मजदूरी एक तरफ किसी वस्तु की उत्पादन लागत का भाग है तो दूसरी ओर श्रमिकों की आय भी है। मजदूरी में कटौती करने से श्रमिकों की आय कम होगी जिससे प्रभावपूर्ण मांग कम होने से बेरोजगारी बढ़ती है। इसी प्रकार आर्थिक प्रणाली में स्वयं समायोजन नहीं हो पाता है। उसे समायोजित करने के लिए कीन्स के अनुसार सरकार जैसी बाहरी शक्तियों की बहुत आवश्यकता हैं। मुद्रा केवल विनियम का माध्यम ही नहीं बल्कि एक सक्रिय तत्त्व है जिसका एक मुख्य कार्य धन का संचय करना भी है। यदि मनुष्य धन का संचय करने लगे तो प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने से रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने मुद्रा के सट्टा मांग की भी उपेक्षा की है। परम्परावादियों की यह धारणा भ्रमपूर्ण है कि बचत व विनियोग ब्याज के माध्यम से बराबर हो जाते हैं। प्रथम तो वास्तविक जीवन में बचत करने वाले तथा विनियोग करने वाले लोग अलग–अलग होते हैं। दूसरा कीन्स के अनुसार बचत आय पर तथा निवेश ब्याज की दर व पूँजी की सीमान्त कुशलता पर निर्भर करती है। अतः ब्याज की दर के स्थान पर आय में परिवर्तन करके बचत और विनियोग में समानता की जा सकती हैं। कीन्स के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आंशिक संतुलन की धारणा को सामान्य संतुलन पर लागू करने का प्रयत्न किया है। इस सिद्धान्त को तर्क की दृष्टि से तो दोष रहित माना जा सकता है, किन्तु यह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। 1930 की आर्थिक मंदी में भंयकर बेरोजगारी तथा अति उत्पादन से उत्पन्न संकट ने प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त का खोखलापन जाहिर कर दिया। कीन्स जो प्रारम्भ में प्रतिष्ठित विचारधारा का समर्थक था, कट्टर आलोचक बन गया। उन्होंने एक नये तर्कयुक्त एवं व्यवहारिक रोजगार सिद्धान्त का प्रतिपादन कर समूची आर्थिक विचारधारा में क्रान्ति ला दी। कीन्स ने बताया कि रोजगार

का स्तर राष्ट्रीय आय तथा उत्पादन के स्तर पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग का सम्बन्ध कुल मांग के उस स्तर से है जिस पर कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है। कुल मांग धन की वह राशि है जो एक अर्थव्यवस्था के लोग रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पन्न वस्तुओं को क्रय करने के लिए व्यय करते हैं जबकि कुल पूर्ति धन की वह राशि है जिस पर एक अर्थव्यवस्था के सभी उद्यमी रोजगार के एक निश्चित स्तर पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए व्यय करेंगे।

इस प्रकार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने आय में वृद्धि या कमी का उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं बताया। यदि हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का गहन अध्ययन करें तो यह बात सामने आती है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उपभोग को भी आय से असम्बन्ध माना एवं यह बताया कि व्यक्तियों की आदतें, रूचियां, सामाजिक वातावरण आदि अल्पकाल में स्थिर रहते हैं। अतः उन्होंने एक प्रकार से उपभोग को भी स्थिर मान लिया था। यही कारण है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में उपभोग फलन का वर्णन इतना अधिक दिखाई नहीं देता है।

2.3 कीन्सियन दृष्टिकोण :

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विपरीत कीन्स ने अर्थशास्त्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाकर समस्त प्रतिष्ठित सिद्धान्तों को चुनौती दे डाली। ये क्रान्तिकारी परिवर्तन मुख्य रूप से 1914 के प्रथम विश्व युद्ध एवं 1930 की विश्व व्यापी आर्थिक मन्दी के पश्चात् ही परिलक्षित हुए जिन्हें कीन्स ने अपनी पुस्तक General Theory of Employment Interest & Money (1936) में प्रस्तुत किया। वास्तव में समष्टि अर्थशास्त्र के विकास की नींव कीन्स की इसी पुस्तक के पश्चात् पड़ी। कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के एक प्रमुख सिद्धान्त जो कि "से" के नियम से जाना जाता है, जिसकी कटु आलोचना करते हुए यह बताया कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह तर्क भ्रमपूर्ण है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। इसके साथ ही इस तर्क की भी आलोचना की है, जिसमे उपभोग को घटाकर बचत में वृद्धि करके अधिक आर्थिक विकास को प्राप्त किया जा सकता है।

जिस प्रकार मार्शल ने मांग फलन का प्रतिपादन किया था ठीक उसी प्रकार कीन्स ने उपभोग फलन की घारणा प्रतिपादित करके आर्थिक चरों में परिवर्तनों का उपभोग से सम्बन्ध बताया। प्रो. हेन्सन ने कीन्स के उपभोग को मार्शल के मांग फलन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण माना हैं। कीन्स ने आय, उपभोग एवं बचत में सम्बन्ध व्यक्त करने हेतु दो फलन प्रस्तुत किये : 1) उपभोग फलन एवं 2) बचत फलन।

2.3.1 उपभोग फलन : उपभोग फलन उपभोग के स्तर एवं उपभोग स्तर को प्रभावित करने वाले चरों में सम्बन्ध को व्यक्त करता है। कीन्स ने अन्य चरों (ब्याज की दर, पूँजीगत लाभ, सम्पत्ति की मात्रा, मुद्रा का स्टॉक, व्यक्ति का दृष्टिकोण एवं उपभोग साख की सुविधा आदि) को अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं मानते हुए आय एवं उपभोग के मध्य सम्बन्ध को व्यक्त किया। वस्तुतः उपभोग फलन/उपभोग प्रवृत्ति आय के भिन्न–भिन्न स्तरों पर कुल उपभोग व्यय के बीच फलनात्मक सम्बन्ध को व्यक्त करता है :

$$C = f(y)$$

C = उपभोग फलन, y = आय, f = उपभोग व आय में सम्बन्ध को बताता है।

उपभोग फलन निम्नांकित बातों को व्यक्त करता है :

1. उपभोग का स्तर आय स्तर पर निर्भर करता है।
2. इन दोनों में धनात्मक सम्बन्ध है। आय में वृद्धि पर उपभोग में वृद्धि तथा आय में कमी पर उपभोग में भी कमी की प्रवृत्ति रहती है।
3. जिस गति से आय बढ़ती है, उपभोग में वृद्धि उस गति से नहीं होती है।
4. गरीब वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति अमीर वर्ग की उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि गरीब की आय कम होने के कारण वे अपनी कुल आय का लगभग पूरा उपभोग कर लेते हैं जबकि अमीर वर्ग की आय अधिक होने के कारण वे अपनी आय का थोड़ा भाग ही उपभोग करते हैं।
5. आय और रोजगार का उपभोग प्रवृत्ति से सीधा सम्बन्ध है। उपभोग प्रवृत्ति के बढ़ने पर कुल उपभोग में वृद्धि होती है जिसके फलस्वरूप आय और रोजगार में वृद्धि होती है। इसी प्रकार उपभोग प्रवृत्ति के कम होने पर कुल उपभोग में कमी होने के कारण आय और रोजगार में कमी आती है।

गणितीय रूप में उपभोग फलन को निम्न प्रकार विश्लेषित कर सकते है :

कीन्स के अनुसार :

$$Y = C + S$$

$$\text{औसत उपभोग प्रवृत्ति} = \frac{\text{कुल उपभोग}}{\text{कुल आय}}, \quad APC = \frac{C}{Y}$$

अल्पकालीन उपभोग फलन :

कीन्सियन अर्थशास्त्र मुख्य रूप से अल्पकालीन विश्लेषण पर आधारित अर्थशास्त्र है। अतः अल्पकालीन उपभोग फलन को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है।

$$C = a + by$$

a = स्वायत्त उपभोग

b = आय रेखा का ढ़ाल = MPC

y = आय

$$1 > \frac{C}{Y} > 0$$

अर्थात् उपभोग का एक ऐसा भाग जो आय से सम्बन्धित नहीं है, स्वायत्त उपभोग कहते हैं। आय कम, अधिक या शून्य रहने पर भी यह उपभोग किया जाता है। यह आवश्यक वस्तुओं का उपभोग होता है। उपभोग का दूसरा भाग आय से सम्बन्धित होता है जो आय के साथ–साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होता है। प्रायः MPC इकाई से कम होती है। अतः आय बढ़ने के साथ–साथ उपभोग बढ़ता है किन्तु अपेक्षाकृत कम तेजी से।

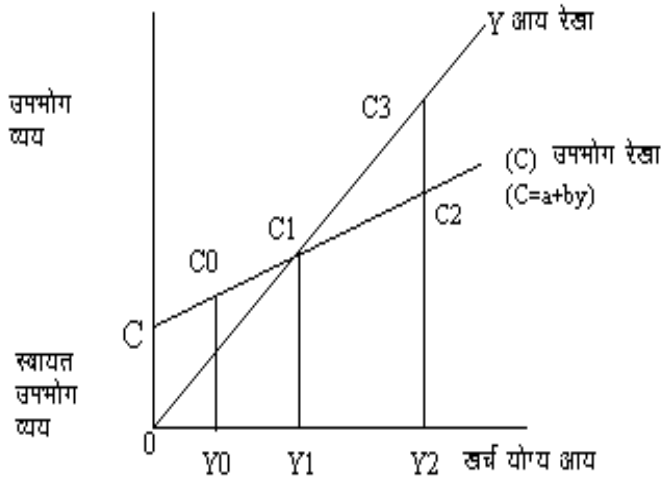

रेखाचित्र 2.1 : अल्पकालीन उपभोग फलन।

रेखाचित्र 2.1 में, Y_1 पर सम–विच्छेद बिन्दु (Break-Even-Point) है, जिस पर C = Y है। Y_2 पर C_2Y_2 उपभोग व्यय तथा C_3Y_2 आय हैं अर्थात् C_3C_2 बचत हैं। इस प्रकार Y_0 आय के स्तर पर बचत नहीं होती है।

कीन्स द्वारा प्रतिपादित उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम उपभोग फलन का आधार है। प्रो. जे. एम. कीन्स के अनुसार ''आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम जिस पर हम मानव स्वभाव के सम्बन्ध में अपने ज्ञान तथा अनुभव के विस्तृत तथ्यों के आधार पर बहुत अधिक विश्वास के साथ निर्भर रहने के अधिकारी हैं। इस नियमानुसार सामान्यतः लोग आय में वृद्धि होने पर अपने उपभोग में भी वृद्धि करते है पर उतनी नहीं जितनी उनकी आय में वृद्धि होती है।'' इस प्रकार यह नियम बताता है कि समान्यतः लोग आय में वृद्धि होने पर उपभोग में भी वृद्धि करते हैं, किन्तु उपभोग में वृद्धि उतनी नहीं होती जितनी वृद्धि आय में होती है अर्थात् उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि के मुकाबले कम होती है।

दीर्घकालीन उपभोग फलन :

दीर्घकालीन उपभोग फलन को निम्न सूत्र में व्यक्त किया जाता है :

C = by

C = कुल उपभोग व्यय

by = प्रेरित उपभोग (Induced Consumption)

यह राष्ट्रीय आय के उस स्थिर अनुपात पर निर्भर है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। दीर्घकाल में उपभोग व आय के बीच एक निश्चित आनुपातिक सम्बन्ध बना रहता है। परिणामस्वरूप दीर्घकालीन औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) तथा दीर्घकालीन सीमान्त प्रवृत्ति (MPC) दोनों स्थिर एवं बराबर (APC = MPC) रहती हैं। रेखाचित्र 2.2 में, y व c रेखा का अन्तर बचत को दर्शाता है।

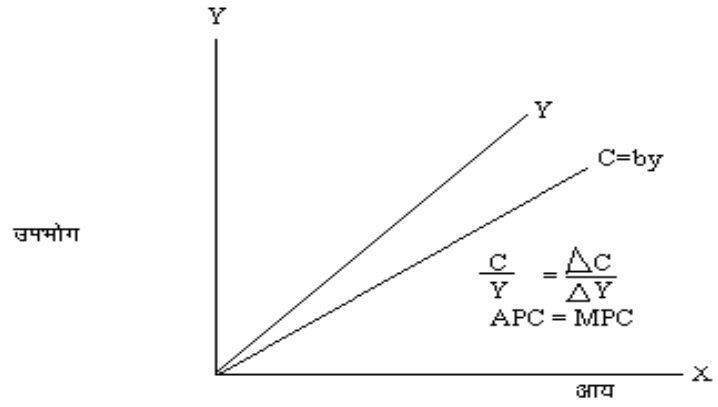

रेखाचित्र 2.2 : दीर्घकालीन उपभोग फलन।

2.3.2 बचत फलन :

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियो ने जहाँ बचत को ब्याज दर का फलन माना है वहाँ कीन्स ने बचत को आय का फलन मानते हुए बताया कि बचत व आय में प्रत्यक्ष व धनात्मक सम्बन्ध होता है। यद्यपि उन्होंने अत्यधिक ऊँची ब्याज दरों से बचत पर होने वाले प्रभाव की औचित्यता को स्वीकार किया था परन्तु फिर भी उन्होंने बचत को प्रभावित करने वाले तत्त्वों में से आय को ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण चर माना था। बचत फलन को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है।

$$\mathbf{S = f(y)}$$

(S= बचत, y= आय, f= फलन है)

$$1 > \frac{ds}{dy} > 0$$

बचत फलन से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :

1. बचत की मात्रा आय के स्तर पर निर्भर करती है।
2. दोनों चरों की मात्रा धनात्मक रूप से सम्बन्धित है।
3. जिस गति से आय में वृद्धि होती है बचत दर में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक होती है अर्थात् MPS निरन्तर बढ़ती है।

कीन्स के अनुसार :

$$\mathbf{Y = C + S}$$

$$\text{औसत बचत प्रवृत्ति} = \frac{\text{कुल बचत}}{\text{कुल आय}},\ APS = \frac{S}{Y}$$

$$\text{सीमान्त बचत प्रवृत्ति} = \frac{\text{बचत में परिवर्तन}}{\text{आय मे परिवर्तन}},\ MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$$

2.4 उपभोग फलन की तकनीकी विशेषताएँ :

अभी तक यह माना गया है कि एक समुदाय का उपभोग खर्च चालू समय में वास्तविक कुल निरपेक्ष प्रयोज्य आय का फलन है। परन्तु आय के स्तर के अतिरिक्त उपभोग आय और बचत आय के तकनीकी गुणांक भी उपभोग के निरपेक्ष स्तर पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ये तकनीकी गुणांक इस बात की व्याख्या करते हैं कि जब आय

का स्तर दिया गया हो तो उपभोग व्यय में कैसे परिवर्तन होते हैं। इन गुणांकों की व्याख्या सारणी 2.1 के माध्यम से की गई है।

सारणी 2.1 : आय, उपभोग एवं बचत में तकनीकी सम्बन्ध।

yd	c	s	$APC = \frac{c}{yd}$	$APS = \frac{s}{yd}$	$MPC = \frac{\Delta c}{\Delta yd}$	$MPS = \frac{\Delta s}{\Delta yd}$
0	40	-40	-	-	-	-
100	120	-20	1.20	-0.20	0.80	0.20
200	200	0	1.00	0.00	0.80	0.20
300	280	20	0.93	0.07	0.80	0.20
400	360	40	0.90	0.10	0.80	0.20
500	440	60	0.88	0.12	0.80	0.20
600	520	80	0.87	0.13	0.80	0.20

रेखीय उपभोग फलन को इस प्रकार व्यक्त कर सकते है :

$$\mathbf{c = c_0 + byd}$$

यहां c_0 स्वतंत्र उपभोग खर्च है जो कि ऐसा उपभोग खर्च है जो शून्य आय पर किया जाता है। सारणी 2.1 में यह 40 रूपये हैं। b उपभोग आय अनुपात या सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) है जो उक्त सारणी के अनुसार 0.80 है। इस प्रकार उपभोग फलन को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं।

$$C = 40+0.80\ yd$$

औसत उपभोग प्रवृत्ति $(APC) = \frac{c}{yd}$

जिसको रेखीय रूप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं :

$$\frac{c}{yd} = \frac{c_0 + byd}{yd}$$

$$\frac{c}{yd} = \frac{c_0}{yd} + b$$

सारणी 2.1 के अनुसार यदि $c_0 = 40$, $yd = 600$ और $b = 0.80$ है तो

$$\frac{c}{yd} = \frac{40}{600} + 0.80$$

$$= 0.07 + 0.80 = 0.87$$

सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति $(MPC) = \frac{\Delta c}{\Delta yd}$

सारणी 2.1 के अनुसार जब आय 500 रू से बढ़कर 600 रू होती है तो उपभोग खर्च 440 रू से बढ़कर 520 रू हो जाता है।

$$MPC = \frac{\Delta c}{\Delta yd} = \frac{520 - 440}{600 - 500}$$

$$= \frac{80}{100} = 0.80$$

औसत बचत प्रवृत्ति $(APS)\frac{s}{yd}$

यदि $yd = 400$ रू व $s = 40$ रू है तो

$$APS\ \frac{s}{yd} = \frac{40}{400} = 0.10$$

रेखीय फलन को निम्न प्रकार से निकाला जा सकता हैः

$$C = c_0 + byd$$
$$C = yd - S$$
$$yd - s = co + byd$$
$$-s = co + byd - yd$$
$$-s = co + (b-1)yd$$
$$s = -co + (1-b)\,yd$$

यदि C_0 = 40 रूपये, yd = 400 रूपये और b = 0.80 हो तो बचत की मात्रा हैः

$$s = -40 + (1-0.80)\,400$$
$$s = -40 + 0.20 \times 400$$
$$= -40 + 80 = 40$$

औसत बचत प्रवृत्ति (APS) के सामान्य रेखीय रूप को निम्न ढ़ंग से प्रकट किया जा सकता है :

$$S = -c_0 + (1-b)\,yd$$
$$APS = \frac{s}{yd} = \frac{-c_0}{yd} + (1-b)$$

यदि yd = 400 रूपये है तो

$$\frac{s}{yd} = \frac{-40}{400} + (1-0.80)$$
$$= -0.10 + 0.20 = 0.10$$

सीमान्त बचत प्रवृत्ति (MPS) बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात है। यह बताता है कि समुदाय द्वारा अतिरिक्त आय में से कितना भाग बचाया जाता है। यह प्रयोज्य आय के विभिन्न स्तरों पर बचत के परिवर्तन की दर को प्रकट करता है। यदि yd = 400 रू से 500 रू, तक बढ़ती है और इसके साथ बचत 40 रूपये से 60 रूपये तक बढ़ती है तो MPS इस प्रकार है :

$$MPS = \frac{\Delta s}{\Delta yd} = \frac{60-40}{500-400} = \frac{20}{100} = 0.20$$

सामान्य रेखीय रूप में सीमान्त बचत प्रवृत्ति को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है :

$$MPS = \frac{\Delta s}{\Delta yd} = (1-b)$$

2.5 आय, उपभोग एवं बचत में आनुभाविक तथ्य :

आय के निर्धारण के सम्बन्ध में कीन्स ने उपभोग फलन की व्याख्या की, जो आय के निर्धारण का एक अभिन्न अंग है। कीन्सियन विश्लेषण एक अल्पकालिक विश्लेषण है जिसके अनुसार वास्तविक उपभोग वास्तविक आय का फलन है। कीन्सियन उपभोग फलन यह प्रतिपादित करता है कि जैसे–जैसे आय में वृद्धि होती जाती है लोग आय का घटता हुआ प्रतिशत उपभोग पर व्यय करते हैं या आय का बढ़ता हुआ प्रतिशत बचत करते हैं। कीन्स ने उपभोग फलन की जो व्याख्या प्रस्तुत की वह एक सैद्धान्तिक धारणा थी, किसी व्यवहारिक या आनुभविक परीक्षण पर आधारित नहीं थी। चूँकि कीन्स एक बाजार व्यवस्था में पायी जाने वाली सामान्य बेरोजगारी की व्याख्या से सम्बन्धित थे, किसी प्रकार के दीर्घकालीन मॉडल के निर्माण से सम्बन्धित नहीं थे, इसलिए उन्हें इस प्रकार के व्यवहारिक परीक्षण की आवश्यकता भी नहीं थी। चूँकि कीन्स ने अपने सैद्धान्तिक विश्लेषण में निष्कर्षात्मक रूप में सरकारी हस्तक्षेप पर बल दिया, इसलिए बाद में कीन्सियन अर्थशास्त्रियों ने एक नियोजन मॉडल के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जिससे दीर्घकालीन स्तर पर कीन्सियन नीति निर्धारक निष्कर्षों को लागू किया जा सके। फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 'कीन्सियन स्कूल' ने इस दिशा में प्रयास करना शुरू किया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने यह महसूस किया कि मॉडल के विभिन्न प्राचालों के पिछले उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर व्यवहारिक परीक्षण किया जाए। उपभोग फलन की व्यवहारिक सत्यता की जाँच इस दिशा में पहला कदम था।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपभोग फलन की सत्यता के सम्बन्ध में कुछ परीक्षण किये गये जिनके आधार पर अर्थशास्त्रियों ने कीन्सियन फलन की सत्यता को संदिग्ध पाया। 1946 में साइमन कुजनेट्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सम्बन्ध में 1869 से 1938 तक के आँकड़े प्रकाशित किये जिनसे उपभोक्ता व्यवहार तथा उस पर आधारित उपभोग के नियम के सम्बन्ध में तीन महत्वपूर्ण बातें सामने आयीं [4] :

1. बजट अंकों के तिर्यक वर्गीय अध्ययन प्रदर्शित करते है कि Y की वृद्धि के साथ S/Y अनुपात बढ़ता है जिससे कि जनसंख्या के तिर्यक वर्गों में MPC < APC।

2. व्यापार चक्रीय या अल्पकालिक आँकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि अधिक C/Y अनुपात अभिवृद्धि की स्थिति में औसत अनुपात से कम रहता है। जबकि अवसाद की स्थिति में औसत अनुपात से अधिक होता है जिससे कि अल्पकाल में जब आय परिवर्तित हो तो MPC < APC।

3.दीर्घकालीन आँकड़े दीर्घकाल में C/Y या S/Y अनुपात में किसी प्रकार के परिवर्तन की प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं करते है इसलिए दीर्घकालीन आय की वृद्धि के साथ MPC = APC बना रहता है।

इन तथ्यों के परीक्षण के लिए समय–समय पर अनेक परिकल्पनायें या सिद्धान्त विकसित किये गये जिनका अध्ययन उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है।

आय, उपभोग एवं बचत पर समय–समय पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन करके अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किये जिनमें से कुछ का अध्ययन निम्नानुसार हैः

प्रो. कीन्स के अनुसार अल्पकालीन MPC दीर्घकालीन MPC से कम होती है, ऐसा इसलिए होता है कि अल्पकाल में व्यक्ति अपनी आय को कम व्यय में समायोजित करने में असमर्थ रहता है लेकिन दीर्घकाल में वह अपनी आय को व्यय हेतु समायोजित कर लेता है। कीन्स के मतानुसार सामान्यतः दीर्घकाल में भी आय तथा APC में विपरीत सम्बन्ध पाया जाता है। यद्यपि स्वयं कीन्स इस प्रवृत्ति के बारे में आश्वस्त नहीं थे। इस प्रकार विभिन्न अर्थशास्त्रियों में उपभोग फलन को लेकर दो प्रकार का मतभेद पाया गया है [1]।

1. अल्पकालीन MPC एवं दीर्घकालीन MPC में क्या सम्बन्ध है।
2. आय एवं उपभोग में अल्पकाल तथा दीर्घकाल में आनुपातिक सम्बन्ध है अथवा गैर–आनुपातिक।

कीन्सोत्तर विचारधारा इन्हीं महत्त्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करती है। दोनों महायुद्धों के बीच की अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने समंक एकत्रित कर यह निष्कर्ष देते हुए कीन्स के विचारों का समर्थन किया कि अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों में ही MPC घटती हैं। इसके विपरीत स्मिथीज व टोबिन ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करके यह बतलाया कि आय एवं उपभोग के मध्य दीर्घकाल सम्बन्ध आनुपातिक नहीं होते। प्रो. साइमन कुजनेट्स ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के 1869–1929 की अवधि में आँकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय एवं उपभोग की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया और बताया कि उक्त अवधि में आय में चार गुना वृद्धि होने पर भी उपभोग एवं आय का अनुपात स्थिर रहता है [4]।

इसके पश्चात् साइमन कुजनेट्स के विचारों का प्रो. गोल्ड स्मिथ ने भी अनुमोदन किया तथा आय व उपभोग की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के पश्चात् बताया कि बचत की

एक विशेषता यह है कि दीर्घकाल में कुल बचत का आय में अनुपात 1/8 पर स्थिर रहता है [14]।

कुछ अर्थशास्त्रियों ने परिक्षेत्री समंक (Cross Section Data) लेकर यह निष्कर्ष दिया कि APC दीर्घकाल में गिरती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह मत व्यक्त किया कि APC व्यापारिक चक्रों से प्रभावित होने के कारण घटती – बढ़ती रहती है।

अल्पकालीन उपभोग फलन एवं दीर्घकालीन उपभोग फलन में क्या सम्बन्ध पाया जाता है इनकी व्याख्या एवं कारण ज्ञात करने हेतु विभिन्न परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की गई हैं।

2.5.1. निरपेक्ष आय परिकल्पना :

निरपेक्ष आय परिकल्पना (Keynes, 1936) की आधारभूत मान्यता यह है कि प्रत्येक व्यक्तिगत उपभोक्ता अपनी निरपेक्ष आय के स्तर के आधार पर यह तय करता है कि वह अपनी घरेलू आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय करेगा और यदि अन्य बातें समान रहें, तो निरपेक्ष आय में वृद्धि आय के अनुपात में कमी लायेगी जो उपभोग पर व्यय होगा। कीन्स ने अपने उपभोग फलन की व्याख्या में यही प्रतिपादित किया, इसीलिए प्रायः यह स्वीकार किया जाता है कि कीन्स निरपेक्ष आय परिकल्पना के प्रतिपादक अर्थशास्त्री है, यद्यपि इनका परिमार्जन बाद के अर्थशास्त्रियों, विशेष रूप से टोबिन तथा स्मिथीज द्वारा हुआ। निरपेक्ष आय परिकल्पना के अनुसार, उपभोग तथा आय के बीच मूलभूत सम्बन्ध अल्पकालीन है। निरपेक्ष आय परिकल्पना के समर्थक अर्थशास्त्रियों ने यह प्रतिपादित किया कि यदि समग्र उपभोग तथा समग्र आय से सम्बन्धित कुछ वर्षों के आँकड़ों को ग्राफ पर अंकित किया जाए तो उपभोग फलन $C = Co+eY$ के स्वरूप का प्राप्त होगा।

उपभोग फलन का ऊपर की ओर विवर्तन अनेक कारणों से हो सकता है। टोबिन यह मत व्यक्त करते हैं कि राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि के कारण समयावधि में उपभोग फलन विवर्तित हो सकता है। सम्पत्ति से टोबिन का अभिप्राय मुख्यतया तरल सम्पत्तियों जैसे–नकद, बैंक जमा तथा बाँण्ड़ों से है। उपभोग फलन का विवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानान्तरण के कारण भी हो सकता है। नये उत्पादों को बाजार में लाने के कारण भी उपभोग फलन का विवर्तन हो सकता है। आयु संरचना में परिवर्तन, सामाजिक बीमा, आय के बँटवारे तथा विलासिता वस्तुओं के आवश्यक वस्तुओं में परिवर्तन के कारण भी उपभोग फलन का ऊर्ध्वमुखी विवर्तन हो सकता है।

जहाँ सापेक्ष आय परिकल्पना एवं स्थायी आय परिकल्पना यह मत व्यक्त करती है कि दीर्घकाल में आय, उपभोग सम्बन्ध सामान्यतः आनुपातिक होता है जबकि स्मिथीज व टोबिन तथा कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने यह मत व्यक्त किया है कि उपभोग का निर्धारण सामान्यतः निरपेक्ष आय से होता है अर्थात् निरपेक्ष आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में भी उसी प्रकार के परिवर्तन दिखायी देते हैं [15]।

चूँकि वर्तमान उपभोग का सम्बन्ध वर्तमान आय से होता है। अतः इन्होंने बताया कि आय, उपभोग का सम्बन्ध आनुपातिक नहीं होता है, अर्थात् APC घटती रहती है लेकिन इन्हीं अर्थशास्त्रियों ने बताया कि समय श्रेणी समंक और गैर–अनुपातिक सम्बन्धों को नहीं दर्शाते जिसके कारण उन्होंने यह बताया कि दीर्घकाल में उपभोग को आय के अतिरिक्त अन्य घटक भी प्रभावित करते है। ये घटक निम्न प्रकार है :

1. सम्पत्तिधारियों को ऊँची आय की प्राप्ति।
2. ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में आगमन।
3. जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन।
4. नई वस्तुओं का बाजार एवं उपभोक्ताओं के बजट में प्रयोग।

इस प्रकार स्पष्ट है, निरपेक्ष आय परिकल्पना के समर्थकों के अनुसार मूल फलन तो अल्पकालीन फलन है और दीर्घकालीन फलन अल्पकालीन उपभोग फलनों के ऊपर की ओर विवर्तन का परिणाम है।

2.5.2. सापेक्ष आय परिकल्पना :

आय एवं उपभोग के मध्य सम्बन्ध को व्यक्त करने हेतु एक पूर्णतया नवीन दृष्टिकोण 1949 में प्रो. जे. एस. ड्यूजनबरी ने अपनी पुस्तक "Income, Saving and the Theory of Consumer Behaviour" में आय उपभोग के बीच आनुपातिक सम्बन्ध को अस्वीकार करके यह प्रतिपादित किया कि आय तथा उपभोग के बीच आधारभूत सम्बन्ध गैर–आनुपातिक ही हैं। ड्यूजनबरी, 1949 ने एक ओर यह अस्वीकार किया कि उपभोग की मात्रा निरपेक्ष आय के ऊपर निर्भर करती है। दूसरी ओर इसे भी गलत सिद्ध किया कि अल्पकालीन उपभोग फलन विवर्तित होकर दीर्घकालीन हो जाता है। ड्यूजनबरी ने यह सुझाव दिया कि मूलतः उपभोग सम्बन्ध दीर्घकालीक तथा आनुपातिक है तथा औसत आय प्रवृत्ति या C/Y अनुपात स्थिर है [6]।

साक्षेप आय परिकल्पना के अनुसार "किसी परिवार की आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय होगा उस परिवार की निरपेक्ष आय पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि अन्य

परिवारों जिनके बीच वह रहता है या जिनसे सम्बन्ध स्थापित करता है कि आय के संदर्भ में उसकी अपनी आय की सापेक्षता के ऊपर निर्भर करता है"। अर्थात् उसका उपभोग उसकी अपनी आय के स्तर पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरों की तुलना में उसकी आय कितनी है। उनके अनुसार यदि एक परिवार की आय बढ़े लेकिन आय मापक पर इसकी सापेक्षिक स्थिति अपरिवर्तित रहे क्योंकि उन सभी परिवारों की आय भी, जिनके साथ वह सम्बन्ध स्थापित करता है, उसी दर से बढ़ गयी हो, तो उपभोग तथा बचत के बीच आय का बँटवारा अपरिवर्तित रहेगा। परिवार की निरपेक्ष आय बढ़ी है इसलिए उसकी निरपेक्ष बचत तथा उपभोग भी बढ़ेगा, लेकिन उपभोग पर होने वाले आय के व्यय का भाग वही बना रहेगा जो निम्नतर आय के स्तर पर था। दूसरी ओर यदि एक परिवार की आय अपरिवर्तित रहे, लेकिन अन्य परिवारों की आय बढ़ जाये, तो उस परिवार की सापेक्षिक आय स्थिति नीचे गिरती है। सापेक्षिक आय परिकल्पना के अनुसार परिवार की सापेक्षिक आय स्थिति में गिरावट उसके उपभोग के ऊपर होने वाले आय के भाग में वृद्धि लायेगी, यद्यपि उसकी निरपेक्ष आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। ड्यूजनबरी के अनुसार प्रत्येक परिवार समाज में अपने सापेक्षिक सामाजिक दर्जे को पूर्ववत् बनाये रखने का प्रयास करता है और इसलिए अपनी निरपेक्ष आय का एक निश्चित अनुपात हमेशा उपभोग पर व्यय करता है।

प्रस्तुत सिद्धान्त सापेक्ष आय परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। यह परिकल्पना निम्न मान्यताओं पर आधारित हैः

1. प्रत्येक व्यक्ति का उपभोग फलन स्वतंत्र न होकर पारस्परिक रूप से निर्भर होता है।
2. समय का उपभोग आय सम्बन्ध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

प्रो. ड्यूजनबरी ने बताया कि उपभोग स्तर का निर्धारण व्यक्ति की निरपेक्ष आय से न होकर वास्तव में उसकी सापेक्ष आय द्वारा होता है। सामान्यतः व्यक्ति अपनी आय की तुलना अन्य व्यक्तियों की आय से करता रहता है। समाज में आय वितरण की स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति आय का कितना प्रतिशत उपभोग पर खर्च करेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि समाज में आय की दृष्टि से उसकी सापेक्ष स्थिति में कैसे परिवर्तन आया है। यदि व्यक्ति की निरपेक्ष आय स्थिर रहे तथा समाज में अन्य व्यक्तियों की आय घटे तो उस व्यक्ति की सापेक्ष स्थिति में सुधार हो जायेगा और उपभोग पर पहले की अपेक्षा थोड़ी बहुत वृद्धि करने लगेगा। यदि व्यक्ति की स्थिति समाज में आय वितरण की स्थिति से अपरिवर्तित है तो वह अपनी आय का उतना ही भाग उपभोग पर व्यय करता

रहेगा चाहे उसकी आय में वृद्धि ही क्यों न हो जाये, तथा यदि आय वितरण की दृष्टि से व्यक्ति की स्थिति पहले की अपेक्षा खराब हो जाये तो वह समाज में अपना जीवन–स्तर बनाये रखने के लिए आय बढ़ने पर उपभोग का अनुपात काफी बढ़ा देगा। ड्यूजनबरी के मत में आय वृद्धि की दर ही अल्पकालीन या दीर्घकालीन उपभोग फलन पर उपभोक्ताओं की स्थिति का निर्धारण करती है। इनके द्वारा प्रस्तुत परिकल्पना के अनुसार उपभोग आय अनुपात पूर्व में अर्जित उच्चतम आय तथा वर्तमान आय के अनुपात पर निर्भर करता है, इस प्रकार वर्तमान में उपभोग पूर्व में अर्जित आय एवं वर्तमान आय के अनुपात पर निर्भर करेगा। इनके अनुसार चूँकि दीर्घकाल में आय में समान रूप से परिवर्तन नहीं होते बल्कि इनमें उतार–चढ़ाव होते रहते हैं। अतः अल्पकाल में उपभोग व आय का सम्बन्ध गैर–आनुपातिक रहता हैं। सापेक्ष आय परिकल्पना को समीकरण के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :

$$\frac{ct}{yt}=a+b(\frac{yt}{yo})b<1:b+MPC$$

इस समीकरण में *yo* पहले ही उच्चतम आय का स्तर है तथा *ct* एवं *yt, t* अवधि में क्रमशः उपभोग एवं आय के वर्तमान स्तर को दर्शाते हैं। c/y का अनुपात APC मंदी के समय अधिक होगा जब *yt<+yo* है तथा समृद्धि काल मे वर्तमान आय पूर्व में प्राप्त उच्च आय से अधिक होती है। अर्थात् *yt > yo*, इसलिए व्यक्ति उपभोग में इतनी वृद्धि नहीं करते अतः APC घटने लगती है। प्रो. फ्रेंको मोडिगिलयानी, एन्डों ने भी ड्यूजनबरी की सापेक्ष आय परिकल्पना का समर्थन किया।

उदाहरण के लिए यदि किसी अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों की आय 20 गुना ऊपर उठ जाये तो इस उच्चतर निरपेक्ष आय स्तर पर भी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए APC की मात्रा पूर्ववत् बनी रहेगी। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की सापेक्षिक आय स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी, अब भी कुछ लोग सापेक्षिक रूप से धनी होंगे जिनके ऊपर आय के अधिक भाग को उपभोग पर व्यय करने के सम्बन्ध में कोई सामाजिक दबाव नहीं होगा तथा कुछ सापेक्षिक गरीब होंगे जिनके ऊपर पहले जैसा सामाजिक दबाव बना रहेगा जिससे वे अपनी सापेक्षिक निम्नता को कम कर सकें और इसलिए वे पहले की तरह अपने निरपेक्ष आय का अधिक भाग उपभोग पर व्यय करते रहेंगे। इसके सम्बन्ध में तर्क देते हुए ड्यूजनबरी कहते है कि लोगों में अपने पड़ोसियों के उपभोग के ढाँचे को अनुकरण करने तथा उच्चतर जीवन निर्वाह स्तर को प्राप्त करने की प्रबल प्रवृत्ति होती है जिसे उन्होंने प्रदर्शन प्रभाव कहा।

इस परिकल्पना से एक महत्त्वपूर्ण नीति सम्बन्धी निष्कर्ष यह निकलता है कि मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का प्रबन्धन इस ढ़ंग से किया जाना चाहिये कि प्रतिकूल आशंसायें पैदा न हों। यदि विराम के समय में सरकार कुछ करों में कमी कर देती है जिससे प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है तो फिर भी उपभोग व्यय में सम्भवतः दो कारणों से वृद्धि न हो। पहला, कर में अचानक कमी से होने वाली आय की वृद्धि को अस्थायी माना जायेगा और यह उपभोग के खर्च को प्रभावित नहीं करेगी। दूसरा, यदि उपभोक्ता कर में कमी को भविष्य में प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों का चिन्ह मान लेते हैं तो प्रयोज्य आय चाहे बढ़ भी गई है फिर भी वे उपभोग खर्च में वृद्धि नहीं करेंगे। ऐसी हालत में सम्भव है कि वे बचत को बढ़ाना शुरू कर दें।

जीवन–चक्र परिकल्पना : जीवन–चक्र परिकल्पना का विकास मोडिग्लियानी, ब्रूमबर्ग और एन्डो के द्वारा किया गया। इन्होंने उपभोग फलन का प्रतिपादन करते हुए यह बताया कि उपभोग एवं आय में मूलतः आनुपातिक सम्बन्ध होता है। परन्तु इसका स्पष्टीकरण उन्होंने ड्यूजनबरी की अपेक्षा एक दूसरे रूप में दिया है। मोडिग्लियानी, ब्रूमबर्ग और एन्डो की परिकल्पना को सामान्यतः उपभोग की जीवन–चक्र परिकल्पना कहा जाता है। इसमें यह तर्क निहित है कि उपभोग सम्पूर्ण जीवन की औसत आय से सम्बन्धित होता है और इस पर वर्तमान आय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एन्डो तथा मोडिग्लियानी द्वारा प्रतिपादित उपभोग फलन के अनुसार व्यक्तिगत उपभोग व्यक्ति के वर्तमान विशुद्ध धन तथा वर्तमान एवं भविष्य में अर्जित होने वाली आय, पूँजी पर प्राप्त होने वाले ब्याज, आय की दर तथा व्यक्ति की आय द्वारा निर्धारित होता है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित जीवन–चक्र परिकल्पना का मूल आधार यह है कि किसी व्यक्ति का दीर्घावधि उपभोग उस व्यक्ति के जीवन की औसत आय से सम्बन्धित होता है तथा इसलिए यह चालू आय में परिर्वतनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यह परिकल्पना इस आनुभाविक तथ्य पर आधारित है कि प्रारम्भिक जीवन काल में एक औसत व्यक्ति की आय उसके व्यय से कम होती है अथवा उस व्यक्ति के प्रारम्भिक जीवन–यापन काल में तथा जीवन के अन्तिम वर्षों में उसका उपभोग व्यय उसकी आय की तुलना में अधिक होता है। जीवन–यापन काल के मध्य में एक औसत व्यक्ति की कुल आय उसके कुल उपभोग व्यय से अधिक होने के कारण वह व्यक्ति धनात्मक बचत करता है [12]।

एन्डो तथा मोडिग्लियानी (1963) के मतानुसार, उपभोग एवं आय के मध्य सम्बन्ध की माप में व्यक्ति की आयु का अत्यधिक महत्त्व है। अपने सम्पूर्ण जीवन काल में व्यक्तियों

को आरम्भ में बहुत कम आय प्राप्त होती है। जीवन के मध्य–वर्षों में व्यक्तियों की आय में निरन्तर वृद्धि हो कर यह शीर्ष को प्राप्त हो जाती है तथा वृद्धा अवस्था में अथवा सेवा से निवृत्त होने पर इस आय में तीव्र कमी हो जाती है [16]।

दूसरी ओर व्यक्तियों के जीवन का उपभोग वक्र उनके सम्पूर्ण जीवन के आय वक्र की तुलना में अधिक चपटा होता है तथा यह प्रदर्शित करता है कि उपभोग जीवन–काल में स्थिर गति से बढ़ता रहता है। परिणामस्वरूप औसत व्यक्ति अपने प्रारम्भिक युवा अवस्था में आय अधिक व्यय करने के कारण कम बचत करता हैं। जीवन के मध्य वर्षों में आय उपभोग से अधिक होने के कारण व्यक्ति धनात्मक बचत करता है। इस बचत से वह अपने प्रारम्भिक जीवन–यापन काल के ऋण का भुगतान करता है तथा वृद्ध अवस्था के लिए प्रावधान करता है। जीवन–चक्र परिकल्पना अल्प अवधि में उपभोग–आय के मध्य गैर–आनुपातिक सम्बन्ध की व्याख्या करने का प्रयास करती है।

2.5.3. स्थायी आय परिकल्पना :

अल्पकालिक उपभोग एवं आय के मध्य गैर–आनुपातिक सम्बन्ध तथा दीर्धकालिक उपभोग एवं आय के मध्य आनुपातिक सम्बन्ध की संगति हेतु 1957 में प्रकाशित मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक "A Theory of the Consumption Function" का काफी महत्त्व हैं। फ्रीडमैन किसी समय अवधि में वास्तव में प्राप्त चालू अथवा मापित आय तथा स्थायी आय के मध्य अन्तर करते हैं। उनका यह विश्वास है कि उपभोक्ता सामान्यतः उपनी स्थायी आय के आधार पर ही उपभोग व्यय सम्बन्धी निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार वे वर्तमान चालू अथवा मापित तथा स्थायी उपभोग के मध्य भी अन्तर बताते हैं। फ्रीडमैन के अनुसार स्थायी आय वह है जिसका कोई उपभोक्ता अपनी सम्पत्ति को अक्षुण्ण बनाये रखते हुए उपभोग कर सकता है अथवा वह ऐसा समझता है कि इसका उपभोग करना सम्भव है, जबकि स्थायी उपभोग किसी निर्दिष्ट समय अवधि में उपभोग की गई सेवाओं का मूल्य है [17]।

मिल्टन फ्रीडमैन ने चालू आय परिकल्पना को अस्वीकार किया तथा उसके स्थान पर उपभोग व्यय के निर्धारक के रूप में स्थायी आय की बात की। उनके अनुसार किसी परिवार की स्थायी आय उसकी उस वर्ष की चालू आय से प्रदर्शित नहीं होती है बल्कि दीर्घकाल में प्राप्त प्रत्याशित आय से प्रदर्शित होती है। फ्रीडमैन के अनुसार किसी एक वर्ष में किसी परिवार की स्थायी आय उस वर्ष में प्राप्त चालू आय द्वारा निर्धारित नहीं होती है बल्कि इसका निर्धारण भविष्य में कई वर्षो में आय प्रत्याशित या संभावित आय द्वारा होता है। फ्रीडमैन के शब्दों में स्थायी आय को औसत आय के रूप में लिया जाना चाहिए जिसे

एक उपभोक्ता इकाई स्थायी आय के रूप में मानती है तथा जो इसके अनुभव तथा दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। स्थायी आय से अभिप्राय उस राशि से है जिसे उपभोक्ता इकाई, अपनी सम्पत्ति को पूर्ववत् बनाये रखते हुए उपभोग कर सकती है। प्रत्येक उपभोक्ता अपनी स्थायी आय का अनुमान अपनी मानवीय तथा गैर–मानवीय सम्पत्ति के आधार पर प्राप्त करता है। व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि में किया गया विनियोग मानवीय सम्पत्ति के उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। इस प्रकार विनियोग जितना ही अधिक होगा भावी आय की प्रत्याशा उतनी ही अधिक होगी। प्राप्त मजदूरी तथा वेतन मानवीय पूँजी से प्राप्त आय होंगे जबकि किराया, ब्याज, लाभांश गैर–सम्पत्ति से प्राप्त आय होगी। इन दोनों ही स्त्रोतों से भावी आय का वर्तमान मूल्य या इसका कटौती किया गया मूल्य ही चालू सम्पत्ति होगी और जब इस सम्पत्ति मूल्य को ब्याज की किसी दर से गुणा कर देते हैं तो स्थायी आय प्राप्त हो जाती है।

फ्रीडमैन के अनुसार किसी परिवार की किसी वर्ष में वास्तविक या मापित आय स्थायी आय से अधिक या कम हो सकती है। फ्रीडमैन किसी परिवार की मापित आय को दो भागों में विभक्त करते हैं :

1. स्थायी आय (Yp) तथा
2. अस्थायी आय (Yt)

आय में अप्रत्याशित वृद्धि या कमी को हम अस्थायी आय कहते हैं। इसलिए अस्थायी आय धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अप्रत्याशित रूप से वर्ष में बोनस मिलना धनात्मक अस्थायी आय प्रदर्शित करता है लेकिन दूसरी ओर किसी आकस्मिक कारण से फैक्ट्री के बन्द हो जाने के कारण आय की हानि ऋणात्मक अस्थायी आय को प्रदर्शित करती है। फ्रीडमैन यह प्रतिपादित करते है कि इस प्रकार की आय की अप्रत्याशित कमी तथा वृद्धि दीर्घकाल में परस्पर निरस्त हो जाती है, लेकिन अल्पकाल में बनी रहती है। अतः

$$Ym = yp + Yt$$

इस प्रकार किसी वर्ष में मापित आय अस्थायी आय के व्यवहार के फलस्वरूप स्थायी आय से अधिक या कम हो सकती है। यदि Yt धनात्मक हुई तो $Ym > yp$ और यदि Yt ऋणात्मक रही हो तो $Ym < yp$, लेकिन यदि Ym तथा Yt बराबर हो तो अस्थायी आय शून्य (Yt) होगी।

इस प्रकार फ्रीडमैन मापित या वास्तविक उपभोग (Cm) को भी दो भागो में विभक्त करते हैं :

1. स्थायी उपभोग (Cp) तथा
2. अस्थायी उपभोग (Ct)

अस्थायी आय की ही तरह अस्थायी उपभोग भी उपभोग में अप्रत्याशित वृद्धि या कमी है। "डिस्काउन्ट सेल" योजना से आकृष्ट होकर किसी वस्तु का अप्रत्याशित रूप से क्रय धनात्मक अस्थायी उपभोग प्रदर्शित करेगा, जबकि कुकिंग गैस की अनुपलब्धता के कारण सामान्य रूप से उपभोग की जाने वाली वस्तु के उपभोग का स्थगन ऋणात्मक अस्थायी उपभोग प्रदर्शित करेगा। मापित आय की ही तरह मापित उपभोग भी अस्थायी उपभोग से अधिक या कम हो सकता है, इस प्रकार की स्थिति अस्थायी उपभोग के कारण होगी। अतः

$$Cm = Cp + Ct$$

काल श्रेणी आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर फ्रीडमैन इस निष्कर्ष पर आते है कि स्थायी उपभोग (Cp) तथा अस्थायी आय (Yp) के बीच आनुपातिक–सम्बन्ध है। इनके अनुसार चूँकि दीर्घकालीन में आय तथा उपभोग दोनों में ही अप्रत्याशित कमी तथा अप्रत्याशित वृद्धि परस्पर निरस्त हो जाते हैं। इसलिए स्थायी उपभोग आय का एक निश्चित भाग बना रहता है। स्थायी आय की मात्रा तथा ब्याज की दर कुल सम्पत्ति (जिसमें मानवीय तथा गैर–मानवीय सम्मिलित है) के अनुपात के रूप में गैर–मानवीय सम्पत्ति तथा रूचि के ऊपर निर्भर करती है। जहाँ तक रूचि की बात है, यह आयु तथा परिवार के ढ़ाँचे के ऊपर निर्भर करती है। स्पष्ट है, कि परिवार की इन विशिष्ट विशेषताओं के कारण स्थायी आय के समान होने के बावजूद भी परिवार के स्थायी उपभोग भिन्न हो सकते हैं। लेकिन यदि यह मान लिया जाए कि परिवार की ये विशेषताएँ आय के स्तर के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं तो यह माना जा सकता है कि स्थायी आय का औसत भाग वही बना रहेगा। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि परिवारों के विभिन्न आय स्तरों पर औसत बचत की प्रवृत्ति वहीं बनी रहेगी। इस तर्क के आधार पर फ्रीडमैन एक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण सामान्य धारणा से विरोधी बात प्रतिपादित करते है, "धनी तथा गरीब दोनों ही अपनी आय का एक ही भाग बचत पर लगाते है"। फ्रीडमैन इस बात के प्रतिपादन के सम्बन्ध में यह तर्क प्रस्तुत करते है कि बचत का प्रमुख उद्देश्य परिवार के लिए भावी उपभोग की व्यवस्था करना है। एक लम्बी अवधि के दौरान, जो जीवन अवधि से कम पर एक वर्ष से अधिक होगी परिवार के उपभोग को बराबर बनाये रखने के लिए ही बचत की जाती है। इस प्रकार का व्यवहार आय के

प्रत्येक स्तर पर परिवारों द्वारा किया जायेगा। इसलिए धनी तथा गरीब दोनों ही इस उद्देश्य के कारण अपनी आय का एक ही भाग बचत करेंगे। लेकिन बहुत लोग फ्रीडमैन की इस बात से सहमत नहीं हैं। उनका यह मत है कि यद्यपि यह मान भी लिया जाये कि धनी तथा गरीब दोनों ही परिवार के भावी उपभोग को बराबर बनाये रखने के लिए बचत करते हैं, चूँकि भावी उपभोग वस्तुओं के सम्बन्ध में वरीयता गरीब परिवार की अपेक्षा धनी परिवार में अधिक होगा, इसलिए गरीब परिवार अपनी अत्यन्त ही कम आय का उतना अनुपात बचत पर नहीं लगा पायेगा जितना धनी परिवार अपनी अत्यधिक आय का लगायेगा। फ्रीडमैन स्थायी उपभोग तथा स्थायी आय सम्बन्ध को इस रूप में व्यक्त करते है :

$$Cp = KYp - (o < K < 1)$$

जिसमें K स्थायी उपभोग (Cp) तथा स्थायी आय (Yp) के बीच आनुपातिक गुणांक है। दिये हुए आनुपातिक सम्बन्ध के साथ, समुदाय की दीर्घकालीन APC दीर्घकालीन MPC के बराबर होगी। गुणांक K सिद्धान्त में स्थिर नहीं है। इसमें जनसंख्या की आयु संरचना, ब्याज की दर तथा गैर–मानवीय आय व स्थायी आय के बीच अनुपात आदि के कारण परिवर्तन हो सकता है। इसलिए उपरोक्त समीकरण में प्रदर्शित उपभोग फलन को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है :

$$Cp = K(i,w,u)\ Yp$$

जिसमें i = ब्याज दर, W = गैर–मानवीय सम्पत्ति तथा Yp के बीच सम्बन्ध u = सम्पत्ति में लगाने की तुलना में उपभोग पर खर्च करने की प्रवृत्ति जो समुदाय की आयु संरचना पर निर्भर करेगी।

यद्यपि अनेक व्यवहारिक अध्ययनों ने मिल्टन फ्रीडमैन की आय परिकल्पना की पुष्टि की है, लेकिन अनेक अर्थशास्त्रियों ने इसकी कमजोरियों का उल्लेख किया तथा आलोचना की है। इसके सम्बन्ध में दी गयी आलोचनायें इस परिकल्पना में निहित प्रमुख रूप से दो मान्यताओं से सम्बन्धित हैं : उपभोग की औसत प्रवृत्ति (APC) के स्थिर होने की मान्यता तथा दूसरा स्थायी आय से सम्बन्धित उपभोग की सीमान्त प्रवृत्ति (MPC) के शून्य होने की मान्यता।

इरविन फ्रेण्ड तथा क्राविस ने APC के स्थिर होने की फ्रीडमैन की धारणा की आलोचना की तथा अपने अध्ययन के बाद यह दावा किया कि स्थायी आय की वृद्धि के साथ APC में गिरावट आती है। क्रेमिन, बर्ड एवं बॉड़किन, तौबमैन आदि ने अस्थायी आय

से सम्बन्धित MPC के शून्य होने की धारणा को चुनौती दी। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद भी स्थायी आय परिकल्पना की उपादेयता हैं [11]।

संक्षेप में फ्रीडमैन के अनुसार स्थायी उपभोग व स्थायी आय में स्थिर अनुपात है लेकिन अल्पकालीन आय व अल्पकालीन उपभोग में कोई सम्बन्ध नहीं है। इस हेतु उन्होंने 1857 के प्रारम्भ काल में इस श्रेणी के आंकड़े प्रस्तुत किये परन्तु स्थायी आय परिकल्पना की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने कटु आलोचना की।

2.5.4. जीवन स्तर में उपभोग का नियम – एंजिल :

एंजिल का उपभोग का नियम लगभग सभी विकसित एवं विकासशील देशों में सही पाया गया है। इसलिए इस नियम को सार्वजनिक नियम कहा जाता है। यह नियम जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एंजिल ने 1957 में सेक्सोनी नामक क्षेत्र में रहने वाले परिवारों का अध्ययन करके प्रस्तुत किया। उन्होंने इन परिवारों को तीन वर्गों में विभक्त किया। उच्च, मध्यम एवं निम्न या मजदूर वर्ग। इन तीनों वर्गों की आय एवं व्यय से सम्बंधित आकड़ों को एकत्रित करके निम्न निष्कर्ष निकाले :

(1) परिवार की कुल आय में वृद्धि होने पर भोजन इत्यादि खाद्य सामग्री पर किये जाने वाले व्यय के प्रतिशत में कमी आने लगती है। निम्न अथवा मजदूर वर्ग अपनी कुल आय का काफी बड़ा भाग खाद्य सामग्री पर ही व्यय करता हैं।

(2) सभी परिवार दो विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत आते हैं जो अपनी कुल आय का व्यय कपड़े, किराये, रोशनी, ईंधन आदि पर करते हैं, इनका प्रतिशत सभी आय–वर्गों के परिवारों में समान रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

(3) कुल आय में वृद्धि के साथ–साथ जीवन–स्तर में वृद्धि करने वाली मदों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन इत्यादि पर किये जाने वाले व्यय का प्रतिशत बढ़ता जाता है।

भारत के लिए एंजिल का नियम लगभग उतना ही सही है जैसा कि उन्होंने जर्मनी के लिए अनुभवगम्य तथ्यों से प्राप्त किया।

2.6 निष्कर्ष :

पिछले 100 वर्षों से विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आय, उपभोग सम्बन्ध का अध्ययन अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दृष्टि से किया है। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि अल्पकालीन उपभोग फलन आय से गैर–आनुपातिक होता है तथा दीर्घकालीन उपभोग फलन की आनुपातिक एवं गैर–आनुपातिक प्रवृत्तियों के मध्य विभिन्न अर्थशास्त्रियों में कुछ मतभेद पाया गया लेकिन आनुभाविक तथ्यों से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि दीर्घकालीन दृष्टि से आय एवं उपभोग में आनुपातिक सम्बन्ध होता है तथा यह अनुपात विभिन्न

अर्थशास्त्रियों ने 0.86 पर स्थिर माना है। इस प्रकार निरपेक्ष आय परिकल्पना जो कि आय एवं उपभोग में गैर आनुपातिक सम्बन्ध बताती है को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

2.7 संदर्भ सूची (References) :

1. Keynes, J. M. **(1936)**. The General Theory of Employment, Interest and Money. ***Harcourt, Brace and Company and Printed in the U.S.A. by the Polygraphic Company of America, New York***, 96-97.
2. Williams, F. M. and Zimmerman, C. C. **(1935)**. Studies of Family in the United States and Other Countries. ***Department of Agriculture, Miscellaneous Publication***, 223.
3. Stigler, G. J. **(1954)**. The Early History of Empirical Studies of Consumer Behaviour. ***The Journal of Political Economy***, LXII: 95-113.
4. Kuznets, S. **(1952)**. Proportion of Capital Formation to National Product. ***American Economic Review***, XLII: 507-526.
5. Brady D. S. and Friedman, R. D. **(1947)**. Savings and the Income Distribution. ***Studies in Income and Wealth, X, New York: National Bureau of Economic Research***, 247-265.
6. Duesenberry, J. S. **(1949)**. Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior. ***Cambridge, Mass.: Harvard University Press***.
7. Modigliani, F. **(1949)**. Fluctuations in the Saving-Income Ratio: A Problem in Economic Forecasting. ***Studies in Income and Wealth, XI, New York: National Bureau of Economic Research***, 371-441.
8. Tobin, J. **(1941)**. Relative Income, Absolute Income and Savings. In Money, Trade and Economic Growth. ***John Henry Williams, New York: Macmillan Co.***, 135-156.
9. Hamburger, W. **(1955)**. Consumption and Wealth. ***Unpublished Ph.D. Thesis at the University of Chicago, The Relation of Consumption to Wealth and the Wage Rate. Economerica***, XXIII: 1-17.
10. Klein, L. R. **(1951)**. Estimating Patterns of Savings Behaviour from Sample Survey Data. ***Econometrica***, XIX (4): 438-454.

11. Friedman, M. and Kuznets, S. **(1945)**. Income from Independent Professional Practice. ***New York: National Bureau of Economic Research***.
12. Modigliani, F. and Brumberg, R. **(1954)**. Utility Analysis and the Consumption Functions: An interpretation of Cross-Section Data. ***Post – Keynesian Economics, (Eds.) Kenneth K. Kurihara. New Brunswick: Rutgers University Press***, 383-436.
13. Pigou, A. C. **(1943)**. The Classical Stationary State. ***Economic Journal***, LIII: 343-351.
14. Goldsmith, R. W. **(1955)**. A Study of Saving in the United States. ***Princeton University Press, Princeton, New Jersey***, 1 & 2.
15. Smithies, A. **(1965)**. Forecasting Post-War Demand. ***Econometrica***.
16. Ando, A. and Modigliani, F. **(1963)**. The Life Cycle Hypothesis of Saving: Aggregated Implications and Tests. ***American Economic Review***, 53: 55-84.
17. Friedman, M. **(1957)**. A Theory of the Consumption Function. ***The National Bureau of Economic Research, Princeton University Press***.

*****

अध्याय – 3

आय–प्रवृत्तियाँ : विभिन्न आय–वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन

आय–प्रवृत्तियाँ : विभिन्न आय–वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन

आय, उपभोग करने के तरीकों का महत्त्वपूर्ण साधन है। प्रति व्यक्ति आय वह पैमाना है जिसके जरिये यह पता चलता है कि किसी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इससे किसी देश, शहर या क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रहन–सहन का स्तर और जीवन की गुणवत्ता का पता चलता है। देश की आमदनी में कुल आबादी का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है [1]।

व्यक्तिगत आय राष्ट्रीय उत्पादन की माप नहीं है क्योंकि इसमें अनेक ऐसी मदों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। अन्य शब्दों में, व्यक्तिगत आय में हम उत्पादक क्रियाओं अथवा आर्थिक सेवाओं द्वारा अर्जित आय तथा उन अन्य प्राप्तियों को भी सम्मिलित करते हैं जिनके बदले में व्यक्तियों द्वारा देश में कोई आर्थिक क्रिया अर्जित नहीं की जाती है। इसलिए व्यक्तिगत आय की संगणना करने के लिए राष्ट्रीय आय में से राष्ट्रीय आय के उस भाग को घटा दिया जाता है जिसे यद्यपि अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों ने आर्थिक क्रियाएं करके अर्जित तो किया है परन्तु जो व्यक्तियों को अर्जित साधन आय के रूप में प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार प्राप्त हुई आय राशि में उन व्यक्तिगत प्राप्तियों को जोड़ दिया जाता है जो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जाती है। अतः राष्ट्रीय आय में से निगम लाभों, सामाजिक बीमा हेतु नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के अंशदान आदि को घटाकर इसमें व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले सरकारी एवं व्यवसायिक हस्तान्तरण भुगतानों, व्यक्तियों को सरकार द्वारा भुगतान किया गया विशुद्ध ब्याज, उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्तियों को किया गया ब्याज भुगतान तथा लाभांश आदि को जोड़कर व्यक्तिगत आय को ज्ञात किया जाता है [2]।

व्यक्तिगत आय में वृद्धि होने के फलस्वरूप समाज के कुल भौतिक (आर्थिक) कल्याण में भी वृद्धि होती है। लेकिन व्यक्तिगत आय में वृद्धि सदैव समाज के लोगों में अधिक खुशहाली लाती है, यह सही नहीं है। आय में वृद्धि आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि करने के साथ–साथ लोगों में वस्तुओं के प्रति अनाशक्ति की भावना को पनपाती है। जैसा कि थोर्स्टीन वैब्लन ने कहा था कि "एक सम्पन्न समाज में लोगों का सन्तोष उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं में निहित उपयोगिता पर नहीं बल्कि समाज में उनके पद पर निर्भर करता है। एक अत्यधिक सम्पन्न समाज में व्यक्ति की निरपेक्ष आय का नहीं अपितु उसकी सापेक्ष आय का, अर्थात् आय संरचना में उसके स्थान का अधिक महत्त्व होता है" [3]।

भारत में आय का वितरण पश्चिमी देशों की तुलना में अधिक असमान है। निश्चित रूप से जागरूकता के प्रति अमीर एवं गरीबों के मध्य बहुत बड़ा अन्तर व्याप्त है। लेकिन

शायद यह एक दृष्टिभ्रम है। भारत में गरीबी इतनी व्यापक है कि वह आर्थिक विकास में बाधक है [4]।

किसी देश में आय की असमानता के कई आयाम हो सकते हैं। अर्थशास्त्री इस बात से चिन्तित है कि मुद्रा का असमान वितरण जो कि परिवारों की आय से सम्बन्धित है, यद्यपि यह सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य है और इसके अलावा आय में असमानता कौशल, शिक्षा, अवसर, खुशी, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, कल्याण, सम्पत्ति और सामाजिक गतिशीलता से भी सम्बन्धित है [5]। यहां आय में असमानता व्यक्तियों की वितरण की असमानता [6], घर या प्रति व्यक्ति आय निर्धारक तत्त्वों से निर्धारित होती है [7]।

लारेन्ज वक्र आय वितरण के आकार और आय में असमानता निर्धारक तत्त्व एवं गरीबी को मापने का एक मानक दृष्टिकोण है। यह वक्र कुल संचयी आय और संचयी आय प्राप्ति की इकाईयों के मध्य बनाया जाता है। लारेन्ज वक्र में दी हुई आय वितरण से विचरण को लारेन्ज वक्र के लिए दिये गये असमानता के सूचकांक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा आय में असमानता के अन्य निर्धारक तत्त्व हैं : विस्तार या सीमा, विचरण, विचरण–गुणांक, निरपेक्ष एवं सापेक्ष विचरण–गुणांक आदि [8]।

भारत सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति जागरूकता और सकारात्मक कार्यवाई करने के बावजूद भी अभी–भी सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान वाले वर्ग के लोग परम्परागत रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं तथा वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं [9]।

भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय में पर्याप्त असमानता व्याप्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं। अतः उनकी आय अस्थिर रहती है। जिस कारण उनका जीवन–स्तर का तरीका भी निम्न होता है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों का जीवन–स्तर का तरीका भी आय द्वारा प्रभावित होता है। वर्तमान में युवाओं की आय पिछले दशकों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा शिक्षित परिवारों जिनकी आय अधिक है, उनका जीवन–स्तर का तरीका कम शिक्षित एवं कम आय वाले परिवारों की तुलना में उच्च होता है [9]।

प्रस्तुत सर्वेक्षण का उद्देश्य आय नामक आर्थिक चर का दौसा जिले में विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह परीक्षण करना है कि दौसा जिले की पारिवारिक इकाईयों में आय की प्रवृत्ति कैसी है? तथा उनमें विगत वर्षों में

क्या–क्या परिवर्तन हुए हैं? इसके अतिरिक्त आय को कौन–कौन से कारक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं?

प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न आय–वर्गों की औसत मासिक आय एवं उनकी परस्पर तुलना, विभिन्न आय–वर्गों के मध्य आय विषमता, विभिन्न आय–वर्गों के वर्ष 2010 से 2014 तक आय सूचकांक, आयु–वर्ग एवं आय–स्तर का सम्बन्ध, कार्य के घन्टे एवं आय–स्तर का सम्बन्ध, आय के सहायक स्त्रोत, आय–स्तर एवं परिवार में आय–अर्जकों की संख्या, वर्तमान अर्जित आय एवं जीवन–स्तर के प्रति दृष्टिकोण, उच्च आय–वर्ग एवं आयकर की प्रवृत्ति का अध्ययन किया है।

सर्वेक्षण हेतु दौसा जिले के 500 परिवारों को आय वर्गों के अनुसार क्रमशः निम्न, निम्न–मध्यम, मध्यम एवं उच्च में बांटा हैं।

3.1 विभिन्न आय–वर्गों की औसत मासिक आय एवं उनकी परस्पर तुलना :

विभिन्न आय–वर्गों की औसत मासिक आय, मानक–विचलन एवं विचरण–गुणांक को सारणी 3.1 में दर्शाकर विभिन्न आय–वर्गों की परस्पर तुलना की हैं।

सारणी 3.1 में मुख्यतया दो बातों की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन किया हैं :

1. विभिन्न आय–वर्गों की औसत मासिक आय की तुलना दो वर्षों के मध्य करके, वर्ष 2014 में विभिन्न आय–वर्गों में औसत मासिक आय में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है।
2. प्रत्येक आय–वर्ग में निहित आय की विषमता की तुलना भी दो वर्षों को लेकर की है अर्थात् वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है तथा प्रत्येक आय–वर्ग में कितनी विषमता व्याप्त है।

अतः स्पष्ट है कि दौसा जिले की सामूहिक मासिक आय वर्ष 2010 में 15959.62 रू थी जो वर्ष 2014 में 27392.69 रू मासिक हो गयी अर्थात् विगत पांच वर्ष में आय में 71.64 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह वृद्धि निम्न आय वर्ग में 37.02 प्रतिशत ही रही तथा मध्यम वर्ग में यह वृद्धि सबसे अधिक 147.87 प्रतिशत रही। वर्ष 2010 में आय–वर्गों में आय की आंतरिक विषमता 38.58 प्रतिशत थी जो कम होकर वर्ष 2014 में 18.96 प्रतिशत रही।

सारणी : 3.1 विभिन्न आय–वर्गों की औसत मासिक आय एवं उनकी परस्पर तुलना।

आय–वर्ग	कुल परिवार	वर्ष 2010			वर्ष 2014			
		औसत मासिक आय	मानक विचलन	विचरण गुणांक	औसत मासिक आय	मानक विचलन	विचरण गुणांक	आय में प्रतिशत परिवर्तन
7500 रू मासिक से कम	200	3902.15	1280.72	32.82	5346.65	1629.98	30.49	37.02
7500 से 16000 रू मासिक	150	8567.69	2430.40	28.37	11954.11	2697.95	22.57	39.53
16000 से 80000रू मासिक	94	23908.44	11767.30	49.22	59261.69	16085.28	27.14	147.87
80000 रू से अधिक मासिक	56	65479.13	16545.24	25.27	93987.50	11723.45	12.46	43.54
योग	500		–	–		–	–	–
सामूहिक माध्य	–	15959.62	–	–	27392.69	–	–	71.64

3.2 विभिन्न आय–वर्गों के मध्य आय विषमता : सारणी 3.2 में विभिन्न आय–वर्गों में आन्तरिक आय विषमता का अध्ययन करके विभिन्न आय–वर्गों की तुलना की है।

सारणी 3.2 : विभिन्न आय–वर्गों के मध्य आय विषमता।

आय–वर्ग (मासिक)	परिवारों की संख्या (प्रतिशत)	परिवारों का संचयी प्रतिशत	2010 में कुल आय (प्रतिशत)	2010 का संचयी प्रतिशत	2014 में कुल आय (प्रतिशत)	2014 का संचयी प्रतिशत
7500 रू से कम	40	40	5.41	5.41	4.89	4.89
7500–16000 रू	30	70	14.67	20.08	13.68	18.57
16000–80000 रू	18.8	88.8	45.67	65.75	46.97	65.54
80000 रू से अधिक	11.2	100	34.25	100	34.46	100
योग	100	–	100	–	100	–

सारणी 3.2 में विभिन्न आय–वर्गों के मध्य कुल आय के वितरण की विषमता वर्ष 2010 व 2014 के मध्य आंकलित की गयी है और हमें यह देखना है कि विभिन्न आय–वर्गों में कितनी आर्थिक विषमता है तथा वर्ष 2010 से 2014 के मध्य आर्थिक विषमता में परिवर्तन किस प्रकार हुए हैं। स्पष्ट है कि वर्ष 2014 में निम्न आय वर्ग के 40 प्रतिशत परिवारों को कुल आय का केवल 4.89 प्रतिशत भाग ही मिलता है जबकि उच्च आय वर्ग के 11.2 प्रतिशत परिवारों को कुल आय का 34.46 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। इसी प्रकार की स्थिति वर्ष 2010 में पायी गयी है जिसमें निम्न आय वर्ग के 40 प्रतिशत परिवारों को कुल आय का केवल 5.41 प्रतिशत भाग ही मिलता है जबकि उच्च आय वर्ग के 11.2 प्रतिशत परिवारों को कुल आय का 34.25 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज में आर्थिक विषमता काफी मात्रा में विद्यमान है। विभिन्न आय–वर्गों के मध्य आय की विषमता का अध्ययन यदि वर्ष 2010 व 2014 को लेकर करें तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्ष 2014 में 2010 की अपेक्षा आर्थिक विषमता में वृद्धि हुई है। यह प्रवृत्ति सभी आय वर्गों में विद्यमान है।

लारेन्ज वक्र : विभिन्न आय–वर्गों के मध्य आर्थिक विषमता का अध्ययन सारणी 3.2 में प्रस्तुत समंकों की सहायता से लारेंज वक्र (रेखाचित्र 3.1) बनाकर किया है।

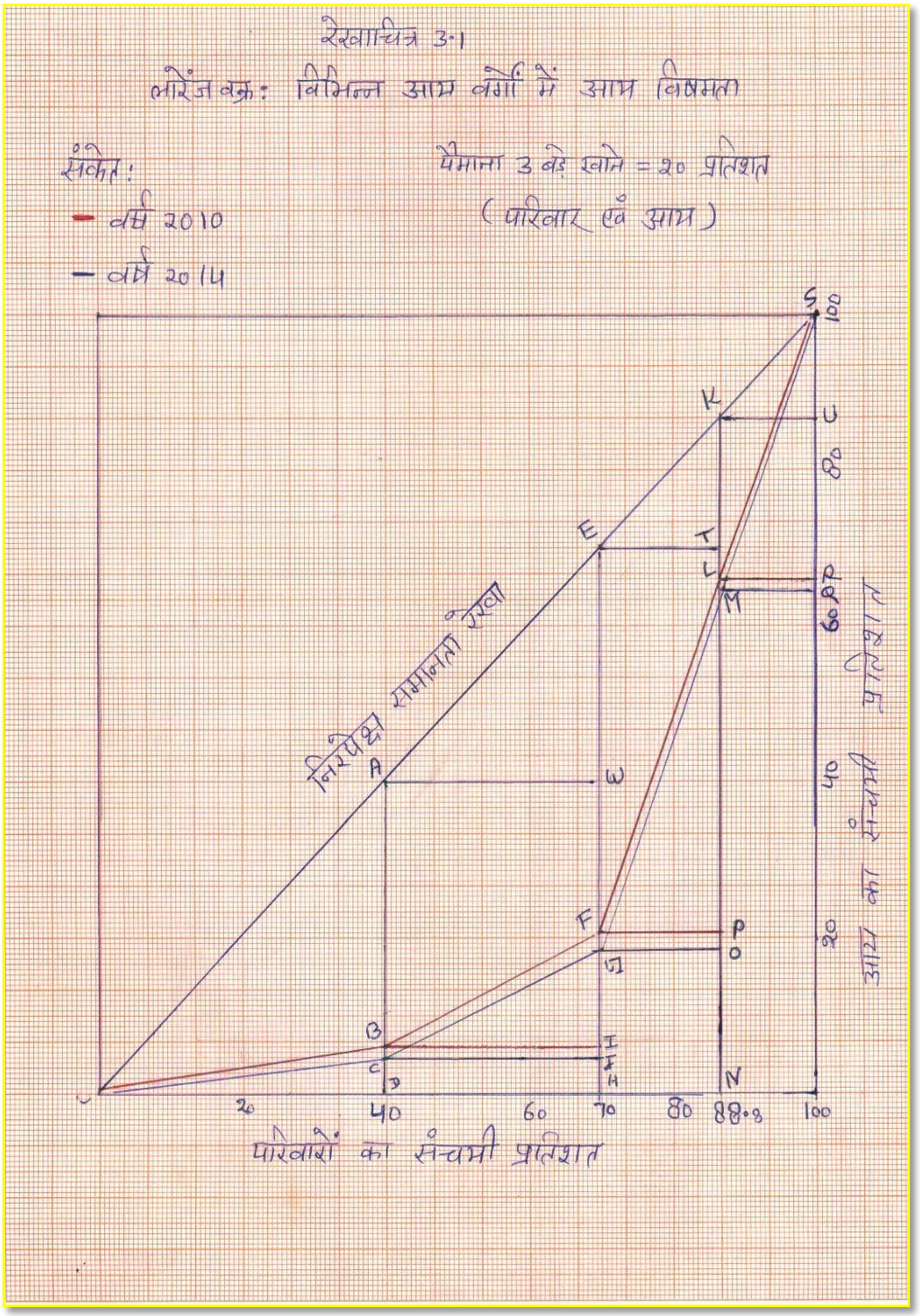

रेखाचित्र 3.1: लारेन्ज वक्र

रेखाचित्र 3.1 से निम्न तथ्य ज्ञात होते हैं। यहाँ रेखा OAEKS निरपेक्ष समानता रेखा है। रेखा OBFLS वर्ष 2010 तथा OCGMS रेखा वर्ष 2014 के लिए लारेंज वक्र है।

1. वर्ष 2010 में निम्न आय वर्ग को कुल आय का AD भाग मिलना चाहिए परन्तु उसे केवल BD भाग ही मिलता है। वर्ष 2014 में मात्र CD भाग ही मिलता है। इस प्रकार इस आय–वर्ग की पांच वर्षों में आय की विषमता में BC की वृद्धि हुई है।
2. निम्न–मध्यम आय वर्ग को आय का EH भाग मिलना चाहिए लेकिन वर्ष 2010 में उसे FI तथा वर्ष 2014 में GJ भाग मिलता है अर्थात् आय में वृद्धि IJ के समान हुई है।
3. मध्यम आय वर्ग को आय का LO भाग मिलना चाहिए परन्तु वर्ष 2010 में उसे LP भाग मिलता है तथा वर्ष 2014 में उसे NO भाग मिलता है। इस आय–वर्ग को पांच वर्षों में वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में आय का अधिक भाग मिलता है।
4. उच्च आय वर्ग को आय का SU भाग मिलना चाहिए, परन्तु वर्ष 2010 में उसे SR मिलता है व वर्ष 2014 में SQ भाग मिलता है, अर्थात् वर्ष 2010 में UR व वर्ष 2014 में UQ भाग अतिरिक्त मिलता है। अर्थात् पांच वर्षों में अतिरेक में वृद्धि RQ हुई है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निम्न आय वर्ग को जितना अंश मिलना चाहिए, उससे कम मिलता है। निम्न–मध्यम, मध्यम व उच्च आय वर्ग को जितना मिलना चाहिए, उससे भी अधिक मिलता है। लारेंज वक्र वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में निरपेक्ष समानता रेखा से अधिक दूरी पर चला गया है। सामूहिक रूप से देखने पर पता चलता है कि वर्ष 2010 से 2014 के दौरान आय की विषमताएँ बढ़ी हैं।

3.3 विभिन्न आय–वर्गों के वर्ष 2010 से 2014 तक आय सूचकांक : प्रस्तुत शोध में कुल चयनित 500 परिवारों के आय सम्बन्धी समंक विगत पांच वर्षों हेतु लिये हैं जो वर्ष 2010 से 2014 (पांच वर्षों) तक के हैं। इन पांच वर्षों में आय वृद्धि की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार रही तथा विभिन्न आय–वर्गों की उन विभिन्न वर्षों में प्रवृत्तियाँ आपस में कितनी भेदमूलक हैं। इन्हें ज्ञात करने के लिए विभिन्न वर्षों के आय सूचकांको को सारणी 3.3 में दर्शाया गया हैं। वर्ष 2010 की आय को आधार वर्ष मानकर विभिन्न अन्य वर्षों को चालू वर्षों में लिया है।

सारणी 3.3 से स्पष्ट है कि समग्र रूप से वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में आय में लगभग 67.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सारणी 3.3 : विभिन्न आय–वर्गों के वर्ष 2010 से 2014 तक आय सूचकांक (आधार वर्ष = 2010)।

आय–वर्ग (मासिक)	परिवारों की संख्या	वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2014
7500 रू से कम	200	100	120.95	126.61	133.22	137.02
7500–16000रू	150	100	119.46	123.77	130.51	139.53
16000–80000रू	94	100	120.88	125.76	230.69	247.87
80000रू से अधिक	56	100	119.93	124.38	128.09	143.54
समग्र स्थिति	–	100	120.31	125.13	155.63	166.99

सूचकांक में सर्वाधिक वृद्धि मध्यम आय वर्ग की आय में हुई है जो कि 147.87 प्रतिशत है व न्यूनतम वृद्धि निम्न आय वर्ग की आय में हुई है जो कि 37.02 प्रतिशत है।

3.4 आयु–वर्ग एवं आय–स्तर का सम्बन्ध : सारणी 3.4 में यह दर्शाया गया है कि विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में आय अर्जित करने वाले सदस्यों की आयु 30 वर्ष से कम, 30–40 वर्ष, 40–50 वर्ष, 50–60 वर्ष व 60 वर्ष से अधिक का प्रतिशत 18.20, 23.60, 27.60, 23.80 व 6.80 है।

सारणी 3.4 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में आय अर्जित करने वाले सदस्यों का आयु के अनुसार वटंन।

आयु–वर्ग (वर्ष में)	आय–वर्ग (मासिक)				योग	प्रतिशत
	7500 रू से कम	7500–16000 रू	16000–80000 रू	80000 रू से अधिक		
30 से कम	59 (29.50)	23 (15.34)	09 (9.57)	–	91	18.20
30 – 40	57 (28.50)	26 (17.33)	32 (34.04)	03 (5.36)	118	23.60
40 – 50	38 (19.00)	42 (28.00)	27 (28.73)	31 (55.36)	138	27.60
50 – 60	39 (19.50)	41 (27.33)	23 (24.47)	16 (28.57)	119	23.80
60 से अधिक	07 (3.50)	18 (12.00)	03 (3.19)	06 (10.71)	34	6.80
योग	200	150	94	56	500	100

प्रस्तुत सारणी में 40–50 आयु–वर्ग वाले आय अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या सर्वाधिक 138 है।

3.5 कार्य के घन्टे एवं आय–स्तर का सम्बन्ध : क्या कार्य के घन्टों एवं आय–स्तर में कोई धनात्मक सह–सम्बन्ध है? क्या उच्च आय–वर्ग को अधिक आय अर्जित करने के लिए उन वर्गों की तुलना में अधिक कार्य करना पड़ता है जिनकी आय अपेक्षाकृत कम है? इस सम्बन्ध को सारणी 3.5 में बताया गया है।

सारणी 3.5 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में कार्य के घन्टे एवं आय स्तर का सम्बन्ध।

आय–वर्ग (मासिक)	कार्य के घण्टे			योग	प्रतिशत
	0 – 6	6 – 10	10 से अधिक		
7500 रू से कम	–	175	25	200	–
प्रतिशत	–	(87.5)	(12.50)	–	–
7500–16000 रू	23	99	28	150	–
प्रतिशत	(15.33)	(66.00)	(18.67)	–	–
16000–80000 रू	13	76	05	94	–
प्रतिशत	(13.82)	(80.85)	(5.34)	–	–
80000 रू से अधिक	24	28	04	56	–
प्रतिशत	(42.85)	(50.00)	(7.14)	–	–
योग	60	378	62	500	–
प्रतिशत	12	75.6	12.4	–	100

उपरोक्त सारणी 3.5 से स्पष्ट है कि अधिकांश व्यक्ति 6 से 10 घंटे ही प्रतिदिन कार्य करते हैं, चाहें वे किसी भी आय–वर्ग में हो जो कि 75.60 प्रतिशत है। मात्र 12.40 प्रतिशत व्यक्ति ही ऐसे है जिन्हें अपेक्षाकृत 10 घंटे से अधिक कार्य करना पड़ता है। इसमें मुख्यतया व्यापारी वर्ग शामिल है जो स्वतः ही अधिक कार्य करते हैं।

3.6 आय के सहायक स्त्रोत : प्रस्तुत शोध में प्रत्येक सर्वेक्षित परिवार से आय–अर्जन के मुख्य स्त्रोतों के अतिरिक्त सहायक स्त्रोतों की भी जानकारी ली है। सामान्यतः व्यक्ति औसतन रूप से 08 घण्टे ही कार्य करता है। क्या अपनी आय वृद्धि के लिए परिवारों ने कोई सहायक स्त्रोत अपना रखे हैं यदि हाँ तो कितने परिवारों ने किस प्रकार के सहायक

स्त्रोत अपना रखे हैं यदि कोई सहायक स्त्रोत नहीं अपना रखे है तो इसके कौन से कारण हैं, उनका विवरण सारणी 3.6 में निम्नानुसार है :

सारणी 3.6 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में आय के सहायक स्त्रोत।

आय–वर्ग (मासिक)	आय के सहायक स्त्रोत		योग
	हाँ	नहीं	
7500 रू से कम	11	189	200
प्रतिशत	(5.50)	(94.50)	–
7500–16000 रू	08	142	150
प्रतिशत	(5.33)	(94.67)	–
16000–80000 रू	20	74	94
प्रतिशत	(21.27)	(78.73)	–
80000 रू से अधिक	14	42	56
प्रतिशत	(25)	(75)	–
योग	53	447	500
प्रतिशत	10.60	89.40	100

उक्त सारणी 3.6 से पता लगता है कि कुल सर्वेक्षित परिवारों का केवल 10.60 प्रतिशत भाग ही आय के सहायक स्त्रोतों में संलग्न हैं। 89.40 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मुख्य आय स्त्रोतों के अतिरिक्त अन्य कोई स्त्रोत नहीं अपना रखा है। यदि हम विभिन्न आय–वर्गों की तुलना करें तो स्थिति स्पष्ट है कि जैसे–जैसे पारिवारिक इकाई निम्न आय वर्ग से उच्च आय वर्ग में प्रवेश करती है वैसे–वैसे सहायक स्त्रोतों को अपनाने वाले परिवारों का प्रतिशत बढ़ता जाता है।

उन परिवारों ने जिन्होंने किसी भी प्रकार का सहायक स्त्रोत नहीं अपना रखा है उनके सम्बन्ध में दो प्रकार के प्रश्न सामने आते हैं। **प्रथम** या तो वे वर्तमान आय स्तर से ही सन्तुष्ट हैं तथा **द्वितीय** उनके समक्ष कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनके कारण वे सहायक स्त्रोत अपनाने में सक्षम नहीं हैं।

सहायक स्त्रोत न अपना सकने के लिए जो कारण सर्वेक्षित परिवारों ने अभिव्यक्त किये हैं वे निम्न हैं : अ) सन्तुष्ट; ब) समय का अभाव; स) वित्तीय कठिनाईयाँ; द) अरूचि/अन्य (इन्हें सारणी 3.7 में दर्शाया है)।

सारणी 3.7 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में आय के सहायक स्त्रोत न अपना सकने के कारण।

आय–वर्ग (मासिक)	सहायक स्त्रोत न अपना सकने के कारण				योग
	सन्तुष्ट	समय का अभाव	वित्तीय कठिनाई	अन्य	
7500 रू से कम	55	56	89	–	200
प्रतिशत	(27.50)	(28.00)	(44.50)	–	–
7500–16000 रू	75	25	50	–	150
प्रतिशत	(50.00)	(16.67)	(33.33)	–	–
16000–80000 रू	76	13	05	–	94
प्रतिशत	(80.85)	(13.83)	(5.32)	–	–
80000 रू से	56	–	–	–	56
अधिक प्रतिशत	(100)	–	–	–	–
योग	262	94	144	–	500
प्रतिशत	52.40	18.80	28.80	–	100

उपरोक्त सारणी 3.7 में सर्वेक्षित पारिवारिक इकाइयों का उनके द्वारा अर्जित आय के प्रति दृष्टिकोण दर्शाया गया है। क्या वे वर्तमान आय से सन्तुष्ट हैं या नहीं? यदि असन्तुष्ट हैं तो आय अर्जित करने हेतु सहायक स्त्रोतों को अपनाने में उन्हें किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, इत्यादि को सारणी में प्रदर्शित किया गया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों का 52.40 प्रतिशत भाग वर्तमान आय से सन्तुष्ट है जबकि 47.60 प्रतिशत परिवार अपनी वर्तमान आय से असन्तुष्ट हैं। उनकी यह धारणा है कि वर्तमान में बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्राप्त आय से परिवार का भरण–पोषण भली प्रकार नहीं हो सकता है। जो परिवार वर्तमान अर्जित आय से असन्तुष्ट हैं, उन्होंने सहायक स्त्रोत न अपनाने का मुख्य कारण वित्तीय कठिनाइयों को माना है। 28.80 प्रतिशत परिवार वित्तीय कठिनाइयों को मानते हैं। निम्नतम आय वर्ग में तो सहायक स्त्रोत न अपनाने का कारण वित्तीय कठिनाई को ही माना है। 18.80 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो सहायक स्त्रोत न अपनाने में समय का अभाव मानते हैं।

3.7 आय–स्तर एवं परिवार में आय अर्जकों की संख्या : सर्वेक्षण में इस तथ्य की जानकारी सर्वेक्षित परिवारों द्वारा ली गई कि क्या उच्च आय वर्ग में आय अर्जकों की संख्या अपेक्षाकृत अन्य आय–वर्गों से अधिक है या नहीं। सारणी 3.8 में विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में आय अर्जकों की संख्या दर्शायी गई है।

अनुपात के अनुसार लगभग 224 परिवार ही ऐसे हैं जिनमें आय अर्जक एक से अधिक हैं। चूंकि दौसा जिले में छोटे–छोटे कुटीर उद्योग प्रचलित है तथा अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा घरेलू कुटीर उद्योग चलाये जाते हैं। अतः उस परिवार से सम्बन्धित व्यवसाय को ही परिवार के अन्य सदस्य अपना लेते हैं अथवा उसमें हाथ बटाते हैं। 276 परिवारों में आय अर्जक के रूप में केवल एक ही सदस्य मुखिया के रूप में है, उनके बच्चे या तो अध्ययनरत हैं या उन्हें किसी प्रकार का कार्य मिला हुआ नहीं है। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों तथा घरेलू कामकाज में व्यस्तता के कारण अधिकांश महिलाएं सामान्यतः कार्य करने हेतु घर से बाहर नहीं जाती हैं।

सारणी 3.8 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में आय अर्जकों की संख्या।

आय अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या	आय–वर्ग (मासिक)				योग	प्रतिशत
	7500 रू से कम	7500–16000 रू	16000–80000 रू	80000 रू से अधिक		
1	110 (55.00)	98 (65.33)	43 (45.74)	25 (44.64)	276	55.20
2	78 (39.00)	31 (20.67)	32 (34.04)	19 (33.93)	160	32.00
3	09 (4.50)	12 (8.00)	17 (18.09)	09 (16.07)	47	9.40
4	03 (1.50)	09 (6.00)	02 (2.13)	03 (5.36)	17	3.40
योग	200	150	94	56	500	100

3.8 वर्तमान अर्जित आय एवं जीवन–स्तर के प्रति दृष्टिकोण : सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षित इकाईयों से ही उनके द्वारा अर्जित आय से वर्तमान स्तर के अनुसार जीवन–स्तर के प्रति दृष्टिकोण की जांच की गयी। सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित तथ्यों से प्राप्त परिणाम को सारणी 3.9 में दर्शाया गया हैं।

सारणी 3.9 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में जीवन स्तर के प्रति दृष्टिकोण।

आय–वर्ग (मासिक)	जीवन–स्तर			योग
	उच्च	मध्यम	निम्न	
7500 रू से कम	–	06	194	200
प्रतिशत	–	(3.00)	(97.00)	–
7500–16000 रू	–	15	135	150
प्रतिशत	–	(10.00)	(90.00)	–
16000–80000 रू	–	89	05	94
प्रतिशत	–	(94.68)	(5.32)	–
80000 रू से अधिक	49	07	–	56
प्रतिशत	(87.50)	(12.50)	–	–
योग	49	117	334	500
प्रतिशत	9.80	23.40	66.80	100

कुल 500 परिवारों में से केवल 9.80 प्रतिशत परिवार ही अपने जीवन–स्तर को उच्च मानते हैं जबकि 23.40 प्रतिशत परिवार अपने जीवन–स्तर को मध्यम मानते हैं एवं 66.80 प्रतिशत परिवार अपने जीवन–स्तर को निम्न मानते हैं। निम्नतम आय–वर्ग के लगभग सभी परिवार अपने जीवन–स्तर को निम्न मानते हैं। निम्न–मध्यम आय वर्ग के 90.00 प्रतिशत परिवार अपने जीवन–स्तर को निम्न ही मानते हैं तथा मध्यम आय वर्ग के 94.68 प्रतिशत परिवार अपने जीवन–स्तर को मध्यम ही मानते हैं।

उक्त सारणी से प्राप्त तथ्य भारतीय निर्धनता–रेखा से नीचे रहने वाले प्रतिशत परिवारों अथवा जनसंख्या का समर्थन करते हैं। वर्तमान में लगभग 26.00 प्रतिशत जनसंख्या निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं। दौसा जिले में रहने वाले 66.80 प्रतिशत परिवार अपने जीवन–स्तर को निर्धनता रेखा से नीचे मानते हैं।

3.9 उच्च आय–वर्ग एवं आयकर की प्रवृत्ति : प्रस्तुत शोध में निर्धारित चार आय–वर्गों में से मध्यम तथा उच्च आय वर्ग ही आयकर की सीमा में आते हैं। उच्च आय वर्ग के सर्वेक्षित समस्त परिवारों की आय इतनी है कि उन्हें आयकर चुकाना पड़ता है। इस वर्ग में 11.20 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो कि आयकर देते हैं। इसी प्रकार मध्यम आय वर्ग के

अधिकांश चयनित परिवार कर चुकाते हैं। निम्न व निम्न–मध्यम आय वर्ग के सर्वेक्षित परिवारों में से कोई भी आयकर नहीं देता है।

3.10 निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध में दौसा जिले के विभिन्न आय वर्ग वाले कुल चयनित 500 परिवारों के आय सम्बन्धी समंक विगत पांच वर्षों हेतु लिये हैं, जो वर्ष 2010 से 2014 के हैं। विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की आय प्रवृत्ति की विषमता का तुलनात्मक अध्ययन औसत मासिक आय, मानक–विचलन एवं विचरण–गुणांक से ज्ञात करके किया है।

दौसा जिले में सर्वेक्षित परिवारों में से लगभग 70.00 प्रतिशत परिवार निम्न एवं निम्न–मध्यम आय वर्ग सीमा में आते हैं। जिनकी औसत मासिक आय 8318 रू के लगभग है जो मुद्रास्फीति के इस समय में कम प्रतीत होती है। विगत पांच वर्षों में दौसा जिले के निवासियों की आय में लगभग 55.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

दौसा जिले में आय विषमता की स्थिति काफी अधिक पायी गई है। निम्नतम आय–वर्ग के 40.00 प्रतिशत परिवारों को कुल आय का जहां वर्ष 2010 में 5.41 प्रतिशत भाग प्राप्त हो रहा था वहां वर्ष 2014 में यह भाग 4.89 प्रतिशत रह गया, जबकि उच्चतम आय वर्ग के 11.20 प्रतिशत परिवारों को जहां वर्ष 2010 में कुल आय का 34.25 प्रतिशत भाग प्राप्त हो रहा था वहां वर्ष 2014 में बढ़कर यह भाग 34.46 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार वर्ष 2010 की अपेक्षा 2014 में आर्थिक विषमता में और भी अधिक वृद्धि हुई है।

प्रस्तुत सर्वेक्षण में यह पाया गया कि लगभग 224 परिवार ही ऐसे हैं जिनमें आय अर्जकों की संख्या एक से अधिक है तथा 40–50 आयु वर्ग वाले आय अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या सर्वाधिक 138 है एवं अधिकांश व्यक्ति 6 से 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, चाहे वे किसी भी आय वर्ग में हो जिसका प्रतिशत 75.60 है।

कुल सर्वेक्षित परिवारों का 52.40 प्रतिशत परिवार अर्जित वर्तमान आय से सन्तुष्ट है जबकि 47.60 प्रतिशत परिवार अपनी वर्तमान आय से असन्तुष्ट हैं। वे यह मानते हैं कि वर्तमान में बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्राप्त आय से परिवार का भरण–पोषण भली प्रकार नहीं हो सकता है। जो परिवार वर्तमान अर्जित–आय से असन्तुष्ट हैं वे सहायक स्त्रोत न अपनाने का मुख्य कारण वित्तीय कठिनाइयों तथा समय के अभाव को मानते हैं।

दौसा जिले के 89.40 प्रतिशत परिवारों के पास आय का कोई सहायक स्त्रोत नहीं है। मात्र 10.60 प्रतिशत परिवार ही ऐसे है जिनके पास आय के सहायक स्त्रोत हैं।

सर्वेक्षित परिवारों में से 66.80 प्रतिशत परिवार अपने जीवन–स्तर को निम्न मानते हैं। वे अपने आय स्तर को वर्तमान महंगाई के युग में पर्याप्त नहीं मानते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते है कि दौसा जिले के विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की आय–प्रवृत्ति में विषमता व्याप्त है।

3.11 संदर्भ सूची (References) :

1. Ackley, G. **(1961)**. Macroeconomic Theory. ***Macmillan and Co., London***.
2. Shapiro, E. **(1984)**. Macroeconomic Analysis. ***(Eds. V) Galgotia Publication, New Delhi***.
3. Pigou, A. C. **(1932)**. The Economics of Welfare. ***(Eds. IV) Macmillan and Co., London***.
4. Datt, G. and Ravallion, M. **(1992)**. Growth and Redistribution Components of Changes in Poverty Measures: A Decomposition with Applications to Brazil and India in the 1980. ***Journal of Development Economics***, 38: 275-295.
5. Subramanian, S. **(1997)**. Measurement of Inequality and Poverty. ***Oxford University Press***.
6. Cowell, F. A. **(2000)**. Measurement of Inequality. ***Handbook of Income Distribution, North Holland***, 87-166.
7. Heshmati, A. **(2004a)**. Inequalities and their Measurement. ***IZA Discussion Paper***, 1219.
8. Anand, S. **(1997)**. The Measurement of Income Inequality, Measurement of Inequality and Poverty. ***Oxford University Press***, 81-105.
9. Datt, G. and Ravallion, M. **(1997)**. Why have some Indian States done Better than others at Reducing Rural Poverty? ***Econommica***, 65 (1): 17-38.

*****

अध्याय – 4

उपभोग–प्रवृत्तियाँ : विभिन्न आय–वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन एवं उपभोग निर्धारक कारक

उपभोग–प्रवृत्तियाँ : विभिन्न आय–वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन

उपभोग एक समाज या समुदाय की आर्थिक विकास की उस स्थिति को दर्शाता है कि वह वित्तीय स्थिति की सीढ़ी में कहाँ खड़ा है। एक ऐसे समाज की आर्थिक स्थिति प्रति व्यक्ति आय, जीवन–स्तर एवं उपभोग के स्तर द्वारा मुख्य रूप से निर्धारित होती है। जीवन–स्तर के विभिन्न वृहद् एवं सूक्ष्म संकेताक आर्थिक विकास के आयाम हैं। आर्थिक विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय वृहद् संकेताक हैं जबकि घरेलू खर्च का वितरण सूक्ष्म स्तर का सूचक है।

किसी परिवार का जीवन–स्तर उपभोग करने के तरीके एवं खपत की गुणवत्ता के आधार पर घर के कल्याण के स्तर को स्पष्ट करता है। किसी भी देश की प्रगति और व्यक्तिगत प्रगति मुख्य रूप से घर के भोजन के उपभोग पर निर्भर करती है [1]।

मानव–जीवन, अंततः अनवरत एवं पोषित उपभोग व्यय द्वारा ही होता है। 20 वीं सदी में विश्व की खपत तेज गति से बढ़ रही है। इस खपत का लाभ दूर–दूर तक फैल गया है। पहले की तुलना में अब अधिक से अधिक लोगों को घर की सुविधा एवं बेहतर भोजन खिलाया जा रहा है। अतः जीवन–स्तर में वृद्धि हो रही है। ये उपलब्धियाँ मानव के विकास को उपभोग व्यय के द्वारा होना बताती हैं। स्पष्ट रूप से खपत दूसरों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले मानव के विकास में योगदान देती है, लेकिन आज यह सम्बन्ध टूटता जा रहा है क्योंकि विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की आय अलग–अलग होने के कारण उच्च आय वर्ग वाले परिवार खपत अधिक करते हैं जबकि गरीब या निम्न आय वर्ग वाले परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपभोग व्यय नहीं कर पाते हैं। जो कि मानव के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है [2]।

आज मानव के विकास के लिए उपभोग व्यय करने के तरीकों में बदलाव जरूरी है। हम सभी के विकास के लिए उपभोक्ता की पसन्द को वास्तविकता में बदलनी चाहिए। खपत बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, मानव–क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, सामाजिक जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए एवं अच्छे भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए [3]।

यद्यपि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन अवधियों में आय उपभोग–व्यय का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निर्धारक है, परन्तु कुल परिसम्पत्ति, नकद परिसम्पत्ति, आय का वितरण, ब्याज की दर, सापेक्ष कीमतें, पूँजीगत लाभ, उपभोक्ता ऋण सुविधाएं, मुद्रा–भ्रमजाल, व्यक्तिगत उपभोग्य आय, मजदूरी एवं परिसम्पत्ति द्वारा प्राप्त आय का अनुपात, स्थगित माँग आदि अनेक चर भी उपभोग को प्रभावित करते हैं [4]।

प्रस्तुत अध्याय उपभोग प्रवृत्तियों से सम्बन्धित है। दौसा जिले की पारिवारिक इकाइयों की औसत उपभोग प्रवृत्तियाँ विभिन्न आय–वर्गों के अनुसार किस प्रकार की रही है? तथा विगत वर्षों में उपभोग का स्तर किस प्रकार बढ़ा है? इत्यादि प्रश्नों से सम्बन्धित तथ्य प्रस्तुत अध्याय में दिये गये हैं। इस अध्याय में विभिन्न आय–वर्गों का औसत मासिक उपभोग एवं उनकी परस्पर तुलना, उपभोग–विषमता, वर्ष 2010 से 2014 तक उपभोग–सूचकांक, उपभोग–व्यय का औसत मासिक प्रतिशत, विभिन्न मदों पर व्यय के औसत प्रतिशत की वर्ष 2010 व 2014 में तुलना, औसत व सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति, विभिन्न मदों पर व्यय की औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC), प्रतीपगमन समीकरण, आय दुगनी होने पर विभिन्न उपभोग मदों पर व्यय, वर्तमान उपभोग स्तर से सन्तुष्टि एवं असन्तुष्टि के कारण, उपभोग पर प्रदर्शन प्रभाव एवं उपभोग निर्धारक कारकों (सामाजिक स्थिति, शिक्षा स्तर, आश्रित सदस्यों की संख्या, सम्पत्ति, रोजगार एवं प्रवर्जन) का विश्लेषण किया है जो हमारे सर्वेक्षण विषय को अधिक व्यवहारिक एवं विश्लेषणात्मक रूप प्रदान करते है।

4.1 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों का औसत मासिक उपभोग एवं उनकी परस्पर तुलना : सर्वप्रथम चारों आय–वर्गों की सर्वेक्षित पारिवारिक इकाइयों के मध्य उपभोग स्तर की तुलना एवं विभिन्न आय–वर्गों में अन्तर्निहित विषमता की जांच करके वर्गों में निहित विषमता की तुलना प्रस्तुत की है। सारणी 4.1 में प्रत्येक आय वर्ग के औसत मासिक उपभोग तथा विभिन्न आय–वर्गों से सम्बन्धित औसत मासिक उपभोग में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाया गया है।

सारणी 4.1 में मुख्यतया दो बातों की तुलनात्मक स्थिति का अध्ययन किया गया है :

1. विभिन्न आय–वर्गों की औसत मासिक उपभोग की तुलना दो वर्षों के मध्य करके वर्ष 2014 में विभिन्न आय–वर्गों में औसत मासिक उपभोग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है?
2. प्रत्येक आय–वर्ग में निहित उपभोग की विषमता की तुलना भी दो वर्षों को लेकर की है अर्थात् वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? तथा प्रत्येक वर्ग में कितनी विषमता व्याप्त है?

सारणी 4.1: विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की औसत मासिक उपभोग एवं उनकी परस्पर तुलना ।

आय–वर्ग (मासिक)	कुल परिवार	औसत मासिक उपभोग 2010	औसत मासिक उपभोग 2014	उपभोग में प्रतिशत परिवर्तन	2010		2014	
					प्रमाप विचलन	विचरण गुणांक	प्रमाप विचलन	विचरण गुणांक
7500 रू से कम	200	3666.68	5304.63	44.67	3954.18	107.84	3911.68	73.74
7500–16000 रू	150	6204.58	10278.42	65.65	4993.59	80.48	7877.49	76.64
16000–80000 रू	94	11471.26	19288.86	68.15	10984.89	95.76	18485.86	95.84
80000 रू से अधिक	56	25086.93	36981.21	47.41	15176.49	60.50	25624.84	69.29
सामूहिक माध्य	500	8294.38	12973.58	56.41	–	–	–	–

स्पष्ट है कि दौसा जिले का सामूहिक मासिक उपभोग वर्ष 2010 में 8294.38 रू था जो वर्ष 2014 में बढ़कर 12973.58 रू मासिक हो गया। अतः विगत पांच वर्ष में उपभोग में 56.41 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह वृद्धि निम्न आय वर्ग में 73.74 प्रतिशत रही तथा उच्च आय–वर्ग में 69.29 प्रतिशत ही रही जो कि अन्य आय–वर्गो की तुलना में कम है साथ ही मध्यम वर्ग में यह वृद्धि सबसे अधिक 95.84 प्रतिशत रही।

4.2 विभिन्न आय–वर्गों के मध्य उपभोग विषमता : सारणी 4.2 विभिन्न आय–वर्गों के मध्य वर्ष 2010 तथा 2014 में उपभोग विषमता की स्थिति को बताती है।

सारणी 4.2 : विभिन्न आय–वर्गों के मध्य उपभोग विषमता।

आय–वर्ग (मासिक)	परिवारों की संख्या		कुल उपभोग (वर्ष)			
			2010	2010	2014	2014
	प्रतिशत	संचयी प्रतिशत	प्रतिशत	संचयी प्रतिशत	प्रतिशत	संचयी प्रतिशत
7500 रू से कम	40	40	7.90	7.90	7.38	7.38
7500–16000 रू	30	70	13.36	21.26	14.31	21.69
16000–80000 रू	18.8	88.8	24.71	45.97	26.84	48.53
80000 रू से अधिक	11.2	100	54.03	100.00	51.47	100.00
योग	100.00	–	100.00	–	100.00	–

प्रस्तुत सारणी 4.2 यह दर्शाती है कि वर्ष 2010 व 2014 दोनों ही वर्षों में पारिवारिक इकाइयों में उपभोग–विषमता काफी मात्रा में विद्यमान है। वर्ष 2010 में निम्नतम आय–वर्ग के 40.00 प्रतिशत परिवारों को कुल उपभोग का मात्र 7.90 प्रतिशत भाग ही प्राप्त होता हैं। ऐसी ही स्थिति निम्न–मध्यम आय वर्ग की है। मध्यम एवं उच्च आय वर्ग उपभोग का अपेक्षाकृत अधिक हिस्सा प्राप्त करता है। उच्च आय–वर्ग के 11.20 प्रतिशत परिवार कुल उपभोग का वर्ष 2010 में 54.03 प्रतिशत भाग प्राप्त करते हैं। यदि विभिन्न आय–वर्गों की तुलना वर्ष 2010 व 2014 में उपभोग व्यय में परिवर्तन को लेकर करें तो यह स्पष्ट होता है कि इन पांच वर्षों में निम्न एवं निम्न–मध्यम आय वर्ग का उपभोग वर्ष 2014 में क्रमशः 7.38 एवं 14.31 प्रतिशत रहा जो कि वर्ष 2010 की तुलना में अपेक्षाकृत निम्न आय वर्ग में कम है तथा निम्न–मध्यम आय वर्ग में अधिक है। जबकि मध्यम आय–वर्ग की स्थिति वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2014 में अपेक्षाकृत बढ़ी है। उच्च आय वर्ग का उपभोग स्तर लगभग 2.56 प्रतिशत कम रहा। वर्ष 2010 व 2014 के बीच विभिन्न आय–वर्गों के

मध्य उपभोग स्तर के विषमता की तुलना आगे दर्शाये गये लारेन्ज वक्र द्वारा स्पष्ट की गयी है।

लारेंज वक्र : रेखा चित्र 4.1 में लारेंज वक्र द्वारा उपभोग वितरण में विषमता को दर्शाया गया है। रेखाचित्र 4.1 से निम्न तथ्य ज्ञात होते हैं। यहां रेखा OAELU निरपेक्ष समानता रेखा हैं। रेखा OBFMU वर्ष 2010 तथा OCGNU रेखा वर्ष 2014 के लिए लारेंज वक्र हैं।

1. निम्न आय वर्ग को AD उपभोग का भाग मिलना चाहिए परन्तु यह वर्ष 2010 में BD व वर्ष 2014 में केवल CD भाग ही उपभोग कर पाते हैं। इस प्रकार उन्हें जो मिलना चाहिए वह भाग नहीं मिलता और पांच वर्षों में यह विषमता BC मात्रा में बढ़ गई है।
2. निम्न–मध्यम आय वर्ग को EH भाग उपभोग हेतु मिलना चाहिए था परन्तु वर्ष 2010 में यह वर्ग FI व वर्ष 2014 में GJ भाग प्राप्त करता है। इस वर्ग को भी पर्याप्त से कम भाग प्राप्त होता है। विषमता IJ बढ़ी है।
3. मध्यम आय वर्ग को LO भाग उपभोग हेतु मिलना चाहिए परन्तु उसे वर्ष 2010 में MP एवं वर्ष 2014 में NQ भाग मिल रहा है। इस वर्ग को पर्याप्त से अधिक मिल रहा है। यहां विषमता PQ के बराबर रही।
4. उच्च आय वर्ग को उपभोग का UV भाग मिलना चाहिए परन्तु वर्ष 2010 में उसे US व वर्ष 2014 में UT मिलता है, अर्थात् वर्ष 2010 में VS व वर्ष 2014 में VT अतिरिक्त मिलता है। विषमता ST के समान रही है।

इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में सामूहिक रूप से यह कह सकते हैं कि उपभोग के रूप में विषमता बढ़ी है क्योंकि वर्ष 2014 का लारेंज वक्र निरपेक्ष समानता रेखा से वर्ष 2010 की अपेक्षा अधिक दूर चला गया है। वर्गानुसार देखने पर प्रतीत होता है कि निम्न तथा निम्न–मध्यम आय वर्ग को उनकी संख्या के अनुपात से कम उपभोग करने को मिलता है तथा मध्यम व उच्च आय–वर्गों को उनके परिवारों की संख्या के अनुपात से अधिक उपभोग करने को मिलता है।

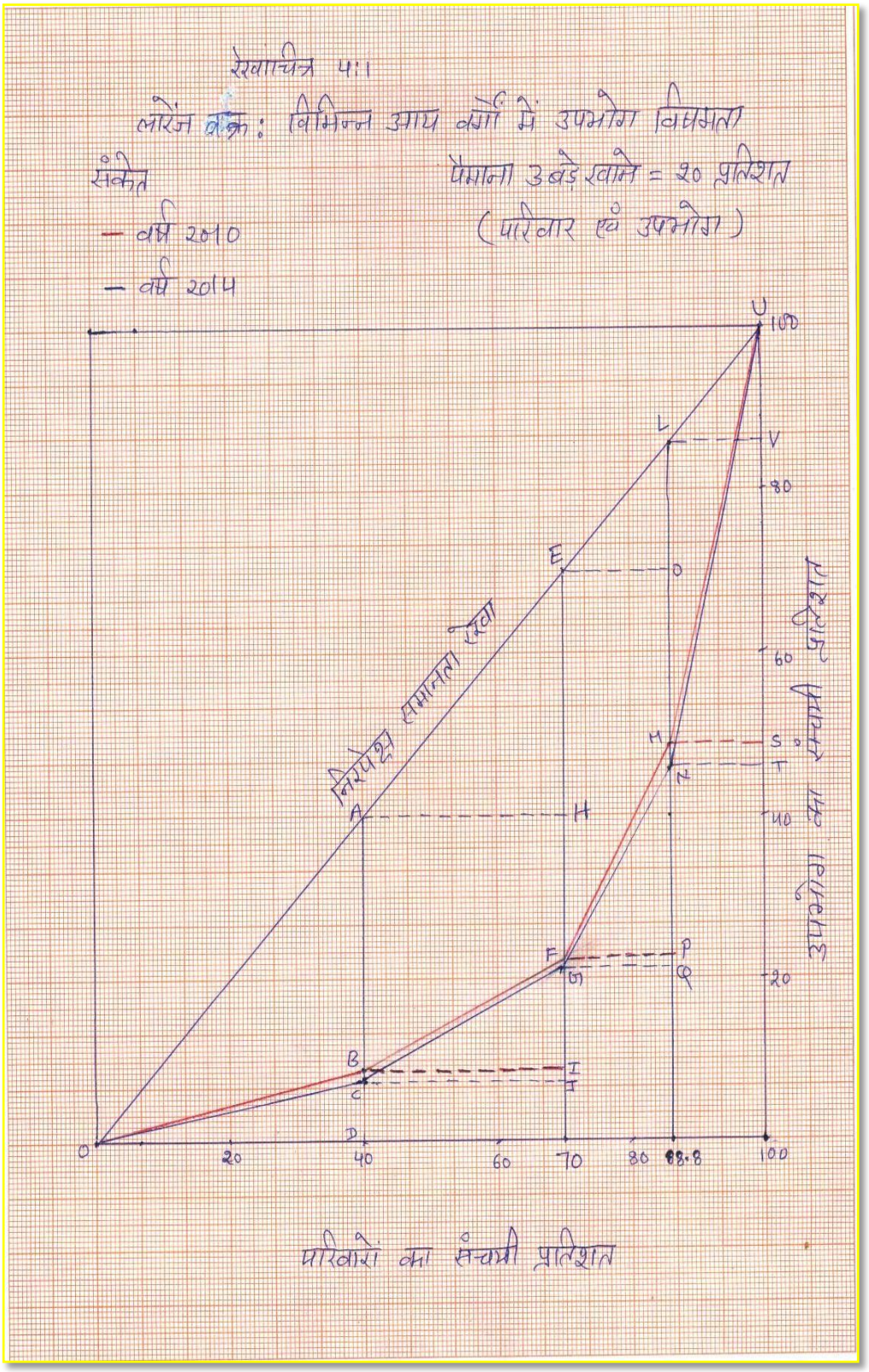

रेखा चित्र 4.1 : लारेन्ज वक्र

4.3 विभिन्न आय–वर्गों के वर्ष 2010 से 2014 तक उपभोग सूचकांक : प्रस्तुत खण्ड में कुल चयनित 500 पारिवारिक इकाइयों के उपभोग सम्बन्धी वर्ष 2010 से 2014 तक के लिए उपभोग सूचकांक प्रस्तुत किये हैं। इन वर्षों में उपभोग वृद्धि की प्रवृत्तियाँ किस प्रकार रही तथा विभिन्न आय–वर्गों की उन विभिन्न वर्षों में प्रवृत्तियाँ कितनी भिन्नता लिये हुए हैं, उन्हें ज्ञात करने के लिए सारणी 4.3 में उपभोग सूचकांक दर्शाये गये हैं। वर्ष 2010 के उपभोग को 100 माना है अर्थात् वर्ष 2010 को आधार वर्ष माना हैं।

सारणी 4.3 : विभिन्न आय–वर्गों के वर्ष 2010 से 2014 तक उपभोग सूचकांक (आधार वर्ष = 2010)।

आय–वर्ग (मासिक)	परिवारों की संख्या	वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2014
7500 रू से कम	200	100	127.38	133.59	141.33	144.67
7500–16000 रू	150	100	131.32	143.21	158.24	165.66
16000–80000 रू	94	100	131.67	142.33	159.32	168.15
80000 रू से अधिक	56	100	128.39	132.68	140.94	147.41
समग्र स्थिति	–	100	129.69	137.95	149.96	156.47

सारणी 4.3 से निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :

1. समग्र रूप से उपभोग–सूचकांक में वर्ष 2010 से 2014 तक वृद्धि हुई है तथा इन वर्षों में उपभोग सूचकांक 100 से बढ़कर 156.47 हो गया है।
2. निम्न–वर्ग के उपभोग–सूचकांक में वृद्धि अन्य वर्गों से कम (44.67 प्रतिशत) हुई है तथा सबसे ज्यादा वृद्धि मध्यम वर्ग के उपभोग सूचकांक में रही जो कि 68.15 प्रतिशत है।

4.4 विभिन्न आय–वर्गों में औसत मासिक उपभोग व्यय का प्रतिशत : रेखाचित्र 4.2 से 4.9 में प्रत्येक आय वर्ग के औसत मासिक उपभोग का विभिन्न मदों पर व्यय के प्रतिशत को दर्शाया गया है। विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में उच्च आय वर्ग वाले परिवार सबसे अधिक उपभोग–व्यय शिक्षा (42.00 प्रतिशत वर्ष 2010 तथा 31.00 प्रतिशत वर्ष 2014) में करते हैं। निम्न आय वर्ग वाले परिवार सबसे अधिक उपभोग व्यय दुग्ध एवं घी (27.00 प्रतिशत वर्ष 2010 तथा 27.00 प्रतिशत वर्ष 2014) में करते हैं तथा शिक्षा पर 4.00 प्रतिशत (वर्ष 2010 तथा 2014) करते हैं।

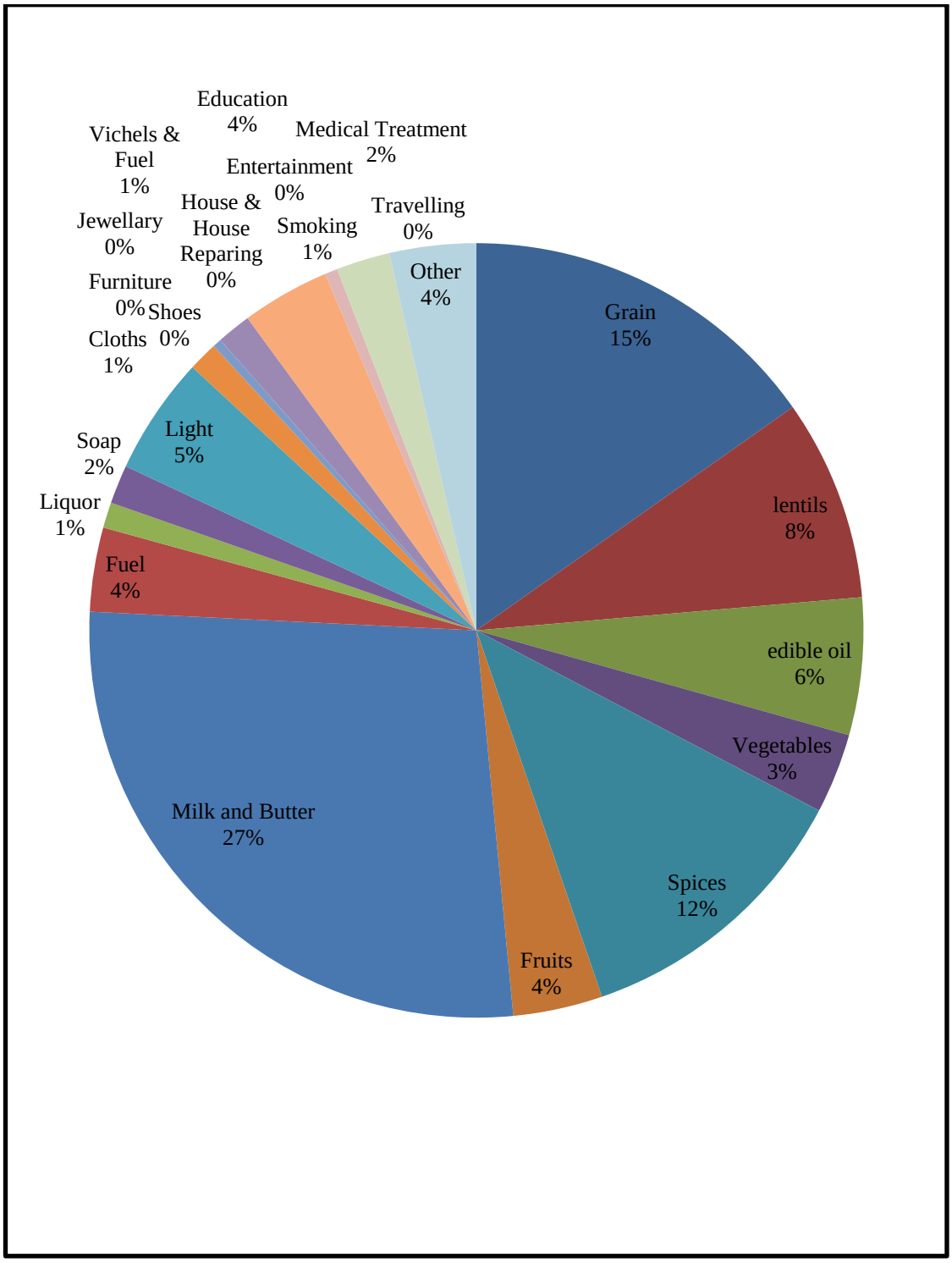

रेखाचित्र 4.2 : 7500 रू मासिक से कम आय–वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2010 में विभिन्न मदों पर उपभोग–व्यय का प्रतिशत।

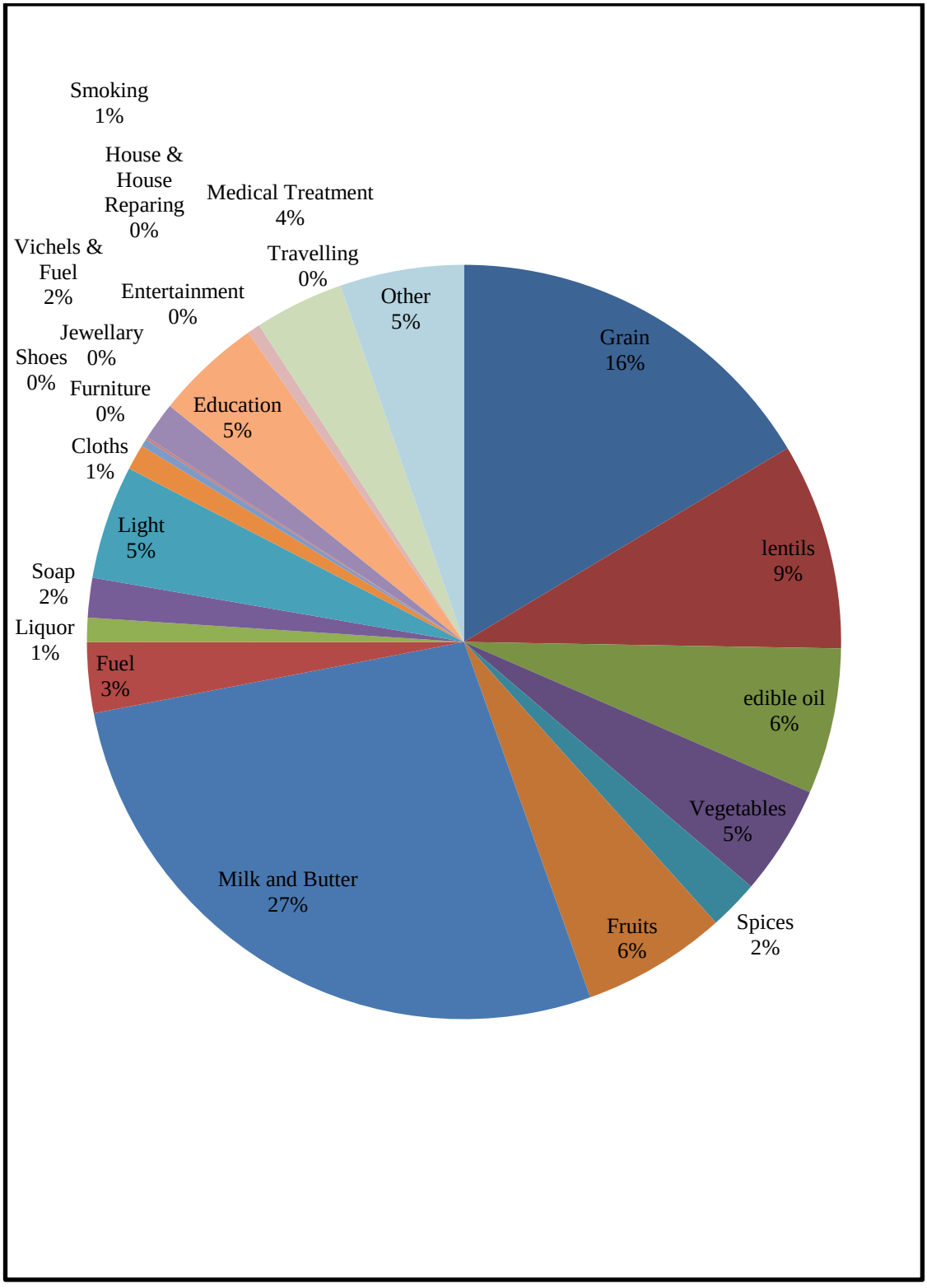

रेखाचित्र 4.3 : 7500 रू मासिक से कम आय–वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2014 में विभिन्न मदों पर उपभोग–व्यय का प्रतिशत।

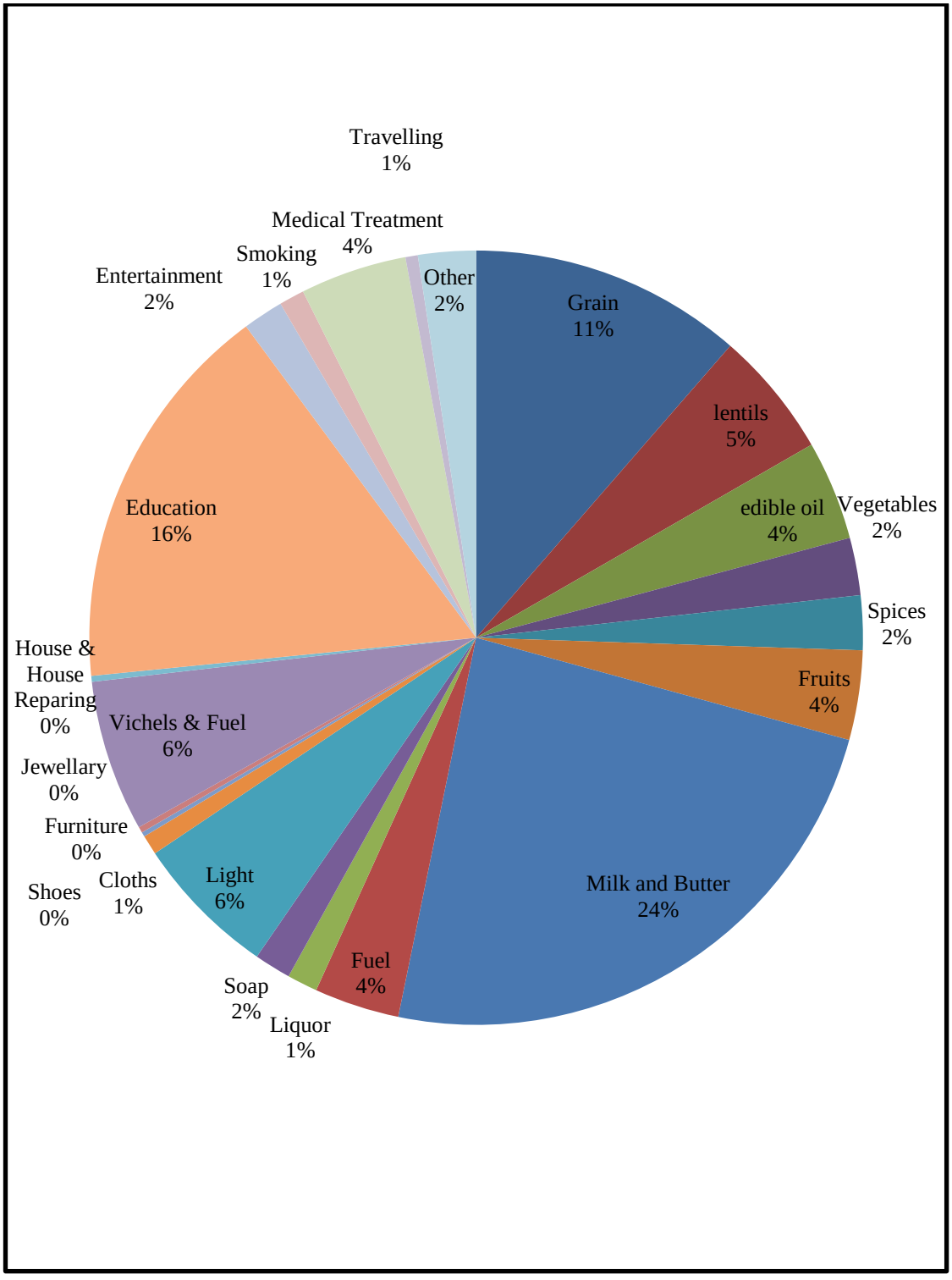

रेखाचित्र 4.4 : 7500–16000 रू मासिक से कम आय–वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2010 में विभिन्न मदों पर उपभोग–व्यय का प्रतिशत।

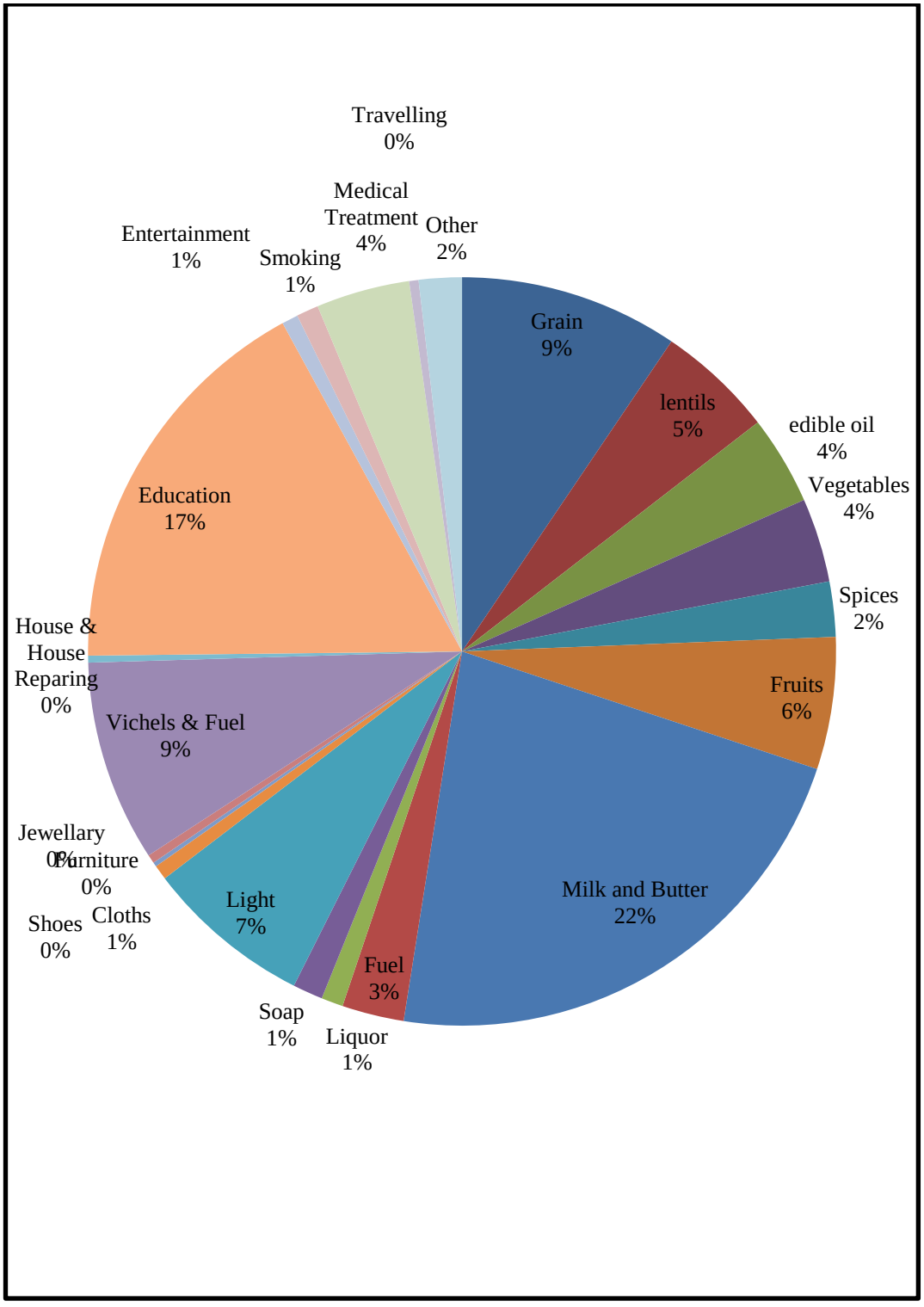

रेखाचित्र 4.5 : 7500–16000 रू मासिक से कम आय–वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2014 में विभिन्न मदों पर उपभोग–व्यय का प्रतिशत।

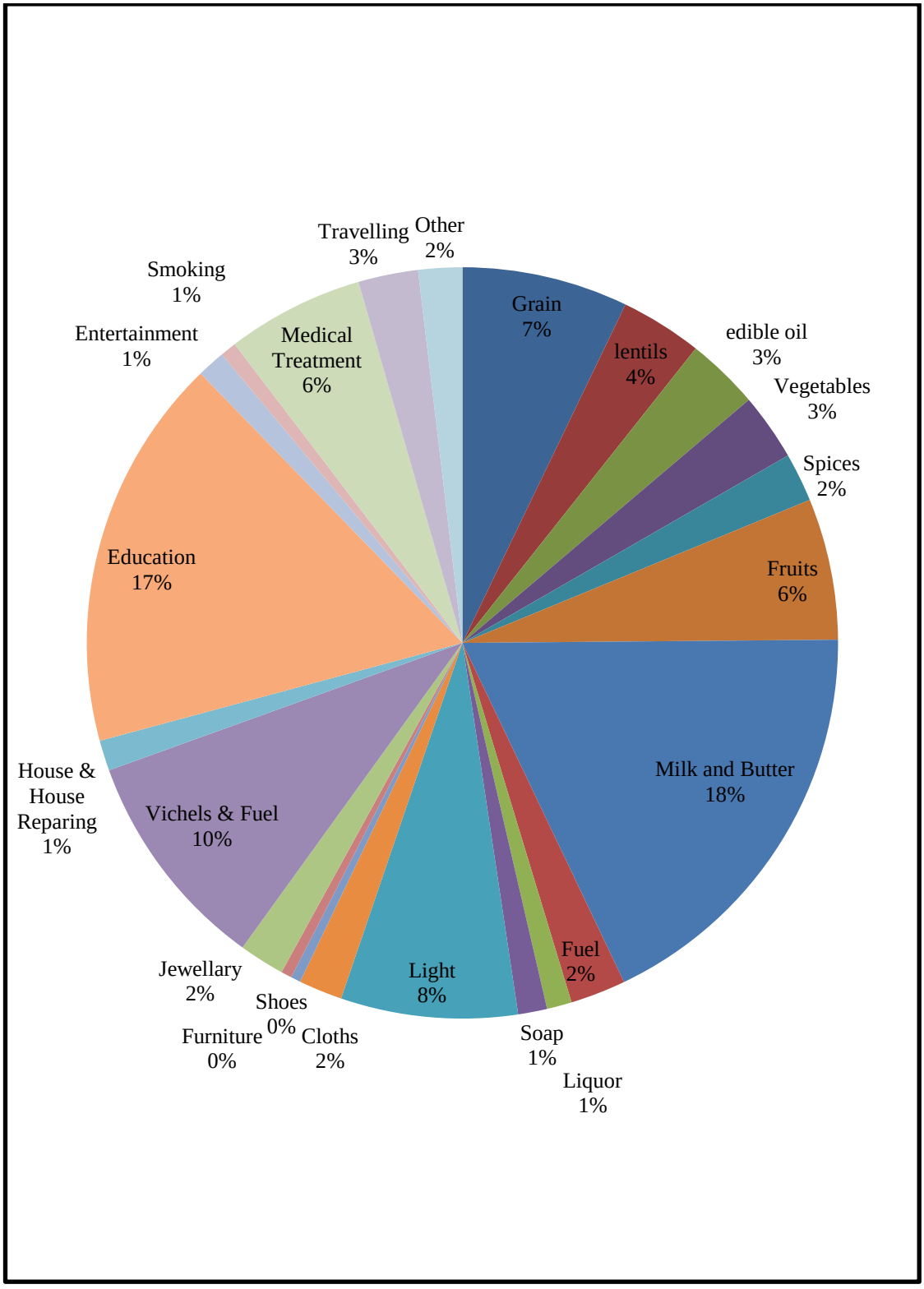

रेखाचित्र 4.6 : 16000–80000 रू मासिक से कम आय–वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2010 में विभिन्न मदों पर उपभोग–व्यय का प्रतिशत।

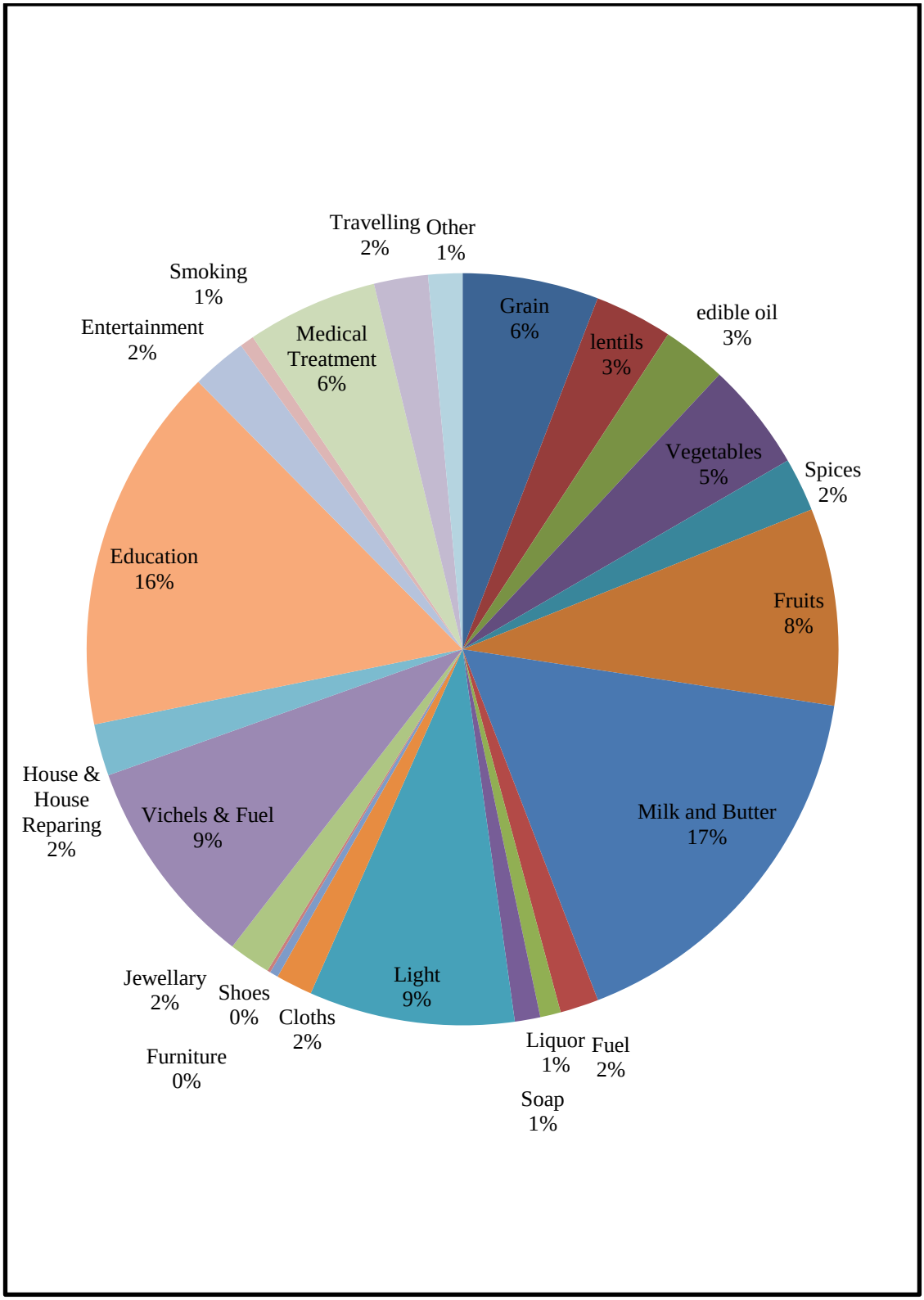

रेखाचित्र 4.7 : 16000–80000 रू मासिक से कम आय–वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2014 में विभिन्न मदों पर उपभोग–व्यय का प्रतिशत।

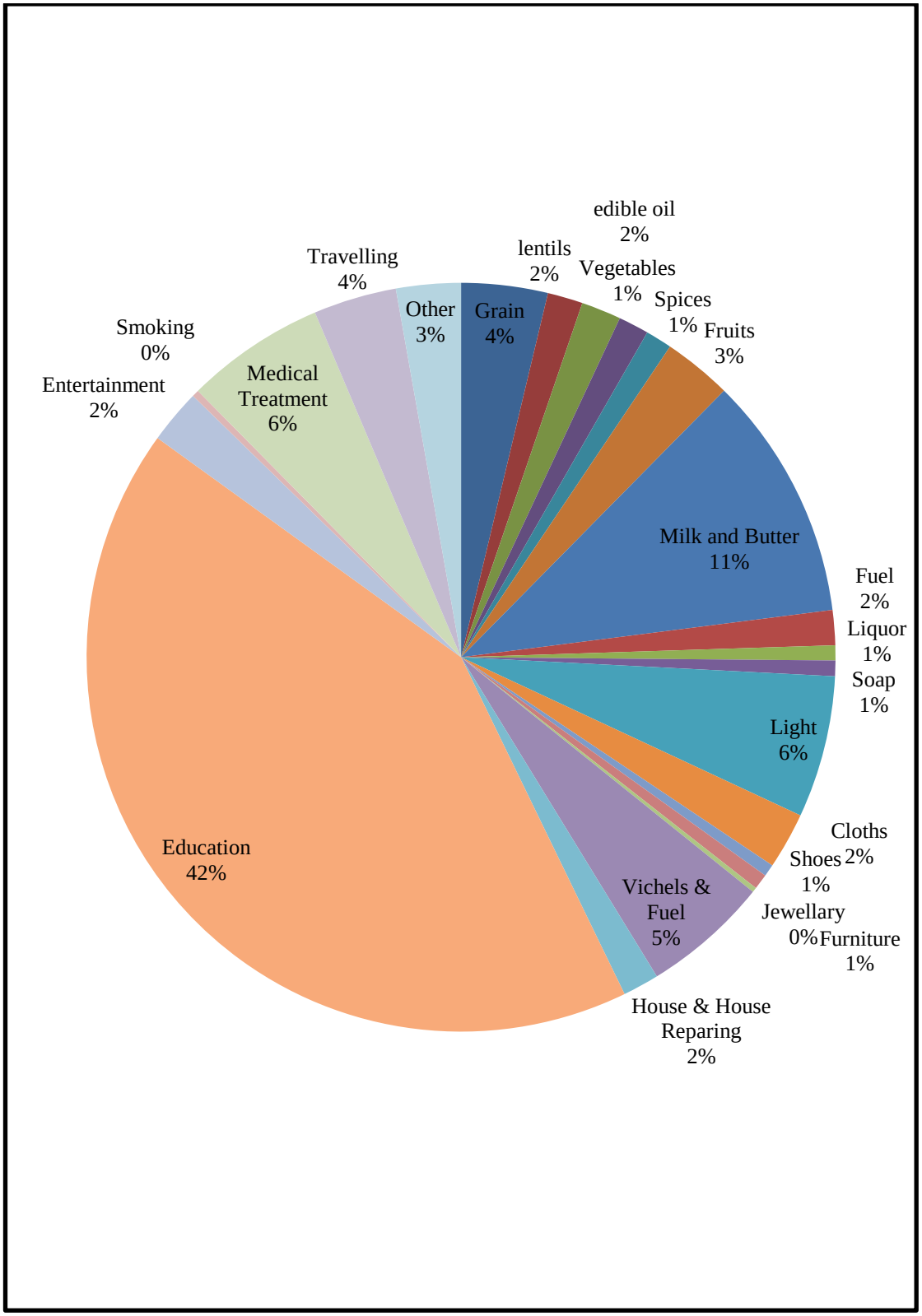

रेखाचित्र 4.8 : 80000 रू मासिक से अधिक आय–वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2010 में विभिन्न मदों पर उपभोग–व्यय का प्रतिशत।

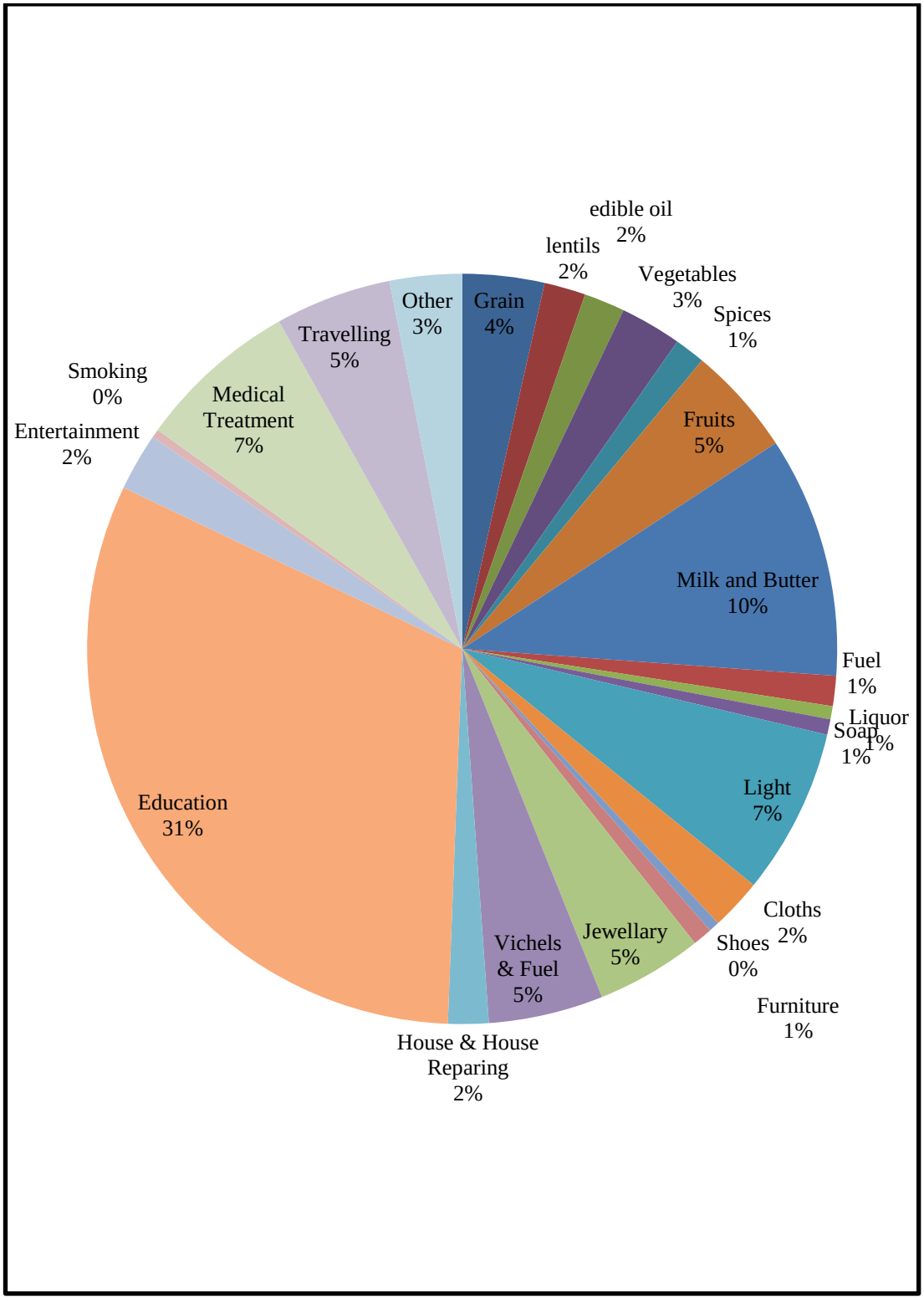

रेखाचित्र 4.9 : 80000 रू मासिक से अधिक आय–वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2014 में विभिन्न मदों पर उपभोग–व्यय का प्रतिशत।

4.5 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की विभिन्न मदों पर व्यय के औसत प्रतिशत की वर्ष 2010 व 2014 में तुलना : सारणी 4.4 में विभिन्न आय वर्ग वाले परिवारों का विभिन्न मदों पर व्यय का औसत प्रतिशत वर्ष 2010 व 2014 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.4 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2010 व 2014 में विभिन्न मदों पर व्यय का औसत प्रतिशत।

क्रम संख्या	मद	विभिन्न मदों पर व्यय का औसत प्रतिशत	
		वर्ष 2010	वर्ष 2014
1	अनाज	6.54	5.97
2	दालें	3.06	3.20
3	खाद्य तेल	2.71	2.66
4	सब्जियाँ	2.01	3.48
5	मसालें	2.39	1.80
6	फल	3.90	5.98
7	दुग्ध एवं घी	15.54	15.07
8	ईंधन	2.16	1.72
9	पेय पदार्थ	0.87	0.74
10	साबुन	1.00	0.95
11	बिजली	6.38	7.45
12	कपड़े	1.99	1.73
13	जूते	0.44	0.38
14	फर्नीचर	0.51	0.53
15	आभूषण	0.59	2.84
16	वाहन एवं ईंधन	6.27	6.35
17	आवासीय भवन एवं मरम्मत	1.20	1.53
18	शिक्षा	29.44	23.23
19	मनोरंजन	1.79	2.02
20	धूम्रपान	0.52	0.53
21	चिकित्सा	5.48	5.95
22	यात्रा	2.65	3.24
23	अन्य	2.58	2.65
	समग्र	**100**	**100**

सारणी 4.4 में विभिन्न मदों की वर्ष 2010 व 2014 में पारस्परिक तुलना से स्पष्ट होता है कि खाद्य, वस्त्र, ईंधन, शिक्षा आदि पर व्यय वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में घटा है जबकि अन्य मदों में बढ़ा है।

4.6 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की औसत व सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति : सर्वेक्षण में चयनित पारिवारिक इकाइयों की उपभोग प्रवृत्तियों का अध्ययन करके औसत एवं सीमान्त उपभोग प्रवृत्तियाँ ज्ञात की हैं, जिनके द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि दौसा जिले के लोग अपनी आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय करते हैं तथा कितना भाग बचाते हैं अर्थात् उनकी उपभोग प्रवृत्तियाँ क्या है? वे अपनी आय के उपभोग व्यय को विभिन्न मदों यथा खाद्य, वस्त्र, मकान, शिक्षा, ईंधन, मनोरंजन आदि पर कितना व्यय करते हैं? साथ ही अपनी आय के बढ़ने पर बढ़ी हुई आय का कितना भाग व्यय करते हैं?

सारणी 4.5 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की औसत व सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति।

आय–वर्ग (मासिक)	परिवारों की संख्या	औसत व सीमान्त उपभोग–प्रवृत्ति			
		APC 2010	**MPC 2010 -2009**	**APC 2014**	**MPC 2014 - 2013**
7500 रू से कम	200	0.93	0.92	0.99	0.83
7500–16000 रू	150	0.72	0.67	0.86	0.60
16000–80000 रू	94	0.48	0.38	0.33	0.25
80000 रू से अधिक	56	0.38	0.17	0.39	0.16
योग	500	–	–	–	–
सामूहिक औसत	–	0.72	0.66	0.76	0.57

सारणी 4.5 में वर्ष 2010 व वर्ष 2014 के लिए APC व MPC प्रत्येक आय–वर्ग के लिए दर्शायी गयी है। समग्र रूप से वर्ष 2010 में APC = 0.72 रही। दौसा जिले के चयनित परिवार आय का 78.00 प्रतिशत भाग वर्तमान उपभोग पर व्यय कर देते हैं। जबकि वर्ष 2014 में APC बढ़कर 0.76 हो गयी। वर्ष 2010 में APC को वर्गानुसार देखने पर यह ज्ञात होता है कि निम्न आय वर्ग की APC = 0.93 रही जो सर्वाधिक है तथा उच्च आय वर्ग की APC = 0.38 रही, जो न्यूनतम है। विगत पांच वर्षों में मध्यम आय वर्ग की APC घटी है। वर्ष 2014 में मध्यम आय वर्ग की APC = 0.33 रही जबकि अन्य तीनों वर्गों की बढ़ी है और उनमें भी निम्न आय वर्ग की सर्वाधिक APC = 0.99 रही हैं। सारणी 4.5 के

अनुसार वर्ष 2010 में MPC = 0.66 थी, लेकिन चयनित परिवारों की MPC वर्ष 2014 में घटकर 0.57 रह गयी।

इस प्रकार आय–वृद्धि के साथ–साथ MPC कम हुई है। वर्ष 2010 में सर्वाधिक MPC निम्न आय वर्ग की (0.92) रही जबकि न्यूनतम (0.17) उच्च आय वर्ग की रही है। इसी प्रकार वर्ष 2014 में निम्न–वर्ग की MPC = 0.83 रही, जो सर्वाधिक है जबकि न्यूनतम MPC = 0.16 उच्च आय वर्ग की हैं। इस प्रकार कम आय वाले वर्ग अपनी मासिक आय का अधिक भाग उपभोग–क्रियाओं पर खर्च करते हैं जबकि अधिक आय वाले वर्ग जिस अनुपात में उनकी आय बढ़ती है उससे कम अनुपात में उपभोग पर खर्च करते हैं।

4.7 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की विभिन्न मदों पर व्यय की औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC) : सर्वेक्षण के दौरान चयनित इकाइयों की विभिन्न मदों के लिए औसत उपभोग प्रवृत्ति हेतु समंक एकत्रित किये हैं जिन्हें सारणी 4.6 में दर्शाया गया है। सारणी 4.6 में प्रत्येक मदों की APC वर्ष 2010 व 2014 में विभिन्न आय वर्गानुसार बतायी गयी है जो निम्नानुसार है।

सारणी 4.6 : विभिन्न आय वर्ग वाले परिवारों की विभिन्न मदों पर व्यय की औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC)।

क्रम संख्या	उपभोग व्यय	औसत उपभोग प्रवृत्ति (APC)							
		7500 रू मासिक से कम		7500–16000 रू मासिक		16000–80000 रू मासिक		80000 रू मासिक से अधिक	
		2010	2014	2010	2014	2010	2014	2010	2014
1	अनाज	0.142	0.162	0.082	0.081	0.034	0.019	0.014	0.013
2	दालें	0.079	0.087	0.038	0.043	0.016	0.010	0.005	0.007
3	खाद्य तेल	0.053	0.062	0.030	0.033	0.015	0.008	0.006	0.006
4	सब्जियाँ	0.031	0.046	0.017	0.031	0.013	0.015	0.005	0.010
5	मसालें	0.113	0.021	0.016	0.020	0.010	0.007	0.004	0.005
6	फल	0.035	0.061	0.027	0.049	0.029	0.027	0.011	0.018
7	दुग्ध एवं घी	0.256	0.271	0.073	0.192	0.086	0.054	0.040	0.040
8	ईंधन	0.032	0.029	0.025	0.023	0.011	0.005	0.005	0.005

9	पेय–पदार्थ	0.010	0.010	0.009	0.008	0.005	0.002	0.002	0.002
10	साबुन	0.015	0.016	0.011	0.011	0.005	0.003	0.002	0.002
11	बिजली	0.046	0.048	0.043	0.061	0.036	0.028	0.023	0.028
12	कपड़े	0.011	0.010	0.005	0.005	0.009	0.005	0.009	0.008
13	जूते	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
14	फर्नीचर	0.0	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003
15	आभूषण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.009	0.005	0.001	0.018
16	वाहन एवं ईंधन	0.013	0.016	0.045	0.074	0.045	0.029	0.020	0.019
17	आवासीय भवन एवं मरम्मत	0.0	0.0	0.001	0.002	0.006	0.007	0.005	0.006
18	शिक्षा	0.034	0.045	0.119	0.148	0.081	0.051	0.161	0.123
19	मनोरंजन	0.0	0.0	0.012	0.006	0.005	0.007	0.008	0.009
20	धूम्रपान	0.004	0.005	0.007	0.008	0.003	0.001	0.001	0.001
21	चिकित्सा	0.021	0.037	0.032	0.034	0.028	0.018	0.023	0.027
22	यात्रा	0.0	0.0	0.003	0.003	0.012	0.007	0.013	0.019
23	अन्य	0.034	0.052	0.017	0.015	0.009	0.004	0.010	0.012

सारणी 4.6 से स्पष्ट होता है कि पारिवारिक आय बढ़ने के साथ–साथ खाद्य सामग्री पर व्यय घटता जाता है। निम्न–मध्यम तथा उच्च आय वर्ग का वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में खाद्य पर व्यय थोड़ा बढ़ा है परन्तु निम्न तथा मध्यम आय वर्ग का व्यय वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में घटा है। शिक्षा, दुग्ध एवं घी पर निम्न तथा निम्न–मध्यम आय वर्गों का वर्ष 2014 में व्यय वर्ष 2010 की अपेक्षा बढ़ा है परन्तु मध्यम आय वर्ग का घटा है। शिक्षा पर व्यय वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में उच्च आय वर्ग का घटा है तथा दुग्ध एवं घी पर स्थिर रहा है।

4.8 प्रतीपगमन समीकरण : उपभोग–प्रवृत्ति का अध्ययन प्रत्येक वर्ग के लिए एवं सामूहिक रूप से वर्ष 2009–2010 व 2013–2014 के लिए आंकलित किया है। यहाँ उपभोग को आश्रित चर व आय को स्वतंत्र चर मानकर प्रतीपगमन समीकरण ज्ञात किये हैं, जिन्हें सारणी 4.7 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.7 : वर्ष 2009–2010 व 2013–2014 के लिए प्रतीपगमन समीकरण।

आय वर्ग (मासिक)	वर्ष 2009–2010	वर्ष 2013–2014
7500 रू से कम	C=0.92y- 549.09	C=0.83y+779.11
7500–16000 रू	C=0.67y+182.56	C=0.60y+3651.08
16000–80000 रू	C=0.38y+3266.97	C=0.25y+13453.79
80000 रू से अधिक	C=0.17y+15559.51	C=0.16y+29440.53
सामूहिक माध्य	C=0.66y+2191.98	C=0.58y+7233.62

सारणी 4.7 में प्रतीपगमन समीकरणों के माध्यम से औसत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाने का प्रयास किया गया है। समग्र रूप से वर्ष 2009–2010 में स्वायत्त उपभोग 2191.98 रूपये था जो वर्ष 2013–14 में बढ़कर 7233.62 रूपये मासिक हो गया है। वर्ष 2009–2010 में आय का 66.00 प्रतिशत भाग तथा 2191.98 रूपये स्वायत्त उपभोग पर व्यय किया गया तथा वर्ष 2013–2014 में आय का 58.00 प्रतिशत भाग व 7233.62 रूपये स्वायत्त रूप से उपभोग पर व्यय हुआ।

यहाँ स्वायत्त उपभोग से अभिप्राय उपभोग के उस भाग से है, जो आय से सम्बन्धित नहीं है तथा आय के शून्य होने पर भी यह आवश्यक होता है। स्वायत्त रूप से चाहे आय शून्य ही क्यों न हो।

4.9 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की आय दुगनी होने पर विभिन्न उपभोग मदों पर व्यय : सर्वेक्षण के दौरान चयनित परिवारों से यह प्रश्न पूछा गया कि यदि इसी समय आपकी आय वर्तमान आय से दुगनी हो जाये तो आप इस बढ़ी हुई आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय करेंगे। एकत्रित समंकों से ज्ञात होता है कि निम्न आय वर्ग इसी समय आय के दुगना होने पर बढ़ी हुई आय का 25.00 प्रतिशत भाग उपभोग पर खर्च कर देंगे। इसी प्रकार अन्य तीन वर्गों ने क्रमशः 15.00, 6.00 एवं 2.00 प्रतिशत भाग खर्च करना बताया।

लगभग 66.67 प्रतिशत चयनित परिवारों की आय कम (16000 रू मासिक तक) होने के कारण अपनी आवश्यकताएँ स्थगित करनी पड़ती हैं। इन अतृप्त आवश्यकताओं को यह प्रश्न पूछकर ज्ञात किया कि यदि आप की आय वर्तमान आय से दुगनी हो जाये तो आप अपनी बढ़ी हुई आय का सर्वाधिक भाग किस मद पर व्यय करेंगे, इसे सारणी संख्या 4.8 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.8 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की आय दुगनी होने पर विभिन्न उपभोग–मदों पर व्यय।

आय–वर्ग (मासिक)	आय दुगनी होने पर विभिन्न उपभोग–मदों पर व्यय							योग	प्रतिशत
	खाद्य	वस्त्र	मकान किराया	शिक्षा	ईंधन	मनोरंजन	विविध		
7500 रू से कम	86	39	11	52	06	02	04	200	–
प्रतिशत	(43.00)	(19.50)	(5.50)	(26.00)	(3.00)	(1.00)	(2.00)	–	–
7500–16000 रू	52	28	14	38	04	06	08	150	–
प्रतिशत	(34.67)	(18.67)	(9.33)	(25.33)	(2.67)	(4.00)	(5.33)	–	–
16000–80000 रू	22	10	04	32	04	08	14	94	–
प्रतिशत	(23.40)	(10.64)	(4.25)	(34.05)	(4.25)	(8.52)	(14.89)	–	–
80000 रू से अधिक	10	14	10	12	02	02	06	56	–
प्रतिशत	(17.86)	(25.00)	(17.86)	(21.43)	(3.57)	(3.57)	(10.71)	–	–
योग	170	91	39	134	16	18	32	500	–
प्रतिशत	34.00	18.20	7.80	26.80	3.20	3.60	6.40		100

सारणी 4.8 से स्पष्ट है कि यदि वर्तमान आय बढ़कर दुगनी हो तो निम्न, निम्न–मध्यम आय वर्ग सर्वाधिक भाग खाद्य पर खर्च करेगा इसके बाद शिक्षा व वस्त्र पर खर्च करेगा जबकि मध्यम आय वर्ग बढ़ी हुई आय का 34.05 प्रतिशत भाग शिक्षा पर व्यय करेगा। इसी प्रकार उच्च आय वर्ग बढ़ी हुई आय को शिक्षा, मकान एवं वस्त्र पर क्रमशः 21.43, 17.86, 25.00 प्रतिशत खर्च करेगा। सामूहिक रूप से देखने पर 26.80 प्रतिशत परिवार शिक्षा पर, 34.00 प्रतिशत परिवार खाद्य पर और 7.80 प्रतिशत परिवार मकान किराये पर व्यय करेंगे। कुल मिलाकर सभी चयनित इकाइयों ने शिक्षा पर व्यय को प्राथमिकता दी है।

4.10 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की वर्तमान उपभोग–स्तर से सन्तुष्टि :

सर्वेक्षण के दौरान सूचनादाताओं से यह भी जानकारी ली गई कि चयनित इकाईयाँ वर्तमान आय से प्राप्त उपभोग–स्तर से सन्तुष्ट हैं या नहीं? इस हेतु एकत्रित समंकों को सारणी 4.9 में दर्शाया गया है।

सारणी 4.9 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की उपभोग–स्तर से सन्तुष्टि।

आय–वर्ग (मासिक)	उपभोग–स्तर से सन्तुष्टि		योग
	हाँ	नहीं	
7500 रू से कम	06	194	200
प्रतिशत	(3.00)	(97.00)	–
7500–16000 रू	43	107	150
प्रतिशत	(28.66)	(71.34)	–
16000–80000 रू	65	29	94
प्रतिशत	(69.15)	(30.85)	–
80000 रू से अधिक	51	05	56
प्रतिशत	(91.07)	(8.93)	–
योग	165	335	500
प्रतिशत	33.00	67.00	100

सारणी 4.9 से स्पष्ट होता है कि निम्न आय वर्ग के 97.00 प्रतिशत सूचनादाता वर्तमान उपभोग–स्तर से सन्तुष्ट नहीं है तथा यही स्थिति निम्न–मध्यम आय वर्ग की है जिसमें 71.34 प्रतिशत इकाईयाँ वर्तमान उपभोग–स्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। यदि हम मध्यम व उच्च आय वर्ग की चयनित इकाईयों को लेते हैं तो दोनों ही वर्तमान उपभोग–स्तर से सन्तुष्ट हैं जिनका प्रतिशत क्रमशः 69.15 व 91.07 है। सामूहिक रूप से देखने पर यह ज्ञात होता है कि 33.00 प्रतिशत परिवार वर्तमान उपभोग स्तर से सन्तुष्ट हैं तथा 67.00 प्रतिशत इकाईयाँ सन्तुष्ट नहीं हैं।

4.11 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की असन्तुष्टि के कारण : सर्वेक्षण के दौरान यह भी जानकारी ली गई कि यदि सूचनादाता वर्तमान उपभोग स्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं तो वे कीमत वृद्धि, कम आय एवं बड़े परिवार में से किसको मुख्य कारण मानते हैं, इन कारणों की जानकारी सारणी 4.10 में दर्शायी गई है।

सारणी 4.10 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की असन्तुष्टि के मुख्य कारण।

आय–वर्ग (मासिक)	असन्तुष्टि के कारण			योग
	कीमत वृद्धि	कम आय	बड़ा परिवार	
7500 रू से कम	39	156	05	200
प्रतिशत	(19.50)	(78)	(2.50)	–
7500–16000 रू	62	83	05	150
प्रतिशत	(41.33)	(55.33)	(3.34)	–
16000–80000 रू	63	29	02	94
प्रतिशत	(67.02)	(30.85)	(2.13)	–
80000 रू से	56	–	–	56
अधिक प्रतिशत	(100)	–	–	–
योग	220	268	12	500
प्रतिशत	44.00	53.60	2.40	100

सारणी 4.10 से स्पष्ट है कि निम्न आय वर्ग के 78.00 प्रतिशत परिवार कम आय तथा 19.50 प्रतिशत परिवार कीमत–वृद्धि व 2.50 प्रतिशत परिवार बड़े परिवार को असन्तुष्टि का कारण मानते हैं। निम्न–मध्यम परिवारों में से 55.33 प्रतिशत ने कम आय व 41.33 परिवारों ने कीमत–वृद्धि को तथा 3.34 प्रतिशत परिवारों ने बड़े परिवार को कारण माना है। इसी प्रकार मध्यम वर्ग ने कीमत–वृद्धि व कम आय क्रमशः 67.02 व 30.85 प्रतिशत दोनों को तथा बड़े परिवार का 2.13 प्रतिशत कारण माना है। परन्तु उच्च वर्ग ने असन्तुष्टि कारण में केवल कीमत–वृद्धि को ही माना है।

4.12 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों का उपभोग पर प्रदर्शन प्रभाव : सूचनादाता का उपभोग मुख्यतः उसकी अर्जित आय से प्रभावित होता है, परन्तु उनके उपभोग पर अन्य तथ्यों का क्या प्रभाव पड़ता है, इनका अध्ययन सर्वेक्षण के दौरान किया गया। उपभोग पर प्रदर्शन प्रभाव को सारणी 4.11 में बताया गया है।

सारणी 4.11 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों का उपभोग पर प्रदर्शन प्रभाव।

आय–वर्ग (मासिक)	उपभोग पर प्रदर्शन प्रभाव		योग
	हाँ	नहीं	
7500 रू से कम	–	200	200
प्रतिशत	–	(100)	–
7500–16000 रू	–	150	150
प्रतिशत	–	(100)	–
16000–80000 रू	06	88	94
प्रतिशत	(6.38)	(93.62)	–
80000 रू से अधिक	11	45	56
प्रतिशत	(19.64)	(80.36)	–
योग	17	483	500
प्रतिशत	3.40	96.60	100

सारणी 4.11 से स्पष्ट है कि निम्न, निम्न–मध्यम आय वर्ग पर प्रदर्शन प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि मध्यम तथा उच्च आय वर्ग के (6.38 तथा 19.64 प्रतिशत) परिवारों पर प्रदर्शन–प्रभाव पड़ता है। उच्च आय वर्ग पर यह प्रदर्शन प्रभाव विलासिता व टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोग व्यय के कारण अधिक पड़ता है।

4.13 उपभोग निर्धारक कारकों का विश्लेषण : दौसा जिले की पारिवारिक इकाइयों की औसत उपभोग प्रवृत्तियाँ विभिन्न आय–वर्गों के अनुसार किस प्रकार की रहीं हैं, इसे उपभोग निर्धारक कारक (सामाजिक स्थिति का उपभोग पर प्रभाव, सम्पत्ति का उपभोग पर प्रभाव, रोजगार का उपभोग पर प्रभाव, प्रवर्जन का उपभोग पर प्रभाव) किस प्रकार प्रभावित करते हैं, से सम्बन्धित विश्लेषण को प्रस्तुत खण्ड में किया गया है।

4.13.1. सामाजिक स्थिति का उपभोग पर प्रभाव : सामाजिक स्थिति आधुनिक समाज की एक बुनियादी अवधारणा है। समाज में व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का निर्धारण सामाजिक नियमों के अनुसार होता है। सामाजिक स्थिति सामाजिक नियमों से अलग नहीं है। किसी व्यक्ति का समाज में क्या अधिकार, कर्त्तव्य, उत्तरदायित्व है, इसका निर्धारण उस व्यक्ति की स्थिति से होता है। आधुनिक जटिल समाज में एक व्यक्ति के एक से अधिक पद होते हैं। व्यक्ति जितने अधिक किस्म के समूहों के साथ अन्तः क्रिया करता है, उसकी

उतनी ही अधिक सामाजिक हैसियत होती है और कभी–कभी एक ही समूह में एक व्यक्ति की एक से अधिक स्थितियाँ होती हैं। बीयरस्टैट के शब्दों में यही कहा जा सकता है कि ''स्थिति एक ऐसा पद है, जो समूह सम्बन्ध, समूह सदस्यता या समूह व्यवस्था से प्राप्त होता है'' [5]।

समाज में, सामाजिक वर्ग आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का समूह है। समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, मानव–वैज्ञानिकों और सामाजिक इतिहासकारो के लिए वर्ग एक आवश्यक वस्तु है। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक वर्ग की अक्सर सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में चर्चा की जाती है [6]। आधुनिक पश्चिमी संदर्भ में स्तरीकरण आम तौर पर तीन वर्गों : उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग में बँटा है। प्रत्येक वर्ग आगे छोटे–छोटे वर्गों में उप–विभाजित हो सकता है [7]। वर्ग समाज में किसी व्यक्ति की वर्ग–स्थिति समूह की सदस्यता होती है, सदस्यता का निर्धारण करने वाले तत्त्वों से सिद्धान्तकार असहमत हैं लेकिन कई बातों में समान विशेषता दिखाई देती हैं। उसमें शामिल हैं : 1) उत्पादक, स्वामित्व और उपभोग के रिस्ते; 2) समारोहिक, व्यवसायिक अधिकारो सहित एक आम कानूनी स्थिति; 3) परिवार, रिस्तेदारियाँ, आदिवासी समूह संगठन या सदस्यता; 4) संस्कृति–संक्रमण सहित शिक्षा [8]।

समाज में व्यक्ति आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के आधार पर विभिन्न सामाजिक वर्गो में बँटा हुआ होता है। सामाजिक वर्ग की विश्लेषणात्मक अवधारणाओं के आधार पर आधुनिक समाज को आय के आधार पर चार वर्गों में बाँटा गया है : उच्च, मध्यम, निम्न–मध्यम एवं निम्न आय वर्ग। आमतौर पर एक ही सामाजिक वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों का उपभोग–व्यय लगभग समान होता है तथा अलग–अलग सामाजिक वर्गों का उपभोग व्यय अलग–अलग होता है। क्योंकि निम्न आय वर्ग के उपभोक्ता का अधिक ध्यान वस्तु के मूल्य पर केन्द्रित होता है जबकि उच्च आय वर्ग से सम्बन्धित उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देता है [9]।

(अ) वस्तुओं की गुणवत्ता : रेखाचित्र 4.10 में विभिन्न आय–वर्गों के परिवारों (प्रतिशत) द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं की गुणवत्ता को दर्शाया गया है। परिवार अपनी आय के अनुसार वस्तुओं का उपभोग करते हैं। निम्न आय वर्ग वाले परिवार अपनी कम आय के कारण बिना ब्रांड की वस्तुओं को अधिक खरीदते है जिसका प्रतिशत 100.00 है। इससे पता चलता है कि निम्न आय वर्ग वाले परिवार ब्रांड वाली वस्तुओं को नहीं खरीदते हैं।

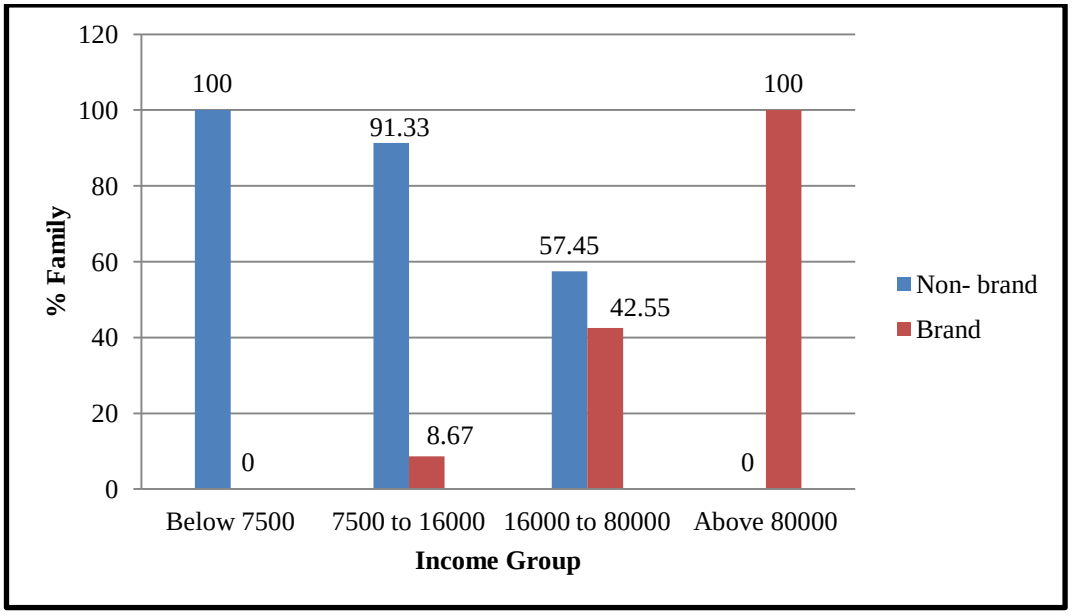

रेखाचित्र 4.10 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों (प्रतिशत) द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं की गुणवत्ता।

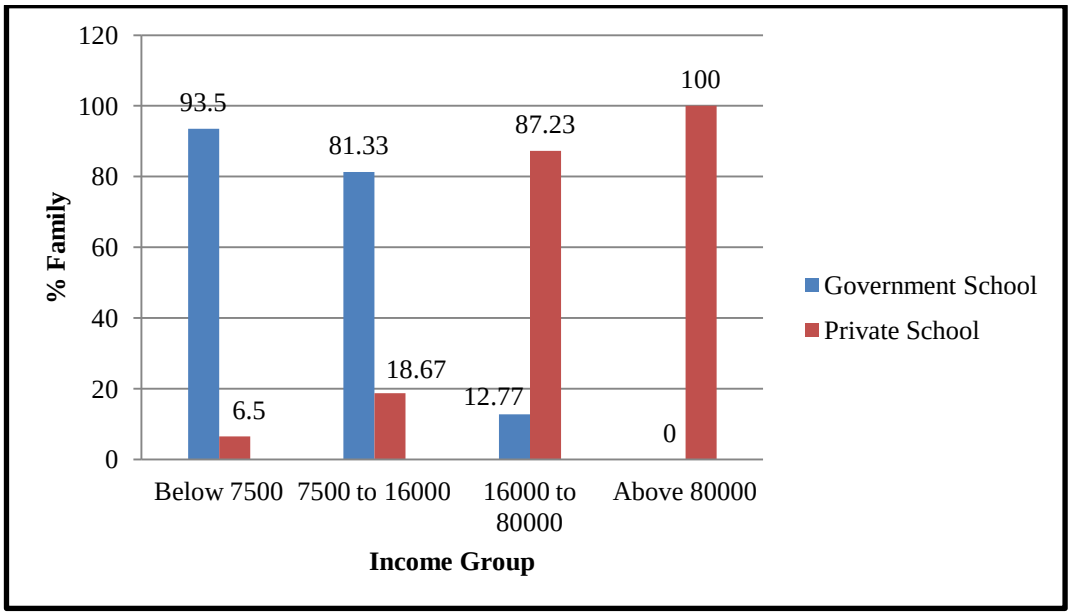

रेखाचित्र 4.11 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों (प्रतिशत) द्वारा अपने बच्चों को दी जाने वाली सरकारी तथा निजी विद्यालय में शिक्षा।

जबकि उच्च आय वर्ग वाले परिवार अपनी अधिक आय के कारण ब्रांड वाली वस्तुएँ को अधिक खरीदते हैं जिसका प्रतिशत 100.00 है। इससे पता चलता है कि उच्च आय वर्ग वाले परिवार बिना ब्रांड वाली वस्तुएँ नहीं खरीदते हैं। यदि हम निम्न–मध्यम तथा मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों को देखें तो पता चलता है कि ये परिवार बिना ब्रांड व ब्रांड वाली दोनों वस्तुओं को खरीदते हैं जिसका प्रतिशत क्रमशः निम्न–मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों में 91.33 व 8.67 है तथा मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों में 57.45 व 42.55 है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि समाज में उपभोग की जा रही वस्तुओं में विषमता काफी मात्रा में विद्यमान है तथा यह प्रवृत्ति सभी आय–वर्गों में विद्यमान है।

(ब) शिक्षा : रेखाचित्र 4.11 में विभिन्न आय–वर्गों के परिवारों (प्रतिशत) द्वारा अपने बच्चों को दी जाने वाली सरकारी तथा निजी विद्यालय में शिक्षा को दर्शाया गया है। परिवारों द्वारा अपनी आय के अनुसार अपने बच्चों को सरकारी तथा निजी विद्यालय में पढ़ाया जाता है। निम्न आय वर्ग वाले परिवार अपने बच्चों को कम आय के कारण सरकारी विद्यालयों में तथा कुछ ही परिवार निजी विद्यालयों में पढ़ाते हैं जिसका प्रतिशत क्रमशः 93.50 व 6.50 है। इससे पता चलता है कि निम्न आय वर्ग वाले परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। जबकि उच्च आय वर्ग वाले परिवार अपनी अधिक आय के कारण अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाना पसंद करते हैं जिसका प्रतिशत 100.00 है। निम्न–मध्यम तथा मध्यम आय वर्ग वाले परिवार को देखें तो इन परिवारों में अपने बच्चों को सरकारी तथा निजी विद्यालयों में पढ़ाने का प्रतिशत क्रमशः निम्न–मध्यम आय वर्ग वाले परिवार में 81.33 व 18.67 है तथा मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों में 12.77 व 87.23 है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा में भी विषमता काफी मात्रा में विद्यमान है।

(स) चिकित्सा : रेखाचित्र 4.12 में विभिन्न आय वर्गों के परिवारों (प्रतिशत) द्वारा अपने परिवार को दी जाने वाली सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा को दर्शाया गया है। परिवार के मुखिया अपनी आय के अनुसार अपने परिवार को इलाज के लिए सरकारी तथा निजी चिकित्सालय ले जाते हैं। निम्न आय वर्ग वाले परिवार अपने परिवार को कम आय के कारण सरकारी चिकित्सालय में तथा कुछ ही परिवार निजी चिकित्सालय में इलाज कराते है इसमें सरकारी व निजी चिकित्सालय में इलाज कराने वाले परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 96.00 व 4.00 है।

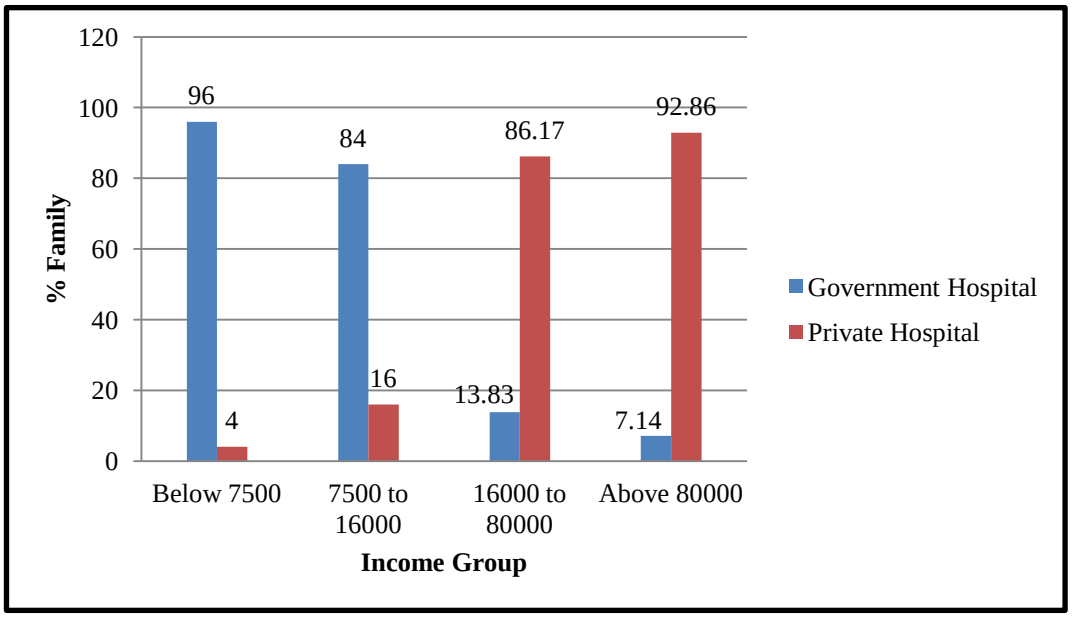

रेखाचित्र 4.12 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों (प्रतिशत) द्वारा अपने परिवार को दी जाने वाली सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा।

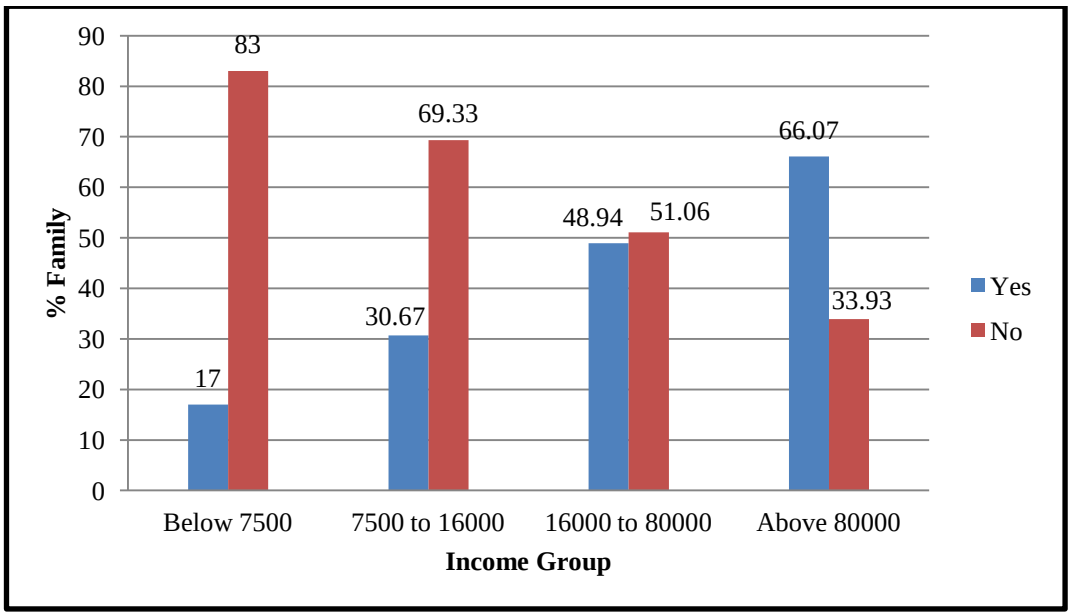

रेखाचित्र 4.13 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों (प्रतिशत) का सामाजिक कार्यों में योगदान।

जबकि उच्च आय वर्ग वाले परिवार अपनी अधिक आय के कारण अपने परिवार को इलाज के लिए निजी चिकित्सालय में ले जाना पसंद करते हैं, इसमें सरकारी व निजी चिकित्सालय में इलाज कराने वाले परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 7.14 व 92.86 है। निम्न–मध्यम तथा मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों को देखें तो इन परिवारों में सरकारी व निजी चिकित्सालय में इलाज कराने वाले परिवारों का प्रतिशत क्रमशः निम्न–मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों में 84.00 व 16.00 है तथा मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों का 13.83 व 86.17 प्रतिशत है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि निम्न आय वर्ग वाले परिवार कम आय होने के कारण तुरन्त अच्छी चिकित्सा नहीं दे पाते, जिससे कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज में आय वर्ग के अनुसार अपने परिवार को दी जाने वाली चिकित्सा में भी विषमता काफी मात्रा में विद्यमान है।

(द) सामाजिक कार्य : सामाजिक कार्य पर भी आय का काफी प्रभाव पड़ता है। जिस परिवार की आय अधिक होती है वे परिवार सामाजिक कार्य में अधिक रूचि लेते हैं। जिसका प्रतिशत रेखाचित्र 4.13 में दर्शाया गया है। निम्न आय वर्ग वाले परिवार अपनी कम आय के कारण सामाजिक कार्यों में रूचि कम लेते हैं, इन परिवारों का सामाजिक कार्य में भाग लेने व नहीं लेने का प्रतिशत क्रमशः 17.00 व 83.00 है। जबकि उच्च आय वर्ग वाले परिवार अपनी अधिक आय के कारण सामाजिक कार्य में अधिक रूचि लेते हैं, इनका सामाजिक कार्य में भाग लेने व नहीं लेने का प्रतिशत क्रमशः 66.07 व 33.93 है। निम्न–मध्यम तथा मध्यम आय वर्ग वाले परिवारों का सामाजिक कार्यों में भाग लेने व नहीं लेने का प्रतिशत क्रमशः 30.67 व 69.33 तथा 48.94 व 51.06 है।

4.13.2. शिक्षा–स्तर का उपभोग पर प्रभाव : शिक्षा विशेष रूप से वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति में ज्ञान, बुद्धि, मन, चरित्र और सामान्य योग्यता के वांछनीय गुणों को विकसित करने का कार्य करती है [10]। सारणी 4.12 यह दर्शाती है कि विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में कुल शिक्षा का स्तर निरक्षर, प्राइमरी, सेकण्डरी, डिग्री व प्रोफेशनल का प्रतिशत 4.60, 11.40, 11.60, 52.40 व 20.00 है, जिसमें निम्न आय वर्ग वाले परिवारों में शिक्षा का स्तर निरक्षर, प्राइमरी, सेकण्डरी, डिग्री व प्रोफेशनल का प्रतिशत 11.50, 28.50, 16.00, 38.00 व 6.00 है तथा उच्च आय वर्ग वाले परिवारों में शिक्षा का स्तर निरक्षर, प्राइमरी, सेकण्डरी, डिग्री व प्रोफेशनल का प्रतिशत 0.00, 0.00, 0.00, 48.21 व 51.79 है।

हम जानते है कि जैसे–जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जाता है वैसे–वैसे जीवन–स्तर को उच्च करने के लिए उपभोग व्यय बढ़ता जाता है।

सारणी 4.12 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में शिक्षा का स्तर।

शिक्षा का स्तर	आय–वर्ग (मासिक)				योग	प्रतिशत
	7500 रू से कम	7500–16000 रू	16000–80000 रू	80000 रू से अधिक		
निरक्षर	23 (11.50)	–	–	–	23	4.60
प्राइमरी	57 (28.50)	–	–	–	57	11.40
सेकण्डरी	32 (16.00)	23 (15.33)	03 (3.19)	–	58	11.60
डिग्री	76 (38.00)	92 (61.33)	67 (71.28)	27 (48.21)	262	52.40
प्रोफेशनल	12 (6.00)	35 (23.34)	24 (25.53)	29 (51.79)	100	20.00
योग	200	150	94	56	500	100

4.13.3. आश्रित सदस्यों की संख्या का उपभोग पर प्रभाव : परिवार का गठन एवं आकार उपभोग व्यय को प्रभावित करता है। फ्रीडमैन (1957) के अनुसार, उपभोग परिवार के सदस्यों की संख्या के छठे मूल के अनुपात में होता है [11]।

सारणी 4.13 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में आश्रित सदस्यों की संख्या।

आश्रित सदस्यों की संख्या	आय–वर्ग (मासिक)				योग	प्रतिशत
	7500 रू से कम	7500–16000 रू	16000–80000 रू	80000 से अधिक		
0	03 (1.50)	07 (4.67)	02 (2.13)	02 (3.57)	14	2.80
1	07 (3.50)	08 (5.33)	04 (4.26)	04 (7.14)	23	4.60
2	11 (5.50)	15 (10.00)	17 (18.08)	08 (14.29)	51	10.20
3	76 (38.00)	29 (19.33)	30 (31.91)	18 (32.14)	153	30.60
4 या अधिक	103 (51.50)	91 (60.67)	41 (43.62)	24 (42.86)	259	51.80
योग	200	150	94	56	500	100

सारणी 4.13 यह दर्शाती है कि विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में कुल आश्रित सदस्यों की संख्या 0, 1, 2, 3 व 4 या अधिक का प्रतिशत 2.80, 4.60, 10.20, 30.60 व 51.80 है जिसमें निम्न आय वर्ग वाले परिवारों में आश्रित सदस्यों की संख्या 0, 1, 2, 3 व 4 या अधिक का प्रतिशत 1.50, 3.50, 5.50, 38.0 व 51.50 है तथा उच्च आय वर्ग वाले परिवारों में आश्रित सदस्यों की संख्या 0, 1, 2, 3 व 4 या अधिक का प्रतिशत 3.57, 7.14, 14.29, 32.14 व 42.86 है। हम जानते हैं कि जैसे–जैसे आश्रित सदस्यों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे–वैसे उपभोग व्यय बढ़ता जाता है।

4.13.4. सम्पत्ति का उपभोग पर प्रभाव : आय के पश्चात् सम्पत्ति को उपभोग का दूसरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्त्व माना गया है। इसके दो कारण हैं प्रथम, उपभोग व्यक्तिगत आय की प्राप्ति मानवीय तथा गैर–मानवीय दोनों प्रकार की सम्पत्ति से होती है। द्वितीय, सम्पत्ति को संचित किया जा सकता है तथा इससे प्राप्त होने वाली आय को श्रम की आय में होने वाले नियोजित एवं अप्रत्याशित परिवर्तनों को दुरूस्त करने में प्रयुक्त किया जा सकता है [12]।

सम्पत्ति के परिमाण में वृद्धि होने से उपभोग फलन में ऊपर की ओर विवर्तन हो जाता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिक सम्पत्तिधारी कम सम्पत्तिधारी की अपेक्षाकृत (आय समान रहने पर) अधिक व्यय करता है [13]।

विभिन्न आय वर्ग वाले परिवार अपनी सम्पत्ति को नगद, स्टॉक, बॉण्ड और आवासीय सम्पत्ति या प्रोपर्टी (मकान एवं जमीन) के रूप में संचित रखते हैं। सामान्यतया व्यक्ति उपभोग–व्यय के लिए नकद राशि को आसानी से खर्च करते हैं क्योंकि व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अपनी कुल सम्पत्ति के नकद भाग का अपनी बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु उपयोग कर सकता है। यदि सम्पत्ति नकदी के रूप में संचित नहीं है तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उसे अपनी सम्पत्ति को बेचकर अथवा किसी अन्य उपाय से इसे (गिरवी रखकर) नकदी में परिवर्तित करना पड़ेगा [14]।

उच्च आय वर्ग वाले परिवारों का जीवन–स्तर अधिक आय होने के कारण उच्च होता है और वे अपनी सम्पत्ति (स्टॉक व बॉण्ड) का उपभोग विभिन्न सामाजिक गतिविधियों जैसे कपड़े, यात्रा करने के तरीके एवं मादक पेय पदार्थों पर व्यय करते हैं। निम्न आय वर्ग वाले परिवारों का जीवन–स्तर कम आय के कारण निम्न होता है जिसके कारण वे अपनी सम्पत्ति का उपभोग विभिन्न सामाजिक गतिविधियों जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ों पर अधिक करते हैं [15]।

सामान्यतया आवासीय सम्पत्ति कुल उपभोग व्यय से अप्रभावित रहती है। लेकिन यह चार उपभोग के तरीकों से प्रभावित होती है : 1) खाद्य पदार्थ पर; 2) उपयोगिताओं पर; 3) घर की मरम्मत पर; 4) व्यक्तिगत देखभाल पर [15]।

रेखाचित्र 4.14 विभिन्न आय वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2010 में सम्पत्ति का उपभोग पर प्रभाव के प्रतिशत को दर्शाता है। निम्न आय वर्ग वाले परिवार अपने उपभोग का 75.77 प्रतिशत घर पर बने खाद्य पदार्थ, 1.23 प्रतिशत कपड़े, 2.23 प्रतिशत चिकित्सा पर करते हैं जबकि उच्च आय वर्ग वाले परिवार अपने उपभोग का 22.08 प्रतिशत घर पर बने खाद्य पदार्थ, 2.44 प्रतिशत कपड़े, 3.59 प्रतिशत यात्रा, 6.02 प्रतिशत चिकित्सा एवं 1.56 प्रतिशत मकान एवं मकान मरम्मत पर करते हैं।

रेखाचित्र 4.15 विभिन्न आय वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2014 में सम्पत्ति का उपभोग पर प्रभाव के प्रतिशत को दर्शाता है। निम्न आय वर्ग वाले परिवार अपने उपभोग का 71.96 प्रतिशत घर पर बने खाद्य पदार्थ, 1.09 प्रतिशत कपड़े, 3.82 प्रतिशत चिकित्सा पर करते हैं जबकि उच्च आय वर्ग वाले परिवार अपने उपभोग का 26.14 प्रतिशत घर पर बने खाद्य पदार्थ, 2.21 प्रतिशत कपड़े, 5.01 प्रतिशत यात्रा, 6.95 प्रतिशत चिकित्सा एवं 1.74 प्रतिशत मकान एवं मकान मरम्मत पर करते हैं।

इस प्रकार हम देखते है कि जैसे–जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे–वैसे उपभोग व्यय करने के तरीके बदलते जाते हैं। जैसे– उच्च आय वर्ग वाले व्यक्ति घर पर बने खाद्य पदार्थ के स्थान पर महँगे होटलों में भोजन करना पसंद करते हैं, उच्च क्वालिटी के कपड़े खरीदते हैं, नये–नये स्थानों पर घूमने के लिए लक्जरी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय–समय पर जांच कराते हैं तथा अच्छे आवासों में रहते हैं जबकि निम्न आय वर्ग वाले परिवार ऐसा करने में असमर्थ हैं।

उच्च आय वर्ग वाले परिवारों के मकान अधिक महँगे होते हैं तथा वे उसकी मरम्मत एवं रख–रखाव पर अधिक उपभोग–व्यय करते हैं क्योंकि ये परिवार अपनी सम्पत्ति के मूल्यों को उच्च बनाये रखने के लिए प्रोत्साहित होकर इस पर अधिक खर्च करते हैं। इस कारण से आवासीय सम्पत्ति का मूल्य समय के साथ–साथ बढ़ता जाता है।

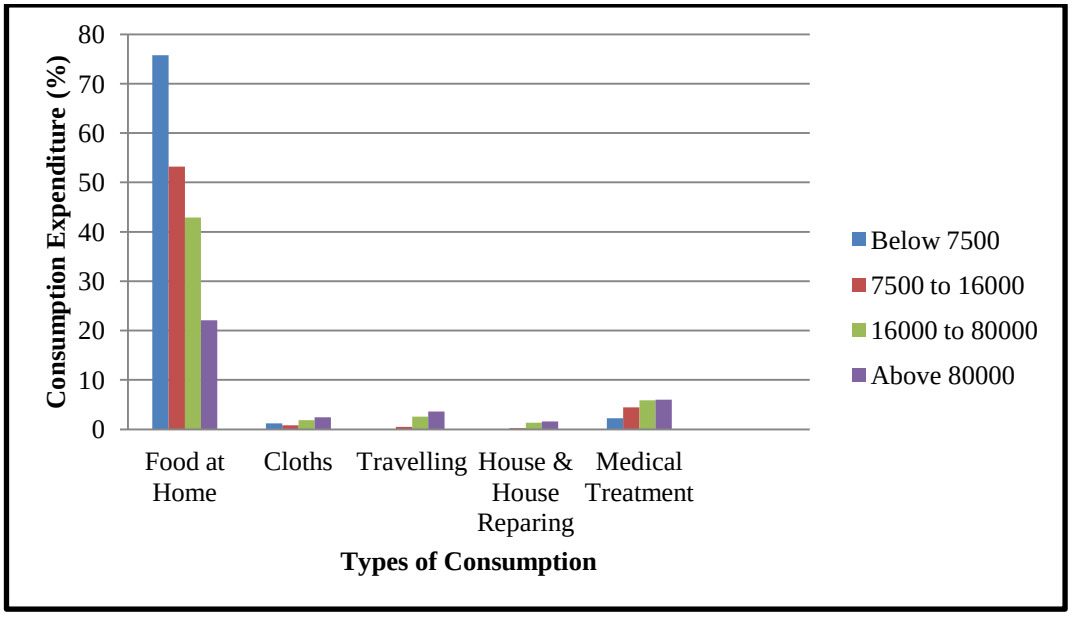

रेखाचित्र 4.14 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2010 में सम्पत्ति का उपभोग पर प्रभाव का प्रतिशत।

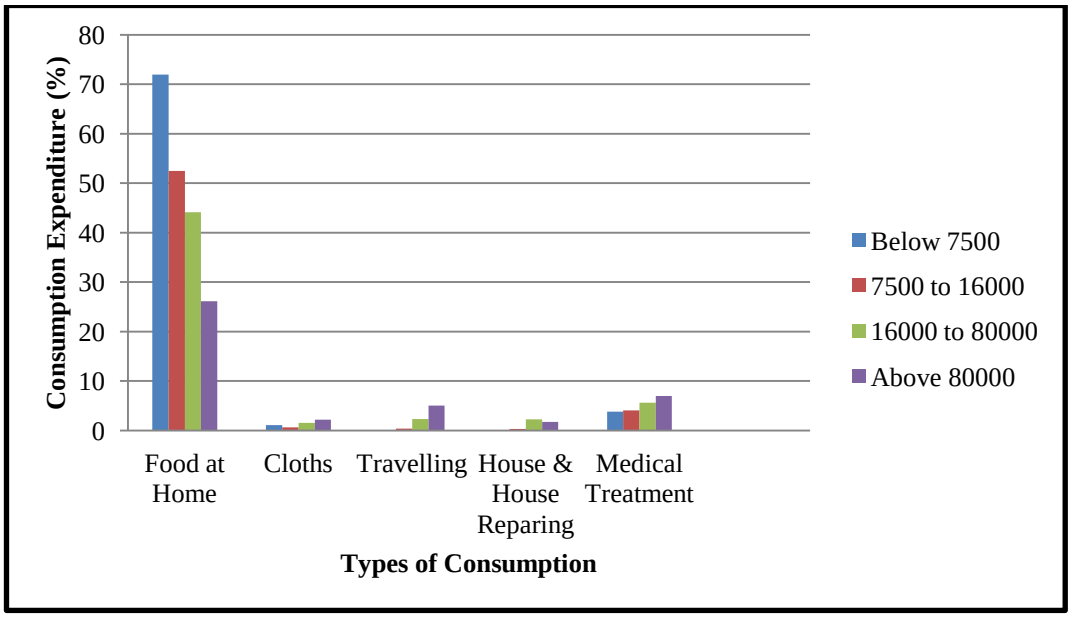

रेखाचित्र 4.15 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2014 में सम्पत्ति का उपभोग पर प्रभाव का प्रतिशत।

अतः उपभोग व्यय को करने में उच्च आय वर्ग वाले परिवारों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है जबकि निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को ऐसा करने में दिक्कत आती है।

4.13.5. रोजगार का उपभोग पर प्रभाव : रोजगार का उपभोग पर काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि रोजगार युक्त व्यक्ति अपनी आय को आवश्यकतानुसार उपभोग पर खर्च करते हैं तथा बेरोजगार या ग्रामीण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आय का लगभग पूरा भाग उपभोग पर खर्च कर देते हैं [10]।

रेखाचित्र 4.16 विभिन्न आय वर्ग वाले परिवारों (प्रतिशत) में रोजगार के विभिन्न प्रकारों को दर्शाता है। निम्न आय वर्ग वाले 34.50 प्रतिशत परिवार कृषि, 28.00 प्रतिशत परिवार मजदूरी, 17.00 प्रतिशत परिवार सरकारी सेवा में, 19.00 प्रतिशत परिवार व्यवसाय व 1.50 प्रतिशत परिवार पेंशन पर निर्भर रहते हैं जबकि उच्च आय वर्ग वाले 57.14 प्रतिशत परिवार सरकारी सेवा में तथा 42.86 प्रतिशत परिवार व्यवसाय में हैं। सरकारी सेवा एवं व्यवसाय में कार्यरत लोगों की आय अधिक होने के कारण उनका उपभोग व्यय तुलनात्मक रूप से कृषि, मजदूरी व पेंशन पर निर्भर रहने वाले लोगों से अधिक होता है।

4.13.6. प्रवर्जन का उपभोग पर प्रभाव : किसी व्यक्ति अथवा वर्ग का अपने सामाजिक ढ़ाँचे में अपनी योग्यता अथवा इच्छा के आधार पर एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति को प्राप्त करना सामाजिक गतिशीलता अथवा प्रवर्जन कहलाता है। यह गतिशीलता की प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन का ही एक रूप है अर्थात् एक व्यक्ति अथवा समूह की एक सामाजिक पदस्थिति को प्राप्त करना ही सामाजिक गतिशीलता है, जो उच्च भी हो सकती है और निम्न भी। सामाजिक गतिशीलता को निम्न तत्त्व प्रभावित करते है : 1) अवसर–संरचना; 2) जनसंख्यात्मक संरचना; 3) व्यवसायिक उन्नति; 4) शिक्षा; 5) आर्थिक सफलता; 6) शासन [9]।

प्रवर्जन का उपभोग पर काफी प्रभाव पड़ता है क्योंकि ग्रामीण लोगों की तुलना में शहरी लोग उपभोग पर अधिक व्यय करते हैं। दौसा जिले की कुल जनसंख्या 16,34,409 है जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 14,32,616 तथा शहरी जनसंख्या 2,01,793 है। सारणी 4.14 यह दर्शाती है कि दौसा जिले में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 87.65 तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 12.35 है। जिसमें शहरी जनसंख्या के पुरूष व महिला प्रतिशत क्रमशः 12.34 व 12.35 है जबकि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत काफी अधिक 87.65 है जिसमें पुरूष व महिला प्रतिशत क्रमशः 87.66 व 87.65 है।

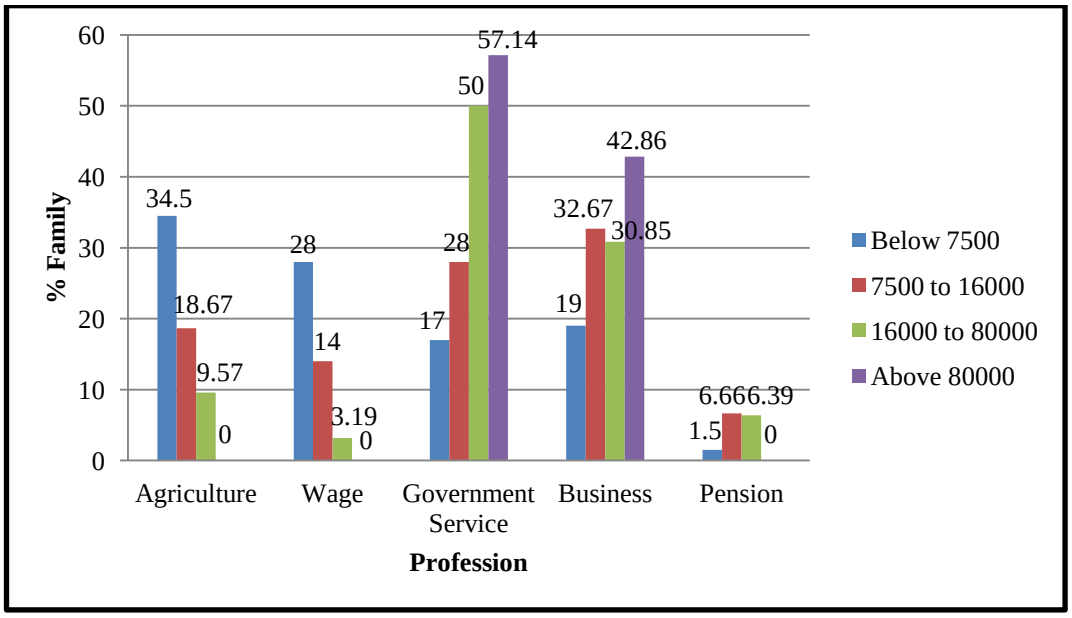

रेखाचित्र 4.16 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों (प्रतिशत) में रोजगार के विभिन्न प्रकार।

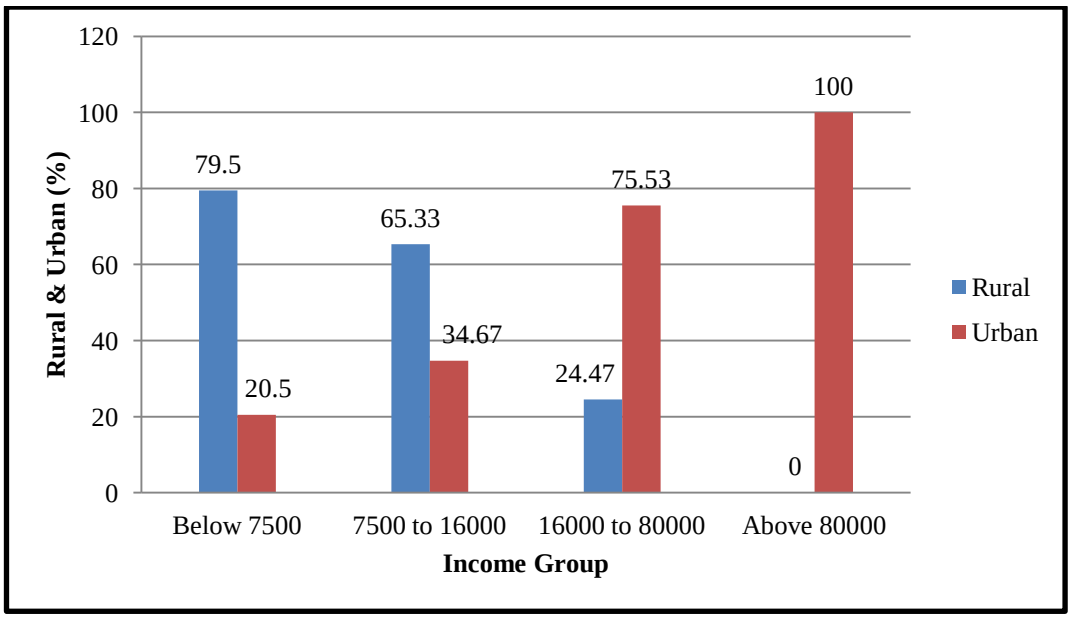

रेखाचित्र 4.17 : विभिन्न आय–वर्ग के अनुसार दौसा जिले की ग्रामीण व शहरी परिवारों के प्रतिदर्श का प्रतिशत।

ग्रामीण परिवार अपने आय के अनुसार उपभोग करते हैं अर्थात् आय कम होने के कारण ग्रामीण परिवार के लोग उपभोग पर कम व्यय करते हैं। शहरी परिवार भी अपनी आय के अनुसार उपभोग करते हैं अर्थात् आय अधिक होने के कारण शहरी परिवार ग्रामीण परिवारों की अपेक्षा अपनी आय का उपभोग पर अधिक व्यय करते हैं।

सारणी 4.14 : दौसा जिले की ग्रामीण व शहरी जनसंख्या का प्रतिशत।

जनसंख्या	ग्रामीण	शहरी	प्रतिशत
जनसंख्या प्रतिशत	87.65	12.35	100.00
पुरूष प्रतिशत	87.66	12.34	100.00
महिला प्रतिशत	87.65	12.35	100.00

रेखाचित्र 4.17 में विभिन्न 500 परिवारों के प्रतिदर्श में ग्रामीण व शहरी परिवारों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। हमारे द्वारा लिए गए प्रतिदर्शों में निम्न आय वर्ग के 79.50 प्रतिशत ग्रामीण परिवार व 20.50 प्रतिशत शहरी परिवार तथा उच्च आय वर्ग के 100.00 प्रतिशत शहरी परिवारों से है।

समंक एकत्रित करते समय हमने परिवारों से यह भी जाना की वे शहरी क्षेत्रों की तरफ धीरे–धीरे प्रवर्जन करते जा रहे हैं। जिसके मुख्य कारण शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य एवं परिवार सुरक्षा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थाएँ, रोजगार के अवसर, चिकित्सा–केन्द्र तथा परिवार सुरक्षा–व्यवस्था, सरकारी सेवाओं का अभाव होने के कारण लोगों का शहरों की तरफ प्रवर्जन हो रहा है, जिसके कारण वे शहरों में रहकर इन सुविधाओं को पाने के लिए अधिक उपभोग–व्यय करते हैं [16]।

4.14 निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध में दौसा जिले के विभिन्न आय–वर्ग वाले कुल चयनित 500 परिवारों के उपभोग सम्बन्धी समंक विगत पांच वर्षों हेतु लिये हैं, जो वर्ष 2010 से 2014 के हैं। विभिन्न आय वर्ग वाले परिवारों की उपभोग–प्रवृत्ति की विषमता का तुलनात्मक अध्ययन औसत मासिक उपभोग, मानक विचलन एवं विचरण–गुणांक से ज्ञात किया है।

सामान्यतया दौसा जिले में आय का 77.00 प्रतिशत भाग उपभोग पर खर्च किया जाता है जबकि 23.00 प्रतिशत भाग ही बचत के रूप में रखा जाता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में 0.72 प्रतिशत से बढ़कर 0.76 प्रतिशत हो गयी है।

चयनित इकाइयों में से विशेष रूप से निम्न एवं निम्न–मध्यम आय वर्ग के परिवारों में उपभोग का स्तर बहुत ही निम्न स्थिति का है जिससे जानकारी मिलती है कि वे अपनी सामान्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं।

उच्च आय वर्ग द्वारा उपभोग पर जो व्यय किया जाता है वह निम्न आय वर्ग की तुलना में नौ गुना अधिक है। यह दौसा जिले में उपभोग विषमता की स्थिति को बताती है। कुल सर्वेक्षित परिवारों के 40.00 प्रतिशत परिवारों को उपभोग का 7.38 प्रतिशत भाग ही प्राप्त होता है जबकि उच्च आय वर्ग के 11.20 प्रतिशत परिवारों को कुल आय का वर्ष 2014 में 51.47 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है।

परिवार अपने उपभोग व्यय का विभिन्न मदों पर इस प्रकार व्यय करते हैं कि कुल व्यय का 38.16 प्रतिशत भाग खाद्य सामग्री तथा शेष 61.84 प्रतिशत भाग कपड़े, मकान किराया, शिक्षा, ईंधन, मनोरंजन एवं विविध मदों पर करते हैं। निम्न आय वर्ग अपनी आय का 91.00 प्रतिशत भाग खाद्य तथा अन्य आवश्यकताओं पर व्यय कर देता है। यह वर्ग धूम्रपान तथा मादक पदार्थों के प्रयोग पर भी काफी व्यय करता है।

समाज का उच्च आय वर्ग अपनी आय को विभिन्न विलासिता की वस्तुओं पर अधिक व्यय करता है। कुछ परिवार उपभोग में वृद्धि सामाजिक प्रतिष्ठा एवं प्रदर्शन–प्रभाव के कारण करते हैं। उपभोग स्तर को देखते हुए अधिकांश परिवारों का जीवन–स्तर अधिक उच्च नहीं कहा जा सकता, यह सामान्य के निकट ही है।

विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की औसत उपभोग प्रवृत्ति विभिन्न उपभोग निर्धारक कारकों (सामाजिक स्थिति का उपभोग पर प्रभाव, सम्पत्ति का उपभोग पर प्रभाव, रोजगार का उपभोग पर प्रभाव, प्रवर्जन का उपभोग पर प्रभाव) द्वारा प्रभावित होती है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दौसा जिले के विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की उपभोग प्रवृत्ति में विषमता व्याप्त है।

4.15 संदर्भ सूची (References) :

1. UNDP, **(1998)**. Human Development Report. ***Oxford University Press, New York***.
2. Sooryamoorthy, R. **(1991)**. The Emergence of Consumerism in Kerala. ***Doctoral Dissertation, University of Kerala, Trivandrum***.
3. Roger, S. M. **(1981)**. Conspicuous Consumption. ***Gower Publishing Company Limited, England***, 18.
4. Weber, W. **(1970)**. The Effect of Interest Rates on Aggregate Consumption. ***The American Economic Review***, 60 (4): 591-600.
5. Roberts, R. **(1975)**. Class Structure. ***The Classic Slum, London, Penguin***, 13-31.
6. Turner, G. **(1990)**. Ethnography, History and Sociology. British Cultural Studies: An Introduction. ***Sydney, Allen & Unwin***, 169-196.
7. Dahrendorf, R. **(1959)**. Class and Class Conflict in Industrial Society. ***Stanford, Stanford University Press***.
8. Britt, S. H. **(1966)**. Consumer Behaviour and the Behavioural Sciences. ***Theory and Applications. New York, John Wiley***.
9. Rani, P. **(2014)**. Factors Influencing Consumer Behaviour. ***International Journal Current Research Academia Review***, 2 (9): 52-61.
10. Abid, S. and Afridi, G. S. **(2010)**. Assessing the Household Saving Pattern of Urban and Rural Households in District Muzaffarabad. ***Pakistan Journal of Life Social Science***, 8 (2): 137-141.
11. Friedman, M. **(1957)**. A Theory of the Consumption Function. ***The National Bureau of Economic Research, Princeton University Press***.
12. Keynes, J. M. **(1936)**. The General Theory of Employment, Interest and Money. ***Harcourt, Brace and Company and Printed in the U.S.A. by the Polygraphic Company of America, New York***.
13. Hamburger, M. J. **(1967)**. Interest Rates and the Demand for Consumer Durable Goods. ***The American Economic Review***, 131-135.
14. Carroll, C. D. **(2004)**. Housing Wealth and Consumption Expenditure. ***Johns Hopkins University***.

15. Lee, H. S. **(2001)**. Factors Influencing the Consumption Expenditures of Retired Elderly Households: Focused on the Factor of Wealth Components. ***Journal of Korean Home Economics Association English Edition***, 2 (1): 17-38.
16. Davis, R., Soberon-Ferrer, H. and Patro, D. **(1993)**. Analysis of Leisure Expenditures in the United States. ***In T. Mauldin (Ed.), Proceedings of the American Council on Consumer Interests. 39th Annual Conference***, 194-200.

*****

अध्याय – 5

बचत–प्रवृत्तियाँ : विभिन्न आय–वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन

बचत–प्रवृत्तियाँ : विभिन्न आय–वर्गों का तुलनात्मक अध्ययन

बचत, पूँजी निर्माण एवं आर्थिक विकास का आधार होती है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का अवलोकन उस देश में रहने वाले नागरिकों की बचत–प्रवृत्तियों के आधार पर कर सकते हैं। कोई देश कितना विकास कितने समय में कर सकेगा यह उस देश की बचत दर पर निर्भर करता है। भारत के समक्ष तीव्रगति से आर्थिक विकास का प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण है। भारत की आर्थिक विकास की दर वांछित विकास की दर से काफी कम हैं। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में पूँजी का अभाव ही माना जाता है। भारत में बड़े–बड़े विकास कार्य वित्तीय कठिनाईयों के कारण पूरे करने में समस्याएँ आती है [1]।

भारत तेजी से अधिक बचत करने वाले देशों की श्रेणी से अपनी स्थिति को खो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट (2011) के अनुसार, वर्ष 2011–12 के दौरान मुद्रास्फीति लगभग 9.0 प्रतिशत थी, जो आगे घटती जा रही है क्योंकि लोगों का वास्तविक उपभोग–व्यय और जीवन–स्तर समय के साथ–साथ बदलता जा रहा है। भारतीय परिवारों के बचत करने के तरीके कई कारकों से प्रभावित होते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में पिछले एक या दो दशकों में घरेलू बचत करने के तरीकों में बदलाव जीवन–शैली और उपभोग मॉडल में बदलाव के कारण आया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू बचत की दर में कई उतार–चढ़ाव आये हैं।

इस प्रकार भारत में वित्तीय स्त्रोतों की समस्या अधिक हैं। इसका उपाय बचत में वृद्धि करके वित्तीय साधनों के अभाव की स्थिति को सुलझाना है। यद्यपि जनसंख्या में वृद्धि एवं सामाजिक वातावरण की प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी भारतीय आर्थिक विकास में बाधक तत्त्व के रूप में हैं [2]। अतः आवश्यकता इस बात की है कि लोग देश के आर्थिक विकास के लिए बचत के महत्त्व को समझकर बचत–दर में वृद्धि करे तथा तीव्र आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए जहां तक हो सके वर्तमान आय में से बचत करके देश के आर्थिक विकास में योगदान करें। इसका अभिप्राय यही नहीं है कि केवल लोगों में बचत करने की आदतों को बढ़ाया जाये बल्कि साथ ही साथ बचत को एकत्रित करने वाली संस्थाएँ एकत्रित बचत का उपयोग विकास कार्यों में करें। लोगों को बचत के लिए प्रेरित करने में भी बचत–संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है [3]।

बचत मुख्यतया किसी परिवार, फर्म और कॉरपोरेट निकायों की आय पर निर्भर करती है। बचत मुख्यतया बचत वितरण के लिए लेखांकन क्षेत्रों के आधार पर तीन भागों में विभाजित की है [4] : 1) घरेलू क्षेत्र की बचत; 2) निजी क्षेत्र की बचत; 3) सार्वजनिक क्षेत्र की बचत।

1. **घरेलू क्षेत्र की बचत :** एक परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो बचत करता है वह घरेलू क्षेत्र की बचत कहलाती है। घरेलू बचत का भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय और वित्तीय–परिसम्पत्तियों के रूप में बड़े पैमाने पर योगदान है। एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में घरेलू स्तर पर लोगों द्वारा की गई बचत को शामिल करते हैं।
2. **निजी क्षेत्र की बचत :** निजी स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा की गयी बचत को निजी क्षेत्र के निगमों के रूप में जाना जाता है। निजी कम्पनी क्षेत्र में 1) गैर–सरकारी या गैर–वित्तीय कम्पनियों; 2) निजी क्षेत्र में काम करने वाले वाणिज्यिक बैंक एवं बीमा कम्पनियों; 3) सहकारी बैंक, क्रेडिट समितियाँ और गैर ऋण समितियाँ; 4) गैर बैंक वित्तीय समितियाँ को शामिल करते हैं।
3. **सार्वजनिक क्षेत्र की बचत :** सार्वजनिक क्षेत्र की बचत में 1) सरकारी बचत; 2) आंतरिक संसाधनों के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पन्न बचत को शामिल करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की बचत का आकलन करने के लिए सार्वजनिक बचत एवं सरकारी बचत एक वैकल्पिक उपाय है जो सरकार की सम्मिलित रिटर्न की कमी के बीच सम्बन्ध की जांच करने के लिए है।

नगद या भौतिक उत्पादों का वह सेट, जो भविष्य के लिए उपयोगी हो, बचत के रूप में जाना जाता हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा निम्न आय वर्ग वाले समुदायों को सरकार और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बचत के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, बचत को पारम्परिक रूप से क्रेडिट रोटेशन समूह, घरेलू पशुओं के खरीद पर व्यय करके करते हैं। धीरे–धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बचत के पारम्परिक तरीके को समाप्त कर दिया है, लोगों ने बचत करने का तरीका अब शेयर स्टॉक, बॉन्ड की तरह भौतिक उत्पादों के रूप में जैसे सोना, जमीन, टिकाऊ वस्तुएँ और वित्तीय सम्पत्ति के रूप में स्थानान्तरित कर दिया है [5]।

बचत करने के तरीकों में विविधताएँ मुख्य रूप से विभिन्न आय–वर्ग वाले समुदायों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक वातावरण पर निर्भर करती हैं। व्यक्ति समाज के

उत्थान के साथ स्वयं को भी परिवर्तित करता है जिसका बचत पर प्रभाव पड़ता है। निम्न आय वर्ग वाले परिवारों की बचत बहुत कम होती है और अक्सर नकद एवं वस्तुओं के रूप में बचत करते हैं। बचत को नकद के रूप में करना सस्ता एवं आसान उपाय है [2]।

विगत् दस सालों में बचत की तरफ मानव की अभिवृत्ति समाज के विकास के साथ परिवर्तित हुई हैं। विभिन्न आय–वर्गों में बचत निम्न कारकों पर निर्भर करती है : 1) आय में अन्तर; 2) उपभोग करने का तरीका; 3) बचत के प्रति जागरूकता; 4) परिवार का आकार व 5) निवेश के अवसर [6]।

प्रस्तुत अध्याय बचत प्रवृत्तियों से सम्बन्धित है। दौसा जिले की पारिवारिक इकाइयों की औसत बचत प्रवृत्तियाँ विभिन्न आय–वर्गों के अनुसार किस प्रकार की रही है? तथा विभिन्न वर्षों में बचत का स्तर किस प्रकार बढ़ा है?, इत्यादि प्रश्नों से सम्बन्धित तथ्य प्रस्तुत अध्याय में दिये गये हैं। इस अध्याय में विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की औसत मासिक बचत–विषमता एवं उनकी परस्पर तुलना, बचत विषमता की स्थिति, वर्ष 2010 से 2014 तक बचत सूचकांक, औसत व सीमान्त बचत प्रवृत्तियाँ, प्रतीपगमन समीकरण, बचत संस्थाएँ, बचत के उद्देश्य, बचत करने में कठिनाईयाँ, बचत वृद्धि के उपाय, बीमा और बचत एवं पारिवारिक ऋण भार का विश्लेषण किया है जो हमारे सर्वेक्षण विषय को अधिक व्यवहारिक एवं विश्लेषणात्मक रूप प्रदान करते है।

5.1 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की औसत मासिक बचत विषमता एवं उनकी परस्पर तुलना : प्रस्तुत अध्याय में बचत प्रवृत्तियों का अध्ययन दौसा जिले के परिवारों को लेकर किया गया है। चयनित परिवार आय का कितना प्रतिशत बचत करते हैं? तथा विभिन्न आय–वर्गों की बचत प्रवृत्तियों में क्या भिन्नताएँ है? इन प्रश्नों तथा बचत संबंधी अन्य सामान्य जानकारियों का अध्ययन, विशेष रूप से परिवारों द्वारा लिये गये ऋण को लेकर किया गया है। सर्वप्रथम विभिन्न आय–वर्गों के सर्वेक्षित परिवारों के मध्य औसत बचत प्रवृत्तियों की तुलना दो वर्षों 2010 व 2014 के मध्य की है। साथ ही विभिन्न आय–वर्गों में अन्तर्निहित विषमता की जाँच की है।

सारणी 5.1 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की औसत मासिक बचत एवं उनकी परस्पर तुलना ।

आय–वर्ग (मासिक)	कुल परिवार	औसत मासिक बचत 2010 में	औसत मासिक बचत 2014 में	परिवर्तन प्रतिशत में	प्रमाप विचलन 2010 में	विचरण गुणांक 2010 में	प्रमाप विचलन 2014 में	विचरण गुणांक 2014 में
7500 रू से कम	200	235.47	42.02	(–) 82.15	232.15	98.59	40.68	96.81
7500–16000 रू	150	2363.11	1675.69	(–) 29.09	2194.40	92.86	1512.61	90.28
16000–80000 रू	94	12437.18	39972.83	221.39	11555.61	92.91	24617.93	61.59
80000 रू से अधिक	56	40392.20	57006.29	41.13	16553.58	40.98	18274.90	32.05
योग	500	–	–	–	–	–	–	–
सामूहिक माध्य	–	7665.24	14419.11	88.11	–	–	–	–

सारणी 5.1 से दो बातों की जानकारी मिलती है।

1. विभिन्न आय–वर्गों की औसत मासिक बचत की तुलना वर्ष 2010 व 2014 के मध्य करके यह पता लगाना है कि वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में विभिन्न आय–वर्गों की औसत मासिक बचत में कितना परिवर्तन हुआ है।
2. प्रत्येक आय–वर्ग में अन्तर्निहित बचत विषमता वर्ष 2010 व 2014 की ज्ञात की है तथा पारस्परिक आय वर्गों में भी विषमता की मात्रा का अध्ययन किया है।

सारणी 5.1 से पता चलता है कि निम्न आय वर्ग की औसत मासिक बचत वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में घटकर 235.47 रूपये से 42.02 रूपये हो गयी है। निम्न–मध्यम वर्ग की 2363.11 रूपये से घटकर 1675.69 रूपये हुई है। इसी प्रकार मध्यम वर्ग की बचत 12437.18 रूपये से बढ़कर 39972.83 रूपये हुई हैं। परन्तु उच्च आय वर्ग की बचत विशेष रूप से बढ़ी है। जहाँ वर्ष 2010 में यह 40392.20 रूपये थी वहाँ वर्ष 2014 में 57006.29 रूपये हुई है। वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में सभी वर्गों की बचत–विषमता में वृद्धि हुई है। वर्ष 2010 में निम्न तथा निम्न–मध्यम आय वर्ग में बचत विषमता समान थी। मध्यम वर्ग में सर्वाधिक तथा उच्च वर्ग में न्यूनतम रही। इसी तरह वर्ष 2014 में निम्न आय वर्ग की अधिक व उच्च वर्ग की सबसे न्यूनतम रही।

5.2 विभिन्न आय–वर्गों के मध्य बचत–विषमता की स्थिति : विभिन्न आय–वर्गों का कुल बचत में कितना–कितना अंश है, वर्ष 2010 व 2014 में विभिन्न आय–वर्गों के संकलित समंकों को सारणी 5.2 में दर्शाया है। बचत–विषमता को लारेंज वक्र की सहायता से भी ज्ञात किया है।

सारणी 5.2 : विभिन्न आय–वर्गों के मध्य बचत विषमता की स्थिति।

आय–वर्ग (मासिक)	परिवारों की संख्या प्रतिशत में	परिवारों का संचयी प्रतिशत	कुल बचत वर्ष 2010		कुल बचत वर्ष 2014	
			प्रतिशत	संचयी प्रतिशत	प्रतिशत	संचयी प्रतिशत
7500रू से कम	40	40	0.42	0.42	0.04	0.04
7500–16000रू	30	70	4.27	4.69	1.80	1.84
16000–80000रू	18.8	88.8	22.44	27.13	40.50	42.34
80000रू से अधिक	11.2	100.00	72.87	100	57.76	100
योग	100	–	100	–	100	–

सारणी 5.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010 में निम्न वर्ग का कुल बचत में हिस्सा केवल 0.42 प्रतिशत है जबकि इस वर्ग के चयनित परिवारों का प्रतिशत कुल चयनित परिवारों में 40.00 प्रतिशत है। निम्न–मध्यम आय वर्ग का कुल बचत में अंश 4.27 प्रतिशत है तथा कुल चयनित परिवारों का अंश 30.00 प्रतिशत है। ये दोनों वर्ग वर्ष 2010 में अपनी पारिवारिक संख्या के अनुपात में कम बचत करते हैं। मध्यम आय वर्ग के परिवारों का अंश 18.80 प्रतिशत है तथा बचत का अंश 22.44 प्रतिशत है। इसी प्रकार उच्च आय वर्ग के परिवारों का अंश 11.20 प्रतिशत होते हुए भी बचत का अंश 72.87 प्रतिशत है। इस प्रकार वर्ष 2010 में बचत की दृष्टि से चारों वर्गों में काफी विषमता है। इसी प्रकार की स्थिति वर्ष 2014 में भी है। यहां निम्न, निम्न–मध्यम, मध्यम, उच्च आय वर्ग का बचतों में अंश क्रमशः 0.04, 1.80, 40.50, 57.76 प्रतिशत रहा। पांच वर्षों की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि निम्न, निम्न–मध्यम, उच्च आय–वर्गों का बचत में अंश वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2014 में घटा है जबकि मघ्यम आय वर्ग का अंश वर्ष 2010 में 22.44 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014 में 40.50 प्रतिशत हो गया।

लारेन्ज वक्र : विभिन्न आय वर्गों के मध्य बचत विषमता का अध्ययन सारणी 5.2 में प्रस्तुत समंकों की सहायता से लारेंज वक्र (रेखाचित्र 5.1) बनाकर किया है।

रेखाचित्र 5.1 से निम्न तथ्य ज्ञात होते हैं। यहां रेखा OAEKQ निरपेक्ष समानता रेखा है। रेखा OBVMQ वर्ष 2010 तथा OCGWQ रेखा वर्ष 2014 के लिए लारेंज वक्र है।

1. निम्न आय वर्ग की बचत उनके परिवार के अनुपातानुसार AD होनी चाहिए। जबकि वर्ष 2014 में CD बचा पाते हैं अर्थात् विगत पांच वर्षों में इन परिवारों की बचत में गिरावट आई है।
2. निम्न–मध्यम आय वर्ग को उनके परिवार संख्या के अनुपात के अनुसार बचतों का EF भाग होना चाहिए। परन्तु उसके पास वर्ष 2010 में VH बचते हैं। वर्ष 2014 में यह भाग घटकर GI हो गया है।
3. मध्यम आय–वर्ग के पास बचतों का KL भाग होना चाहिए परन्तु वर्ष 2010 में MN व वर्ष 2014 में WO बचत पर उसका अधिकार रहा।
4. उच्च आय–वर्ग का समाज की बचतों में योगदान उसके परिवारों की संख्या के अनुपात में QR होना चाहिए परन्तु उसका योगदान वर्ष 2010 में QS व वर्ष 2014 में घटकर QT हो गया है अर्थात् इस वर्ग के पास वर्ष 2010 में RS बचत अतिरेक था जो वर्ष 2014 में घटकर RT हो गया। इस प्रकार पांच वर्षों में बचत अतिरेक में कमी ST हुई है।

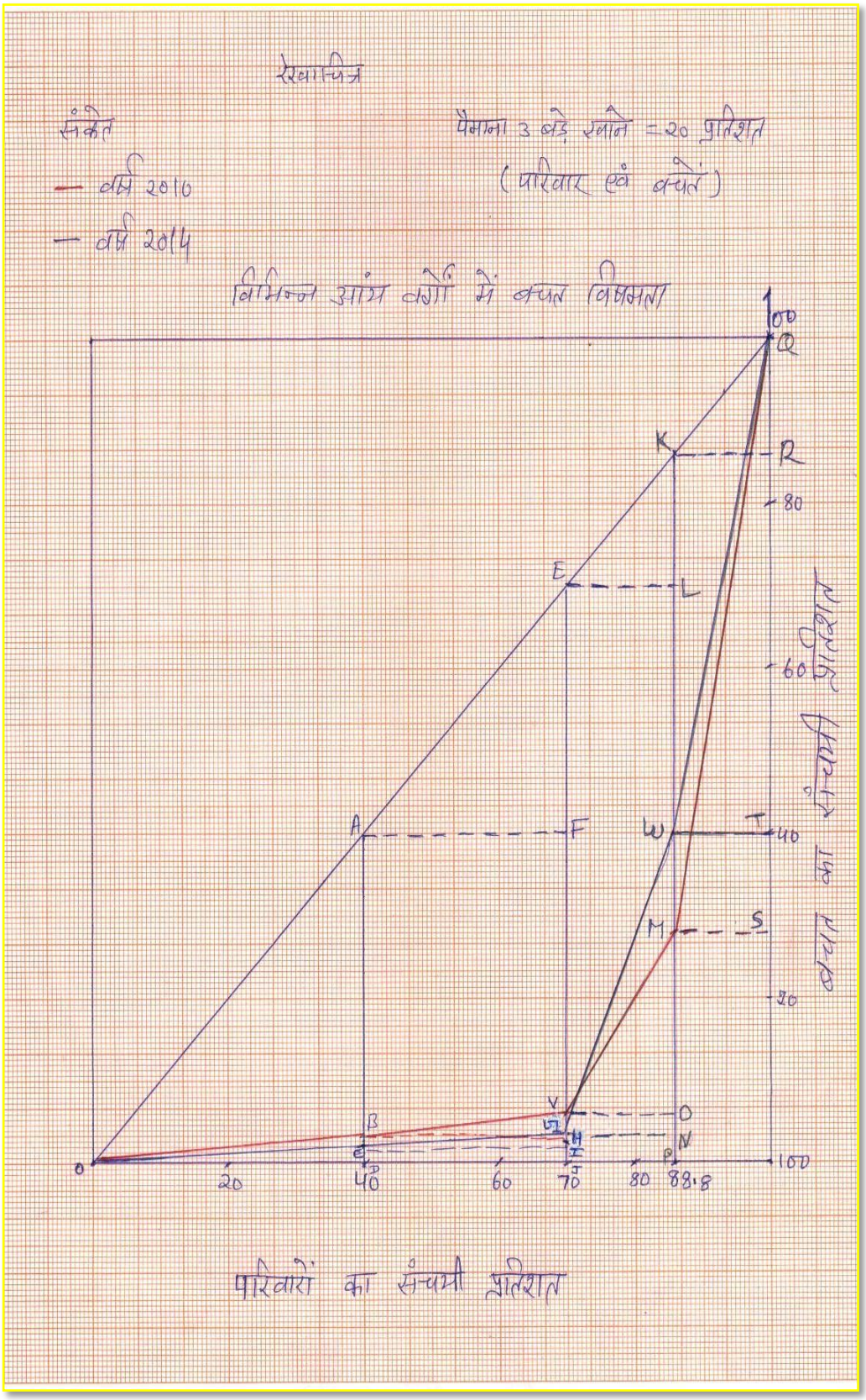

रेखाचित्र 5.1 : लारेंज वक्र

सामूहिक रूप से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2010 के मुकाबले वर्ष 2014 में बचत वितरण की विषमता बढ़ी है। यह वर्ष 2014 के लारेंज वक्र की निरपेक्ष समानता रेखा से वर्ष 2010 के वक्र के मुकाबले दूर निकलने से स्पष्ट होता है। इस अवधि में निम्न, निम्न–मध्यम तथा उच्च आय–वर्गों के पास बचत का भाग कम हुआ है व मध्यम आय वर्ग के पास बचत की मात्रा में वृद्धि हुई है।

5.3 विभिन्न आय–वर्गों के वर्ष 2010 से 2014 तक बचत सूचकांक : इसमें कुल चयनित 500 पारिवारिक इकाईयों के बचत सूचकांक वर्ष 2010 से 2014 तक के लिये है, ताकि विगत् पांच वर्षों में बचत की प्रवृत्तियों में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण कर सकें। इसे सारणी 5.3 में दर्शाया है।

सारणी 5.3 : विभिन्न आय–वर्गों के वर्ष 2010 से 2014 तक बचत सूचकांक

(आधार वर्ष 2010 = 100)।

आय–वर्ग (मासिक)	आधार–वर्ष	बचत–सूचकांक			
	वर्ष 2010	वर्ष 2011	वर्ष 2012	वर्ष 2013	वर्ष 2014
7500 रू से कम	100	20.83	17.96	7.03	17.85
7500–16000 रू	100	88.32	72.73	57.70	70.91
16000–80000 रू	100	110.93	110.48	296.53	321.40
80000 रू से अधिक	100	114.68	119.23	120.10	141.13
समग्र स्थिति	100	83.69	80.10	120.34	137.82

सारणी 5.3 से ज्ञात होता है कि वर्ष 2010 से वर्ष 2014 में समग्र रूप से बचत सूचकांक 100 से बढ़कर 137.82 हो गया तथा वर्ष 2013 में 120.34 हो गया। निम्न आय वर्ग की बचत इन पांच वर्षों में सबसे कम रही है। वर्ष 2014 में सर्वाधिक बचत सूचकांक मध्यम आय वर्ग का रहा।

5.4 विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की औसत व सीमान्त बचत–प्रवृत्तियाँ : सर्वेक्षण के दौरान चयनित पारिवारिक इकाईयों की उपभोग प्रवृत्तियों का अध्ययन करके बचत–प्रवृत्तियों को आंकलित किया है। वर्ष 2010 व 2014 के लिए औसत बचत प्रवृत्ति व सीमान्त बचत प्रवृत्ति को ज्ञात करके सारणी 5.4 में दर्शाया है।

सारणी 5.4 से ज्ञात होता है कि वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में निम्न, निम्न–मध्यम व उच्च आय–वर्गों की औसत बचत प्रवृत्ति में गिरावट आयी है जबकि मध्यम

आय वर्ग की औसत बचत प्रवृत्ति बढ़ी है। इसी प्रकार वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में सभी आय–वर्गों की सीमान्त बचत प्रवृत्ति बढ़ी है।

सारणी 5.4 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की औसत व सीमान्त बचत–प्रवृत्तियाँ।

आय–वर्ग (मासिक)	परिवारों की संख्या	वर्ष 2010		वर्ष 2014	
		APS	MPS (2009-2010)	APS	MPS (2013-2014)
7500 रू से कम	200	0.06	0.07	0.008	0.17
7500–16000 रू	150	0.28	0.33	0.14	0.40
16000–80000 रू	94	0.52	0.62	0.67	0.75
80000 रू से अधिक	56	0.62	0.83	0.61	0.84
योग	500	–	–	–	–
सामूहिक औसत	–	0.27	0.34	0.24	0.43

5.5 प्रतीपगमन समीकरण : बचत प्रवृत्तियों को प्रतीपगमन समीकरण के रूप में सारणी 5.5 में दर्शाया गया है। प्रत्येक आय वर्ग के लिए इनका आंकलन वर्ष 2010 व 2014 के लिए किया गया है।

सारणी 5.5 : प्रतीपगमन समीकरण।

आय–वर्ग (मासिक)	वर्ष 2009–2010	वर्ष 2013–2014
7500 रू से कम	S=0.07y+151.38	S=0.17y+9.42
7500–16000 रू	S=0.33y+664.72	S=0.40y+693.28
16000–80000 रू	S=0.62y-1547.64	S=0.75y+6900.59
80000 रू से अधिक	S=0.83y-18827.39	S=0.84y+627.31
सामूहिक माध्य	S=0.34y-2139.66	S=0.42y+1579.32

सारणी 5.5 से जानकारी मिलती है कि वर्ष 2010 में समग्र रूप से आय का 34.00 प्रतिशत भाग बचाया जाता था तथा 2139.66 रू की ऋणात्मक स्वायत्त बचतें हो रही थी। जबकि वर्ष 2014 में समग्र रूप से आय का 42.00 प्रतिशत भाग बचाया जाता है तथा 1579.32 रूपये की स्वायत्त बचतें हुईं।

5.6 बचत–संस्थाएँ : बचत बढ़ाने के लिए बचत संस्थाओं का बहुत अधिक महत्त्व होता है। दौसा जिले में बचत को जमा कराने के लिए विभिन्न संस्थाएँ हैं, जैसेः विभिन्न बैंक

शाखाएँ, डाकघर आदि। इसी प्रकार सरकार से अनुबन्धित अन्य संस्थाएँ हैं, जिनके एजेन्ट बचत कर्त्ताओं को प्रोत्साहित व प्रेरित करके बचत संकलन का कार्य करते हैं। विभिन्न आय–वर्गों में अपनी बचत को जमा कराने की प्रवृत्ति दौसा जिले में किस प्रकार की है?, इसे सारणी 5.6 में प्रस्तुत किया है।

सारणी 5.6 : बचत–संस्थाएँ।

आय–वर्ग (मासिक)	बचत–संस्थाएँ						योग
	बचत/मयादी जमा खाता	नकद	बॉण्डस	शेयर	भौतिक सम्पत्ति क्रय	अन्य	
7500 रू से कम	178	05	09	02	04	02	200
प्रतिशत	(89.00)	(2.50)	(4.50)	(1.00)	(2.00)	(1.00)	–
7500–16000 रू	98	27	04	02	05	14	150
प्रतिशत	(65.33)	(18.00)	(2.67)	(1.33)	(3.33)	(9.34)	–
16000–80000रू	44	14	08	09	13	06	94
प्रतिशत	(46.81)	(14.90)	(8.51)	(9.57)	(13.83)	(6.38)	–
80000 रू से	24	08	06	10	07	01	56
अधिक प्रतिशत	(42.86)	(14.29)	(10.71)	(17.86)	(12.50)	(1.78)	–
योग	344	54	27	23	29	23	500
प्रतिशत	68.80	10.80	5.40	4.60	5.80	4.60	100

चयनित परिवारों द्वारा बचत को जमा कराने की प्रवृत्ति को दर्शाने वाली सारणी 5.6 बतलाती है कि 68.80 प्रतिशत परिवार अपनी बचत बैंकों में रखते हैं। विशेष रूप से निम्न–मध्यम, मध्यम व उच्च आय–वर्ग के लोग अपनी बचतों को बैंकों में ही रखते हैं जिनका प्रतिशत क्रमशः 65.33, 46.81 व 42.86 हैं। निम्न आय वर्ग के 2.50 प्रतिशत व निम्न–मध्यम आय वर्ग के 18.00 प्रतिशत परिवार अपनी बचतें घर पर रखते हैं। जो परिवार बचतों को घर पर रखते हैं वे अपसंचय की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं अर्थात् राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान नहीं देते हैं।

5.7 बचत के उद्देश्य : बचत के उद्देश्य की जानकारी इसलिए की है कि किस तरह के दृष्टिकोण बचत को सम्भव बनाते हैं। इन उद्देश्यों को सारणी 5.7 में सूचीबद्ध किया है।

सारणी 5.7 : बचत के उद्देश्य।

आय–वर्ग (मासिक)	बचत के उद्देश्य								योग
	बच्चों की भावी आवश्यताओं (फीस आदि) को पूरा करने हेतु	टिकाऊ उपभोग–वस्तु क्रय करने हेतु	पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों को पूरा करने हेतु	आकस्मिक घटनाओं से निपटने हेतु	निवेश करने के लिए	अवकाश के दिनों का आनन्द लेने हेतु	बुढ़ापे में सुरक्षा हेतु	ऋण के भुगतान हेतु	
7500 रू से कम	111	12	43	23	02	01	03	05	200
प्रतिशत	(55.50)	(6.00)	(21.50)	(11.50)	(1.00)	(0.50)	(1.50)	(2.50)	–
7500–16000 रू	75	10	25	19	06	02	07	06	150
प्रतिशत	(50.00)	(6.67)	(16.67)	(12.66)	(4.00)	(1.33)	(4.67)	(4.00)	–
16000–80000 रू	17	14	13	12	10	12	07	09	94
प्रतिशत	(18.09)	(14.89)	(13.83)	(12.77)	(10.63)	(12.77)	(7.45)	(9.57)	–
80000 रू से अधिक	15	12	06	06	04	06	04	03	56
प्रतिशत	(26.79)	(21.45)	(10.71)	(10.71)	(7.14)	(10.71)	(7.14)	(5.35)	–
योग	218	48	87	60	22	21	21	23	500
प्रतिशत	43.60	9.60	17.40	12.00	4.40	4.20	4.20	4.60	100

सारणी 5.7 से पता चलता है कि समग्र रूप से पारिवारिक व सामाजिक दायित्वों को पूरा करने हेतु 17.40 प्रतिशत व बच्चों की भावी आवश्यताओं (फीस आदि) को पूरा करने हेतु 43.60 प्रतिशत परिवार बचत करते हैं। आकस्मिकताओं, टिकाऊ उपभोग–वस्तु क्रय करने हेतु, निवेश करने के लिए, अवकाश के दिनों का आनन्द लेने हेतु, बुढ़ापे में सुरक्षा हेतु एवं ऋण के भुगतान हेतु क्रमशः 12.00, 9.60, 4.40, 4.20, 4.20 एवं 4.60 प्रतिशत परिवार बचत करते हैं।

5.8 बचत करने में कठिनाईयाँ : यदि परिवार बचत करने में विभिन्न प्रकार की कठिनाईयाँ महसूस करते है तो निश्चय ही बचत करने की क्षमता होने पर भी कम मात्रा में बचत करेंगे। सर्वेक्षण के दौरान सूचनादाताओं से यह जानकारी ली गयी कि क्या वे बचत करने में कठिनाईयाँ झेलते है, यदि हां तो किस प्रकार की? इसको सारणी 5.8 में दर्शाया गया हैं।

सारणी 5.8 : बचत करने में मुख्य कठिनाईयाँ।

आय–वर्ग (मासिक)	बचत करने में मुख्य कठिनाईयाँ				योग
	बचत शक्ति या आय का अभाव	निवेश पर प्रतिफल दर कम होना	बचत सुविधा का अभाव	मुद्रास्फीति की अधिक दर	
7500 रू से कम	200	–	–	–	200
प्रतिशत	(100.00)	–	–	–	–
7500–16000 रू	100	28	–	22	150
प्रतिशत	(66.67)	(18.67)	–	(14.66)	–
16000–80000 रू	39	32	–	23	94
प्रतिशत	(41.49)	(34.04)	–	(24.47)	–
80000 रू से अधिक	03	43	–	10	56
प्रतिशत	(5.36)	(76.79)	–	(17.85)	–
योग	342	103	–	55	500
प्रतिशत	68.40	20.60	–	11.00	100

सारणी 5.8 बताती है कि 68.40 प्रतिशत परिवार बचत शक्ति या आय का अभाव को बचत करने में कठिनाई मानते हैं। 20.60 प्रतिशत परिवारों में निवेश पर प्रतिफल दर

कम होना है तथा 11.00 प्रतिशत परिवारों ने मुद्रास्फीति की अधिक दर को कठिनाई माना है।

5.9 बचत वृद्धि के उपाय : बचत आय का फलन है या ब्याज दर का, इस प्रश्न को लेकर प्रतिष्ठित एवं कीन्सवादी अर्थशास्त्रियों में मतभेद पाया जाता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का यह तर्क था कि बचत ब्याज दर पर निर्भर करती है। लेकिन कीन्स इस बात को सही नहीं मानते थे। कीन्स के अनुसार बचत आय–स्तर पर निर्भर करती है। वास्तव में कुछ अंशों तक दोनों ही बातें सही प्रतीत होती हैं। दौसा जिले के परिवार बचत में वृद्धि कब करेंगे, आय बढ़ने पर या ब्याज दर बढ़ने पर। इस प्रश्न की जाँच सर्वेक्षित परिवारों से करने पर पता चलता है कि उनकी बचत में वृद्धि तभी हो सकेगी जब उनके आय–स्तर में वृद्धि हो। अधिक ब्याज दर का प्रलोभन उनकी बचत–दर में वृद्धि नहीं कर पाता। इस प्रकार सर्वेक्षित परिवार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की अपेक्षा प्रो. कीन्स के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

5.10 जीवन बीमा और बचत : वर्तमान मानव जीवन अनिश्चितताओं से परिपूर्ण है। इन अनिश्चितताओं से मुक्ति दिलाने व भावी जीवन में सुरक्षा की गारन्टी देने के साथ–साथ बचत करने का एक ठोस आधार प्रस्तुत करने में बीमा पद्धति अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साथ ही यह नियमित एवं अधिक बचत करने की प्रेरणा भी देती है। दौसा जिले की चयनित इकाइयों पर बीमा सुविधा का बचत पर कितना प्रभाव पड़ा है?, इसको सारणी 5.9 में दर्शाया है।

सारणी 5.9 : जीवन–बीमा कराने के मुख्य कारण।

आय–वर्ग (मासिक)	जीवन–बीमा कराने के मुख्य कारण			योग
	आयकर बचाना	परिवार की सुरक्षा	बचत का सरल तरीका	
7500 रू से कम	–	176	24	200
प्रतिशत	–	(88.00)	(12.00)	–
7500–16000 रू	–	136	14	150
प्रतिशत	–	(90.67)	(9.33)	–
16000–80000 रू	76	18	–	94
प्रतिशत	(80.85)	(19.15)	–	–
80000 रू से अधिक	31	25	–	56
प्रतिशत	(55.36)	(44.64)	–	–
योग	107	355	38	500
प्रतिशत	21.40	71.00	7.60	100

सारणी 5.9 से जानकारी मिलती है कि सभी चयनित इकाइयों ने बीमा करवा रखा है। इनमें से 71.00 प्रतिशत परिवारों ने पारिवारिक सुरक्षा के लिए बीमा करवा रखा है। आयकर बचाने के लिए 21.40 प्रतिशत परिवार व बचत को सरल तरीका मानने वालों में 7.60 प्रतिशत परिवार शामिल हैं। इस प्रकार बीमा करवाने के पीछे मुख्य कारण पारिवारिक सुरक्षा है।

5.11 पारिवारिक ऋण भार : सर्वेक्षण करते समय चयनित इकाइयों द्वारा लिये गये ऋण का भी अध्ययन किया है। यह परिवारों की इस प्रवृत्ति को दर्शाता है कि क्या परिवार ऋण लेकर अपनी आवश्कताओं की पूर्ति करते हैं? यदि हां तो वे किन उद्देश्यों को लेकर एवं किन स्त्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं? चयनित परिवारों में से 122 परिवार ही ऐसे हैं जिन्होंने किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण लिया है। जिन उद्देश्यों से प्रेरित होकर परिवारों ने ऋण लिये है, उन्हें सारणी 5.10 में बताया गया हैं।

सारणी 5.10 : ऋण लेने के प्रमुख कारण।

आय–वर्ग (मासिक)	ऋण लेने के प्रमुख कारण				योग
	शिक्षा	मकान	विवाह	व्यवसाय	
7500 रू से कम	10	08	10	23	51
प्रतिशत	(19.61)	(15.69)	(19.61)	(45.09)	–
7500–16000 रू	11	16	07	04	38
प्रतिशत	(28.95)	(42.11)	(18.42)	(10.52)	–
16000–80000 रू	05	03	02	09	19
प्रतिशत	(26.32)	(15.79)	(10.53)	(47.36)	–
80000 रू से अधिक	–	–	–	14	14
प्रतिशत	–	–	–	(100.00)	–
योग	26	27	19	50	122
प्रतिशत	21.31	22.13	15.57	40.99	100

सारणी 5.10 से पता चलता है कि निम्न तथा निम्न–मध्यम, मध्यम आय–वर्ग के चयनित परिवारों ने शिक्षा, मकान, विवाह तथा व्यवसाय आदि कार्यों के लिए ऋण लिया है जबकि उच्च आय वर्ग के परिवारों ने मुख्यतः व्यवसाय के लिए ऋण लिया है। अतः सामूहिक रूप से स्पष्ट होता है कि लगभग 56.56 प्रतिशत परिवारों ने व्यवसाय, विवाह

आदि सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए व 21.31 प्रतिशत परिवारों ने शिक्षा हेतु ऋण लिया है। मकान बनवाने के लिए केवल 22.13 प्रतिशत परिवारों के व्यक्तियों ने ऋण ले रखा है।

5.11.1 ऋण की मात्रा : सर्वेक्षण के दौरान सूचनादाताओं से ली गयी ऋण की मात्रा की जानकारी को आय वर्गानुसार सारणी 5.11 में दर्शाया है।

सारणी 5.11 : ऋण की मात्रा।

आय–वर्ग (मासिक)	ऋण की मात्रा			योग
	2500 रू से कम	2500–10000 रू	10,000 रू से अधिक	
7500 रू से कम	27	22	02	51
प्रतिशत	(52.94)	(43.14)	(3.92)	–
7500–16000 रू	02	27	09	38
प्रतिशत	(5.26)	(71.05)	(23.69)	–
16000–80000 रू	–	08	11	19
प्रतिशत	–	(42.11)	(57.89)	–
80000 रू से अधिक	–	–	14	14
प्रतिशत	–	–	(100.00)	–
योग	29	57	36	122
प्रतिशत	23.77	46.72	29.51	100

सारणी 5.11 से स्पष्ट है कि सामूहिक रूप से 29.51 प्रतिशत परिवारों पर ऋण का भार 10,000 रू से अधिक है तथा 46.72 प्रतिशत परिवारों पर ऋण भार 2500–10,000 रू के मध्य है एवं 23.77 प्रतिशत परिवारों पर ऋण भार 2500 रू से कम है अर्थात् निम्न व निम्न–मध्यम आय–वर्ग पर ऋण भार कम तथा मध्यम व उच्च आय वर्ग पर ऋण भार अधिक है।

5.11.2 ऋण प्राप्ति के स्त्रोत : सामान्यतया ऋण प्राप्ति के तीन स्त्रोत होते हैं। प्रथम सरकारी जिसमें बैंक या सरकारी समितियाँ प्रमुख हैं। दूसरा सहकारी क्षेत्र से ऋण लेना तथा तीसरा निजी व्यक्तियों से ऋण लेना। ऋण प्राप्ति के स्त्रोतों को सारणी 5.12 में दर्शाया गया है।

सारणी 5.12 : ऋण प्राप्ति के स्त्रोत।

आय–वर्ग (मासिक)	ऋण प्राप्ति के स्त्रोत			योग
	सरकारी	सहकारी	निजी	
7500 रू से कम	05	13	33	51
प्रतिशत	(9.80)	(25.49)	(64.71)	–
7500–16000 रू	11	11	16	38
प्रतिशत	(28.95)	(28.95)	(42.10)	–
16000–80000 रू	10	08	01	19
प्रतिशत	(52.63)	(42.11)	(5.26)	–
80000 रू से अधिक	07	07	–	14
प्रतिशत	(50.00)	(50.00)	–	–
योग	33	39	50	122
प्रतिशत	27.05	31.97	40.98	100

सारणी 5.12 प्रदर्शित करती है कि सामूहिक रूप से चयनित परिवारों के 27.05 प्रतिशत परिवारों ने सरकारी स्त्रोतों से व 40.98 प्रतिशत परिवारों ने निजी स्त्रोतों से ऋण ले रखा है तथा 31.97 प्रतिशत परिवारों ने सहकारी स्त्रोतों से ऋण ले रखा है। निम्न व निम्न–मध्यम आय वर्ग के क्रमशः 64.71 व 42.10 प्रतिशत परिवारों ने साहूकारों से ऋण ले रखा है। इनसे लिये गये ऋण को अनुत्पादक कार्यों में लगाया जाना सम्भव प्रतीत होता है। जमानत के अभाव में तथा सरकारी व सहकारी ऋण लेने की प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने के कारण साहूकारो से ऋण लेते हैं। इसी प्रकार चयनित इकाइयों में से मध्यम आय वर्ग के 94.74 प्रतिशत व उच्च आय–वर्ग के शत–प्रतिशत परिवार सरकारी ऋण व सहकारी ऋण लेते हैं क्योंकि ये ऋण उत्पादक कार्यों के लिए लेते हैं अर्थात् उनकी साख अच्छी होने से ऋण आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार गरीब परिवार आज भी महाजन के शिकंजे में फंसा हुआ है तथा उच्च आय–वर्ग सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाता है।

5.11.3 ब्याज दर : चयनित परिवारों में से जिन्होंने ऋण ले रखा है, उन्हें ब्याज की दर कितनी देनी पड़ती है। कहीं ऋणदाता ऊँची ब्याज दर लेकर उनका शोषण तो नहीं कर रहा है। इसके लिए सर्वेक्षण से प्राप्त समंकों (ब्याज दर) को सारणी 5.13 में दर्शाया है। सारणी 5.13 में ब्याज की दर प्रतिवर्ष प्रति 100 रूपये पर दर्शायी गयी है।

सारणी 5.13 : प्रचलित ब्याज–दर प्रतिशत में।

आय–वर्ग (मासिक)	ब्याज–दर प्रतिशत में			योग
	12 रू से कम	12 से 18 रू	18 रू से अधिक	
7500 रू से कम	05	13	33	51
प्रतिशत	(9.80)	(25.49)	(64.71)	–
7500–16000 रू	11	11	16	38
प्रतिशत	(28.95)	(28.95)	(42.10)	–
16000–80000 रू	10	08	01	19
प्रतिशत	(52.63)	(42.11)	(5.26)	–
80000 रू से अधिक	07	07	–	14
प्रतिशत	(50.00)	(50.00)	–	–
योग	33	39	50	122
प्रतिशत	27.05	31.97	40.98	100

सारणी 5.13 से स्पष्ट है कि औसत रूप से 40.98 प्रतिशत परिवारों को 18.00 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर चुकानी पड़ती है तथा 31.97 परिवारों को 12.00 से 18.00 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मिला हुआ है।

5.11.4 भुगतान–अवधि : विभिन्न आय–वर्गों ने विभिन्न स्त्रोतों से ऋण ले रखा है परन्तु वे उन पर ऋण के भार को कब तक चुका देंगे। उनके द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि को सारणी 5.14 में बताया गया है।

सारणी 5.14 : ऋण–भुगतान अवधि।

आय–वर्ग (मासिक)	ऋण–भुगतान अवधि			योग
	2 वर्ष से कम	2 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	
7500 रू से कम	13	24	14	51
प्रतिशत	(25.49)	(47.06)	(27.45)	–
7500–16000 रू	10	13	15	38
प्रतिशत	(26.32)	(34.21)	(39.47)	–
16000–80000 रू	01	08	10	19
प्रतिशत	(5.26)	(42.11)	(52.63)	–
80000 रू से अधिक	–	04	10	14
प्रतिशत	–	(28.57)	(71.43)	–
योग	24	49	49	122
प्रतिशत	19.68	40.16	40.16	100

सारणी 5.14 यह दर्शाती है कि चयनित परिवारों में से जिन परिवारों ने ऋण ले रखा है वे उनके द्वारा लिये गये ऋण का भुगतान कब तक कर देंगे। इनमें से 40.16 प्रतिशत परिवारों द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान की अवधि 5 वर्ष से अधिक है तथा 40.16 प्रतिशत परिवार 5 वर्ष तक व 19.68 प्रतिशत परिवार 02 वर्ष तक भुगतान कर देंगे। अनिश्चित अवधि में भुगतान करने वाले परिवार निम्न तथा निम्न–मध्यम आय वर्ग के हैं। स्पष्ट है कि जिन्होंने व्यवसायिक कार्यों के लिए ऋण लिया हैं वे निर्धारित अवधि में भुगतान कर देते हैं।

5.12 निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध में दौसा जिले के विभिन्न आय–वर्ग वाले कुल चयनित 500 परिवारों के बचत सम्बन्धी समंक विगत पांच वर्षों हेतु लिये हैं, जो वर्ष 2010 से 2014 तक के हैं। विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों की बचत–प्रवृत्ति की विषमता का तुलनात्मक अध्ययन औसत मासिक बचत, मानक–विचलन एवं विचरण–गुणांक से ज्ञात करके किया है।

दौसा जिले में बचत करने की प्रवृत्ति अधिक नहीं हैं। समाज में व्यक्ति अपनी आय का बहुत कम भाग ही बचाते हैं। औसत बचत प्रवृत्ति वर्ष 2010 में 0.27 है जो कि वर्ष 2014 में घटकर 0.24 हो गई है अर्थात् 0.03 कम हुई है। सर्वेक्षित परिवारों में बचत दर कम होने के कारणों में से कीमत वृद्धि ही उनकी बचत क्षमता में कमी का मुख्य कारण है।

कुल बचत की विवरणात्मक स्थिति का अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि दौसा जिले में बचत प्रवृत्तियों में काफी विषमता विद्यमान है। निम्न आय–वर्ग जो कि लगभग 40.00 प्रतिशत है वह कुल बचत में अपना योगदान मात्र 3.00 प्रतिशत ही करता है जबकि उच्च आय वर्ग के 11.20 प्रतिशत परिवार कुल बचत में अपना योगदान 62.00 प्रतिशत करते हैं। यह विषमता वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में काफी बढ़ी है। वर्ष 2010 में निम्न तथा उच्च आय वर्ग का बचत में योगदान क्रमशः 5.00 व 45.00 प्रतिशत के लगभग था।

सर्वेक्षित परिवारों का निम्नतम आय वर्ग बचत करने में सक्षम नहीं है तथा यह वर्ग जो भी बचत करता है, वह विभिन्न कारणों से आर्थिक विकास में योगदान के दायरे में नहीं आता। इसी प्रकार मध्यम व उच्च आय वर्ग जिसमें बचत की अधिक क्षमता विद्यमान है, वह अपनी बचत का 80.00 प्रतिशत भाग विकास के कार्यों में योगदान देता है तथा शेष को अनुत्पादक कार्यों पर खर्च कर देता है।

दौसा जिले में बचत को एकत्रित करने वाली संस्थाओं की संख्या पर्याप्त होने के बावजूद भी विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं एवं कागजी कार्यवाही के अलावा नियमों की क्लिष्टता व अनभिज्ञता आदि के कारण बचत को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। अधिकांश

परिवार अपनी बचत को घर पर ही अपसंचय के रूप में रखकर उसे अविवेकपूर्ण तरीके से खर्च कर देते हैं।

5.13 संदर्भ सूची (References):

1. Abid, S. and Afridi, G. S. **(2010)**. Assessing the Household Saving Pattern of Urban and Rural Households in District Muzaffarabad. ***Pakistan Journal of Life Social Science***, 8 (2): 137-141.
2. Salam, A. and Kulsum, U. **(2000)**. Savings Behaviour in India: An Empirical Study. ***The Indian Economic Journal***, 50(1): 78-80.
3. Tarujyoti, B. **(2009)**. Household Savings in India: An Econometric Assessment. ***The Journal of Income and Wealth***, 31 (1).
4. Rao, V. K. R. V. **(1980)**. Saving, Capital Formation and National Income. ***Economic and Political Weekly***, 15: 965.
5. Rehman, H., Faridi, M. and Bashir, F. **(2010)**. Households Saving Behaviour in Pakistan: A Case of Multan District. ***Pakistan Journal of Social Sciences***, 30(1): 17-29.
6. Burney, N. and Khan, A. H. **(1992)**. Socio-Economic Characteristics and Household Savings: An Analysis of Household Saving Behaviour in Pakistan. ***The Pakistan Development Review***, 31 (1): 31-48.

*****

अध्याय – 6

आय, उपभोग एवं बचत अध्ययन के निष्कर्ष एवं नीतिगत निहितार्थ

आय, उपभोग एवं बचत अध्ययन के निष्कर्ष एवं नीतिगत निहितार्थ

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य दौसा जिले की पारिवारिक इकाईयों की आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर यह ज्ञात करना हैं कि ये प्रवृत्तियाँ किन कारकों से प्रभावित होती हैं तथा इनमें परिवर्तन किस दिशा में हैं। प्रस्तुत शोध में कुल 500 सर्वेक्षित परिवारों को चार पृथक–पृथक आय–वर्गों में विभाजित कर उनकी आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों का पृथक–पृथक रूप से अध्ययन किया गया है। अध्ययन में यह पाया कि यहां के निवासियों का जीवन स्तर अधिकांशतः निम्न तथा मध्यम स्थिति को दर्शाता है। दौसा जिले में महिलाओं द्वारा व्यवसाय करने की प्रवृत्ति बहुत कम है एवं व्यवसायिक दृष्टि से दौसा जिला जयपुर जिले से प्रतियोगिता के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जिसके कारण कस्बे की जनसंख्या अधिक होने के बावजूद बाजार के आकार से विनियोगकर्ता विनियोग हेतु प्रेरित नहीं होते हैं।

सामान्यतया यह माना जाता है कि समाज व देश के लिए बचत आर्थिक विकास का आधार है तथा यह आय एवं उपभोग के अन्तर पर निर्भर करती हैं। बचत की मात्रा कितनी होगी यह आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। निम्न आय वर्ग की आय कम होने के कारण यह वर्ग बचत कम कर पाता है जबकि उच्च आय वर्ग की आय अधिक होने के कारण बचत करने में सक्षम होता है। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न आय वर्ग की अधिकता के कारण क्या इससे बचत की अपेक्षा न रखी जावे अथवा केवल उन लोगों से ही अधिक बचत की अपेक्षा की जावे जो संख्या में बहुत ही कम हैं। साथ ही उच्च आय वर्ग अपनी आय को प्रतिष्ठा के वशीभूत होकर विलासिता की वस्तुओं एवं अनुत्पादक मदों पर व्यय करता है। वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है कि उच्च आय वर्ग की उस आय को बचत के रूप में एकत्रित किया जावे जो आय व्यय के रूप में अनुत्पादक कार्यों में प्रयोग की जाती है। साथ ही निम्न आय वर्ग को भी छोटी–छोटी बचत के लिए प्रेरित किया जावें, क्योंकि बूंद–बूंद से ही सागर भरता है।

इस हेतु चयनित पारिवारिक इकाइयों की आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों का विस्तृत एवं गहन अध्ययन हम पिछले तीन अध्यायों में पृथक–पृथक कर चुके हैं। इस पृथक–पृथक अध्ययन से प्रस्तुत सर्वेक्षण में विभिन्न प्रश्नों एवं समस्याओं का अध्ययन किया गया है। परन्तु इन तीनों चरों का पृथक–पृथक अध्ययन करने से इनकी तुलनात्मक स्थिति को एक साथ प्रदर्शित न कर पाने के कारण प्रस्तुत शोध अपूर्ण प्रतीत होता है। इसलिए विषय को सरल, तर्कसंगत एवं बोधगम्य बनाने हेतु प्रस्तुत अध्याय के प्रथम खण्ड में तीनों

आर्थिक चरों की कुछ प्रवृत्तियों को विभिन्न आय–वर्गों एवं वर्षों के आधार पर सामूहिक रूप से प्रदर्शित कर तथ्यों की पारस्परिक तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

इसी अध्याय के द्वितीय खण्ड में सर्वेक्षित परिवारों की आय, उपभोग एवं बचत वृद्धि से सम्बंधित विभिन्न समस्याओं एवं तृतीय खण्ड़ में इन समस्याओं को दूर करने के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं।

6.1 आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन :

6.1.1 औसत आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियाँ : पिछले तीन अध्यायों से प्राप्त आय, उपभोग एवं बचत से सम्बन्धित तथ्यों को तुलनात्मक रूप देकर उन्हें सामूहिक रूप से सारणी 6.1 में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी 6.1 विभिन्न आय–वर्गों की औसत आय, उपभोग एवं बचत की तुलना न केवल आय वर्गानुसार ही प्रस्तुत करती है, बल्कि औसत आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों की तुलना वर्ष 2010 एवं वर्ष 2014 के मध्य प्रत्येक आय–वर्ग में परिवर्तित स्थितियों को भी दर्शाती है।

सारणी 6.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2010 की अपेक्षा वर्ष 2014 में कुल आय में तथा निरपेक्ष रूप से उपभोग एवं बचत में वृद्धि हुई है। सामूहिक रूप से भी उक्त स्थिति ही रही है। जब हम सापेक्ष रूप से देखते हैं तो निम्न आय वर्ग की आय, उपभोग एवं बचत का प्रतिशत परिवर्तन वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2014 में क्रमशः 37.02 प्रतिशत, 44.67 प्रतिशत एवं (–) 82.15 प्रतिशत है। आय की अपेक्षा उपभोग का प्रतिशत अधिक रहने से बचत ऋणात्मक रही है। अतः निम्न आय वर्ग ने अपनी बचत में कमी की है। इसी प्रकार निम्न–मध्यम एवं मध्यम वर्ग में आय की तुलना में उपभोग का प्रतिशत अधिक रहा है तथा इन दोनों वर्गों की बचत का प्रतिशत क्रमशः (–) 29.09 एवं 221.39 है। इस प्रकार निम्न, निम्न–मध्यम व मध्यम आय वर्गों में उपभोग का प्रतिशत अधिक रहा है। जिसका कारण पारिवारिक आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ–साथ कीमतों में वृद्धि को माना है। इसके विपरीत जब उच्च आय वर्ग को देखते हैं तो इनकी आय 43.54 प्रतिशत बढ़ी है जबकि उपभोग 47.41 प्रतिशत ही बढ़ा हैं, फलस्वरूप बचत का प्रतिशत 41.13 रहा हैं। अतः एक सीमा के बाद ज्यों–ज्यों आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, परन्तु उपभोग में वृद्धि का प्रतिशत आय के प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है।

सारणी 6.1 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों का वर्ष 2010 एवं 2014 में औसत आय, उपभोग एवं बचत का तुलनात्मक विश्लेषण।

आय–वर्ग (मासिक)	परिवारों की संख्या	वर्ष 2010			वर्ष 2014			प्रतिशत परिवर्तन		
		मासिक औसत			मासिक औसत					
		आय	उपभोग	बचत	आय	उपभोग	बचत	आय	उपभोग	बचत
7500 रू से कम	200	3902.15	3666.68	235.47	5346.65	5304.63	42.02	37.02	44.67	(–) 82.15
7500–16000 रू	150	8567.69	6204.58	2363.11	11954.11	10278.42	1675.69	39.53	65.65	(–) 29.09
16000–80000 रू	94	23908.44	11471.26	12437.18	59261.69	19288.86	39972.83	147.87	68.15	221.39
80000 रू से अधिक	56	65479.13	25086.93	40392.20	93987.50	36981.21	57006.29	43.54	47.41	41.13
योग	500	–	–	–	–	–	–	–	–	–
सामूहिक माध्य	–	15959.62	8294.38	7665.24	27392.69	12973.5	14419.11	71.64	56.41	88.11

उपर्युक्त तथ्यों को सारणी 4.5 से MPS एवं सारणी 5.4 से MPS के माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। सामूहिक रूप से देखने पर वर्ष 2010 में जो MPC = 0.66 व MPS = 0.34 थी, वह वर्ष 2014 में MPC = 0.57 तथा MPS = 0.43 हो गयी। निरपेक्ष रूप से निम्न आय–वर्ग की वर्ष 2010 में जो MPC = 0.92 व MPS = 0.07 थी वर्ष 2014 में वह MPC = 0.83 व MPS = 0.17 हो गयी। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि–

1. खर्च योग्य आय एवं उपभोग में धनात्मक सरलरेखीय गैर–आनुपातिक सम्बन्ध पाया जाता है।

2. अधिक औसत आय वाले परिवारों में कम आय वाले परिवारों की तुलना में औसत उपभोग प्रवृत्ति कम पायी जाती है।

3. आय बढ़ने के साथ–साथ औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती जाती है, लेकिन $APC > MPC$ रही हैं।

6.1.2 विभिन्न आय–वर्गों में आय, उपभोग एवं बचत में विषमता की स्थिति : सर्वेक्षण में औसत आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों के अध्ययन के साथ–साथ विभिन्न आय–वर्गों में अन्तर्निहित विषमताओं का अध्ययन आय, उपभोग एवं बचत की मात्रा का सम्बन्ध वर्ष 2010 व वर्ष 2014 के माध्यम से दर्शाया गया है। आय, उपभोग एवं बचत के सम्बन्ध में किस आय–वर्ग में विषमता अधिक है, को सारणी 6.2 में दर्शाया गया हैं।

सारणी 6.2 : विभिन्न आय वर्ग वाले परिवारों में आय, उपभोग एवं बचत में विषमता की स्थिति।

आय–वर्ग (मासिक)	परिवारों की संख्या (प्रतिशत)	आय (प्रतिशत)		उपभोग (प्रतिशत)		बचत (प्रतिशत)	
		वर्ष 2010	वर्ष 2014	वर्ष 2010	वर्ष 2014	वर्ष 2010	वर्ष 2014
7500 रू से कम	40.00	5.41	4.89	7.90	7.38	0.42	0.04
7500–16000 रू	30.00	14.67	13.68	13.36	14.31	4.27	1.80
16000–80000 रू	18.8	45.67	46.97	24.71	26.84	22.44	40.50
80000 रू से अधिक	11.2	34.25	34.46	54.03	51.47	72.87	57.76
योग	100	100	100	100	100	100	100

सारणी 6.2 से स्पष्ट है कि वर्ष 2014 में निम्नतम आय वर्ग के 40.00 प्रतिशत परिवारों को कुल आय का 4.89 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है जबकि उच्चतम आय वर्ग के 11.20 प्रतिशत परिवारों को कुल आय का 34.46 प्रतिशत भाग प्राप्त होता है। निम्न–मध्यम

आय वर्ग की स्थिति कुछ अंशों में निम्न आय–वर्ग के अनुकूल है परन्तु मध्यम आय वर्ग की स्थिति उच्च आय–वर्ग की तरह परिवर्तित होती रही है। जहां उपभोग एवं बचत में विषमता का प्रश्न है उच्च एवं मध्यम आय वर्गों का उपभोग एवं बचत स्तर काफी अधिक है।

जबकि निम्न एवं निम्न–मध्यम आय वर्गों का उपभोग एवं बचत स्तर तुलनात्मक रूप से दयनीय स्थिति में है। अतः सारणी से स्पष्ट है कि आय, उपभोग एवं बचत तीनों में ही काफी मात्रा में वर्गानुसार वैषम्य दौसा जिले में विद्यमान है।

6.1.3 विभिन्न आय–वर्गों में आय, उपभोग एवं बचत सूचकांकों की तुलना : विगत पांच वर्षों में विभिन्न आय–वर्गों के मध्य आय, उपभोग एवं बचत में परिवर्तन की प्रवृत्तियों का अध्ययन सूचकांकों के माध्यम से पृथक–पृथक रूप से पिछले अध्यायों में किया गया है। प्रस्तुत खण्ड में आय, उपभोग एवं बचत की तुलना वर्ष 2010 को 100 मानकर वर्ष 2014 के लिए की गयी है। विभिन्न आय वर्ग वाले परिवारों में आय, उपभोग एवं बचत सूचकांकों को सारणी 6.3 में प्रदर्शित किया है।

सारणी 6.3 : विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों में आय, उपभोग एवं बचत सूचकांक की परस्पर तुलना ।

आय–वर्ग (मासिक)	आधार वर्ष 2010	आय–सूचकांक 2014	उपभोग–सूचकांक 2014	बचत–सूचकांक 2014
7500 रू से कम	100	137.02	144.67	17.85
7500–16000 रू	100	139.53	165.66	70.91
16000–80000 रू	100	247.87	168.15	321.40
80000 रू से अधिक	100	143.54	147.41	141.13
योग (औसत)	100	166.99	156.47	137.82

सारणी 6.3 से कुल सर्वेक्षित परिवारों की समग्र स्थिति का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि आधार वर्ष 2010 = 100 की तुलना में वर्ष 2014 में आय, उपभोग एवं बचत क्रमशः 166.99, 156.47, 137.82 हो गयी हैं।

अतः स्पष्ट है कि उपभोग में वृद्धि बचत की तुलना में अधिक हुई है। निम्न वर्ग का बचत सूचकांक घटकर 17.85 रह गया है। जबकि बचत सूचकांक में सर्वाधिक वृद्धि मध्यम आय वर्ग में रही है। उपभोग में भी सर्वाधिक वृद्धि मध्यम आय वर्ग की रही है।

यदि इन प्रवृत्तियों का कारण जानना चाहें तो यह स्थिति सामने आती है कि उच्च आय वर्ग का उपभोग स्तर वर्ष 2014 में निम्न–मध्यम एवं मध्यम आय वर्गों से कम रहा है।

निम्न आय वर्ग की आय अधिक नहीं होने के कारण उपभोग का स्तर बढ़ने से बचत कम हुई है। मध्यम आय वर्ग को अपने स्तर को बनाये रखने हेतु अधिक उपभोग करना पड़ा है।

6.2 समस्याएँ :

सर्वेक्षण के दौरान यह पाया की विभिन्न आय–वर्गीय परिवारों के समक्ष किन–किन कठिनाईयों ने इनकी आय, उपभोग एवं बचत में वृद्धि पर रोक लगा रखी है। ये समस्याएँ निम्न हैं :

1. दौसा जिले में अधिकांश परिवार निर्धनता की स्थिति में होने के कारण नये सहायक व्यवसाय शुरू करने में एवं वंशानुगत व्यवसाय के संचालन में वित्तीय कठिनाईयों को महसूस करते हैं। साथ ही मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त आय के सहायक स्त्रोतों को अपनाने में भी उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्थात् ग्रामीण वातावरण के कारण परिवार आय अर्जित करने के सहायक स्त्रोतों की जानकारी नहीं रखते। साथ ही अपनी आय–व्यय का ब्यौरा भी सामान्यतः नहीं रखते हैं।
2. सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमों के अभाव के कारण भी रोजगार का स्तर निम्न बना हुआ है जिससे लोगों को आय अर्जित करने हेतु अन्यत्र स्थानों पर जाना पड़ता है।
3. अधिकांश परिवार का मौसमी व्यवसायों में संलग्न रहने के कारण आय की अस्थिरता युक्त जीवन यापन करते हैं।
4. बाजार के आकार में वृद्धि नहीं होने के कारण व्यवसायिक विकास में बाधा आती है।
5. बचत को एकत्रित करने वाली संस्थाओं जैसे– बैंक, डाकघर आदि द्वारा उन परिवारों तक पर्याप्त प्रचार व प्रसार नहीं हो पाता जिनकी बचत अल्प है।
6. परिवारों को सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा उचित ब्याज दर पर पर्याप्त मात्रा में ऋण न मिल पाने के कारण महाजनों से अधिक ब्याज दरों पर ऋण लेना पड़ता है जिसके कारण ये कई वर्षों तक महाजनों के चंगुल से नहीं निकल पाते हैं।

6.3 अनुशंसाएँ :

अध्ययन में पाया गया कि दौसा जिले के अधिकांश परिवारों का जीवन–स्तर अब भी उम्मीदों से काफी नीचे है। दौसा जिले का एक बड़ा प्रतिशत भाग निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत आता है। यह उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति एवं अधिक लागत वाले रोजगारों के कारण है। उनके आर्थिक उत्थान के लिए सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके आय, उपभोग एवं बचत स्तर में सुधार की आवश्यकता है। अतः पारिवारिक इकाईयों को उस स्तर तक प्रशिक्षित एवं जागरूक करने की आवश्यकता है, जहां वे आय, उपभोग एवं बचत सम्बन्धी निर्णय अपने विवेक से लेकर अपने परिवार को ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज को लाभान्वित कर सके। इसके लिए तीन प्रकार के वर्गों [1) परिवारों के वे सदस्य जिन्हें आय व्यय सम्बन्धी निर्णय स्वयं लेने हैं; 2) स्वयं सेवी संस्थाओं, जो इस दिशा में योगदान करने हेतु तैयार हैं; 3) सरकार अथवा स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थायें तथा वित्तीय संस्थायें] को मिल–जुलकर इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। इन तीनों प्रकार के वर्गों को समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए जिससे कि आय, उपभोग एवं बचत में अत्यधिक वृद्धि हो सके। इस हेतु कुछ सुझाव निम्न प्रकार हैं :

1. **सरकारी योंजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रचार–प्रसार :** अध्ययन–क्षेत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निम्न आय–वर्ग के परिवारों के आवास–स्थिति दुःखद पायी गई है। हांलाकि सरकार ने बेहतर योजनाओं को लागू किया है लेकिन इन योजनाओं के बारे में जागरूकता नहीं होने के कारण इनका सही उपयोग नहीं हो पाया हैं। अतः इस प्रकार की योजनाओं व कार्यक्रमों की सुव्यवस्थित क्रियान्वित के साथ–साथ आमजन एवं सुदूर–क्षेत्रों तक इनके समुचित प्रचार–प्रसार की अत्यधिक आवश्यकता है।
2. **स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता :** निम्न आय वर्ग वाले परिवारों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने के लिए उनके आय, उपभोग एवं बचत स्तर में सुधार आवश्यक है। पर्याप्त शिक्षित नहीं होने के कारण ऐसे परिवारों में स्वास्थ्य के मानक स्तर के बारे में या तो जानकारी नहीं है या स्वास्थ्य के प्रति उदासीन हैं। इसलिए वे नशा अर्थात् तंबाकू, नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के शिकार हो जाते हैं जोकि उनके स्वास्थ्य एवं जीवन–स्तर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।
3. **शैक्षिणिक स्तर में सुधार :** सामाजिक वातावरण में उन्नति हेतु शिक्षा एक प्रमुख कारक है अतः शिक्षा का प्रसार विशेषतः स्त्री शिक्षा का प्रसार करना भी समाज की

आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों में अनुकूल परिवर्तन ला सकता है। क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही बचत का महत्त्व अच्छी तरह समझ सकता है तथा वह उपभोग सम्बन्धी निर्णय भी विवेकपूर्ण ढ़ंग से ले सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों और निम्न आय वर्ग वाले परिवारों का शैक्षिणिक स्तर शहरी एवं उच्च आय वर्ग वाले परिवारों की तुलना में काफी कम है, अतः उनके शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए आवश्यक रियायते एवं प्रभावी कार्यक्रम आवश्यक हैं।

4. **निम्न आय वर्ग के विकास हेतु विशेष योजनाओं का संचालन :** पांच दशकों के बाद भी निम्न आय वाले परिवारों के उत्थान सम्बन्धी कार्यक्रम क्रियान्वित होने के बाद भी उनके विश्लेषण में निराशाजनक तस्वीर सामने आई है। उनके आर्थिक उत्थान के लिए आजीविका के साधनों तथा कार्यशैली तरीकों में बदलाव आवश्यक है। इसके अलावा कृषि मजदूरों के मामले में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी लागू किया जाना चाहिए।
5. **आजीविका के परम्परागत तरीकों में बदलाव या अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग :** ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवारों के पास स्वयं की कृषि हेतु जमीन नहीं होती है वे दूसरे लोगों के यहां कृषि सम्बन्धी मजदूरी करते हैं अर्थात् वे कृषि योग्य भूमि की अनुपलब्धता से विकलांग हैं। साथ ही कुछ किसानों के पास संसाधनों की कमी भी उनकी जमीन के विकास के लिए बाधक है। इसलिए ऐसे परिवारों को कृषि एवं लधु उद्योग क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने चाहिए ताकि उनका आर्थिक विकास हो सके।
6. **कृषि, लघु व कुटीर उद्योगों का विकास :** सरकार को आय, उपभोग एवं बचत वैषम्य को कम करने के लिए उच्च आय वर्ग के व्यवसायिक एकाधिकार पर नियंत्रण के उपायों के साथ–साथ ऐसे सार्वजनिक उद्यमों का विकास करना चाहिए जिसमें न केवल कमजोर वर्गों को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों सके बल्कि जमाखोरी पर रोक लगाकर उच्च आय वर्ग की बढ़ती आय को नियन्त्रित किया जा सके।
7. **सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार :** उपभोग सम्बन्धी वैषम्य को कम करने के लिए सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास करना चाहिए। साथ ही उनके नियन्त्रण एवं संचालन में यथोचित सुधार करने चाहिए। कमजोर वर्ग को विशेष रियायतों के साथ विभन्न सार्वजनिक सेवायें उपलब्ध करानी चाहिए।

8. **कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकासार्थ वित्तीय सहायता :** मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त सहायक स्त्रोतों के विकास पर सरकार को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए तथा वित्तीय संस्थाओं को इस प्रकार के निर्देश दिये जाने चाहिए कि वे समाज के कमजोर वर्गों का विशेष ध्यान रखें। सरकार को कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकासार्थ वित्तीय सहायता के साथ–साथ तकनीकी एवं अन्य जानकारियाँ भी देनी चाहिए।
9. **उपभोक्ता सहकारिता–संघों की स्थापना :** सरकार को रोजगार कार्यालय खोलकर लोगों को रोजगार के अवसरों की जानकारी समय–समय पर देनी चाहिए। वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों पर नियंत्रण हेतु जिले में उपभोक्ता सहकारिता संघ का विकास किया जाना चाहिए।
10. **अनुत्पादक कार्यों के व्ययो पर नियंत्रण :** सरकार को अनुत्पादक कार्यों के व्यय पर रोक लगाने हेतु कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि मादक वस्तुओं का उपभोग नियंत्रित हो सके तथा इस व्यय को लोग अन्य मदों पर व्यय करके जीवन–स्तर सुधारें या फिर बचत के रूप में रक्षित करें।
11. **मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण :** सरकार को कीमत–वृद्धि की प्रवृत्ति पर रोक लगानी चाहिए अर्थात् कीमत प्रभाव और आय प्रभाव से सम्बन्धित नीतियों को बचत करने के तरीकों में शामिल करना चाहिए ताकि लोगों में आर्थिक स्थिरता की भावना विकसित हो तथा वे अधिक बचत करने हेतु प्रेरित हों।
12. **वित्तीय संस्थाओं की पारदर्शिता में वृद्धि :** ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को जनहितकारी होना चाहिए। इन वित्तीय संस्थाओं जैसे–बैंक, डाकघर आदि को बचत के महत्त्व को लोगों तक पहुँचानें के लिए प्रचार–प्रसार का माध्यम अपनाना चाहिए तथा वित्तीय संस्थाओं को लोगों में इस प्रकार की भावना जाग्रत करनी चाहिए कि वे अपनी बचतों को घर पर न रखकर बैंकों में जमा करवायें। इस भावना को जागृत करने के लिए वित्तीय संस्थानों की ब्याज दर नीतियों एवं सरकारी नीतियों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उचित एवं प्रभावी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए अर्थात् बैंकों द्वारा न केवल पर्याप्त ब्याज राशि का प्रलोभन दिया जाना चाहिए बल्कि बचत को जमा करवाने एवं वापस निकलवाने की प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए।
13. **जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण :** जनसंख्या की वृद्धि के कारण भी परिवार की प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है जिससे उपभोग एवं बचत स्तरों में कमी आती है।

अतः समाज को परिवार नियोजन का महत्त्व समझना चाहिए तथा सरकारी एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को इस हेतु और अधिक प्रयत्न करने चाहिए।

14. **सरकार द्वारा विभिन्न आय–वर्गों का समय–समय पर समंक संग्रह :** दौसा जिले के विभिन्न आय–वर्ग वाले परिवारों के आय, उपभोग एवं बचत सम्बन्धित पर्याप्त समंक राज्य स्तर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके अध्ययन की एक प्रमुख समस्या है। अतः इस क्षेत्र से सम्बन्धित गहन समंक संग्रह शोधकर्ताओं की मदद करने के लिए आवश्यक है।

आय, उपभोग एवं बचत की प्रवृत्तियाँ जो दौसा जिले में विद्यमान हैं उनमें अनुकूल परिवर्तन हेतु उपर्युक्त सुझाव तब तक केवल सुझाव मात्र ही रहेंगे जब तक दौसा जिले के परिवार स्वयं आगे आकर इन प्रवृत्तियों में सुधार हेतु प्रयास नहीं करेंगे। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य भी तभी सार्थक हो सकेगा, जब इनका विस्तृत अध्ययन कर सामूहिक कदम उठाकर अनुकूल परिवर्तन लाये जावें।

*****

अध्ययन का अपेक्षित योगदान

अध्ययन का अपेक्षित योगदान

प्रत्येक देश के लोक–कल्याण से सम्बन्धित सभी कार्य उस देश की आर्थिक नीति पर निर्भर करते हैं। एक लोक–कल्याणकारी सरकार आर्थिक नीतियों का निर्धारण इस प्रकार करती है, जिससे देश में रोजगार, उत्पादन एवं उपभोग के स्तर में वांछनीय प्रगति हो सके। सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में आय, उपभोग एवं बचत से सम्बंधित आँकड़ों का संग्रहण एवं विश्लेषण करना आवश्यक होता है, ताकि उपयुक्त नीति का निर्धारण किया जा सके।

विकसित एवं विकासशील देशों के तीव्र आर्थिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने के लिए आय, उपभोग एवं बचत सम्बंधित आँकड़ों का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

प्रस्तुत शोध आगे अनुभवजन्य अनुसंधान के लिए अवसर प्रदान करता है ताकि दौसा जिले में सरकार द्वारा उचित आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जा सके।

अतः प्रस्तुत शोध भारतीय समाज में आय, उपभोग एवं बचत–प्रवृत्तियों को समझने तथा समष्टिगत स्तर पर इनके निहितार्थो का व्याख्यात्मिक करने की दृष्टि से एक सार्थक प्रयास होगा, अर्थात् यह अध्ययन शैक्षणिक एवं नीति निर्धारक दोनों दृष्टियों से सार्थक योगदान दे सकेगा।

*****

संदर्भ ग्रन्थ (Bibliography)

संदर्भ ग्रन्थ (Bibliography)

1. Abramovitz, M. **(1956)**. Resource and Output Trends in the United States since 1870. ***American Economic Review***, 46: 5-23.
2. Abramowitz, M. **(1955)**. Capital Formation and Economic Growth. ***Princeton University Press, National Bureau of Economic Research and Stanford University***.
3. Ackley, G. **(1961)**. Macroeconomic Theory. ***Macmillan and Co., London***.
4. Akhtar, S. **(1986)**. Dependency, Urbanization, Education and Household Saving. ***Some Preliminary Evidence from Pakistan, Saving and Development Review***, 11 (4).
5. Ali, S. M. **(1985)**. Household Consumption and Saving Behaviour in Pakistan: An Application of the Extended Linear Expenditure System. ***The Pakistan Development Review***, 24.
6. Attanasio, O. P. **(1998)**.Consumption Demand. ***NBER Working Paper No. 6466***.
7. Ayub, F. **(2001)**. Determinates of Household Saving in Pakistan. ***Unpublished M. A (Economics) Thesis, Department of Economics. Fatima Jinnah Women University, Rawalpindi***.
8. Azhar, A. B. **(1995)**. Rural Savings their Magnitude, Determinants and Mobilization. ***The Pakistan Development Review***, 34: 779-788.
9. Banerjee, D., Shivani, S. **(2011)**. Analysis of Literature Review of Consumption Pattern – An Important Indicator of Economic Development. ***International Journal of Enterprise Computing and Business Systems***, 1 (2): 1-14.
10. Bover, O. **(2005)**. Wealth Effects on Consumption: Microeconometric Estimates from the Spanish Survey of Household Finances. ***Bank of Spain working paper, Documentos de Trabajo, Nº 0522***.
11. Campbell, J. Y. and Mankiw, N. G. **(1989)**. Consumption – Income and Interest rates: Reinterpreting the Time Series Edidence. ***NBER Macroeconomics Annual, MIT Press***, 4: 185-246.
12. Carroll, C. D. **(2001b)**. A Theory of the Consumption Function, With and Without Liquidity Constraints. ***Journal of Economic Perspectives***, 15: 23-46.
13. Carroll, C. D. **(2001c)**. A Theory of the Consumption Function, With and Without Liquidity Constraints. ***NBER Working Paper W8387***.

14. Chambers, M. J. **(1991)**. An Alternative Time Series Model of Consumption: Some Empirical Evidence. ***Applied Economics***, 23: 1361-1366.
15. Chaturvedi, S. and Barbar, R. (2014). Impact of Social Media on Consumer Behaviour. ***International Journal of Research in Management and Business Studies***, 2 (2): 107-114.
16. Chowa, G. A. N., Ansong, D. and Masa, R. **(2010)**. Assets and Child Well-Being in Developing Countries. ***A Research Review and Children & Youth Services Review***, 32: 1508-1519.
17. Cochran, W.G. **(1977)**. Sampling Techniques (Eds. III). ***John Wiley & Sons, Inc., New York***.
18. Dardis, R., Derrick, F. and Lehfeld, A. **(1981)**. Clothing Demand in the United States: A Cross-Sectional Analysis. ***Home Economics Research Journal***, 10 (2): 212-222.
19. Davidson, J. E. H., Hendry, D. F., Srba, F. and Yeo, S. **(1978)**. Econometric Modeling of Aggregate Time Series Relationship between Consumers, Expenditure and Income in United Kingdom. ***The Economic Journal***, 88: 661-692.
20. Davis, M. A. **(1984)**. The Consumption Function in Macroeconomic Models: A Comparative Study. ***Applied Economics***, 16: 799-838.
21. Davis, R., Soberon-Ferrer, H. and Patro, D. **(1993)**. Analysis of Leisure Expenditures in the United States. In T. Mauldin (Eds.), ***Proceedings of the American Council on Consumer Interests. 39th Annual Conference***, 194-200.
22. Deaton, A. **(1992)**. Understanding Consumption. ***Clarendon Press***.
23. Delgado, C. L., Hopkins, J., Kelly, V. A., Hazell, P., Mckenna, A. A., Gruhn, P., Hojjati, B., Sil, J. and Courbois, C. **(1998)**. Agricultural Growth Linkages in Sub-Saharan Africa. ***Washington, DC: International Food Policy Research Institute***.
24. Denison, E. F. **(1962 a)**. The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before Us. New York. ***Committee on Economic Development. Supplementary***, Paper No. 13, 1- 297.
25. Denison, E. F. **(1962 b)**. United States Economic Growth. ***Journal of Business***, 35: 109-121.

26. Denison, E. F. **(1967)**. Why Growth Rates Differ: Post-War Experience in Nine Western Countries. ***Washington, D.C.: Brookings Institution***.
27. Dornbusch, R., Fischer, S. and Startz, R. **(2009)**. Macro Economics. ***Tata Mcfraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi***.
28. Enthoven, A. **(1957)**. The Growth of Instalment Credit and the Future of Prosperity. ***The American Economic Review***, 913-929.
29. Erulkar, A. and Chong, E. **(2005)**. Evaluation of a Savings and Micro-Credit Program for Vulnerable Young Women in Nairobi. ***Nairobi: Population Council***.
30. Friedman, M. **(1957)**. A Theory of the Consumption Function. ***The National Bureau of Economic Research, Princeton University Press***.
31. Gianie, A. and Purwanto **(2013)**. Analysis of Consumer Behavior Affecting Consumer Willingness to Buy in 7-Eleven Convenience Stores. ***Universal Journal of Management***, 1 (2): 69-75.
32. Giovanni, A. **(1983)**. The Interest Elasticity of Saving in Developing Countries: The Existing Evidences. ***World Development***, 11: 890-951.
33. Glewwe, P. and Jacoby, H. **(2004)**. Economic Growth and the Demand for Education: Is there a Wealth Effect. ***Journal of Development Economics***, 74(1): 33-51.
34. Gross, D. B. and Souleles, N. S. **(2002)**. Do Liquidity Constraints and Interest Rates Matter for Consumer Behaviour? Evidence from Credit Card Data. ***Quarterly Journal of Economics***, 117 (1): 149-185.
35. Haque, M. and Saleem, M. A. **(1991)**. From Accounts, Family Budgets of Rural Families and Cost of Production of Major Crops in Punjab: 1988-89. ***Punjab Economic Research Institute, Lahore***.
36. Harrison, B. **(1986)**. Spending Patterns of Older Persons Revealed in Expenditure Survey. ***Monthly Labor Review***, 15-17.
37. Hazell, P. B. R. and Haggblade, S. **(1993)**. Farm-Non-Farm Growth Linkages and the Welfare of the Poor. In Lipton, M. & Van Der Graag, J. (Eds.), ***Proceedings of A Symposium Organized by the World Bank and the International Food Policy Research Institute. Washington, DC: World Bank***, 190-204.
38. Hendriks, S. L. **(2002)**. Expenditure Elasticities and Growth Linkages for Rural Households in Two Study Areas of KwaZulu-Natal. ***Unpublished PhD Thesis,***

Discipline of Agricultural Economics, University of Natal, Pietermaritzburg, South Africa.

39. Hussein, M. A. **(1996)**. Long Run Determinates of Private Savings Behaviour in Pakistan. ***The Pakistan Development Review***, 34: 1057-1066.
40. Iqbal, Z. **(1993)**. Institutional Variations in Saving Behaviour in Pakistan. ***The Pakistan Development Review***, 32: 1293-1311.
41. Jorgenson, D. W. and Griliches, Z. **(1967)**. The explanation of productivity change. ***Review of Econoic Studies***, 34: 249-283.
42. Jorgenson, D. W., Gollop, F. M. and Fraumeni, B. M. **(1987)**. Productivity and U.S. Economic Growth. Cambridge, Mass. ***Harvard University Press***.
43. Katona, G., Klein, L. R., Lansing, J. B. and Morgan, J. N. **(1954)**. Statistical Estimation of Economic Relations from Survey Data. ***Contributions of Survey Methods to Economics, New York: Columbia University Press***, 189-240.
44. Kazmi, A. **(1996)**. National Saving Rates of India and Pakistan: The Macro econometric Analysis. ***The Pakistan Development Review***, 34: 1313-1324.
45. Kendrick, J. W. **(1961)**. Productivity Trends in the United States. ***Princeton, N.J.: Princeton University Press***.
46. Kendrick, J. W. **(1973)**. Postwar Productivity Trends in the United States, 1948-1969. ***New York: Columbia University Press***.
47. Khan, A. H. **(1988)**. Financial Repression Development and Structure of Saving in Pakistan. ***The Pakistan Development Review***, 27: 702-713.
48. Khan, A. H. Z. and Nasir, M. **(1998)**. Stylized Facts of Household Saving: Findings from the HIES 1993-94. ***The Pakistan Development Review***, 37: 749-763.
49. Kuznets, S. **(1937)**. National Income and Capital Formation, 1919-1935. ***National Bureau of Economic Research***.
50. Kuznets, S. S. **(1965)**. Economic Growth and Structure. ***New York: Norton***.
51. Kuznets, S. S. **(1966)**. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. ***New Haven, Conn.: Yale University Press***.
52. Kuznets, S. S. **(1971)**. Economic Growth of Nations. ***Cambridge, Mass.: Harvard University Press***.
53. Kuznets, S. S. **(1973)**. Population, Capital and Growth. ***New York: Norton***.

54. Lerman, R. I. and Mc-Kernan, S. M. **(2009)**. Benefits and Consequences of Holding Assets. In S. M. McKernan, & M. Sherraden (Eds.), ***Asset Building and Low-Income Families. Washington DC: Urban Institute Press***, 175-206.
55. Lewis, W. A. **(1954)**. Economic Developnrent with Unlimited Supplies of Labour. ***Manchester School of Economics and Social Sciences***, 158.
56. Molana, H. **(1990)**. The Time Series Consumption Function: Error Correction, Random Walk and Steady State. ***Economic Journal***, 101: 382-402.
57. Muellbauer, J. N. (1994). The Assessment: Consumer Expenditure. ***Oxford Review of Economic Policy***, 10: 1-41.
58. Nasir, S. and Khalid, M. **(2004)**. Saving-investment Behaviour in Pakistan: An Empirical Investigation. ***The Pakistan Development Review***, 43 (4): 665–682.
59. Neal, E. G., Schwenk, F. N. and Courtless, J. C. **(1990)**. Apparel Expenditures of Older Consumers. ***Family Economica Review***, 3: 12-17.
60. Norum, P. S. **(1987)**. Household Expenditures on Clothing and Textiles. In V. Hampton (Eds.), ***Proceedings of the American Council on Consumer Interests. 33th Annual Conference***, 277-281.
61. Panikar, P. G. K. **(1970)**. Rival Serving in India, Bombay. ***Somaya Publications***, 29.
62. Patinkin, D. **(1965)**. Money, Interst and Prices. ***(Eds. II) Harper and Row, New York***, 50.
63. Qureshi, Z. M. **(1981)**. Household Saving in Pakistan: Some Findings from Time Series Data. ***The Pakistan Economics Review***, 20: 375- 397.
64. Rehman, H. and Ahmed, S. **(2008)**. An Empirical Analysis of the Determinants of Bank Selection in Pakistan. ***Pakistan Economic and Social Review***, 46(2): 147-160.
65. Sadaf, N. **(1994)**. Household Saving Behaviour in Life Cycle Hypothesis. ***Department of Economics. Quaid-e-Azam University, Islamabad***.
66. Schreiner, M. and Sherraden, M. **(2007)**. Can the Poor Save? Saving and Asset Building in Individual Development Accounts. ***New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers***.
67. Schwenk, N. E. **(1993)**. Housing Expenditures of the Elderly: Owners and Renters. ***Family Economics Review***, 6: 2-7.

68. Sethi, T. T. **(1981)**. Monetary Economics. ***S. Chand and Company, New Delhi***.
69. Sewamala, F. M. and Ismayilova, L. **(2009)**. Integrating Children Savings Accounts in the Care and Support of Orphaned Adolescents in Rural Uganda. ***Social Service Review***, 83: 453-472.
70. Shapiro, E. **(1996)**. Macroeconomic Analysis. ***Galgotia Publication, New Delhi***.
71. Shem, A. O. **(2002)**. Financial Sector Dualism: Determining Attributes for Small and Micro Enterprises in Urban Kenya: A Theoretical and Empirical Approach Based on Case Studies in Nairobi and Kisumu. ***Aachen, Shaker Verlag***.
72. Siddique, R. and Siddique, R. **(1993)**. Household Saving Behaviour in Pakistan. **The Pakistan Development Review**, 32: 1-27.
73. Smithies, A. **(1965)**. Forecasting Post-War Demand. ***Econometrica***.
74. Solow, R. M. **(1956)**. A Contribution to the Theory of Economic Growth. ***Quarterly Journal of Economics***, 70: 65-94.
75. Solow, R. M. **(1957)**. Technical Change and the Aggregate Production Function. ***Review of Economics and Statistics***, 39: 312-320.
76. Sukhatme, P.V. and Sukhatme, B.V. **(1986)**. Sampling Theory of Surveys with Applications. ***Iowa State University Press and Indian Society of Agriculture Statistics, New Delhi***.
77. Talbot, M. N. **(1990)**. Households with Expenditures for Entertainment Services. ***Family Economics Review***, 2: 21-24.
78. Volker, C. B. and Winter, M. **(1989)**. Primary Household Production of Food, Food Expenditure and Reported Adequacy of Food. ***Home Economics Research Journal***, 18: 32-46.
79. Walker, R. C. and Schwenk, F. N. **(1991)**. Income and Expenditure Patterns of Consumer Units with Reference Person Age 70 to 79 and 80 or Older. ***Family Economics Review***, 4: 8-13.
80. Williams Shanks, T. R., Kim, Y., Loke, V. and Destin M. **(2010)**. Assets and Child Well-Being in Developed Countries. ***Children and Youth Services Review***, 32: 1488-1496.

*****

प्रश्नावली

आय, उपभोग एवं बचत सर्वेक्षण

प्रश्नावली

आय, उपभोग एवं बचत सर्वेक्षण

(A) परिचयात्मक खण्ड :

(1) सूचनादाता का नाम– श्री / श्रीमती .....

(2) लिंग – पुरूष / महिला .....

(3) धर्म – हिन्दू / मुश्लिम / सिख / ईसाई / अन्य .....

(4) आयु .....

(5) जाति – सामान्य / एस.टी. / एस.सी. / ओ.बी.सी. / अन्य .....

(6) निवास का पता – ग्राम / कस्बा / शहर .....

तहसील....., जिला ....., राज्य .....,

(B) पारिवारिक संरचना :

क्रम संख्या	सदस्यों का नाम	आयु वर्षो में	लिंग	मुखिया से सम्बन्ध	शैक्षणिक स्तर	कार्यशील सदस्यों का व्यवसाय
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

(C) कृषि–भूमि (क्षेत्रफल हेक्टेयर में) :

1. स्वाधिकृत (Owned)	
2. पट्टे पर ली गई (Leasedin)	
3. अन्य (Other)	
4. कुल धारित (Total Possessed)	

(D) परिवार की मासिक आय (Memory Recall) :

क्रम संख्या	आय स्त्रोत	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	कृषि						
2.	अन्य कृषि उद्यम						
3.	मजदूरी/वैतनिक रोजगार						
4.	गैर कृषि उद्यम						
5.	पेंशन						
6.	ब्याज तथा लाभांश						
7.	अन्य						
कुल वार्षिक आय							
औसत मासिक आय							

(E) गत माह में रोजगार व आय–उपार्जन की स्थिति :

क्रम संख्या	परिवार के कार्यशील सदस्यों का नाम	रोजगार के प्रकार	रोजगार की स्थिति			उपार्जित आय (रू)
			पूर्ण कालिक रोजगार	आंशिक बेरोजगार	पूर्णतः बेरोजगार	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
कुल आय						

(F) आपकी राय में उक्त आय से एक सामान्य परिवार का जीवन–स्तर रह सकता हैं :– उच्च/मध्यम/निम्न

(G) क्या आप वर्तमान कार्य एवं आय–स्तर से सन्तुष्ट हैं :– हाँ/नहीं। नहीं तो भविष्य के लिए क्या सोच हैं ?

(H) उपभोग व्यय : परिवार का औसत मासिक व्यय विवरण (MRC) :

(H -i) अनाज समूह :

क्रम संख्या	अनाज समूह	मात्रा	वर्ष 2009			वर्ष 2014		
			मात्रा	मूल्य	व्यय	मात्रा	मूल्य	व्यय
1.	चावल	कि.ग्रा.						
2.	गेहूँ/आटा	कि.ग्रा.						
3.	मैदा	कि.ग्रा.						
4.	सूजी	कि.ग्रा.						
5.	बाजरा	कि.ग्रा.						
6.	मक्का	कि.ग्रा.						
7.	जौ	कि.ग्रा.						
8.	अन्य	कि.ग्रा.						
कुल वार्षिक व्यय								
औसत मासिक व्यय								

(H-ii) दाल समूह :

क्रम संख्या	दाल समूह	मात्रा	वर्ष 2009			वर्ष 2014		
			मात्रा	मूल्य	व्यय	मात्रा	मूल्य	व्यय
1.	अरहर	कि.ग्रा.						
2.	चना	कि.ग्रा.						
3.	मूंग	कि.ग्रा.						
4.	उड़द	कि.ग्रा.						
5.	मसूर	कि.ग्रा.						
6.	अन्य	कि.ग्रा.						
कुल वार्षिक व्यय								
औसत मासिक व्यय								

(H-iii) दुग्ध समूह :

क्रम संख्या	दुग्ध समूह	मात्रा	वर्ष 2009			वर्ष 2014		
			मात्रा	मूल्य	व्यय	मात्रा	मूल्य	व्यय
1.	दुग्ध तरल	लीटर						
2.	शिशु आहार	लीटर						
3.	दूध(पाउडर)	लीटर						
4.	दही	लीटर						
5.	घी	लीटर						
6.	मक्खन	लीटर						
7.	अन्य	लीटर						
कुल वार्षिक व्यय								
औसत मासिक व्यय								

(H-iv) खाद्य तेल समूह :

क्रम संख्या	खाद्य तेल	मात्रा	वर्ष 2009			वर्ष 2014		
			मात्रा	मूल्य	व्यय	मात्रा	मूल्य	व्यय
1.	वनस्पति तेल	कि.ग्रा.						
2.	सरसों का तेल	कि.ग्रा.						
3.	मूंगफली का तेल	कि.ग्रा.						
4.	नारियल का तेल	कि.ग्रा.						
5.	अन्य	कि.ग्रा.						
कुल वार्षिक व्यय								
औसत मासिक व्यय								

(H-v) सब्जियाँ समूह :

क्रम संख्या	सब्जियाँ समूह	मात्रा	वर्ष 2009			वर्ष 2014		
			मात्रा	मूल्य	व्यय	मात्रा	मूल्य	व्यय
1.	आलू	कि.ग्रा.						
2.	अरबी	कि.ग्रा.						
3.	लौकी	कि.ग्रा.						

4.	करेला	कि.ग्रा.						
5.	गोभी	कि.ग्रा.						
6.	बैंगन	कि.ग्रा.						
7.	भिंडी	कि.ग्रा.						
8.	पालक	कि.ग्रा.						
9.	अन्य	कि.ग्रा.						
कुल वार्षिक व्यय								
औसत मासिक व्यय								

(H-vi) फल समूह :

क्रम संख्या	फल समूह	मात्रा	वर्ष 2009			वर्ष 2014		
			मात्रा	मूल्य	व्यय	मात्रा	मूल्य	व्यय
1.	केला	कि.ग्रा.						
2.	तरबूज	कि.ग्रा.						
3.	अनार	कि.ग्रा.						
4.	अमरूद	कि.ग्रा.						
5.	संतरा/मौसमी	कि.ग्रा.						
6.	सेव	कि.ग्रा.						
7.	आम	कि.ग्रा.						
8.	अंगूर	कि.ग्रा.						
9.	नाशपती	कि.ग्रा.						
10.	अन्य	कि.ग्रा.						
कुल वार्षिक व्यय								
औसत मासिक व्यय								

(H-vii) सेवा उपभोग –

क्रम संख्या	सेवा समूह	वर्ष 2009	वर्ष 2014
		व्यय	व्यय
1.	शिक्षा		
2.	चिकित्सा		
3.	यात्रा		
कुल वार्षिक व्यय			
औसत मासिक व्यय			

(H-viii) अन्य उपभोग समूह :

क्रम संख्या	अन्य समूह	मात्रा	वर्ष 2009			वर्ष 2014		
			मात्रा	मूल्य	व्यय	मात्रा	मूल्य	व्यय
1.	चीनी	कि.ग्रा.						
2.	गुड़	कि.ग्रा.						
3.	नमक	कि.ग्रा.						
4.	हल्दी	ग्राम						
5.	कालीमिर्च	ग्राम						
6.	सूखीमिर्च	ग्राम						
7.	लहसून	ग्राम						
8.	अदरक	ग्राम						
9.	चाय	ग्राम						
10.	कॉफी	ग्राम						
11.	बीड़ी	पैकिट संख्या						
12.	सिगरेट	पैकिट संख्या						
13.	बिजली	यूनिट						
14.	मिट्टी का तेल	लीटर						
15.	गैस सिलेण्डर	संख्या						
16.	कपड़े	मीटर						
17.	जूते	नग						

18.	साबुन	पैकिट संख्या						
19.	फर्नीचर	नग						
20.	टेलीविजन	नग						
21.	आभूषण	नग						
22.	वाशिंगमशीन	नग						
23.	रेफ्रीजरेटर	नग						
24.	प्रेशर कूकर	नग						
25.	मोटर कार/जीप	नग						
26.	मोटरसाइकिल/ स्कूटर/साइकिल	नग						
27.	आवासीय भवन/ मरम्मत	नग						
28.	परिवार के बर्तन	नग						
29.	अन्य							
कुल वार्षिक व्यय								
औसत मासिक व्यय								

क्रम संख्या		**2009 वर्ष**	**2014 वर्ष**
1.	**समग्र कुल व्यय**		
2.	**मासिक औसत व्यय**		

(H-ix) क्या आप वर्तमान उपभोग–स्तर से सन्तुष्ट हैं : हाँ/नहीं। यदि नहीं तो

(i) आपके द्वारा वांछित उपभोग–स्तर न पाने का कारण :

(अ) कीमत–वृद्धि (ब) कम आय

(स) बड़ा परिवार (द) अन्य

(ii) किन मदों पर आप इच्छानुसार व्यय करने की स्थिति में नहीं हैं ?

.....

(iii) सरकार की विभिन्न योजनाओं से आपका परिवार किस तरह का लाभ ले रहा हैं ?

क्रम संख्या	कार्यक्रम का नाम	आर्थिक लाभ
1.		
2.		
3.		
4.		

(H-x) आप उपभोग सम्बन्धी निर्णय करते हैं :

क्रम संख्या	उपभोग निर्णय	हाँ/नहीं में
1.	परिवार की वर्तमान आवश्यकतानुसार	
2.	सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार	
3.	आदतों से प्रभावित होकर	
4.	भविष्य की स्थिति को ध्यान में रखकर	
5.	अन्य	

(I) परिवार का औसत मासिक बचत विवरण :

(I-i) क्या आप अपनी आय में से बचत करते है। हाँ/नहीं, यदि हाँ तो निम्न में सें किन उद्देश्यों के लिए बचत करते हैं :

क्रम संख्या	बचत के उद्देश्य	हाँ/नहीं में
1.	बच्चों की भावी आवश्यताओं (फीस आदि) को पूरा करने हेतु	
2.	टिकाऊ उपभोग वस्तु क्रय करने हेतु	
3.	पारिवारिक व सामाजिक (विवाह, उत्सव, संस्कार आदि) दायित्वों को पूरा करने हेतु	
4.	अवकाश के दिनों का आनन्द लेने हेतु	
5.	आकस्मिक घटनाओं से सुरक्षा/मानसिक शांति हेतु	
6.	निवेश करने के लिए	
7.	बुढ़ापे में सुरक्षा हेतु	
8.	ऋण के भुगतान हेतु	

(I-ii) आपकी पिछले पांच वर्ष की औसत वार्षिक आय, व्यय एवं बचत का विवरण :

वर्ष	आय	व्यय	बचत
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			

(I-iii) आपकी गत माह में बचत की गई राशि .....

आप बचत किस रूप में निवेश करते हैं :

क्रम संख्या	**बचत का रूप**	**हाँ/नहीं में**
1.	बचत/मयादी जमा खाता में	
2.	नकद	
3.	बॉण्डस	
4.	इक्विटीज में (शेयर बाजार में)	
5.	भौतिक सम्पत्ति क्रय में	

(I-iv) क्या आप अपेक्षानुसार बचत कर पाते हैं – हाँ/नहीं। यदि नहीं तो क्यों ?

क्रम संख्या	**बचत नहीं करने का कारण**	**हाँ/नहीं में**
1.	बचत शक्ति / आय का अभाव	
2.	बचत सुविधा का अभाव	
3.	निवेश पर प्रतिफल दर कम होना	
4.	मुद्रास्फीति की अधिक दर	

(I-v) क्या आप बचत को अधिक करेंगे –

क्रम संख्या	**कारण**	**हाँ/नहीं में**
1.	आय बढ़ने पर	
2.	ब्याज दर बढ़ने पर	

(I-vi) आपने जीवन बीमा करवा रखा है – हाँ/नहीं। यदि हाँ तो :

क्रम संख्या	कारण	हाँ/नहीं में
1.	सरकारी योजनान्तर्गत है	
2.	स्वेच्छा से करवाया है	

(I-vi-i) उद्देश्य :

क्रम संख्या	कारण	हाँ/नहीं में
1.	आय कर बचाने के लिए	
2.	परिवार की सुरक्षा हेतु	
3.	बचत का सरल तरीका	

(I-vii) क्या आप आयकर देते हैं – हाँ/नहीं। यदि हाँ तो कितना .....

(I-viii) क्या आपने ऋण ले रखा है। हाँ/नहीं। यदि हाँ तो ऋण स्त्रोत :

क्रम संख्या	संस्थाएँ	ऋण की मात्रा	ब्याज दर	पुनर्भुगतान राशी (मासिक)
1.	सरकारी			
2.	सहकारी			
3.	निजी			
4.	बैंक से			
	कुल ऋण की मात्रा			

(I-ix) विशिष्ट जानकारी :

(i) आय के सम्बन्ध में .....

.....

(ii) बचत के सम्बन्ध में .....

.....

*****

शोध–पत्र

Published Research Papers

(1) Narendra Kumar Meena, Aruna Kaushik. Assessing the Saving Pattern of Different Income Group Households in District Dausa, Rajasthan. ***International Journal of Marketing & Financial Management***, Volume 4, Issue 2, pp. 61-68, Year 2016. (Impact factor: 0.98).

Participated/Papers Presented in National/International Conferences

1. International Conference on "India as an Emerging Power in 21st Century: Possibilities and Challenges before Indian Foreign Policy". January, **2013**. Govt. College, Kota, (Raj.).
2. National Seminar on "Yoga for Health, Wealth and Fitness". December, **2014**. Rajesh Pilot Govt. P.G.College, Lalsot, Dausa (Raj.).
3. Annual Research Seminar. January, **2015**. J. D. B. Govt. Girls College, Kota, (Raj.).
4. 4th Conference on "Health System Strength and Reforms in India: Retrospect and Prospect". February, **2015**. Department of Economics at University of Rajasthan and Azim Premji University.
5. National Seminar on "Literature Surgeon and Environment Protection". January, **2016.** Rajesh Pilot Govt. P.G.College, Bandikui, Dausa (Raj.).
6. 37th Annual Conference of Rajasthan Economic Association on "Sustainable Development and Inclusive Growth: Prospects and Challenges". January, **2017.** Department of Social Sciences, University of Kota.

*****